Motion Of Thanks On The President's Address

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ:-

?कि राष्ट्रपति जी की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए:-

?कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण, जो उन्होंने 31 जनवरी, 2025 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, के लिए उनके अत्यंत आभारी हैं ।?

महोदया, मैं इस पवित्र और सम्मानित सदन में माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के समर्थन में अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूँ ।

सभापति महोदया, मेरे लिए यह बेहद सौभाग्य की बात है कि मुझे आदरणीय राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण पर चर्चा की शुरूआत करने का अवसर प्राप्त हुआ है । इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं । माननीय राष्ट्रपति जी का अभिभाषण न केवल भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधान मंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार की नीतियों का दर्पण है, बल्कि यह देश के उज्ज्वल भविष्य की दिशा को भी स्पष्ट करने वाला है । यह भारत का सौभाग्य है कि आज हमारे देश का नेतृत्व एक ऐसे दूरदर्शी और विश्व प्रसिद्ध राजनेता माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के हाथों में है, जिनके हृदय में देश की 140 करोड़ जनता के लिए प्रेम का सागर उमड़ता है । उन्हें इस देश की मिट्टी से बेइंतहा लगाव है और उनकी आंखों में भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना निरंतर पलता है । जैसा कि आदरणीय राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा है कि आज हमारा देश चहुंमुखी विकास के रास्ते पर है । बीते दस वर्षों में भारत ने तरक्की और विकास के लिए प्रतिमान स्थापित किए हैं । माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में उनकी सरकार का तीसरा काल भारत की समृद्धि का नया इतिहास रचेगा । जनकल्याण की नीतियों को तेजी से लागू किया जा रहा है । यह सचमुच भारत में समृद्धि का अमृतकाल है ।

आदरणीय सभापति महोदया, मैं प्रधान मंत्री जी के प्रति बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने आम बजट में 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगाया है । इसकी घोषणा भी इस सदन में भारत की माननीय वित्त मंत्री महोदया ने की है । देश के मध्यम वर्ग के लोगों के लिए यह एक ऐतिहासिक फैसला है । देश की किसी भी सरकार ने आज तक मध्यम वर्ग को इतनी बड़ी राहत नहीं दी है । आठवें वेतन आयोग का गठन भी किया गया है ।

महोदया, इस वर्ष भारतीय संविधान के 75 वर्ष पूरे हुए हैं । इस अवसर पर संविधान के निर्माता पूज्य डॉ. भीम राव अम्बेडकर को सारा देश नमन करता है । पूरे देशवासियों को इस बात की खुशी है कि माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी देश के पहले प्रधान मंत्री हैं, जिन्होंने बाबा साहब की 125वीं जयंती पर उनके जन्म स्थान महू में जाकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं । बाबा साहब के जीवन से जुड़े पांच प्रमुख स्थलों का पंच तीर्थ

के रूप में विकास किया गया है । ये पंच तीर्थ उनका जन्म स्थान महू, दीक्षा स्थान नागपुर, मुम्बई में स्मारक, लंदन में स्मारक और दिल्ली में अलीपुर रोड स्मारक । इसके अलावा दिल्ली में जनपथ पर भी बाबा साहब की स्मृति में डॉ. भीम राव अम्बेडकर इंटरनेशल सेंटर का निर्माण भी किया गया है । वर्ष 1990 से पहले संसद के सैंट्रल हाल में बाबा साहब की तस्वीर नहीं थी । जब वर्ष 1990 में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से देश में सरकार बनी, देश के भूतपूर्व प्रधान मंत्री भारत रत्न श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस समय जो सरकार भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से चल रही थी, उस सरकार से आग्रह किया कि देश की संसद में सैंट्रल हाल में बाबा साहब की तस्वीर लगाई जाए । बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि जी जाए और इसके साथ-साथ बाबा साहब के जन्म दिन पर छुट्टी घोषित की जाए । माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के आग्रह पर यह सब कुछ संभव हो पाया ।

महोदया, भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है । मैं आज सदन में कहना चाहता हूं कि आज पूरा राष्ट्र देश के प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के प्रति गौरव महसूस कर रहा है, उनका अभिनंदन कर रहा है । मैं एक किसान परिवार से ताल्लुक रखता हूं । हमारे प्रधान मंत्री जी के हृदय में किसानों के प्रति गहरा लगाव है । प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि के तहत देश के करोड़ों किसानों के बैंक खातों में लगभग तीन लाख करोड़ रुपयों से ज्यादा रकम भेजी गई है । देश के किसानों की आय में वृद्धि हुई है । भारत में 332 मिलियन टन अनाज का रिकार्ड उत्पादन हुआ है । हमारा देश लगातार दूध, दलहन, मसालों का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश बना हुआ है । किसानों को दिए जाने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य में लगातार वृद्धि हुई है और महान किसान नेता देश के भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न की उपाधि देकर सम्मानित किया है । यह सभी किसानों के लिए गौरव की बात है ।

आदरणीय सभापति महोदया, जहां तक प्रधान मंत्री आवास योजना की बात है, तो माननीय प्रधान मंत्री जी ने अपने दस सालों के शासन काल में लगभग साढ़े चार करोड़ गरीब लोगों के मकान बनाने का लक्ष्य रखा, उसमें से पौने तीन करोड़ मकान बन चुके हैं ।

महोदया, मुझे यह बताते हुए बहुत कष्ट हो रहा है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में प्रधान मंत्री आवास योजना को लागू नहीं होने दिया । दिल्ली में लाखों लोग रहते हैं । इनमें ज्यादातर वे लोग हैं, जो पूर्वांचल से आए हैं । यदि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में प्रधान मंत्री आवास योजना को लागू हो जाने देती तो दिल्ली के लाखों लोगों को प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान मिल जाते । मैं देश के प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि मोदी जी ने दिल्ली में लाखों झुग्गी-झोपड़ी वासियों के लिए, ?जहां झुग्गी वहीं मकान? बनाने की योजना शुरू की है । 7,000 झुग्गी वासियों को पक्के फ्लैट्स दिए गए हैं । झुग्गी वासियों को जो फ्लैट दिए गए हैं, उस एक फ्लैट की मार्केट वैल्यू 40 लाख रुपये है ।

आदरणीय सभापति महोदया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार की सहायता से दिल्ली के झुग्गी-झोपड़ी वासियों के लिए दिल्ली में 53,000 फ्लैट्स बनाए गए । मोदी जी की सरकार ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार से बार-बार आग्रह किया कि ये जो 53,000 फ्लैट्स बनाए गए हैं, जो केन्द्र सरकार की सहायता से बनाए गए हैं, इन फ्लैट्स को दिल्ली के झुग्गी-झोपड़ी वासियों को एलॉट किया जाए । दिल्ली के अन्दर अरविन्द केजरीवाल की सरकार ने सैकड़ों झुग्गी-झोपड़ी वासियों को उजाड़ा, लेकिन उसने एक भी झुग्गी वासी को किसी फ्लैट में पुनर्वासित नहीं किया, जिससे आज फ्लैट्स की हालत जर्जर हो गयी है । यह स्थिति आज दिल्ली के अन्दर पैदा हुई है । एक तरफ मोदी जी दिल्ली के झुग्गी-झोपड़ी वासियों के लिए ?जहां झुग्गी वहीं मकान? बनाने की व्यवस्था कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अपने रहने के लिए 179 करोड़ रुपये खर्च करके ?शीशमहल? बनाते हैं, कानून-कायदे का उल्लंघन करके ? शीशमहल? बनाते हैं ।

आदरणीय अध्यक्ष महोदया, पूरे देश में आयुष्मान भारत योजना लागू हो गयी । पूरे देश में लगभग 7 करोड़ लोगों को इसका फायदा पहुंचा है । मोदी जी की सरकार ने इस योजना के ऊपर लगभग 1 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, उसने दिल्ली के अन्दर आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं होने दिया । हम आदरणीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि उन्होंने यह फैसला लिया कि जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, जिनकी उम्र 70 साल से ज्यादा है, चाहे वे अमीर हैं, चाहे वे गरीब हैं, सभी के लिए 5 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की व्यवस्था की जाएगी । इस 5 लाख के अलावा और 5 लाख रुपये इसके लिए दिल्ली में बनने वाली भाजपा सरकार देगी । 10 लाख रुपये वरिष्ठ नागरिकों के इलाज पर मोदी जी की सरकार खर्च करेगी । आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में इसे लागू नहीं होने दिया ।

आदरणीय सभापति महोदया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब किसी गरीब का बेटा बीमार होता है, उसे अस्पताल में दाखिल किया जाता है और मोदी जी की जो आयुष्मान भारत योजना है, उस योजना के चलते जब अस्पताल में उसका ठीक-ठाक से इलाज हो जाता है और जब वह इलाज कराकर ठीक होकर घर लौट कर आता है तो उस बेटे के माँ-बाप भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं और उसके बाद उसकी माँ कहती है - ?मेरा बेटा ठीक हो गया, मेरी उम्र भी मोदी जी को लग जाए ।? यह उसके अन्दर से आवाज़ आती है । ऐसी योजना को दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में लागू नहीं होने दिया । मैं इसकी कड़ी निंदा करना चाहता हूं ।

आदरणीय सभापति महोदया, दिल्ली के अंदर पीएम-विश्वकर्मा योजना को लागू नहीं होने दिया गया । लगभग दो करोड़ 62 लाख लोग अभी तक पूरे देश में रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं । हमारे कारीगर चाहे लुहार, खाती, कुम्हार, मोची या राजमिस्त्री हैं, ऐसे जो लोग

हैं, जिनके पास हाथ का हुनर है, जो अपना कारोबार करना चाहते हैं, सम्मान के साथ कारोबार करना चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं आर्थिक संकट उनके सामने आ जाता है तो मोदी जी की सरकार ने पीएम-विश्वकर्मा योजना शुरू की । यदि किसी कारीगर को अपना कारोबार शुरू करने के लिए धन की आवश्यकता है, तो रजिस्ट्रेशन करवाइए, एक लाख रुपये से ले कर तीन लाख रुपये 15 दिनों के अंदर उपलब्ध हो जाएंगे । इस पीएम-विश्वकर्मा योजना को भी दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने लागू नहीं होने दिया ।

आदरणीय सभापति महोदया, दिल्ली में ही नहीं, पूरे देश भर में मोदी जी की सरकार ने 12 करोड़ शौचालय बनाए हैं । दिल्ली में हमारे लाखों झुग्गीवासी हैं, जिनके पास शौचालय नहीं है । मोदी जी की सरकार चाहती थी कि दिल्ली के अंदर भी शौचालय बनाए जाएं, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार ने, दिल्ली के पूर्व मुख्य मंत्री ने दिल्ली में शौचालय बनाने की अनुमति नहीं दी । यह जानकारी भी मैं इस हाउस के अंदर देना चाहता हूँ ।

आदरणीय सभापति महोदया, देश के यशस्वी प्रधान मंत्री आदरणीय मोदी जी देश के 80 करोड़ लोगों को हर महीने मुफ्त राशन उपलब्ध करा रहे हैं । दिल्ली के अंदर मोदी जी की सरकार 72 लाख लोगों को चार किलो गेहूं, एक किलो चावल मुफ्त उपलब्ध करा रही है । लेकिन पिछले दस सालों से दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली के गरीब लोगों को राशन कार्ड बना कर नहीं दिए । यदि दिल्ली के गरीब लोगों को राशन कार्ड मिल जाएगा तो इससे मोदी जी की लोकप्रियता गरीब लोगों में बढ़ जाएगी । अरे! दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेताओं, कम से कम यदि गरीबों के लिए कोई योजना देश के प्रधान मंत्री मोदी जी के द्वारा चलाई जा रही है, आप उसमें अड़चन क्यों उत्पन्न कर रहे हो । मैं इसकी कड़ी निंदा करना चाहता हूँ ।

आदरणीय सभापति महोदया, दिल्ली के अंदर उज्जवला योजना के अंतर्गत 10 करोड़ महिलाओं को लाभ पहुंचा है । देश भर में 14000 जन औषधी केंद्र खोले गए हैं । मैं दिल्ली के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ कि 642 जन औषधी केंद्र बनाए गए हैं । जो दवाई मार्केट में 100 रुपये की मिलती है, वही जन औषधी केंद्र से 20 रुपये में उपलब्ध हो जाती है । हज़ारों-करोड़ रुपये का फायदा मोदी जी की सरकार के द्वारा जन औषधी केंद्र खोल कर पहुंचाया गया है ।

आदरणीय सभापति महोदया, बेहतर कौशल और नए अवसरों के सृजन के लिए दो लाख करोड़ रुपये का पैकेज स्वीकृत किया गया है । इससे रोज़गार के नए अवसर पैदा हुए हैं । मैं आपको दिल्ली के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ, कांग्रेस के लोग भी यहां बैठे हुए हैं, दिल्ली में जब शीला दीक्षित की सरकार थी, तब वर्ष 2012 में सिंगापुर के साथ मिल कर एक वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर की नींव 40 एकड़ ज़मीन पर रखी गई । वहां कम से कम दस हज़ार बच्चों को ट्रेनिंग मिलती । मोदी जी की सरकार ने लैंड यूज़ चेंज कर

दिया । लेकिन वर्ष 2012 से ले कर आज तक, जौनापुर में सिंगापुर सरकार की सहायता से जो वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर बनना था, दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने उसको नहीं बनने दिया । यह दिल्ली देहात के युवाओं की पीठ में छुरा घोंपा गया है, उनके साथ विश्वासघात किया गया है ।

आदरणीय सभापति महोदया, आज मैं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक स्टेटमेंट देख रहा था कि भाजपा के पास न नेता है और न कोई विज़न है । मैं उनको आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारे पास अभी वर्ष 2025 का जो सर्वे है, उसके मुताबिक हमारे पास दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी हैं । उनके पास काम करने की नीति भी है और काम करने की नीयत भी है ।

उन्होंने आज इस बात की चर्चा की है कि भाजपा के पास कोई विजन नहीं है । मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से और केन्द्र सरकार की ओर से माननीय हाउस को जानकारी देना चाहता हूं कि पिछले दस सालों में श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने दिल्ली को अनेकों विकास के तोहफे दिए हैं । आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर अपने कान खोलकर सुनें । मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद दिल्ली के चारों तरफ ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल रोड बनाया गया ।

सभापति महोदय, यह विकास की बात हो रही है, सुन लीजिए । मैं हाउस को जानकारी देना चाहता हूं कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद दिल्ली के चारों तरफ पेरिफेरल रोड बनाया गया, 43 हजार करोड़ रुपये उस पर खर्च हुए, दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को 3700 करोड़ रुपये उसके लिए देने थे लेकिन एक पाई पैसा नहीं दिया गया । जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के ध्यान में यह बात लायी गई तो मोदी जी ने कहा कि काम को रोकना नहीं है, दिल्ली के अंदर हर रोज 60 हजार ट्रक एंटर करते हैं और दिल्ली को प्रदूषित बनाते हैं, आज पेरिफेरल रोड बनकर तैयार हो गया है, 60 हजार ट्रक की एंट्री दिल्ली में बैन हो गई है । मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं । अपोजिशन के लोग जरा सुनने का माद्दा रखिए, हम भी आपको सुनते हैं ।

मोदी जी ने साउथ दिल्ली के बदरपुर में दुनिया का सबसे ? (व्यवधान) आप सुनने का माद्दा रखिए । आपको जब बोलने का अवसर मिलेगा तब आपको जो बोलना होगा, बोलिएगा । मोदी जी ने साउथ दिल्ली के बदरपुर में दुनिया का सबसे बड़ा ईको पार्क बनाया है, उसी ईको पार्क में जॉगिंग ट्रैक है, साइकिल ट्रैक है, इको पार्क में सफारी है, चिड़ियाघर है, उसी ईको पार्क में डेढ़ लाख दरख्त लगाए गए हैं । आपको मालूम है कि यह ईको पार्क कहां बनाया गया है । वहां एनटीपीसी का राख का ढ़ेर था, 885 एकड़ जमीन पर राख का ढ़ेर था । आज उस राख के ढ़ेर पर दुनिया का सबसे बड़ा ईको पार्क दिया है, जिसमें सफारी है, चिड़ियाघर है और डेढ़ लाख दरख्त भी लगाए गए हैं ।

सभापति महोदय, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि उस ईको पार्क में राख के ढ़ेर पर बोटिंग लेक बनाया गया है, हमारे बच्चे बोटिंग करेंगे, आज मैं यह बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं, इस धरती पर अगर भगवान आ जाए तब यह काम संभव है या जो यह चमत्कार दिल्ली की धरती पर हुआ है, ऐसा चमत्कार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी कर सकते हैं, कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता है ।

प्रगति मैदान के साथ डेढ़ किलोमीटर लंबी टनल बनायी गई है, दिल्ली में ट्रैफिक की समस्या है, एक हजार करोड़ रुपये डेढ़ किलोमीटर की टनल बनाने में खर्च किये गये, दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को 20 परसेंट देना था, हमारे कॉमर्स मिनिस्टर अभी नहीं हैं । मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि एक नया पैसा उस टनल को बनाने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार ने कंट्रीब्यूट नहीं किया ।

जब देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने यह मामला लाया गया तो उन्होंने कहा कि दिल्ली ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करना है, पैसा जितना भी लग जाए । दिल्ली की आम आदमी पार्टी एक पैसा न भी दे, लेकिन टनल के काम को नहीं रोकना है ।

सभापति महोदया, मैं साउथ दिल्ली को रिप्रेजेंट करता हूं । आप कभी मथुरा रोड पर गई होंगी । ऑपोजिशन के सारे माननीय सदस्य भी जाते हैं । मथुरा रोड पर घंटों-घंटों जाम लगा रहता था । मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने सराय काले खान से कालिंदी कुंज होते हुए और मीठापुर, फरीदाबाद, पलवल, सोहना होते हुए बड़ौदा, मुम्बई हाइवे तक 6500 करोड़ रुपये खर्च करके छ: लेन का हाइवे दिया है । मथुरा रोड पर अब ट्रैफिक जाम नहीं लगता है । मैं दिल्ली के लोगों की ओर से आदरणीय मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं ।

सभापति महोदया, दिल्ली में कोई वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर नहीं था । हमारे पास केवल एक विज्ञान भवन था । आदरणीय मोदी जी ने यशोभूमि द्वारका में 6500 करोड़ रुपये खर्च करके वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर बनाया है । मोदी जी ने एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर प्रगति मैदान में बनाया है । द्वारका में जो कन्वेंशन सेंटर बना है, उसमें 25,000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं । क्या इस हाउस को इसके लिए मोदी जी को धन्यवाद नहीं देना चाहिए? क्या उनके प्रति आभार व्यक्त नहीं करना चाहिए?

सभापति महोदया, दिल्ली में कोई वर्ल्ड क्लास पार्क नहीं था । मोदी जी के मार्गदर्शन में द्वारका में 137 एकड़ जमीन पर ?वंदना पार्क? विकसित किया गया, जिसके ऊपर 560 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं । उसकी नींव देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने रखी थी । वह बनकर तैयार हो गया है । आज दिल्ली के लाखों लोग उसमें मॉर्निंग वाक करते हैं । उसमें ओपन जिम लगे हुए हैं । जब बच्चे उसमें कसरत करते हैं तो मन से वे मोदी जी को दुआ देते हैं । यह मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं ।

सभापति महोदया, यदि हम इंडिया गेट की तरफ चलें तो वहां नेशनल वार मेमोरियल बनाया गया है । मोदी ने नेशनल वार मेमोरियल दिया है । देश के शहीदों को, देश के फौजियों को, पैरामिलिट्री फोर्सेज में जो लोग काम करते हैं, जो देश के लिए शहीद हो गए, उनकी याद में जो नेशनल वार मेमोरियल बनाया है, मैंने वशिंगटन में अमेरिका का भी नेशनल वार मेमोरियल देखा है, वशिंगटन का वह नेशनल मेमोरियल इसके सामने कहीं नहीं टिकता है । इसके लिए क्या हमें मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त नही करना चाहिए? हमें इस बात की खुशी है कि इंडिया गेट पर, जहां कभी इंग्लैंड के राजा की प्रतिमा लगती थी, आज उस स्थान पर मोदी जी ने नेता सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा लगाकर देश के शहीदों को जो सम्मान दिया है, यह पूरा राष्ट्र उनका ऋणी रहेगा । यह देश उनके प्रति आभार व्यक्त करता है ।

सभापति महोदया, आज मैं जिस ऐतिहासिक इमारत में खड़ा होकर बोल रहा हूं, यह इमारत भी मोदी जी ने बनाकर दी है ।

सभापति महोदया, मोदी जी ने जो कर्तव्य पथ दिया है, आज लाखों लोग हर रोज कर्तव्य पथ पर, इंडिया गेट पर एकत्रित होते हैं और मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं । हजारों खोखा पट्टी के लोगों को, जो फल, आइसक्रीम और पानी बेचते हैं, उनको रोजगार मिला है । कर्तव्य पथ की जो रौनक बढ़ी, वह देखने में अपने आप में बिल्कुल अलग है । दिल्ली के लोग मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं ।

सभापति महोदया, मैं यह जानकारी देना चाहता हूं कि आजादी के बाद से लेकर मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने तक दिल्ली पुलिस के पास अपना कोई पुलिस हेडक्वार्टर नहीं था । मोदी जी की सरकार ने जयसिंह रोड पर, कनॉट प्लेस में 1000 करोड़ रुपये खर्च करके दिल्ली पुलिस के लिए वर्ल्ड क्लास पुलिस हेडक्वार्टर बनाया है । मैं इसके लिए भी उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं ।

सभापति महोदया, वर्ष 2014 में दिल्ली-एनसीआर में मेट्रो का जो कुल नेटवर्क था, वह 200 किलोमीटर था । अब वह बढ़कर दोगुना हो गया है ।

मैं दिल्लीवासियों की ओर से प्रधानमंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि अभी हाल ही में उनके कर-कमलों द्वारा दिल्ली में रिठाला-नरेला-कुंडली कॉरिडोर बनाने का काम शुरू हो गया है । देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी ने उसका फाउंडेशन स्टोन रखा है । मैं दिल्ली के लोगों की तरफ से उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं ।

आदरणीय सभापति महोदया, यहां उत्तर प्रदेश के भी माननीय सदस्य बैठे हुए हैं । क्या यह हमारे लिए खुशी की बात नहीं है कि दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस ट्रेन केवल 45 मिनट्स में दिल्ली से मेरठ पहुंच रही है । नमो मेट्रो दिल्ली और एनसीआर को जोड़ रही है । दिल्ली एयरपोर्ट द्वारका-गुरुग्राम की कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट टर्मिनल वन से एयरोसिटी तक मेट्रो की कनेक्टिविटी, तुगलकाबाद से कालिंदी कुंज तक मेट्रो की कनेक्टिविटी,

दिल्ली से सहारनपुर-नीमराना-बहरोड़ ?नमो भारत? कॉरिडोर के द्वारा हो रहा है । गुरुग्राम-फरीदाबाद-नोएडा ?नमो भारत? कॉरिडोर और सेन्ट्रल विस्टा से मेट्रो कनेक्टिविटी की मंजूरी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी ने दी है । मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं ।

आदरणीय सभापति महोदया, दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है । मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उनकी सरकार ने दिल्ली के लोगों के लिए 1,600 इलेक्ट्रिक बसेज़ मुफ्त में दी हैं । मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी, तो डीटीसी के बास 6,000 बसेज़ थीं, आज वे घटकर 2,500 रह गई हैं । जो 2,500 बसेज़ हैं, वे भी आउटडेटेड हैं । सुरक्षा की दृष्टि से उनको सड़कों पर नहीं चलाया जा सकता है । यदि मोदी जी ने 1,600 इलेक्ट्रिक बसेज़ न दी होतीं, तो आप सोचिए कि हमारा क्या हाल होता? मैं देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने इस बात की घोषणा की है कि दिल्ली को 13,000 नई इलेक्ट्रिक बसेज़ दी जाएंगी । मैं दिल्ली के लोगों की ओर से उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं ।

आदरणीय सभापति महोदया, दिल्ली दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी बन गई है । यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह डब्यूएचओ कह रहा है । सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि आज दिल्ली सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी बनी है, तो उसके दो कारण बताए गए हैं । एक कारण है कि दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ध्वस्त कर गया है । दूसरा कारण है कि दिल्ली की सड़कें टूटी पड़ी हैं जर्जर हालत में हैं । जब उन सड़कों पर गाड़ी चलती है, जिससे धूल उड़ती है, तो पीएम2.5 सबसे ज्यादा धूल से जेनरेट होता है । सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है कि यदि दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठीक हो जाए, आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली की सड़कों के बारे में कहा था कि हम पेरिस और लंदन जैसी सड़कें बनाएंगे, उस पार्टी के नेता को दिल्ली के लोगों से माफी मांगनी पड़ी है । वे यमुना नदी को भी साफ नहीं कर पाएं, वे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी ठीक नहीं कर पाएं, वे दिल्ली के लोगों को पीने का पानी भी नहीं दे पाएं । वे कह रहे हैं कि हमें पांच साल और दे दीजिए, हम इसको ठीक कर देंगे । अब तो मोदी जी की पार्टी की सरकार ही दिल्ली की हालत ठीक करेगी, दिल्ली को विकसित करेगी । मैं उनको यह जानकारी जरूर देना चाहता हूं ।

आदरणीय सभापति महोदया, दिल्ली के अंदर हर रोज उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से 40,000 कॉमर्शियल वाहन आते हैं । उनको रोकने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में जो कदम उठाए गए हैं, मैं उसकी जानकरी देना चाहता हूं । दिल्ली में अर्बन एक्सटेंशन रोड, जिसको हम तीसरा रिंग रोड भी कहते हैं । उसके ऊपर मोदी जी की सरकार 12,500 करोड़ रुपये खर्च कर रही है ।

वह लगभग बनकर तैयार हो गया है । मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि यह जो तीसरा रिंग रोड बनाया जा रहा है, इसमें 27 फ्लाईओवर्स हैं और 18 अंडरपासेज़ हैं । मैं इस माननीय सदन को यह जानकारी देना चाहता हूं कि जिस सरकार के पास हर साल 80,000 करोड़ रुपये का बजट है ।?(व्यवधान) वह दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए एक भी फ्लाईओवर नहीं बना पाए हैं । मैं आपको इसकी जानकारी जरूर देना चाहता हूं ।

आदरणीय सभापति महोदया, दिल्ली से मुंबई तक नेशनल हाईवे, दिल्ली से मेरठ एक्सप्रेसवे, अक्षरधाम से सहारनपुर तक नेशनल हाईवे दिया है । शिव मूर्ति से नेल्सन मंडेला मार्ग तक सुरंग बनेगी । उसका हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया है और जिसकी घोषणा भी की है । दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे को केएमपी एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा, ताकि एयरपोर्ट तक अलग से जाने के लिए रास्ता मिले । दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को ट्रॉनिका सिटी के निकट गाजियाबाद से जोड़ा जा रहा है । दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से गाजियाबाद, नोएडा के लिए अलग रास्ता मिलेगा ।

आदरणीय सभापति महोदया, आपको यह जानकर खुशी होगी कि दिल्ली में कड़कड़डूमा क्षेत्र के विकास के लिए मोदी जी ने 1,168 करोड रुपये दिए हैं । वहां लगभग काम पूरा हो गया है । मैं दिल्ली के लोगों की ओर से भारत के प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं । आपको जानकर खुशी होगी कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली को एक भी स्पोर्ट्स कॉम्पलैक्स नहीं दे पाई है । आदरणीय मोदी जी का सहयोग और उनके मार्गदर्शन में द्वारका में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्पलैक्स बनाया गया है, जिसके ऊपर 572 करोड रुपये खर्च हो रहे हैं । मैं यह जानकारी उनको दे रहा हूं, जो यह कहते हैं कि इनके पास विज़न नहीं है । मैं विज़न की जानकारी दे रहा हूं । ? (व्यवधान) आप चिंता मत कीजिए । आपकी भी लड़ाई उन्हीं से है । आपको मुझे सपोर्ट करना चाहिए । उन्होंने आपके नेता के बारे में क्या कहा है, मेरा मुंह मत खुलवाइए, इसी में भलाई है ।

आदरणीय सभापति महोदया, हम सभी दिल्ली के लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि नरेला सिटी में एजुकेशन हब की मंजूरी प्रधानमंत्री जी ने दे दी है । मैं दिल्लीवासियों की ओर से उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं । नरेला में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्टेडियम और क्रिकेट स्टेडियम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सहयोग और उनके मार्गदर्शन में बनाया जा रहा है । मैं दिल्ली के लोगों की ओर से उनके प्रति बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं । दिल्ली में मोदी जी की सरकार के मार्गदर्शन में यमुना के किनारे 12 डायवर्सिटी पार्क बनाए गए हैं । दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार एक भी पार्क नहीं बना पाई । मैं यह जानकारी भी इस हाउस को देना चाहता हूं कि ये पार्क्स दिल्ली में यमुना के किनारे बनाए गए हैं । आप जाकर देखिए । आप मेरे साथ चलिए । मैं आपको एयर कंडीशन बस में लेकर चलूंगा और देसी घी का खाना

खिलाऊंगा । आप मेरे साथ चल कर देखिए । जो कुछ मोदी जी ने दिया है, उसके लिए आप मोदी जी को दिल से धन्यवाद देंगे । यमुना के किनारे जो असिता पार्क दिया है, वह मोदी जी की सरकार ने दिया है, जहां पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा लगाई गई है । आप वहां चलकर देखिए । उसके साथ-साथ वहां पर यमुना वाटिका दी है । आप सराय काले खां जाकर देखिए । वहां पर बहुत बेहतरीन वर्ल्ड क्लास पार्क मोदी जी की सरकार ने दिल्ली के लोगों को दिया है । वह भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर दिया है । उसके ऊपर लगभग 843 करोड रुपये खर्च हुए हैं । उस पार्क में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा लगाई गई है और उसको देखकर आपका मन गदगद हो जाएगा । मैं यह जानकारी आपको देना चाहता हूं । उस पार्क का नाम बांसेरा पार्क है । वहां पर भगवान बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा लगाई गई है ।

आदरणीय सभापति महोदया, दिल्ली में लाखों खोखा-पटरी वाले लोग हैं । आदरणीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के दो लाख खोखा-पटरी के लोगों को 10000 रुपये से लेकर 50000 रुपये तक उपलबध कराए हैं, ताकि वे सम्मान और इज्जत के साथ अपना कारोबार कर सकें । आज खोखा-पटरी के लोग दिल्ली से देश के आदरणीय प्रधान मंत्री मोदी जी को दुआएं दे रहे हैं । अभी हाल ही में 30000 रुपये तक बैंक एटीएम से निकासी की सुविधा भी मोदी जी की सरकार ने खोखा-पटरी के लोगों को दे दी है । यह सुविधा कभी अमीर लोगों के पास होती थी । खोखा-पटरी के लोगों को मोदी जी ने यह सुविधा देकर जो सम्मान दिया है, मैं दिल्ली के लाखों खोखा-पटरी के लोगों की ओर से उनके प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं ।

आदरणीय सभापति महोदय, दिल्ली में लगभग 30 लाख लोग झुग्गी-झोपड़ी में रहते हैं । मोदी जी ने जहां झुग्गी, वहीं मकान योजना को शुरू किया है । सात हजार फ्लैट्स बनाकर दे दिए हैं । बाकी झुग्गी-झोपड़ीवासियों के लिए फ्लैट्स बनाने का कार्य शुरू हो गया है । अभी हाल ही में प्रधान मंत्री जी ने अपने कर-कमलों द्वारा लगभग साढ़े तीन हजार झुग्गी-झोपड़ीवासियों को फ्लैट्स दिए, उनकी चाबी दी और उनके मन से मोदी जी के लिए दुआ निकल रही थी कि मोदी जी, हम जीवन में सोच नहीं सकते थे कि हमारे पास कभी दिल्ली शहर में, जहां अगल-बगल में अमीर लोग रहते हैं, हम लोगों को भी इतना शानदार फ्लैट बनाकर दे देंगे । केवल फ्लैट ही बनाकर नहीं दिया, बल्कि उनके बच्चों के खेलने के लिए खेल का मैदान, पार्क, प्राइमरी स्कूल, पीने का पानी, घर में बिजली देकर मोदी जी ने दिल्ली में इतिहास रचा है । दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में बड़ी संख्या में झुग्गी-झोपड़ीवासियों को उजाड़ा है ।

आदरणीय सभापति महोदया, मैं जानकारी देना चाहता हूं कि लंबे समय से दिल्ली में हमारे जो दुकानदार भाई हैं, जिनकी दुकानें दिल्ली की सड़कों पर चल रही हैं, मोदी जी की सरकार ने 50 हजार दुकानों को फ्री होल्ड में परिवर्तित कर दिया है । दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने ऐसी 352 सड़कों, जिन सड़कों के बारे में, जब दिल्ली नगर

निगम में भाजपा थी, तो दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार से आग्रह किया कि इन 352 सड़कों को कमर्शियल डिक्लेयर कर दिया जाए, क्योंकि इनके ऊपर सीलिंग की तलवार लटकती रहती है, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार ने 352 सड़कों को कमर्शियल रोड डिक्लेयर नहीं किया, अब चूंकि उनकी किस्मत में ही नहीं है तो 8 फरवरी, 2025 को जब हम दो तिहाई से ज्यादा बहुमत से दिल्ली में सरकार बनाएंगे तो मोदी जी के नेतृत्व में इन सारी रोड्स को कमर्शियल रोड्स डिक्लेयर कर देंगे ताकि वहां के लोग इज्जत के साथ रोजी-रोटी कमा सकें । जिन 13000 दुकानों को सील किया गया था, उनको डी-सील करने का फैसला लिया गया है । मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के प्रति बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं ।

आदरणीय सभापति महोदया, दिल्ली में लगभग 1700 अनअथोराइज्ड कालोनियां हैं । इनमें 60 लाख लोग रहते हैं, जिनमें ज्यादातर बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग हैं । पूरे देश भर से लोग इन अनअथोराइज्ड कालोनियों में रहते हैं । वे नारकीय जीवन जी रहे थे । मोदी जी की सरकार ने फैसला किया कि हम दिल्ली की सभी 1700 अनोथराइज्ड कालोनियों को नियमित करेंगे । इनमें नागरिक सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे । हम इनको मालिकाना अधिकार देंगे । सभापति महोदया मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि मोदी जी की सरकार आने से पहले यदि कोई व्यक्ति इन अनोथराइज्ड कालोनियों में घर बनाता था तो एमसीडी और उस एरिया के आम आदमी पार्टी के काउंसलर जबरन वसूली करते थे । अब क्या व्यवस्था की गयी है, यह सुनने वाली बात है । दिल्ली की जिन 1700 अनोथराइज्ड कालोनियों को मोदी जी की सरकार ने मालिकाना अधिकार दिया हैा, उनकी रजिस्टरी की जा रही है और कोई अनोथराइज्ड कालोनी का निवासी अब रजिस्ट्रार के ऑफिस में नहीं जा रहा है, बल्कि सब-रजिस्ट्रार अनोथराइज्ड कालोनी में कैम्प लगाता है । लोग लाइन में खड़े होकर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और वहीं उनको रजिस्टरी करके दे दी जाती है । यह है मोदी जी का न्याय, यह है मोदी जी का गरीब लोगों के प्रति इंसाफ ।

13.00 hrs

आज हमें इसे सुनने की जरूरत है । इससे आगे मोदी जी की सरकार ने जो एक कदम उठाया है, उसके लिए मैं दिल्ली के 60 लाख अनअथॉराइज्ड कॉलोनियों के निवासियों की ओर से उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ । उन्होंने यह फैसला लिया कि दिल्ली की अनअथॉराइज्ड कॉलोनीज़ में यदि गरीब आदमी अपना घर बनाएगा तो बिल्डिंग बायलॉज के मुताबिक वह अपना घर शान के साथ, सम्मान के साथ, बिना किसी डर के बना सकता है । यदि वह अपना घर तोड़कर बनाना चाहता है तो उसको नक्शा पास नहीं करवाना पड़ेगा । वह बिल्डिंग बायलॉज के मुताबिक अपना घर बना सकता है । यह ऐतिहासिक फैसला आदरणीय मोदी जी ने दिल्ली की 1700 कॉलोनियों के लिए लिया है । मैं दिल्ली के अनअथॉराइज्ड कॉलोनीज़ के 60 लाख लोगों की ओर से आदरणीय मोदी जी के प्रति बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ ।

आदरणीय सभापति महोदया, मैं इस ऑनरेबल हाउस को जानकारी भी देना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली को दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी बना दिया है । लोग दिल्ली छोड़कर जा रहे हैं । हर साल प्रदूषण की वजह से दिल्ली में 12 हजार लोगों की मौत हो रही है । दिल्ली के लोग कैंसर जैसी बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं । आदरणीय मोदी जी की सरकार ने फैसला लिया कि दिल्ली के अंदर अब जो इंडस्ट्रीज़ लगाई जा रही हैं इंडस्ट्रियल इलाकों में, केवल और केवल सर्विस और हाइटेक इंडस्ट्रीज़ ही लगेंगी । यह ऐतिहासिक फैसला आदरणीय मोदी जी की सरकार ने लिया है । हम दिल्लीवासियों की ओर से उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं । दिल्ली की सभी इंडस्ट्रीज़ के मालिक यह चाहते थे, दिल्ली के लोग यह चाहते थे ।

आदरणीय सभापति महोदया, मैंने आपको यह बताया कि दिल्ली प्रदूषित क्यों हुई । मैं एक छोटा सा उदाहरण इस ऑनरेबल हाउस के सामने रखना चाहता हूँ । दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार के मुख्य मंत्री ने घोषणा की कि अब हम पराली से खाद बनाएंगे और एक केमिकल घोल तैयार किया गया । उसके ऊपर 30 हजार रुपये का खर्चा हुआ, लेकिन थोड़ी सी भी पराली से खाद नहीं बनी और दिल्ली के मुख्य मंत्री ने अपना चेहरा चमकाने के लिए 24 करोड़ रुपये प्रचार और विज्ञापन के ऊपर खर्च कर दिए । आप बताइए कि 24 करोड़ रुपये प्रचार पर खर्च किए जा रहे हैं और पराली से थोड़ी सी भी खाद नहीं बनी है । दिल्ली में जो स्मॉग टावर लगाए गए, जिसके ऊपर 23 करोड़ रुपये खर्च किए गए, वे बंद पड़े हुए हैं । दिल्ली का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है । दिल्ली की सड़कें टूटी पड़ी हैं । दिल्ली के लोग प्रदूषण से दुखी हैं । वे दिल्ली को छोड़कर जा रहे हैं । हमने दिल्ली के लोगों से आग्रह किया है कि आप कृपा करके दिल्ली छोड़कर मत जाइए । हम प्रदूषण से दिल्ली के लोगों को छुटकारा दिलाएंगे ।

आदरणीय सभापति महोदया, हमने दिल्ली के लोगों को इसका विश्वास दिलाया है । मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि मोदी जी की सरकार ने दिल्ली में तीन नए कॉलेज भी दिए हैं । मोदी जी की सरकार ने हाल ही में सूरजमल विहार में दिल्ली विश्वविद्यालय का ईस्ट कैंपस दिया है । मोदी जी की सरकार ने हाल ही में द्वारका में दिल्ली विश्वविद्यालय का वेस्ट कैंपस भी दिया है । रोशन पुरा नजफगढ़ में वीर सावरकर जी के नाम पर कॉलेज की नींव भी रखी गई है ।

मैं दिल्ली के लोगों की ओर से आदरणीय प्रधान मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ । इसके अलावा मैं इस ऑनरेबल हाउस को यह जानकारी भी देना चाहता हूँ कि किसी समय दिल्ली में श्री मदन लाल खुराना जी की सरकार थी, वे दिल्ली के मुख्य मंत्री थे । उसके बाद डॉ. साहिब सिंह वर्मा दिल्ली के मुख्य मंत्री बने । उन्होंने दिल्ली को फुली फंडेड बाय दिल्ली गवर्नमेंट 12 नए कॉलेजेस दिए । दिल्ली की आम आदमी

पार्टी की सरकार टीचिंग स्टाफ को और नॉन टीचिंग स्टाफ को हाई कोर्ट के डायरेक्शन के बाद वेतन नहीं दे पा रही है । यह है ? आम आदमी पार्टी की सरकार ।

सभापति महोदया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोदी जी ने दिल्ली के लोगों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में जो कुछ भी व्यवस्था की हैं, मैंने उसकी चर्चा की है । दिल्ली के अंदर एक नया कॉलेज पिछले 10 सालों में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं खोल पाई । दिल्ली के अंदर 50 नए कॉलेजेज खोलने का वायदा किया गया था । दिल्ली के अंदर 500 नए स्कूल्स खोलने की बात कही गई थी । दिल्ली में 78 स्कूल्स बंद कर दिए गए ।

आदरणीय सभापति महोदया, आज दिल्ली के 60 प्रतिशत स्कूल्स में प्रिंसिपल्स नहीं हैं, 40 प्रतिशत स्कूल्स में वाइस प्रिंसिपल्स नहीं हैं और दिल्ली के 70 प्रतिशत स्कूल्स में साइंस की पढ़ाई नहीं है एवं 45 प्रतिशत स्कूल्स में कॉमर्स की पढ़ाई नहीं है । मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे बच्चे डॉक्टर्स-इंजीनियर्स कैसे बनेंगे? गेस्ट टीचर्स के साथ वायदा किया जाता है कि हम सरकार में आएंगे, तो हम दिल्ली के 25 हजार गेस्ट टीचर्स को रेग्युलराइज करेंगे । आज गेस्ट टीचर्स को नौकरी से बाहर किया गया है । आज दिल्ली के स्कूल्स में 25 हजार टीचर्स की कमी है ।?व्यवधान)

आप इनके कारनामें सुन लीजिए । ये कहते हैं कि हमारा वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मॉडल है । मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि 12वीं क्लास में दिल्ली छठे स्थान पर रही है, जबकि 10वीं क्लास में दिल्ली का स्थान 15वाँ रहा है ।? (व्यवधान) दिल्ली का स्थान पटना, भोपाल, प्रयागराज और भुनेश्वर के बाद है । ये है ? वर्ल्ड क्लास एजुकेशन ।? (व्यवधान) आप जरा सुनने का माद्दा रखिए ।? (व्यवधान) आप सुनिए ।

आदरणीय सभापति महोदया, मैं आज इस हाउस में विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस दिल्ली को बहुत ही बेदर्दी के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार ने लूटा भी है और इसको बर्बाद भी किया है । मैं यह कह सकता हूं कि दिल्ली को महमूद गजनी ने भी लूटा, मोहम्मद गोरी ने भी लूटा, तैमूर लंग ने भी लूटा, नादिरशाह ने भी लूटा, अहमदशाह अब्दाली ने भी लूटा, अंग्रेजों ने भी लूटा और इस दिल्ली को बहुत बेदर्दी के साथ आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी लूटा है ।

आदरणीय सभापति महोदया, देश के प्रधान मंत्री जी के पास अपने रहने के लिए घर नहीं है । दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते थे कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो दो कमरे के घर में रहूंगा, मैं आज इस ऑनरेबल हाउस को जिम्मेवारी के साथ जानकारी देना चाहता हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, जो उनका पूराना घर था, कॉम्पिटैंट अथॉरिटी से अनुमति नहीं ली और उसको तोड़ दिया गया । उसके स्थान पर 179 करोड़ रुपए खर्च करके शीश महल बनाया । आदरणीय सभापति महोदया, उस पर 179 करोड़ रुपए खर्च हुए और उसके निर्माण पर 53 करोड़ रुपए खर्च हुए । अंग्रेज के समय के जो पेड़ लगे हुए थे, कॉम्पिटैंट अथॉरिटी से उनको काटने के लिए अनुमति नहीं ली गई और उनको काट दिया गया । जो शीश महल बनाया गया है, उन्होंने सबसे बड़ा पाप किया है कि उन्होंने कॉम्पिटैंट

अथॉरिटी से उसका नक्शा भी पास नहीं करवाया है । बगैर नक्शा पास कराए, शीश महल बना दिया गया ।

आदरणीय सभापति महोदया, उनके घर के बगल में 21 क्लास वन ऑफिसर्स के फ्लैट्स थे । उसमें एक जज भी रह रहे थे । उनके फ्लैट को तोड़ दिया गया । जज सभी को न्याय देते हैं, वे दिल्ली के मुख्यमंत्री से गुहार करते रहे कि मुझे थोड़ा समय दे दीजिए, मेरे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मैं थोड़े समय के बाद यह फ्लैट खाली कर दूंगा, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई और 21 के 21 फ्लैट्स को तोड़ कर चीफ मिनिस्टर रेसिडेंस का हिस्सा बना लिया गया ।

मैं आपको यह जानकारी भी देना चाहता हूं कि उनके बगल में दिल्ली के होम सैक्रेट्री की कोठी थी, उनके बगल में डीडीए के वाइस चेयरमैन की कोठी थी, दोनों कोठियों को दिल्ली मुख्यमंत्री निवास का हिस्सा बना लिया गया । सीपीडब्ल्यूडी के नॉर्म्स क्या कहते हैं? यदि आप सड़क बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, बनाइए, लेकिन क्या आप पीडब्ल्यूडी नार्म्स का पालन करेंगे या नहीं? दस करोड़ रुपये उस घर पर खर्च हो रहा था, उसे बढ़ाकर 53 करोड़ रुपये कर दिए गए और टेंडर नहीं बुलाए गए । मैं समझता हूं कि देश में इससे बड़ा भ्रष्टाचार का दूसरा उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा ।

सभापति जी, मैं ऑनरेबल हाउस से कहना चाहता हूं कि हमारा दिल रोता है कि कैसी दिल्ली थी और अब दिल्ली को कितना बदहाल बना दिया गया है । दिल्ली की यमुना को साफ करने के लिए मोदी जी की सरकार ने साढ़े आठ हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराए । भारत सरकार के जल मंत्री, पहले नितिन गडकरी साहब थे फिर शेखावत जी हो गए, ने बार-बार दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी कि साढ़े आठ हजार करोड़ रुपये आखिर कहां खर्च हुए, इसकी जानकारी दें, इसका हिसाब-किताब दें । जल बोर्ड के खातों की तो सीएंडएजी से जांच नहीं करवाई जाती है जबकि हाई कोर्ट ने भी डायरेक्शन दी है । साढ़े आठ हजार करोड़ रुपये दिए थे ताकि दिल्ली के 24 गंदे नाले जो यमुना में गिरते हैं, वहां 24 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाए जाएं, लेकिन दिल्ली में एक भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बनाया गया । दिल्ली की यमुना पहले से तीन गुना ज्यादा दूषित हो गई है ।

सभापति जी, मैं इस ऑनरेबल हाउस को एक और इंटरस्टिंग बात बताना चाहता हूं । मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं और आपको सुनकर हैरानी होगी कि सुप्रीम कोर्ट यमुना को साफ करवाते-करवाते थक गया तो उन्होंने एनजीटी को जिम्मेदारी दी कि यमुना की सफाई करवाए । एनजीटी भी यमुना की सफाई करवाते-करवाते थक गया क्योंकि दिल्ली की आम पार्टी सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं थी । एनजीटी ने क्या आदेश दिया? एनजीटी ने दिल्ली के माननीय एलजी को आदेश दिया कि आप दिल्ली की यमुना को साफ करवाने की जिम्मेदारी लीजिए, इसके लिए हम एक कमेटी का गठन कर रहे हैं और इसका चेयरमैन आपको बनाया जा रहा है । दिल्ली के ऑनरेबल लैफ्टिनेंट

गवर्नर ने दिन-रात लगकर कमेटी के मैम्बर्स के साथ, दिल्ली सरकार के अधिकारियों के साथ मिलकर यमुना का 11 किलोमीटर स्ट्रेच साफ करवाया और इसके बाद दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई है कि एनजीटी ने दिल्ली के माननीय लैफ्टिनेंट गवर्नर को जो काम दिया है, इसे रोका जाए और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया । दिल्ली के ऑनरेबल एलजी ने एनजीटी के आदेश पर यमुना की सफाई का काम शुरू किया गया था, अगर स्टे नहीं दिया जाता तो आज यमुना की सफाई हो जाती ।

मैं आज इस हाउस में खड़े होकर कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी के नेताओ, आपने यमुना मैया के साथ पाप किया है । 8 फरवरी. 2025 को जब नतीजे आएंगे, यमुना मैया का श्राप आपको लगेगा, आज मैं यह बात इस हाउस में कह रहा हूं । आपका झगड़ा रामवीर सिंह से हो सकता है, आपका झगड़ा मोदी जी के साथ हो सकता है, लेकिन यमुना दूषित हो गई और इसी यमुना का पानी ट्रीटमेंट के बाद लुटियंस जोन में हम सब लोग पीते हैं । यदि दिल्ली के ऑनरेबल एलजी ने एक शानदार और ऐतिहासिक पहल की थी तो उसका स्वागत होना चाहिए था, लेकिन उसका विरोध किया गया ।

सभापति जी, केंद्र सरकार ने दिल्ली में पीने की पानी की समस्या को समाप्त करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड को लगभग 7000 करोड़ रुपये से ज्यादा रकम उपलब्ध करवाई ।

जो 7 हजार करोड़ रुपये दिए गए, उनका कोई हिसाब-किताब केन्द्र सरकार को दिया नहीं जा रहा है । दिल्ली के लोग बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं । दिल्ली के अंदर दिल्ली जल बोर्ड ने, यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि दिल्ली जल बोर्ड की रिपोर्ट कह रही है । दिल्ली जल बोर्ड ने साढ़े सात हजार सैम्पल्स उठाये और उनमें से ढाई हजार सैम्पल्स फेल हो गए । डॉक्टर्स की रिपोर्ट यह है कि इस पानी को पीकर दिल्ली के लोगों का पेट खराब हो रहा है, लोगों की किडनी खराब हो रही है, लिवर खराब हो रहा है । आपके शासन में जल बोर्ड, हमारे एमपी साहब यहां बैठे हुए हैं, 600 करोड़ रुपये के मुनाफे में था और आज 75 हजार करोड़ रुपये के घाटे में चल रहा है । जल बोर्ड में सैकड़ों करोड़ रुपये के घोटाले हुए हैं । हाई कोर्ट ने बार-बार कहा कि खातों की जांच सी एंड एजी से कराई जाए । हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हुआ । आज तक खातों की जांच नहीं हुई, क्योंकि सैकड़ों रुपये का ? (व्यवधान) 2800 करोड़ रुपये का, चूंकि आगे जब दिल्ली में भाजपा की सरकार आ रही है, तो उसकी जांच-पड़ताल तो कराई जाएगी और उनके खिलाफ कार्रवाई तो होगी ।

आदरणीय सभापति महोदया, दिल्ली के अंदर अनेक ऐतिहासिक विकास के कार्य आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा किए गए हैं और दूसरी तरफ आप देखते हैं कि जिन लोगों ने वायदा किया था कि हम दिल्ली में 50 कॉलेज खोलेंगे । हम दिल्ली में नए 500 स्कूल्स खोलेंगे । उन लोगों ने 500 स्कूल्स तो नहीं खोले, 50 नए कॉलेज तो नहीं खोले, लेकिन दिल्ली में एक ऐसी नई शराब नीति लाई गई, जिसके बारे में कहा गया कि यह

वर्ल्ड क्लास एक्साइज पॉलिसी है । मैं बताना चाहता हूं कि जब हाउस में इसके ऊपर चर्चा हो रही थी तो मैं लीडर ऑफ अपोजिशन था । यह कहा गया कि यह जो नई एक्साइज पॉलिसी लाए हैं, दिल्ली के युवाओं को, महिलाओं को आसानी से शराब सुलभ हो जाएगी । यह भी कहा गया कि दिल्ली सरकार की आय बढ़ जाएगी । यह भी कहा गया कि यह वर्ल्ड क्लास एक्साइज पॉलिसी है । शराब के ठेकेदारों का कमीशन 2 परसेंट से बढ़ा कर 12 परसेंट कर दिया । दिल्ली के अंदर 20 हजार करोड़ रुपये की शराब हर साल बेची जाती है । कई हजार करोड़ रुपये शराब के ठेकेदारों की जेब में डाल दिया गया । शराब बेचने का समय रात को 10 बजे तक होता था, उसको बढ़ाकर 3 बजे तक कर दिया गया ।

आदरणीय सभापति महोदया, रेजिडेंशियल एरियाज़ में जब शराब के हजारों ठेके खोले तो हमने दिल्ली के मुख्य मंत्री की आंख में आंख डालकर हाउस में खड़े होकर कहा था कि हम दिल्ली में रिहायशी क्षेत्रों में शराब के ठेके नहीं खुलने देंगे । अपने युवाओं को बर्बाद नहीं होने देंगे । हम भगवान की सौगंध खाते हैं कि यदि हम विफल हो गए तो हाउस की मैम्बरशिप छोड़कर चले जाएंगे । अरे, स्कूल खोलने वालों, कॉलेज खोलने वालों एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री देने का काम शुरू कर दिया । स्कूल-कॉलेज खुले नहीं, अद्धा के साथ पव्वा फ्री, बोतल के साथ बोतल फ्री, यह हाल हमने दिल्ली का होते हुए देखा है । चूंकि आपने घंटी बजा दी है, मैं अंत में एक बात जरूर कहना चाहता हूं । ? (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, आप अपनी बात कम्पलीट कीजिए ।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी : अभी शीश महल पर सुनाया तो है । ? (व्यवधान)

माननीय सभापति : रामवीर बिधूड़ी जी, प्लीज आप अपनी बात कम्पलीट कीजिए ।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी सभापति महोदया, घंटी बज गई है । इन शब्दों के साथ, मैं अपने भाषण को समाप्त करने जा रहा हूं । 18 फरवरी, 2025 को हम आएंगे, दिल्ली को भ्रष्टाचारमुक्त, मोदी जी के सपनों की विकसित दिल्ली बनाएंगे ।

मैं इन शब्दों के साथ राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण का जोरदार तरीके से समर्थन करता हूं । उनके प्रति बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं । आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपके प्रति भी बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं ।

हमारे जो अपॉजिशन के साथी हैं, वे छोटी-मोटी टोका-टाकी करते रहे, लेकिन दिल से तो वे भी सुनना चाहते थे कि जिस आदमी ने दिल्ली को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया, इसको जितना भी टोका जाए, यह हाउस भी सुनना चाहता है, मैंने हाउस की यह भावना देख ली । यदि दिल्ली के लो सुन रहे होंगे, तो आज उनके मुँह से आवाज़ निकल रही होगी कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने इस दिल्ली को बेदर्दी से लूटा है, इस दिल्ली को नरक में तब्दील कर दिया है । 8 फरवरी को, मोदी जी के मार्गदर्शन में दिल्ली में 50 से ज्यादा सीटें जीतकर भाजपा की सरकार बनेगी और मोदी जी

का जो सपना है कि दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाया जाए । दिल्लीवासियों का यह सपना मोदी जी के मार्गदर्शन में दिल्ली में बनने वाली भाजपा की सरकार पूरा करेगी । बहुत-बहुत धन्यवाद । जय हिंद ।

श्री रवि शंकर प्रसाद (पटना साहिब) : माननीय सभापति जी, महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा दिये गये अभिभाषण पर माननीय सदस्य बिधूड़ी जी ने धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ ।

भारत के संविधान के 75 वर्ष पूरे हो गये हैं । महामहिम राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संबोधित करती हैं । बजट सत्र है, बाकी सत्र हैं, नया सत्र होता है । यह एक स्थापित परम्परा है । सदन को यह बताना जरूरी है कि राष्ट्रपति भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठते हैं या बैठती हैं । वे सेना के कमांडर-इन-चीफ भी होते हैं और भारत के संविधान के आर्टिकल 79 के मुताबिक वे संसद के पार्ट भी होते हैं । मुझे यह बताना बहुत जरूरी है कि,

> ?There shall be a Parliament for the Union, which shall consist of the President and two Houses, to be known respectively as the Council of States and the House of the People?.

महामहिम राष्ट्रपति संसद के पार्ट हैं । हम सभी का नैतिक दायित्व है, संवैधानिक दायित्व है कि हम उनका सम्मान करें ।

महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी बहुत ही साधारण परिवार से आगे बढ़ी हैं । वे अपनी मेहनत, शिक्षा, लगन और सेवा-भाव से राज्यपाल बनीं । मैं कहना चाहूंगा कि राज्यपाल के पद से हटने के बाद वे अपने गाँव चली गईं । उनके परिवार में कई कष्ट हुए । उन्होंने बेटियों को पढ़ाने के लिए स्कूल खोला । बाद में, मुझे भारत के प्रधानमंत्री जी पर गर्व है कि उन्होंने एक वंचित आदिवासी समाज की एक योग्य नेत्री को भारत का राष्ट्रपति बनाया गया ।

मैं यह बात बहुत ही शालीनता से कहना चाहूँगा कि पिछले दो वर्षों में, जब से वे राष्ट्रपति हैं, उन्होंने अपनी गरिमा, अपनी शालीनता से राष्ट्रपति के पद को एक नयी ऊँचाई दी है, यह मैं इस सदन में कहना चाहूँगा ।

राजनीति में विरोध होता है, हम अपनी बात कहेंगे, वे अपनी बात कहेंगे, लेकिन विरोध का कोई स्तर होगा कि नहीं होगा, विरोध की कोई गरिमा होगी या नहीं होगी? यह सवाल मैं बड़ी जिम्मेवारी से आज इस सदन में रखना चाहता हूँ । महामहिम राष्ट्रपति जी के उद्बोधन के बाद, विपक्ष के एक बड़ी पार्टी की बड़ी नेत्री ने उनके बारे में क्या कहा- पूअर लेडी । ये शब्द हैं क्या? इसका क्या मतलब है? आज मैं बहुत गम्भीरता से यह विषय उठाना चाहता हूँ ।? (व्यवधान) सभापति जी, मैंने किसी का नाम नहीं लिया है ।? (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, आपको भी बोलने का अवसर दिया जाएगा ।

? (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री; तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री किरेन रिजिजू) : माननीय सदस्य ने किसी का नाम नहीं लिया है ।? (व्यवधान)

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: I am not yielding. आप बैठ जाइए ।? (व्यवधान)

महोदया, मैंने किसी का नाम नहीं लिया है ।? (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, आप बैठ जाएं । आपको बोलने का अवसर दिया जाएगा ।

? (व्यवधान)

श्री रवि शंकर प्रसाद : सभापति जी, राष्ट्रपति भवन को शायद पहली बार एक प्रेस रिलीज करके इसका प्रतिकार करना पड़ा और मैं उसे पढ़ना चाहता हूं । The President office believes it might be the case that these leaders have not acquainted themselves with the idiom and discourse in the Indian language of Hindi and thus, formed a wrong impression. In any case, such comments are in poor taste, unfortunate and entirely avoidable. राष्ट्रपति जी के द्वारा जो टिप्पणी की गई है, वह मेरे पास है । मैं आज इस सदन में अपने भाषण में महामहिम राष्ट्रपति जी के ऊपर जिम्मेदार लोगों के द्वारा जो टिप्पणी की गई है, उसकी बहुत भर्त्सना करना चाहता हूँ । यह गलत है, यह नहीं होना चाहिए था और हम सभी को महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी पर बहुत गर्व है, जिस तरह से उन्होंने आचरण किया है, उन्होंने भाषण दिया है ।? (व्यवधान)

महोदया, यह कोई नयी बात नहीं है, आज जब विषय निकला है तो उसको रखना जरूरी है । क्या यह पहली बार हुआ है? इस देश के विपक्ष का यह बड़ा परिवार है । वह समझता है कि हमारा इनटाइटलमेंट है इस देश पर राज करना । याद करिए, आज मैं कुछ कहना चाहता हूँ, देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद जी के साथ क्या-क्या व्यवहार किया गया था । आज मैं डॉक्यूमेंट रखूँगा । वे देश के महान देता थे । वे मेरे अपने प्रदेश बिहार से आते थे । आज मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि राजेन्द्र प्रसाद जी साधारण परिवार से, छपरा के स्कूल से उन्होंने कोलकाता बोर्ड में मैट्रिक में टॉप किया मतलब आज के बिहार, आज के झारखंड, आज के बंगाल, आज के बांग्लादेश, आज के ओडिशा और आज के असम में वे टॉप नंबर पर आये थे । ये राजेन्द्र प्रसाद जी थे । कोलकाता यूनिवर्सिटी में भी एलएलबी में टॉप, बीए ऑनर्स में टॉप, बहुत बड़े वकील बने, पटना हाई कोर्ट में वकालत की । मुझे लोगों ने बताया कि वर्ष 1920 में गांधी जी के कॉल पर उन्होंने वकालत छोड़ी, 20 हजार प्रति महीना उनकी वकालत थी, उसका त्याग कर दिया । बाद में वे जेल गए और संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में जो उन्होंने काम किया,

सब लोग कहते हैं कि संविधान बनाने में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है । पंडित जवाहर लाल नेहरू कभी उनको राष्ट्रपति नहीं बनाना चाहते थे ।? (व्यवधान)

सभापति जी, दुर्गादास देश के एक बहुत बड़े पत्रकार थे, उन्होंने 1959 में एक किताब लिखी इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर, इसके चैप्टर 13 में इसका विस्तार से जिक्र है कि नेहरू जी 1952 में उनको राष्ट्रपति नहीं बनाना चाहते थे । 1957 में भी उन्हें राष्ट्रपति नहीं बनाना चाहते थे ।? (व्यवधान) जो व्यक्ति सरदार पटेल और मौलाना आजाद, इन दोनों ने कहा है, ? (व्यवधान) दुर्गादास जी देश के बड़े पत्रकार थे । एक बात और जानिए, यह बहुत जरूरी है । डॉ. राजेन्द्र प्रसाद का निधन वर्ष 1963 में हुआ, उस समय भारत के राष्ट्रपति राधाकृष्णन जी थे ।

राधाकृष्णन जी ने नेहरू जी से कहा कि मैं उनके अंतिम संस्कार में पटना जाना चाहता हूं और आप भी चलिए । नेहरू जी ने कहा कि मैं फंड कलेक्शन करने के लिए राजस्थान जा रहा हूं इसलिए मैं नहीं जाऊंगा और आपको भी नहीं जाना चाहिए । मैं इस किताब से पढ़ रहा हूं और इसमें कोई छिपाने की बात नहीं है । मैं इस किताब के पेज 339 को पढ़ रहा हूं ।

?Nehru told Radhakrishnan that he was going to Rajasthan to collect money for the Prime Minister?s Relief Fund and would not be able to attend the former President's funeral in Patna. He added, I do not see any reason for you to go. Radhakrishnan replied, no, I think I must go and attend the funeral. That respect is due to him and must be paid. I think you should also give up your tour programme and come with me. But Nehru stuck to his programme.?

ये सभी रिकार्ड की बातें हैं । नेहरू जी भारत के प्रथम राष्ट्रपति के अंतिम संस्कार में नहीं गए । आज यहां बात हो रही है, तो इस किताब की एक बात और कोट करना चाहता हूं । मैं सदन के सामने रखना चाहूंगा कि मौलाना आजाद के साथ दुर्गादास जी हर रविवार को कॉफी पीते थे और उन्होंने अपने मरने से दो साल पहले एक बात कही थी क्योंकि हर रविवार दुर्गादास जी मौलाना आजाद से मिलते थे । मैं उस बात को सदन के सामने रखना चाहता हूं ।

?Azad revised his opinion of Nehru in the last two years of his life?

? (*Interruptions*)

आप इस बात को सुनें ।

?Indeed, he went to the extent of expressing regret for being unfair to Patel and asserting that he was sure the country would have been better off if Sardar Vallabhbhai Patel had been the Prime Minister.

What motivated this change? Toward the end of his life, Azad realised that the best protection for Muslims was the goodwill of Hindus and a strong Government. He told me that he had come to the conclusion that Nehru?s policies had weakened the administration.?

मैं साठ साल पहले की किताब पढ़ रहा हूं ।? (व्यवधान) महोदया, यह सवाल सिर्फ डॉ. राजेन्द्र प्रसाद का नहीं है, याद कीजिए फ़खरुद्दीन अली अहमद भारत के राष्ट्रपति थे । इमरजेंसी लगाई गई थी । हम लोगों ने संघर्ष किया था और उनसे बिना केबिनेट की अप्रूवल के इमरजेंसी साइन कराई गई, यह सम्मान ये लोग राष्ट्रपति को देते हैं ।? (व्यवधान) ज्ञानी जैल सिंह के साथ राजीव गांधी का क्या व्यवहार था, यह सब रिकार्ड की बात है और हम सभी जानते हैं ।? (व्यवधान) मैं यह कहना चाहता हूं कि इन लोगों का बस चलता तो प्रणब मुखर्जी जी को ये कभी भारत का राष्ट्रपति नहीं बनने देते । उन्होंने सम्मान से काम किया और यह हमारी सरकार है जिसने उन्हें भारत रत्न भी दिया ।? (व्यवधान) माननीय राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी के साथ जो टिप्पणी की गई, वह कोई नई बात नहीं है । यह इनकी परम्परा में है । यह इनका पालिटिकल डीएनए है ।? (व्यवधान) माननीय मित्रों ने साफ कहा कि they have got a chronic habit of insulting the Rastrapati of India यह उनकी परम्परा बन गई है और यह बात मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं । डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, डॉ. राधा कृष्णन, श्री फ़खरुद्दीन अली अहमद, ज्ञानी जैल सिंह, श्री प्रणब मुखर्जी और अब माननीय द्रौपदी मुर्मू के साथ ऐसा किया, यह समझना बहुत जरूरी है ।

महोदया, राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा है कि तीसरी बार जीतने पर सरकार की विकास की गति को नई दिशा मिली है । वे पहली जीत पर ही वर्ष 2014 में परेशान थे । वर्ष 2019 में और ज्यादा परेशान हो गए । अब तीसरी बात जीत गए तो कहने लगे कि कमजोर हो गए हैं । जनता ने जवाब दिया और हरियाणा में कस कर पिट गए । उसके बाद जनता को लगा कि मोदी जी को और मजबूत करना है तो महाराष्ट्र में इन्हें और कस कर पीट दिया और अब आठ तारीख को दिल्ली की बारी है ।

सभापति महोदया, ये इतने सिमट गए हैं, इतने सिमटते जा रहे हैं, फिर भी इनमें वही अहंकार है, वही गुरूर है, यह मुझे आज तक समझ में नहीं आया । थोड़ा तो सम्मान करना सीखिए ।

कल मैंने हमारे विपक्ष के गुणी नेता का एक वक्तव्य देखा कि ?हम संविधान बदलना चाहते हैं, वे संविधान बदलने नहीं देंगे ।? बदलने की बात कौन कह रहा है? यह आलाप तो आप दो सालों से, तीन सालों से कर रहे हैं । लेकिन, मैं उनसे कहूंगा कि आप संविधान बचाने की बात करते हैं तो पहले संविधान के संरक्षक राष्ट्रपति जी का सम्मान करना सीखिए । यह मैं कहना चाहता हूं । मैंने आर्टिकल-75 को जान-बूझ कर पढ़ा कि

राहुल गांधी जी पढ़ें और समझें । वे तो होमवर्क करते नहीं हैं, आप जानती हैं ।? (व्यवधान)

सभापति जी, माननीय राष्ट्रपति जी ने एक नयी ऊर्जा की बात की है । कुम्भ में जो महान आयोजन चल रहा है, राष्ट्रपति जी ने उसकी भी चर्चा की है । कल रात तक खबर मिली कि उसमें 35 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं । जो एक हादसा हुआ, उसके लिए उन्होंने दु:ख भी प्रकट किया । उसकी भी जांच चल रही है और उस जांच में भी षड्यंत्र की बू आ रही है । जब पूरी जांच रिपोर्ट सामने आएगी तो वह हादसा किसने करवाया, उन्हें शर्म से झुकना पड़ेगा, यह भी मैं कहना चाहता हूं ।? (व्यवधान)

सभापति जी, मुझे एक बात जरूर कहनी है कि कुम्भ का नाम सुनते ही और सनातन का नाम सुनते ही उनको परेशानी क्यों हो जाती है, उन्हें क्या हो जाता है? इस सदन में एक बात मैं साफ-साफ कहना चाहता हूं कि ?सनातन का अपमान, नहीं सहेगा हिन्दुस्तान?, यह आप जान लीजिए ।? (व्यवधान) हमें गर्व है कि हमारे देश में सनातन परम्परा है ।

सभापति जी, मैं बड़ी विनम्रता के साथ एक बात और कहूंगा, हजारों सालों में तो लोग सनातन को कमजोर नहीं कर सके, तो ये लोग क्या हैं, जो सनातन को कमजोर कर पाएंगे? ? (व्यवधान)

सभापति जी, माननीय राष्ट्रपति जी ने नयी ऊर्जा की बात की है, देश में बदलाव का भी संकल्प लिया है । बदलाव कैसे होता है? कुछ लोग बदलाव की बात करते हैं और कुछ लोग बदलाव की बात ही नहीं करते, बल्कि बदलाव को करके दिखाते हैं । यह आप जान लीजिए । जैसे ?गरीबी हटाओ? का एक बहुत बड़ा नारा चला था, लेकिन क्या हुआ? यहां पर अगर मोदी जी ने कहा कि ?मेरी सरकार गरीबों के लिए जीएगी, किसानों के लिए जीएगी?, तो उसे उन्होंने करके दिखाया है । राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में उसकी चर्चा की है । 80 करोड़ लोगों को खाना मिल रहा है या नहीं और वह कितने वर्षों से मिल रहा है? सैकड़ों की संख्या में शौचालय बने हैं या नहीं? 11 करोड़ किसानों के अकाउंट्स में 41,000 करोड़ रुपये जाते हैं या नहीं जाते हैं? आज गांव की सड़कें बनी हैं या नहीं बनी हैं? ये सारे स्कूल्स हों, अस्पताल हों, आयुष्मान भारत योजना हो, गरीबों की सेवा हो, ? लखपति दीदी? हो या ?ड्रोन दीदी? हो, ये भारत के बदलाव के लिए नए कार्यक्रम हैं, जो बिना किसी घोटोले के चल रहे हैं, ईमानदारी से चल रहे हैं ।

जब वर्ष 2014 में मोदी जी की सरकार आई थी, पहली बार जिसका ज़िक्र माननीय राष्ट्रपति जी ने किया है, तो उस समय क्या था? सभापति जी, मैं उस समय उस हाउस में था । हमने कहा कि अब एक-दो घोटाला हो गया है, थोड़ी शांति हो । फिर नया घोटाला आ गया । कभी कोयला घोटाला है, कभी 2जी घोटाला है, कभी कॉमनवेल्थ घोटाला है, कभी अंतरिक्ष का देवास घोटाला है । सभापति जी, यह शरीर पंच तत्व से बनता है । बाद में मालूम हुआ कि उनकी सरकार को यह बताया गया था कि पंचतत्व का सिद्धांत तब तक

सफल नहीं होगा, जब तक पांचों तत्वों में घोटाला नहीं करोगे । अब आप देख लीजिए कि ज़मीन का घोटाला कर के दिखाया । आकाश का घोटाला, हैलिकॉप्टर घोटाला कर के दिखाया । वायु का 2जी घोटाला कर के दिखाया । जल में सबमरीन घोटाला कर के दिखाया । यह नहीं छोड़ा तो पाताल में भी चले गए और कोयला घोटाला कर दिया । ये लोग क्या बोलेंगे? आज जो स्थिति आ रही है, मोदी जी की सरकार ईमानदारी से काम करती है । ? (व्यवधान) मैं इनकी खीज को समझता हूँ । राजीव गांधी का एक वक्तव्य था कि मैं दिल्ली से एक रुपया भेजता हूँ, और ज़मीन पर 15 पैसे पहुंचते हैं । मोदी जी की सरकार में सौ रुपये भेजते हैं, तो गांवों में सौ रुपये डिजिटल तरीके से पहुंचते हैं । यह अंतर है ।

सभापति जी, मैं थोड़ा देश की अर्थव्यवस्था के बारे में बोलना चाहता हूँ । क्योंकि महामहिम राष्ट्रपति जी ने उसकी चर्चा की है । बाकी हमारे बहुत ही गुणी मित्र रामवीर बिधुड़ी जी ने शौचालय कितने बने, क्या बने, वह चर्चा की है तो मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा । लेकिन अर्थव्यवस्था पर कुछ बोलना ज़रूरी है । याद कीजिए कांग्रेस वालो! वर्ष 2014 में भारत की अर्थव्यवस्था फ्रेजाइल फाइव थी । मलतब इतनी कमज़ोर पांच में कि कब गिर जाए, पता नहीं । आज मैं अपना एक व्यकितगत अनुभव इस हाउस में बताना चाहता हूँ । सभापति जी, मैं वर्ष 2013 में एक सेमिनार को एड्रेस करने न्यूयॉर्क गया था । उस समय मैं राज्य सभा में विपक्ष का उपनेता था । मैं एक निजी यात्रा पर था । जब वहां मालूम हुआ कि मैं आया हूँ, तो जितने भी भारत में पूंजी निवेशक थे, वे सभी कहने लगे कि हम आपसे मिलना चाहते हैं । वे बोले कि हमारा पैसा सेफ है कि नहीं है? क्या हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था डूबने जा रही है? सभापति जी हम उनकी तरह नहीं हैं, जो विदेश में जा कर भारत की आलोचना करें । हमने एक ही बात कही कि भारत ठीक होगा । उन्होंने पूछा कि क्या आपकी सरकार आ रही है? हमने कहा कि ज़रूर आ रही है और भारत की अर्थव्यवस्था मज़बूत करेगी । आज फ्रेजाइल फाइव से भारत की इकोनॉमी टॉप फाइव में पहुंच गई है ।

सभापति जी, क्या वर्ल्ड बैंक, क्या इनवेस्टर्स, इन सभी ने भारत की अर्थव्यवस्था की भूरि-भूरि प्रशंसा की है । मुझे मालूम है कि यह उनको पचता नहीं है । इसलिए उनकी परेशानी मैं समझता हूँ । अगर आपको पांचवीं अर्थव्यवस्था से परेशानी है, तो हम तीसरी भी कर के दिखाने वाले हैं । आप देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन कर दिखाएगी ।

महोदया, पूंजी निवेश कैसे होता है, यह बहुत बेसिक बात समझने की ज़रूरत है । आपके यहां सरकार कैसी है । सरकार स्टेबल है कि नहीं, पॉलिसी स्टेबल है या नहीं, निर्णय ईमानदारी से होते हैं या नहीं, ये सब बातें देखनी पड़ती हैं । जब यह होता है, तो जनता भारत की उद्यमशीलता पर विश्वास करती है । आज देखिए, माननीय राष्ट्रपति जी ने भारत के डिजिटल बदलाव की चर्चा की है । डिजिटल बदलाव क्या है? डिजिटल इंडिया,

मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, ये सब जो कार्यक्रम शुरू किए गए, आधार का कितना विरोध इन लोगों ने किया था । आज आधार के माध्यम से जो डिजिटल बायोमीट्रिक्स हैं, वह सीधा आपके अकाउंट में पहुंच रहा है । 135 करोड़ आधार कार्ड हैं ।

सभापति महोदया, 120 करोड़ मोबाइल फोन्स हैं, जिसमें 95 करोड़ स्मार्ट फोन्स हैं और सभी में इंटरनेट है । आज गांव-गांव में लोग मोबाइल का उपयोग करते हैं, गुगलिंग करते हैं, सर्फिंग करते हैं, यह देश में बदलाव हुआ है । कोरोना के समय वर्क फ्रॉम होम हुआ या नहीं, अदालतों में सुनवाई हुई या नहीं, स्कूलों में पढ़ाई हुई या नहीं । पूरा देश डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर से चला, आज डिजिटल पेमेंट की चर्चा महामहिम राष्ट्रपति जी ने की । भारत की डिजिटल पेमेंट दुनिया का 50 परसेंट है । जब गरीब आदमी इम्पॉवर होता है तो इनको परेशानी होती है । एक ऑटो वाला, एक रिक्शा वाला, सब्जी वाला भी आजकल डिजिटल पेमेंट कर रहा है । इससे इनको परेशानी होती है कि मोदी जी ने क्या कर दिया । हम करते रहेंगे क्योंकि हमारे पास बदलने की हिम्मत है, हमारे नेता की जो सोच है उसको हम जमीन पर उतारते हैं ।

एक-दो बात विदेश नीति और रक्षा नीति पर कहना चाहता हूं, जिसकी चर्चा महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में की है । याद कीजिए, इनकी सरकार में क्या आलम था, देश के सैनिकों के पास बुलेटप्रूफ जैकेट नहीं थी, इसकी चर्चा सदन में बहुत हुई है, याद है न । आप रिकार्ड देख लीजिए, अगर बाहर से वेपन नहीं पहुंची तो लड़ाई करना मुश्किल । आज मोदी जी की अगुवाई में भारत में मेड इन इंडिया केवल डिफेंस प्रोडक्ट्स ही नहीं बना रहा है बल्कि दूसरे देशों को लगभग बीस हजार करोड़ रुपये का एक्सपोर्ट भी कर रहा है । अभी दो बड़े-बड़े युद्धपोत मेड इन इंडिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने डेडिकेट किये हैं । सरहद पर सड़कें बनी हैं, लद्दाख से निकलकर अरूणाचल पहुंच जाइए, आपको हर जगह सड़कें मिलेंगी ।

आज मैं सदन में एक बात कहना चाहता हूं, पहले क्या हाल था? इनके पूर्व के डिफेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट ऑन रिकार्ड है कि सरहद पर सड़कें नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमें चीन को इरिटेट नहीं करना है, ? (व्यवधान) यह रिकार्ड पर है । मैंने किसी का नाम नहीं लिया है । ? (व्यवधान) गडकरी जी हमारी पार्टी के अध्यक्ष थे, उन्होंने कश्मीर की स्थिति का अध्ययन करने के लिए एक कमेटी बनायी थी, राजनाथ जी उसके अध्यक्ष थे । मैं उसका सचिव था, हम लोग लद्दाख गए थे । हमें वहां बताया गया ।

SHRI HIBI EDEN (ERNAKULAM): Hon. Chairperson, I have a Point of Order. .... *(Interruptions)*

माननीय सभापति : क्या पाइंट ऑफ ऑर्डर है?

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: I am not yielding. ....*(Interruptions)*

SHRI HIBI EDEN: Madam, I have a Point of Order under Rule 352 ? Rules to be Observed while speaking, which says,

?A Member shall not make a personal reference by way of making an allegation imputing a motive to or questioning the bona fides of any member of the House.?

The hon. Member has been continuously referring to Shri Rahul Gandhi ji and the former Defence Minister while speaking. He himself was the former Law Minister. He knows the rules and procedures of the House. *....(Interruptions)* He is making an allegation with regard to China, which is baseless. *....(Interruptions)* It is totally politically motivated. So, it has to be removed from the records. *....(Interruptions)*

श्री रवि शंकर प्रसाद : सभापति महोदय, मैं अपनी सीमाओं को समझता हूं, इसका कोई आधार नहीं है । मैं एक सार्थक आलोचना कर रहा हूं, मैंने राष्ट्र की सुरक्षा के मामले में किसी का नाम नहीं लिया है । हम लोग लद्दाख गए थे, वहां पर मुखिया लोगों ने कहा कि ग्रामीण सड़कें नहीं बन रही हैं, क्यों नहीं बनती हैं ।

उन्होंने कहा कि उधर से विरोध होता है । हमने सेना के लोगों से बात की । उन्होंने कहा कि दिल्ली से आदेश है कि चीन को इरिटेट नहीं करना है । ? (व्यवधान) यहां पर आकर मैंने सवाल किया था । मैं राज्य सभा में था । मुझे कहा गया कि रवि जी, यह सवाल मत पूछिए । यह बहुत सेंसिटिव है । आज हमारे मोदी जी की सरकार है । कोई कुछ भी कहे, लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक सड़कें बन गई हैं और उस पर सेना की गाड़ी दौड़ती है । ? (व्यवधान) ये क्या बात करेंगे? एक पिटाई उरी में की थी और दूसरी पिटाई कहीं और की है । क्या अब कोई दिल्ली और मुम्बई जैसे हमले की हिम्मत कर सकता है? ? (व्यवधान) पुलवामा में अटैक हुआ तो पिटाई करके ठंडा कर दिया । यह हमारी हिम्मत है । ? (व्यवधान)

सभापति महोदया, आज कश्मीर का चुनाव हो गया । ये लोग हल्ला करते थे कि अनुच्छेद ? 370 हटेगा तो तूफान आ जाएगा, भूचाल आ जाएगा । अभी हमारे एक साथी ने सही कहा कि ये लोग बोलते थे कि खून की नदी बहेगी । आज मुझे अपने नेता नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप पर गर्व है । उन्होंने हिम्मत दिखाई और करके दिखाया ।

आज मैं माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का भी अभिनन्दन करना चाहूंगा कि उन्होंने हिम्मत के साथ पूरे मामले को क्रियान्वित किया । आज वहां कितनी शांति है, यह आपने देखा है । जिस लाल चौक पर पाकिस्तान का झंडा लहरता था, आज वहां तिरंगा लहरता है और भारत माता की जय होती है । ? (व्यवधान) अगर कोई पाकिस्तान की शह पर घुस गया तो उसकी जिन्दगी दो दिन की होती है । उसमें उसका सफाया हो जाता है । क्या अंतर है? अंतर यही है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बात साफ कही है कि पहली

गोली तुम नहीं चलाओगे, लेकिन अगर उधर से गोली चली तो तुम गिनती नहीं करोगे, जब तब ठंडा नहीं कर दोगे । यह फ्रीडम उन्होंने दी है । जब देश के नेता देश की सेना के साथ बहादुरी के साथ खड़े होते हैं तो देश के जवानों में नई हिम्मत आती है ।

सभापति महोदया, आज मैं बहुत गर्व से बोलता हूं । मैं राजपथ पर अपने देश की बेटियों को कमांड करते हुए देखता हूं । आजकल मैं देखता हूं कि जब देश की पायलट बेटियां राफेल फाइटर प्लेन उड़ाती हैं तो देश में एक नया उत्साह बनता है, चाहे वह ड्रोन दीदी हो, जेट की पायलट दीदी हो, बीमा सखी हो या बीएसएफ, सीआरपीएफ की हमारी बहनें हों, जो सरहद पर सुरक्षा करती हैं । उन्होंने देश की बेटियों को एक नया सम्मान दिया है । इसके बारे में महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में भी कहा है । यह इसीलिए हुआ, क्योंकि जब हम कहते हैं ?सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास? तो इस देश की बेटियां भी उसमें आती हैं । मोदी जी ने कहा है कि देश की बेटियों का विकास बहुत जरूरी है । यही सोच थी, जिसके कारण एक वंचित समाज की अपनी नेत्री द्रौपदी मुर्मू जी को भारत का राष्ट्रपति बनाया गया । यह भी उसी सोच का परिणाम है । ये लोग हम लोगों से क्या बात करेंगे? देश का बदलाव कैसे होता है, यह हम लोगों ने करके दिखाया है । क्या अर्थशास्त्र, सुरक्षा, एम्पॉवरमेंट, महिलाओं का एम्पॉवरमेंट या डिजिटल आप सभी क्षेत्रों में देखिए, इसे कहते हैं बदलाव । किसान और किसानी की बात तो बहुत की गई है, मैं उसको नहीं दोहराऊंगा, लेकिन किसानों के बारे में हम लोगों की सोच क्या है? ? (व्यवधान) अरे भाई जरा 1984 की घटना को याद रखो । हमसे बहस मत करो, चुप रहो । 1984 में क्या हुआ था, आप उनके साथ खड़े हों और शांत हो जाइए । ? (व्यवधान)

सभापति महोदया, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा और यह बात बताना बहुत महत्वपूर्ण है । क्या सबकी चिंता की गई है या नहीं?

मैं आज इस सदन में बहुत जिम्मेवारी के साथ एक बात कहना चाहता हूं । अगर फ्री गैस दी गई, तो क्या उसमें हिन्दू-मुसलमान देखा गया? अगर ग्रामीण सड़कें बनी हैं, तो क्या यह कहा गया कि यहां पर अल्पसंख्यक का परिवार रहता है, यहां की सड़क को साइड कर दो? क्या ऐसा कहा गया? अगर नेशनल हाइवे बना, तो क्या कुछ लोगों को छोड़ दिया गया? कभी नहीं, हमें कोई वोट दे या न दे, हम कहते हैं कि सबका साथ, सबका प्रयास, तो हम सबके लिए काम करते हैं । यह काम करके दिखाया है ।

सभापति जी, उत्तर प्रदेश-बिहार की बात कहने की जरूरत नहीं है । मैं बिहार से आता हूं । अभी मैं उसकी चर्चा करने जा रहा हूं । वहां पर क्या हुआ? मुख्यमंत्री कहते थे कि यहां पर सड़क मत ले जाओ, हमें वोट नहीं मिला है । क्या यह सच्चाई है या नहीं? यूपी की सच्चाई है या नहीं? यह सोच हमारे मोदी जी की है और हम लोगों ने इतनी ईमानदारी से कहा कि सबको एक निगाह से देखो ।

सभापति जी, मैं बिहार से आता हूं । अब बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा, तो बड़ी हाय-तौबा मची हुई है । गोपाल जी ठाकुर कहां है? यहां पर हैं । मैंने उस क्षेत्र में बहुत

काम किया है । गोपाल जी हैं, अशोक यादव जी हैं, हम लोग बहुत घूमे हैं । मखाना कौन उगाता है? जो सबसे दलित होते हैं, वे मखाना उगाते हैं । मखाना की संभावना बहुत थी, हम लोगों का भी आग्रह था, वहां के सांसदों ने भी कहा था । वे पूछ रहे हैं कि बिहार में मखाना बोर्ड क्यों बन रहा है ।

सभापति जी, मेरी बुद्धि थोड़ी चकरा गई । मुझे लगा कि इस सदन में कुछ बताना जरूरी है । चाय बोर्ड कहां है- कोलकाता में है । रबड़ बोर्ड कहां है- कोट्टयम (केरल) में है । असम के बाद पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक चाय पैदा होती है । केरल में रबड़ पैदा होती है । कॉफी बोर्ड कहा है- कर्नाटक में है । कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कहां है- मुंबई में है, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे अधिक कॉटन का उत्पादन होता है । तंबाकू बोर्ड कहां है- गुंटूर (आंध्र प्रदेश) में है । भारतीय मसाला बोर्ड कहां है- कोचीन (केरल) में है । क्या केरल में मखाने का उत्पादन होता है? इसका क्या मतलब है? अरे बिहार में मखाने का उत्पादन होता है, तो मखाना बोर्ड तो बिहार में ही खुलेगा ।?(व्यवधान)

सभापति जी, हम लोग बचपन में एक नारा सुनते थे कि पढ़ना-लिखना सीखो । मैं आज कांग्रेस के मेरे मित्रों से कहूंगा कि होमवर्क करना सीखो, पढ़ना-लिखना सीखो ।? (व्यवधान) बिहार का विकास क्यों नहीं होगा? बिहार इस देश का हिस्सा है । अब कह रहे है कि सिर्फ दिल्ली और बिहार के चुनाव के लिए यह बजट आया है । आप वन नेशन, वन इलेक्शन की बात मान जाइए, जो मोदी जी कह रहे हैं कि एक देश, एक चुनाव, तो सारी परेशानी खत्म हो जाएगी ।

सभापति जी, क्या मिडिल क्लॉस के लोग सिर्फ दिल्ली में रहते हैं? क्या बिहार में नहीं हैं, क्या मुंबई में नहीं हैं, क्या गुजरात में नहीं हैं, क्या कोलकाता में नहीं हैं, क्या चेन्नई में नहीं हैं, क्या केरल में नहीं हैं? यह कौन-सी सोच है कि मिडिल क्लॉस को जो दिया गया है, वह सिर्फ यहां के लिए दिया गया है? यह सोच बहुत गलत है ।?(व्यवधान) जहां तक बिहार की बात है । मैं आज बिहार के बारे में एक बात कहना चाहूंगा कि मुझे गर्व है कि मैं पूर्वांचली हूं ।?(व्यवधान)

डॉ. मोहम्मद जावेद (किशनगंज) : एएमयू किशनगंज का क्या हुआ?...(व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, आप बैठ जाइए ।

? (व्यवधान)

श्री रवि शंकर प्रसाद : सभापति जी, महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में पूर्वोत्तर के विकास की चर्चा की है और पूर्वोदय की भी चर्चा की है । मुझे गर्व है कि मैं भारतीय हूं, मुझे गर्व है कि मैं बिहारी हूं और पटना का सांसद हूं । विकास होना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए । ?(व्यवधान)

14.00 hrs

माननीय सभापति जी, आज जो लोग कह रहे हैं तो मेरा एक परिचय और भी है कि मैं सांसद भी हूं तथा पेशे से वकील भी हूं । मुझे प्रभु रामलला और हिंदुओं के अयोध्या के

केस में बहस करने का लखनऊ हाई कोर्ट बेंच में सौभाग्य मिला । चारा घोटाला और अलकतरा घोटाले में सीबीआई इंक्वायरी कराने वाला वकील भी मैं ही हूं । स्वर्गीय सुशील मोदी हमारे पिटीशनर थे । उन 15 सालों में बिहार में क्या होता था, कितनी लूट होती थी, कितना भ्रष्टाचार था, यह सभी जानते हैं । जब आज बिहार बदल रहा है तो परेशानी हो रही है?

14.01 hrs (Hon. Speaker *in the Chair*)

जब आज बिहार आगे बढ़ रहा है तो दर्द हो रहा है । आज बिहार का विकास हो रहा है, हमें बहुत प्रसन्नता है । ? (व्यवधान) ठीक है, आप बैठिए । इस पूर्वांचल से बाबू कुंवर सिंह आते हैं, पूर्वांचल से विद्यापति आते हैं, इसी पूर्वांचल से भिखारी ठाकुर आते हैं, इसी पूर्वांचल से स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद और लोक नायक जयप्रकाश नारायण आते हैं, इसी पूर्वांचल से रामधारी सिंह दिनकर आते हैं और इसी पूर्वांचल से भारत रत्न गरीबों के मसीहा कर्पूरी ठाकुर आते हैं, जिन्होंने विकास का काम किया है । पूर्वांचल में पूर्वी उत्तर प्रदेश भी है । हमारे प्रधानमंत्री जी तो काशी से ही सांसद हैं, पूर्वांचल से सांसद हैं । यहां पूर्वांचल से काफी सदस्य बैठे हुए हैं । हमारे धर्मेंद्र यादव जी कहां बैठे हुए हैं? क्या वह है या गायब हो गए हैं? धर्मेन्द्र बाबू ध्यान रखिए कि आजमगढ़ भी पूर्वांचल में आता है । ? (व्यवधान)

सर, आज पूर्वांचली दिल्ली में बसे हुए हैं, देश भर में बसे हुए हैं । आप मुझे पांच मिनट का समय दीजिए, मैं सदन में आज एक बात कहना चाहूंगा । ये पूर्वांचली, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग 150 वर्ष पहले अंग्रेजों के द्वारा गुलाम बनाकर मॉरीशस, टोबैगो, फिज़ी कहां-कहां नहीं गए? वहां पर एक गिरमिटिया घाट है । मैंने यह जानने की कोशिश की कि वह गिरमिटिया क्यों है? यह बताया गया कि उनको गिरमिट घाट पर लेकर आते थे । आज उस संघर्ष से वहां से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बने । हमें उन पूर्वांचलियों का सम्मान करना चाहिए । आज पूर्वांचलियों को लेकर कुछ लोगों के मन में परेशानी है, लेकिन भारत का भी विकास होगा, नॉर्थ ईस्ट का भी विकास होगा और पूर्व उदय भी होगा । महामहिम राष्ट्रपति जी ने यह एक बात कही है ।

सर, जो एक अंतिम बात मुझे कहनी है, वह यह है कि सरदार पटेल के 150 वर्ष पूरे हो गए हैं और आज हम उनकी जयंती मना रहे हैं । क्या हमने उनके साथ न्याय किया? बड़े सम्मान से महामहिम राष्ट्रपति ने उनको याद किया है । मैंने दुर्गादास की किताब से कई चीजें पढ़ी और मैं फिर रिपीट करना चाहूंगा कि सरदार पटेल वर्ष 1950 मरे, लेकिन उनको भारत रत्न वर्ष 1991 में मिला । ऐसा क्यों? वह देश के रत्न थे । उन 550 रियासतों में एक को छोड़कर बाकी सब रियासतें सरदार पटेल ने हैंडल की थीं और वहां कोई समस्या नहीं है । उनमें से एक कश्मीर को नेहरू जी ने हैंडल किया और नरेंद्र मोदी को उसको संभालने के लिए आना पड़ा तथा आज वहां पर चुनाव हुए हैं । सरदार पटेल के साथ यह अन्याय क्यों? मैं आज उनकी 150वीं जयंती पर यह बात उठाना चाहूंगा । इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि वर्ष 1991 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? उस

समय नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे । अगर वर्ष 1991 में परिवार के लोग प्रधानमंत्री होते, फिर भी यह काम नहीं होता । यह काम अटल बिहारी वाजपेई को ही करना पड़ता । मौलाना आजाद वर्ष 1959 में मरे । वह एक महान देशभक्त थे । आपने उनको भारत रत्न नहीं दिया, क्यों नहीं दिया?

आपने बीच में बहुतों को दिया, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है । लेकिन सरदार पटेल को क्यों नहीं दिया गया, मौलाना आजाद को क्यों नहीं दिया गया? मौलाना आजाद को भारत रत्न वर्ष 1992 में मिला । वह वर्ष 1959 में मरे और इतने दिनों के बाद उनको दिया गया । यह इनकी सोच है । अटल जी की बात याद आती है कि छोटी सोच से कोई बड़ा नहीं होता । लेकिन सरदार पटेल की आलोचना क्यों, मौलाना आजाद की आलोचना क्यों? क्योंकि दोनों नेहरू जी से सवाल पूछते थे । मैंने डॉक्यूमेंट्स से उनको दिखाया है । आज भारत को आजाद हुए 75 वर्ष हो गए हैं तो हमें लगता है कि हमें इन सवालों को ईमानदारी से देखना पड़ेगा । इन सवालों को ईमानदारी से समझना पड़ेगा ।

स्पीकर सर, माननीय राष्ट्रपति जी ने एक और बात कही है और वह सांस्कृतिक चेतना के पुनर्जागरण की बात है । यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसके बारे में मैं कहना चाहता हूं । डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती हम मनाएंगे । आज डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में इस सदन में कुछ कहने की इच्छा है । बहुत से मित्रों को मालूम होगा, आपको भी मालूम होगा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी बैरिस्टर थे । 33 साल की उम्र में वे कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने और उनके पिता जी सर आशुतोष मुखर्जी कलकत्ता हाई कोर्ट के बहुत प्रमाणिक जज थे । जब उन्होंने राष्ट्रवाद के नाम पर इस्तीफा दिया और जनसंघ के पहले अध्यक्ष बने तो वह कश्मीर गए थे । उन्होंने कहा था कि बिना परमिट के कश्मीर जाऊंगा और उनके 25 साल के एक सेक्रेटरी थे, उनका नाम था श्री अटल बिहारी वाजपेयी और जब वह माधोपुर की चौकी से घुसे तो उन्होंने कहा कि अटल बिहारी जाकर देश को बताओ कि मैं कश्मीर में बिना परमिट के घुस गया हूं । हम लोग बचपन से एक बात कहते हैं कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है । एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे! आज जब कश्मीर में तिरंगा लहरा रहा है तो लगता है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ ।

अध्यक्ष जी, राजेन्द्र बाबू आर्टिकल 370 के पक्ष में नहीं थे और सरदार पटेल भी नहीं थे । सरदार पटेल के सेक्रेटरी वी. शंकर, आईसीएस थे । उन्होंने एक किताब लिखी है और उस किताब में जब सरदार पटेल लौटकर के आए तो पूछा कि आपने क्यों मान लिया? उन्होंने कहा कि नेहरू जी मुझ से बात करके अमेरिका चले गए कि सरदार पटेल इसको देख लीजिएगा । अब गोपाल स्वामी अयंगर जी ने इसको मूव किया । सारे कांग्रेसी इसके खिलाफ थे कि यह हम क्यों कर रहे हैं? हैदराबाद को नहीं दिया, जूनागढ़ को नहीं दिया तो हम कश्मीर को क्यों दे रहे हैं? सरदार पटेल ने उन सब को समझाया । उनके

सेक्रेटरी ने बाद में कहा कि सर, क्या यह ठीक हुआ? उनका जवाब था- गलत तो हुआ है । जिस दिन इस देश में एक बहादुर प्रधान मंत्री आएगा, इसको खत्म कर देगा । यह उनके सेक्रेटरी ने कहा और मैं उनको कोट कर रहा हूं । वी. शंकर, आईसीएस उनके प्राइवेट सेक्रेटरी थे, उन्होंने अपनी किताब में कहा है और मैं उसको कोट कर रहा हूं । जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के 125 वर्ष पूरे हो रहे हैं तो हमें देश को आगे बढ़ाना है ।

महोदय, आज हमारे प्रधान मंत्री जी ने जिस तरह से भारत के सांस्कृतिक केंद्रों के प्रतिष्ठापन की बात कही है, वह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है । मैं उसकी भी चर्चा यहां करना चाहूंगा । जिसमें भगवान महावीर की जयंती, महाकवि संत तिरूवल्लुवर की स्मृति में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम, काशी-तमिल संगम, काशी-तेलुगु संगम, सौराष्ट्र-तमिल संगम है । इन लोगों को काशी-तमिल संगम की बात कभी क्यों नहीं सूझती है? इन लोगों ने इतने साल राज किया है । My friends from Tamil Nadu never thought that there is a need to bring Tamil Nadu and Kashi together because of the great historical and cultural linkage.

इसलिए वोट बैंक की बात उठती है । अध्यक्ष महोदय, यह वोट बैंक की पॉलिटिक्स कब तक चलेगी? तीन तलाक, तो वोट बैंक, वक्फ की बात, तो वोट बैंक । ये हार गए, सिमटते जा रहे हैं, फिर भी वोट बैंक की बात करते हैं । मैं कांग्रेस के लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि मैं बिहार से आता हूँ । सन् 1990 में यूपी में कांग्रेस स्वर्गीय मुलायम सिंह जी के पीछे चली और लालू प्रसाद यादव जी के साथ बिहार में चली । आज लगभग 35 साल हो चुके हैं । 35 सालों में वे कहां पहुंच गए और आप कहां से कहां पहुंच गए । क्या कभी आप सोचते हैं कि वोट बैंक पर विचार करना चाहिए? यहां पर विपक्ष के नेता बैठे हुए हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप कहां पहुंच गए और हम कहां पहुंच गए, उसे भी देखिए । यह देश कैसे बदल रहा है, उसको समझिए । यह देश अब राष्ट्रवाद पर चलेगा । यह देश अब सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा से प्रेरित होकर चलेगा । यह देश राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करके चलेगा । यह देश भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत बनाना चाहता है और यह बनकर रहेगा ।

अध्यक्ष जी, इनको एक बात समझ में नहीं आती है कि दुनिया कैसे बदल रही है । गल्फ कंट्रीज़ के जितने भी लोग हैं, उन सबने अपने देश का सर्वोत्तम सम्मान हमारे देश के प्रधान मंत्री जी को दिया है । उन्होंने प्रेम से दिया है । उनके काम के कारण दिया है । उसके बाद भी क्या संकेत है? अध्यक्ष जी मुझे वह गाना याद आता है कि ?समझने वाले समझ गए, न समझे जो अनाड़ी हैं ।? ये कब समझेंगे? आज वोट बैंक के कीचड़ के दलदल में फंसी हुई हिंदुस्तान की राजनीति को बदलना जरूरी है । देशभक्तों में बिना विभेद के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के बदलना जरूरी है । अभी हमारे प्रधान मंत्री जी ने वक्फ बोर्ड के लिए हिम्मत दिखाई है ।

अध्यक्ष जी, मैं वक्फ बोर्ड के बारे में बोलकर अपना भाषण समाप्त करूंगा । मैं बताना चाहता हूँ कि वक्फ की संपत्ति का कितना गलत इस्तेमाल होता है । हमारे पटना संसदीय क्षेत्र के शहर में दो एकड़ का एक बड़ा प्लॉट है । वहां छठ पर अर्घ्य होता है । उसके बदले में कब्रिस्तान की जमीन अंग्रेजों ने सन् 1920 में दे दी थी । वहां पर कब्रिस्तान है फिर भी ये दावा करते हैं कि वह वक्फ प्रॉपर्टी है । यह मामला जब हाई कोर्ट में गया तो सरकार ने कहा कि यह वक्फ की जमीन नहीं है तो फिर ट्रिब्यूनल ने बिना किसी नोटिस के डिक्लेयर कैसे कर दिया कि वह वक्फ की जमीन है? अभी उस पर लड़ाई चल रही है । वक्फ एक बहुत पावन चीज है । ईमानदारी से जो लोग अपनी सम्पत्ति देते हैं, उसका अल्लाह के नाम पर सदुपयोग कीजिए, दुरुपयोग मत कीजिए और अगर दुरुपयोग होगा तो वक्फ का कानून आएगा, जो ईमानदारी के साथ आ भी रहा है ।

अध्यक्ष जी, मैं इतना ही कहूंगा कि महामहिम राष्ट्रपति जी का भाषण समग्रता का है । सर्वव्यापी स्पर्शी है । यहां गरीब की चिंता है । यहां बदलाव की चिंता है । यहां भारत के आर्थिक विकास का आत्मविश्वास है । मोदी जी की सरकार के द्वारा भारत की सेना-सुरक्षा के बारे में एक नया सकंल्प दिखाई दिया है । जिस तरह से आज कश्मीर की स्थिति है और जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में कश्मीर से कन्याकुमारी और सिलचर से सूरत तक भारत जुड़ा है, उसकी भी कहानी है ।

यही तो एकता होती है । अगर आज कोई सूरत से निकलता है तो उसका मन करता है कि गाड़ी से ही कामख्या चला जाए और दर्शन करके आ जाए । मैंने कन्याकुमारी में वह जगह देखी है, जहां कश्मीर से कन्याकुमारी की सड़क समाप्त होती है ।

मैं वहां गया था । मैं उस गोल चक्कर पर रुका और मैंने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को सम्मान दिया और प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी को भी सम्मान दिया कि एक सपना होता है । इनके द्वारा कितना विरोध हुआ था कि क्या कर रहे हैं, कहां से जमीन आएगी, कहां से लोहा आएगा, कहां से सिमेंट आएगा? आज देखिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक सड़क बन गई ।

सर, विकास की भूख होती है । पार्टी के काम से मुझे असम के पांच लोक सभा क्षेत्र देखने का दायित्व मिला था । मैं लौट रहा था, तो रास्ते में लगभग एक हजार आदिवासी खड़े थे । उन्होंने कहा कि आप आए हैं, हमारे इस नेशनल हाइवे में 25 किलोमीटर नहीं बना है, आप इसे बनवा दीजिए । हमने पहले विरोध किया था । यह होता है - विकास की भूख, जब ईमानदारी से काम किया जाता है ।

सर, वे जितना बोलें, देश आगे बढ़ेगा, दुनिया में नाम करेगा, हमारे नेता दुनिया के एक लोकप्रियतम नेता है । उनकी बात दुनिया सुनती है और सुनेगी । आप भी थोड़ा बहुत सुनना सीख जाइए, तो अच्छा रहेगा, आपका भी कल्याण होगा ।

सर, मैं एक बात कहूंगा कि वे जितना भी विरोध करें, देश अब सकारात्मक सोच, रचनात्मक सोच, भारतीय संस्कार, भारतीय प्रेरणा, भारतीय संस्कृति के साथ चल पड़ा है और यह रुकने वाला नहीं है । राष्ट्रपति जी के पूरे अभिभाषण में इसका बहुत बड़ा जिक्र है । आपने मुझे बोलने का समय दिया है, इसके लिए मैं कृतज्ञ हूं । मैं अपने इन्हीं शब्दों के साथ महामहिम राष्ट्रपति जी को बहुत सम्मान के साथ साधुवाद देता हूं कि उन्होंने संबोधित किया । बहुत-बहुत धन्यवाद, अभिनंदन ।

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

?कि राष्ट्रपति जी की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए:-

?कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण, जो उन्होंने 31 जनवरी, 2025 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, के लिए उनके अत्यंत आभारी हैं ।?

माननीय सदस्यगण, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जिन माननीय सदस्यों के संशोधन परिचालित किए गए हैं । यदि वे अपने संशोधनों को प्रस्तुत करने के इच्छुक हैं, तो 15 मिनट के भीतर सभा पटल पर अपनी पर्चियां भेज सकते हैं, जिनमें उन संशोधनों की क्रम संख्या दर्शाई गई हो, जिन्हें वे प्रस्तुत करना चाहते हैं । केवल उन संशोधनों को ही प्रस्तुत किया समझा जाएगा, जिनके संबंध में पर्चियां बताए गए समय के भीतर सभा पटल पर प्राप्त होगी । इस प्रकार प्रस्तुत किए गए संशोधनों की क्रम संख्या को दर्शानेवाली सूची कुछ समय पश्चात सूचना पट्ट पर लगा दी जाएगी । माननीय सदस्य यदि सूची कोई विसंगति बातें हैं, तो कृपया उसे तत्काल सभा पटल पर अधिकारियों को अवगत कराने की कृपा करें ।

माननीय श्री राहुल गांधी जी ।

SHRI RAHUL GANDHI (RAEBARELI): Thank you, Speaker Sir for allowing me to speak on the President?s Address. I heard the President?s Address. I sat there with Kharge ji and I listened to it. I must say that I struggled through the President?s Address to maintain my attention on what was being said because I had heard pretty much the same President?s Address the last time, the time before that and the time before that. It was the same laundry list of things that the Government has done ? we have done this; we have done this; we have done this ? 50 or 100 things that the Government has done. So, while I was sitting there, I was thinking, okay I am being critical about what is being said. I am saying that this is not the type of President?s Address that should be delivered. Well, the question came to my mind, what type of an Address would the INDIA *Gathbandhan* Government deliver?

How would that Address be different from the Address we heard because it is no point me saying that it is a laundry list and then, not providing an alternative idea? And so, today, I would like to lay out some dimensions of what an alternative Address would look like; what the INDIA *Gathbandhan* would probably focus on and where we would lay emphasis. The future of this country is going to be decided by the young men and women of this country, the youth of this country. So, I think, anything we say, has to be addressed to them; has to be spoken to them.

The first thing in front of us ? and this is something I am sure the Prime Minister would accept and pretty much everybody in this room will accept ? is that even though we have grown fast, we are growing slightly slower now but we are still growing. A universal problem that we have faced is that we have not been able to tackle the problem of unemployment. Neither the UPA Government nor today?s NDA Government has given a clear-cut answer to the youth of India about employment. I do not think anybody in this room will disagree with me.

I will give little statistics for the Prime Minister. The Prime Minister proposed the Make-in-India programme. It is something I would agree with directionally. I think it is a good idea. We saw the statues. We saw the functions. We saw the so-called investment and the result is right in front of you. The manufacturing fell from 15.3 per cent of GDP in 2014 to 12.6 per cent of GDP today. That is the lowest share of manufacturing in 60 years. I am not even blaming the Prime Minister because, I think, it would not be fair to say that he did not try. I could say that the Prime Minister tried, and I think, conceptually, Make-in-India was the good idea, but it is pretty clear that he failed because manufacturing went from 15.3 per cent of GDP to 12.6 per cent. So, the first question that any alternative vision would answer to the youngsters of our country is: what and how are we going to solve this problem of employment?

Any country basically organises two things. You can organise consumption and then, you can organise production. The modern way of saying ?organising consumption? is services. The modern way of saying ? organising production? is manufacturing. But there is more to production than simply manufacturing. For example, agriculture also is about

production. Now, pretty much, every Government since 1990 has done a decent job on consumption, on organising consumption. Which are the companies that organise consumption? Uber organises consumption. Reliance organises consumption. Adani organises consumption. But we have, as a country, failed in organising production. We have excellent companies that try to organise production. The Mahindra is of this world. The Bajaj is of this world. Part of Tata organises production. But the record of the country in organising production is dismal. And essentially, what we have done is that we have handed over the organisation of production to the Chinese.

So, regarding mobile phone, even though we are saying that we make this mobile phone in India, that is not a fact. This phone is not made in India. This phone is assembled in India. All the components of this phone are made in China. The network that has produced this phone is made in China and is owned by China.

So, every time we use a phone, every time we wear a Chinese shirt or a Bangladeshi shirt, every time we wear a pair of Chinese sneakers, we are paying a tax to China because some Chinese youngster is earning a salary to make or produce that product. So, the first message I would give in a Presidential Address would be that India has to focus completely on production because if we do not focus on production and we continue to focus only on consumption, we will find that we will run huge deficits, we will increase inequality and eventually, we will run into a serious problem, and then social problem because of unemployment which we are already facing. If you look at the numbers of the amount of people who are in jail, if you look at the numbers that are spent on internal security, if you look at the numbers spent on our police forces, they have all spiralled; they are all rising and everybody understands this social tension is on rise in India.

So, now, the next question comes. So, where is this employment going to come from and what is India going to produce? And for that, I would like to tell all the youngsters of this country that there is a revolution taking place. It is an exciting revolution. The world is transforming completely and the change is taking place. At the heart of the change that is taking place, we are moving from the world of the internal combustion

engine to the world of the electric motor. We are moving from petrol to batteries, we are moving towards wind, solar and potentially, nuclear energy. So, our entire way of moving is changing and this is going to change every single thing. It is going to change warfare. It is going to change medical treatment. It is going to change education. It is going to change how we eat. It is going to change every single thing.

Now, there was a revolution called the computer revolution. The Government of India had a clear focus. We looked at that revolution. It was the Congress Government that looked at the revolution, and we decided clearly that we are going to focus on the development of software and we wrote the wave of revolution and today, you can see the result. I remember people laughing when the computer was being talked about. You mentioned Mr. Vajpayee. I respect Mr. Vajpayee. But Mr. Vajpayee gave a speech saying that computers are of no consequence to India. So, what is important when there is a revolution? What is important is that you understand what are the drivers of that revolution and where exactly do you need to focus, where exactly do you need to sit in that revolution. I said that there is revolution which is going to change everything. And I want the youngsters in this country to think about it.

There is a war going on in Ukraine. The war in Ukraine is actually a war between the internal combustion engine and the electric motor. The electric motor is inside the drone; the engine is inside the tank. And if you look at what is going on in Ukraine, the tanks are dying by the thousands and small little drones with electric motors, small batteries, not much bigger than that phone, are destroying the entire tank, artillery, infrastructure of both Ukraine and Russia. So, the drone is the electric motor. The drone is the battery. The drone also needs to see. So, the drone is the camera. In the same way, electric car is a motor. Electric car is a battery. Electric car is camera. Robots are exactly the same thing. Robots are electric motors, multiple electric motors with cameras with batteries. And this is what the revolution is going to look like.

So, there are basically four technologies that are driving this entire change in mobility ? electric motors, batteries, optics and then on top of that, you can apply AI.

People talk about AI. But it is important to understand that AI, on its own, is absolutely meaningless because AI operates on top of data. Without data, AI means nothing. if we look at data today, there is one thing which is very clear. Every single piece of data that comes out of the production system in the world, the data that is used to make this phone, the data that is used to make electric cars, the data that is used to make basically all electronics on the planet today is owned by China and the consumption data is owned by the United States.

In China, the consumption data is owned by China. But in India, companies like Google, companies like Facebook, companies like Instagram, X own our consumption data. So, if India wants to talk about AI, it has to first answer the question, what data is going to power that AI? And the answer today is that India does not have that data. Neither does India have production data nor does India have consumption data. We have handed our consumption data to the big American companies and we do not have the production data anyway.

So, what would that vision look like? The first thing is, we would start getting youngsters excited about this revolution. We would start to introduce the idea of a completely new way of moving, a complete revolution in how things move. We would start teaching our children in schools about batteries, about electric motors, about how these things combine, about how drones, robots, electric cars are structured, how they will work together etc., and most importantly, we have to start building a production network so that we can get access to production data.

Now, what would we focus on? We would not give you a laundry list. China has at least a ten-year lead on India in this space. China has been working on batteries, robots, motors, optics for the last ten years and we are lagging behind. So, what would our President?s Address say to the youngsters? We will choose critical areas in each one of these technologies and we will start to build capabilities in those areas.

The second thing we would do is we would ensure that our banking system is not captured by two or three companies which basically do not allow you to build a production system. But our banking system is open,

dynamic, and accessible to small and medium businesses and to millions and millions of entrepreneurs who want to take part in this revolution.

Our foreign policy would take into account this revolution. When we talk to the United States, we would not send our Foreign Minister to invite our Prime Minister to his coronation. We would not send him three or four times to say please invite our Prime Minister. If we had a production system and if we were working on these technologies, the American president would come here and invite the Prime Minister. So, it is important to understand? (*Interruptions*)

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS; AND MINISTER OF MINORITY AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU): Sir, the Leader of Opposition cannot make such a serious unsubstantiated statement. ? (*Interruptions*) This is related to the relationship between the two countries and he is making an unverified statement about invitation of the Prime Minister of our country.? (*Interruptions*) It is a matter of our dignity. How can you make such kind of a statement? He is the Leader of Opposition. He should be responsible for making such a statement. ? (*Interruptions*) This is not right ? (*Interruptions*)

SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Sir, LOP is giving us very, very positive suggestions. Why are they worried?

SHRI KIREN RIJIJU: Has the Leader of Opposition got this information from any official source? ? (*Interruptions*) He must inform the House? (*Interruptions*) If Leader of Opposition has the information, he may please inform the House who has told him that Foreign Minister has visited US for the purpose which you have mentioned. You must specify it.

SHRI RAHUL GANDHI: I am sorry, that this question disturbed you. I apologize for disturbing your peace of mind. ? (*Interruptions*) It is okay. ? (*Interruptions*) I have apologized. I have apologized for disturbing your peace of mind. I am sorry.? (*Interruptions*)

SHRI KIREN RIJIJU: You should apologize for lying to the House. ऐसा नहीं होता है । ? (व्यवधान) लीडर ऑफ अपोजिशन को गंभीर होना चाहिए ।? (व्यवधान) कम से कम देश के मामले में तो एक हों ।? (व्यवधान) देश के मामले में तो एक आवाज से बोलना चाहिए ।? (व्यवधान) यह गलत बात है ।? (व्यवधान) यह ठीक नहीं है ।? (व्यवधान)

लीडर ऑफ अपोजिशन को इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए ।? (व्यवधान) य67ह गंभीर विषय पर चर्चा चल रही है ।? (व्यवधान)

SHRI RAHUL GANDHI: So, we would start by telling our young men and women that they have to be at the forefront of this revolution. We cannot afford that the Chinese are at the forefront of this revolution. This is number one.

Secondly, we should ensure that the absolute best experts on these technologies would talk to our students, youngsters, and guide them on what these future technologies are going to do. We would make them partners in this revolution.

Now, we talk about defense. Today, we have the Chinese, and the Prime Minister has denied it, and the army has contradicted the Prime Minister.? (*Interruptions*) It is true. The Prime Minister has denied it. ? (*Interruptions*) The Prime Minister has denied it, and the Army has disagreed with the Prime Minister that China is sitting on 4,000 square kilometres of land. ? (*Interruptions*)

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री; तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी) : सर, ये क्या बोल रहे हैं?? (व्यवधान)

श्री किरेन रिजिजू : इस सदन में आप मनचाही बात नहीं बोल सकते हैं ।? (व्यवधान) सर, यह बिल्कुल ठीक नहीं है ।? (व्यवधान) यह सीरियस मामला है ।? (व्यवधान) आप फॉरेन पॉलिसी पर, बार्डर इश्यू पर कैसे मजाक में बात कर सकते हैं ।? (व्यवधान) आप अपने मनमाफिक कहानियाँ बनाकर बोल रहे हैं ।? (व्यवधान) यह बहुत गंभीर मामला है ।? (व्यवधान)

***m18माननीय अध्यक्ष :** माननीय प्रतिपक्ष के नेता, जो विषय आप बोल रहे हैं, उसके तथ्यों को आप सदन के पटल पर रखना ।

? (व्यवधान)

SHRI RAHUL GANDHI: Let me speak. ? (*Interruptions*)

श्री किरेन रिजिजू : सर, मेरा अनुरोध है कि लीडर ऑफ अपोजिशन बोलें, हम लोग शांति से सुनेंगे । ? (व्यवधान) बोलने का आपका अधिकार है, मगर आप ऐसे गंभीर इश्यू पर मनचाहे तरीके से कैसे बोल सकते हैं? ? (व्यवधान) यह गंभीर मामला है ।? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सदन में बोल रहे हैं, आपको तथ्य तो पेश करने पड़ेंगे ।

? (व्यवधान)

श्री किरेन रिजिजू : आप अपनी मर्जी से बोलते हो ।? (व्यवधान) आप फॉरेन मिनिस्टर की बात क्यों करते हो? ? (व्यवधान) आप सीमा की बात करते हो ।? (व्यवधान) आप ऑफिशियल

मैटर पर अलग बात करते हो ।? (व्यवधान) आप ऐसा मत बोलिए, यह देश के लिए ठीक नहीं है ।? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपको तथ्य पेश करने पड़ेंगे । डिफेंस महत्वपूर्ण विषय हैं । आप इन विषयों पर जो बोलें, उनके संदर्भ में तथ्य पेश कर दें ।

? (व्यवधान)

श्री किरेन रिजिजू : लीडर ऑफ अपोजिशन, आपको सीरियस होना पड़ेगा ।? (व्यवधान) इस गंभीर मामले पर आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं ।? (व्यवधान)

SHRI RAHUL GANDHI: The Prime Minister has denied that Chinese forces are inside our territory. But for some reason, our Army keeps talking to the Chinese about their entry into our territory. Our Chief of Army Staff has said that the Chinese are inside our territory. This is a fact.? (*Interruptions*) This is not an invention. This is a fact. ? (*Interruptions*) Now, it is important to know the reason why China is inside our territory. It is because people think that wars are fought between armies and their weapons. But, the fact of the matter is that wars are fought by industrial systems. The fact of the matter is that China has an industrial system that is far stronger, far bigger than our industrial system. And, that is why, they have the guts to come inside this country. The reason China is sitting inside this country is because ?Make in India? has failed. ? (*Interruptions*) The reason China is sitting inside this country is because India is refusing to produce.

And, I am worried that India is going to give up this revolution to the Chinese once again. ? (*Interruptions*) The reason I made this reference is because everything is connected. If and when we fight a war with China, we will be fighting with Chinese electric motors, Chinese batteries, Chinese optics, and we will be buying Chinese motors, Chinese optics, Chinese batteries. ? (*Interruptions*) It is a non-sustainable proposition. ? (*Interruptions*) That is why for our security, for the future of our children, for the future of our country, we have to build a production system and we cannot allow this revolution to go by.

Now, the next step, we have a strategic partner called the United States. The partnership should focus on how India and the United States can work together to take advantage of this revolution. That is what the conversation should be on. Please understand that India is as important as the United States for the simple reason that they cannot build an industrial

system without us. They cannot build a production system without us. No matter what they say, the Americans simply cannot do what India can do because their cost structure is much, much, much more expensive than ours. We can build things that the Americans would never imagine. India can do that. So, that would be the first part of the President's Address. We would talk to the youngsters in India and say to them, ?We want you to be partners in this revolution, we want to change the Indian banking system so that you can have access to it; we believe in you; we have trust in you; and we believe that you can take on the Chinese.? That is the first part.

The second part would be about participation. We have done a caste census in Telangana, and what we have found is shocking. Almost 90 per cent of Telangana?s population is either Dalit, Adivasi, backward, or minority. It is almost 90 per cent. And, I am convinced that that is the story across the country. I am absolutely convinced that the OBC population of this country is not one less than 50 per cent, possibly 55 per cent. About 16 per cent are Dalits, 9 per cent are Adivasis, and 15 per cent are minorities. During the last Budget, there was a photograph. You remember the photograph. ? (*Interruptions*) वह मक्खन बांटने वाली फोटो, हलवा बांटने वाली फोटो । मैं हैरान हो गया कि इस बार फोटो ही हटा दी । हलवा खिलाया, लेकिन दिखाया नहीं कि किसे हलवा खिलाया है ।? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप चेयर को संबोधित कीजिए ।

? (व्यवधान)

SHRI RAHUL GANDHI: So, at the center of any new development paradigm for this country, which runs parallel with the production paradigm I spoke of, which works together with the production paradigm I spoke of, is the participation of lower castes, OBCs, Dalits, Adivasis, in the wealth of this country. If we look at the largest corporates in this country, they are all owned. None of them are owned by OBCs; none of them are owned by Dalits; none of them are owned by tribals. If we look at the biggest Media companies that support the Prime Minister ? every day we see the Prime Minister's pleasant face, smiling face on these Media channels ? none of them are owned by OBCs; none of them are owned by Dalits; none of them are owned by Adivasis. ? (*Interruptions*) This is a fact. So, central to any new development paradigm is the architecture of a new paradigm.

And, that architecture of a new paradigm can only be built once the caste census is placed on this Table. ? (*Interruptions*) It is because once the caste census is placed on the Table, we will know exactly how much of this country's wealth, how much of this country's power, and how many of this country's institutions are owned by 90 per cent population of this country.

There are OBC MPs in the BJP. There are Dalit MPs in the BJP. There are Adivasi MPs in the BJP. Remember, you are OBCs. You have 50 per cent of the population and you have absolutely no power. I know that you are sitting there and you cannot even open your mouth. That is the truth of the country. *....(Interruptions)*

संसदीय कार्य मंत्री; तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री किरेन रिजिजू) : क्या आपको प्रधान मंत्री जी का चेहरा दिखाई नहीं देता है?? (व्यवधान) क्या आप ... * हो गए हैं? ? (व्यवधान) क्या देश के सबसे बड़े नेता का चेहरा आपको दिखाई नहीं देता है? ? (व्यवधान) क्या ?लीडर ऑफ ऑपोजीशन? को कुछ दिखाई नहीं देता है?? (व्यवधान)

SHRI RAHUL GANDHI: Speaker, Sir, the idea is, on one side, allow India and the Indian youngsters to participate in the coming mobility revolution, allow them to participate in building robots, in building drones, in building electronic items, in building EVs *....(Interruptions)*

***m28 श्री गौरव गोगोई :** सर, यह नसीहत केवल हमें मिलती है ।? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं, ऐसा नहीं है । मैंने उनको भी मना किया है । आप भी बहुत डिस्टर्बेंस करते हैं ।

SHRI RAHUL GANDHI: Sir, there are parallel ideas. One idea is, participate in the mobility revolution. Whether you are thinking of the economy, weapons, production or healthcare, India should participate in this revolution. India should become the master of the electric motor, master of the battery, master of optics, and master of AI applied on top of that production system.

Now, imagine the power of AI when we apply it to the caste census. You imagine what we will do with AI, and what we will do with the social revolution in this country when we start to apply AI on the data that we get from the caste census. So, we are going to run a parallel track. On one side, revolutionizing the participation of Dalits, OBCs, Adivasis in the ruling of this country, in the institutions of this country, in distribution of wealth of this country, and, on the other side, there would be a parallel track,

challenge the Chinese and participate in the revolution, defeat the Chinese in electric motors, batteries, solar panels, and wind. These are the first two parts of any Presidential Address that any INDIA *gatbandhan* leader would give you.

Finally, of course, we go back to the Constitution. Just like the production system is a weapon, just like *jatiya janganana* is a weapon of transformation. This is what the entire architecture is built on. I remember before the elections, all of you were saying *400 paar,* and you were saying you would change this. Then, I was glad to see that the Prime Minister walked in and was forced to bow his head in front of the Constitution. It was a moment of pride for all Congress people that we had explained to the Prime Minister and to the whole country that no force will dare touch this.

I know that the RSS has never accepted this. ... * has said that India did not get Independence in 1947. *....(Interruptions)* He has said that this Constitution is meaningless. *....(Interruptions)* I know that is in your heart. We will never let your dream come true. This Constitution is going to rule India always. *....(Interruptions)*

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट । आप प्रतिपक्ष के नेता हैं । मेरा आपसे आग्रह है कि जो विषय आप रखें, उनको आप तथ्यों के आधार पर रखें । यह उचित होगा । मैंने आपको पहले भी कहा है कि जो सदन के सदस्य नहीं हैं, उनकी चर्चा न करें । आप नियम-प्रक्रियाओं का पालन करें । यही आपसे अपेक्षा है ।

? (व्यवधान)

***m32 श्री राहुल गांधी :** सर,... *ने स्टेटमेंट दिया है ।

Speaker Sir, ...* made a statement saying: ?India did not receive Independence in 1947. It received Independence when the Ram Mandir was inaugurated.? We will place it on the Table.

Now, I would like to mention one small thing, but very important thing. Speaker Sir, this Constitution is supported by the vote of our people. Without the secure vote of the Indian people, this Constitution means nothing. Now I want to bring to the notice of this House, some data, some information about the Maharashtra election. It is very simple stuff. Between the Lok Sabha election, which the INDIA Alliance won, and the Vidhan

Sabha election, the voting population of Himachal Pradesh was added to the voting roll of Maharashtra. It means the entire population of Himachal Pradesh was added to the voter rolls of Maharashtra. Please understand what I am saying. The difference of voters between Lok Sabha elections and the Vidhan Sabha elections was the population of Himachal Pradesh. The entire population of almost 70 lakh new voters suddenly arrived between Lok Sabha and Vidhan Sabha elections. Now the most interesting part is this. The Prime Minister is not looking at me. ? (*Interruptions*)

श्री किरेन रिजिजू : कोई नहीं सुन रहा है ।? (व्यवधान) आप तर्क पर बात करो । ? (व्यवधान) सब सुनेंगे । ? (व्यवधान)

***m34 श्री राहुल गांधी :** उन्होंने सडनली मुंह नीचे कर लिया । ? (व्यवधान) The most interesting part is more voters were added in five months in Maharashtra than were added in five years in Maharashtra. जितने पांच सालों में एड हुए, उससे ज्यादा पांच महीनों में एड हो गए हैं, आखिरी पांच महीनों में, लोक सभा चुनावों के बाद । सर, शिरडी में एक बिल्डिंग में सात हज़ार नए वोटर्स एड हुए । ? (व्यवधान) एक बिल्डिंग में सात हज़ार नए वोटर्स एड हुए हैं । ? (व्यवधान) मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ । ? (व्यवधान) मैं सिर्फ यह कह रहा हूँ कि इसमें कुछ न कुछ प्रॉब्लमैटिक है कि हिमाचल प्रदेश जितने बड़े प्रदेश के बराबर की संख्या में वोटर्स लोक सभा चुनावों के बाद जादू से आ जाते हैं । अब हम क्या कह रहे हैं? हमने इलेक्शन कमीशन से रिपीटिडली कहा है कि हम आरोप नहीं लगा रहे हैं । आप एक काम कीजिए कि हमें लोक सभा की वोटर्स लिस्ट दे दीजिए, नेम, एड्रेस और इलेक्ट्रॉनिकली दीजिए और विधान सभा । ? (व्यवधान) नहीं सर, नहीं है । ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : वह सब वेबसाइट पर रहती है, सब जानते हैं । कभी भी कोई भी निकाल सकता है ।

SHRI RAHUL GANDHI: Speaker Sir, we are asking this question. ? (*Interruptions*) The population of Himachal Pradesh has voted extra in Maharashtra. We are saying to the Election Commission to please give us the names, addresses and polling booths of all the voters in the Lok Sabha and all the voters in the Vidhan Sabha so that we can calculate who these new voters are.

Interestingly, the new voters are mostly in the constituencies that BJP has swept. Please understand this. The new voters have been added mostly in the constituencies where BJP has swept. I am still not making an

allegation. I am saying on the floor of the House that the Election Commission has to give the data of the Maharashtra elections to the Congress Party, Shiv Sena and NCP so that we can see exactly where these voters have been added, who has been subtracted and where they have been added. This is not an irresponsible request. This is a very simple request for them to fulfil. ? (*Interruptions*)

The reason I am saying this is because the rules have been changed. This is not just said in isolation. The Election Commissioner used to be chosen by the Prime Minister, the Leader of Opposition and the Chief Justice. The Chief Justice was removed from that Committee. Why is it so? ? (*Interruptions*) This is a question to the Prime Minister. Why was the Chief Justice removed from the Committee? In a few days, I am to go to the meeting where there will be Mr. Amit Shah and Mr. Modi ji and there is going to be me. It would be 2:1. Why am I even going to the meeting? What is the purpose of me going to the meeting? I am only going to the meeting to certify what Modi ji and Amit Shah ji are going to say. Right? Whereas, if the Chief Justice was there, then there could be a discussion. The Chief Justice and the Leader of Opposition could say that ?No, we do not agree?. So, there seems to be a calculated strategy.

Now, just prior to the Lok Sabha elections, the Election Commissioner was changed and two new Election Commissioners were replaced. ? (*Interruptions*) We know that the election dates were changed. We know that the elections were postponed. These are facts. These are not things that I am inventing. So, in order to safeguard this Constitution, the entire Opposition requests the data for the Maharashtra elections. ? (*Interruptions*) We request the data and the electoral voters list for the Lok Sabha elections and the corresponding list for the Vidhan Sabha elections. And I am very confident that the Election Commission will not give us this information. ? (*Interruptions*)

Speaker Sir, the third element of our President?s Address would be a determined defence of India?s institutions, of our democratic system, and a relook at our entire democratic framework and looking again at all the institutions that have been taken away from the people of India. So,

those would be the type of things that we would say in a Presidential Address.

Finally, I would like to say one thing. ? (*Interruptions*) So, in the last, there is a philosophical background to what I am saying. Essentially, what I am saying to the youngsters of India and to this House is that instead of focussing on multiple things, instead of telling us a laundry list, give us a strategy and give us a vision. Make it clear. Right? Now, there is a philosophical basis to this. ? (*Interruptions*) There is even a deep philosophical basis to this. I showed you the picture of Shiv ji, which you did not allow me to show. I showed that picture for a reason.

15.00 hrs

What does that picture tell us? If you look at that picture carefully, it tells us, ?Focus carefully, do not get distracted, do not look here and there, do the job at hand?. So, there is a philosophical basis to the speech I have given. I have not told the House and the country that we will do this, this, this, this, this and this. This is the philosophy of Shiv ji. Say what you have to say, but be clear that you are going to do that one thing, not 50, 60 or 70 different things. So, there is a link between our philosophical tradition, our religious tradition, and what I am saying and that is what India needs to do. India needs to connect the past, the values of the past. You talk about Sardar Patel ji, but you destroy Sardar Patel ji's values every day. You talk about Ambedkar ji, you destroy his values every day. You talk about Nehru ji, no, you do not talk about Nehru ji. You bow in front of Buddha, you destroy what he says. So, the point is, you have to be truthful to what you are.

And it is important that when you are giving a way forward to the nation, there is clarity, there is clarity of purpose, there is no hatred, there is no violence, and there is no anger, because these things are destroying our country. So, my speech has not been angry, has not been nasty. My speech has been very polite, and very kind, and I thank the hon. Prime Minister, Modi ji, for coming and listening to it.

TEXT OF AMENDMENTS

SHRI AMRA RAM (SIKAR): I beg to move:

That at the end of the motion, the following be added, namely:-

"but regret that there is no mention in the Address about the growing unemployment in the country." (1)

That at the end of the motion, the following be added, namely:-

"but regret that there is no mention in the Address about the inability of the Government to curb the price rise particularly the price of petrol and diesel."(2)

That at the end of the motion, the following be added, namely:-

"but regret that there is no mention in the Address about the economic slowdown and steps taken to revive the Indian economy." (3)

That at the end of the motion, the following be added, namely:-

"but regret that there is no mention in the Address about bribery allegations and favouritism against an Indian conglomerate."(5)

That at the end of the motion, the following be added, namely:-

"but regret that there is no mention in the Address about digitisation, which allegedly is trampling the rights of rural poor as evident in the dreadful plight of MNREGA workers."(6)

That at the end of the motion, the following be added, namely:-

"but regret that there is no mention in the Address about the denial of relief fund by Central Government for the Wayanad landslides."(7)

That at the end of the motion, the following be added, namely:-

"but regret that there is no mention in the Address about the administrative mismanagement in the arrangements of Mahakumbh resulting into loss of lives and injury at the Mahakumbh."(8)

That at the end of the motion, the following be added, namely:-

"but regret that there is no mention in the Address about the growing attacks against minority communities like Muslims and Christians and Scheduled Castes/Scheduled Tribes."(9)

That at the end of the motion, the following be added, namely:-

?but regret that there is no mention in the Address about the proposal to guarantee minimum support price for the purchase of all Kharif and Rabi crops, including moong and groundnut from Rajasthan."(53)

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): I beg to move:

That at the end of the motion, the following be added, namely:-

"but regret that there is no mention in the Address about the alleged failure of the Government in controlling the Manipur violence."(4)

That at the end of the motion, the following be added, namely:-

"but regret that there is no mention in the Address about any special package for the State of West Bengal."(20)

That at the end of the motion, the following be added, namely:-

"but regret that there is no mention in the Address about any concrete step taken to control price rise, especially the prices of essential items in the country."(21)

That at the end of the motion, the following be added, namely:-

"but regret that there is no mention in the Address about establishing a permanent mechanism for controlling the price of petroleum products and a special scheme for reduction of petroleum prices." (22)

That at the end of the motion, the following be added, namely:-

"but regret that there is no mention in the Address about the continuing protest demanding legal support for Minimum Support Price to various agricultural products and welfare schemes of farmers in the country."(23)

That at the end of the motion, the following be added, namely:-

"but regret that there is no mention in the Address about the employment generation for the lakhs of unemployed youth." (24)

That at the end of the motion, the following be added, namely:-

"but regret that there is no mention in the Address about the release of central funds due for the State of West Bengal." (25)

That at the end of the motion, the following be added, namely:-

"but regret that there is no mention in the Address about the steps taken to regulate central agencies like ED and CBI to ensure fairness in their working." (26)

That at the end of the motion, the following be added, namely:-

"but regret that there is no mention in the Address about the measures countering the influence of China in neighbouring countries." (27)

That at the end of the motion, the following be added, namely:-

"but regret that there is no mention in the Address about the importance of maintaining communal harmony and steps to control the atrocities on women and children across the country." (28)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): I beg to move:

That at the end of the motion, the following be added, namely:-

"but regret that there is no mention in the Address about a special package for women empowerment and sustainable development." (10)

That at the end of the motion, the following be added, namely:-

"but regret that there is no mention in the Address about any project/scheme for management of man-animal conflict." (11)

That at the end of the motion, the following be added, namely:-

"but regret that there is no mention in the Address about the programme for increasing the food production in the country by giving special assistance, subsidy and support to the farmers." (12)

That at the end of the motion, the following be added, namely:-

"but regret that there is no mention in the Address about any effective programme and project for providing more employment opportunities to the youth. (13)

That at the end of the motion, the following be added, namely:-

"but regret that there is no mention in the Address about any special scheme for protecting the cashew industry, providing employment and ensuring welfare of cashew workers." (14)

That at the end of the motion, the following be added, namely:-

"but regret that there is no mention in the Address about any programme and measure for controlling and regulating inflation and price rise." (15)

That at the end of the motion, the following be added, namely:-

"but regret that there is no mention in the Address about increasing the minimum pension in Employees? Provident Fund Scheme and time bound implementation of Supreme Court judgment on pension and higher wages." (16)

That at the end of the motion, the following be added, namely:-

"but regret that there is no mention in the Address about increasing the wages and other benefits of Anganwadi workers, ASHA workers and other categories of workers in the unorganised sector and extend the benefit of Employees? State Insurance Corporation to all the workers in the unorganised sector." (17)

That at the end of the motion, the following be added, namely:-

"but regret that there is no mention in the Address about any programme or project for protecting child health and for reducing the death rate of children due to malnutrition." (18)

That at the end of the motion, the following be added, namely:-

"but regret that there is no mention in the Address about any schemes/ programmes or project for ensuring livelihood of fisherfolk and for improving their living standard." (19)

श्री सुधाकर सिंह (बक्सर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थातः-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है । (29)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थातः-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषि संकट और कृषि उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी देने में विफलता के कारण किसानों का बिचौलियों और बाजार द्वारा शोषण किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।" (30)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थातः-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में निजीकरण और रेलवे में भर्ती के अभाव के कारण रोजगार संकट तथा एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी और यूपीएससी जैसी परीक्षाओं में पेपर लीक और देरी का कोई उल्लेख नहीं है ।(31)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थातः-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में महंगाई तथा एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल, डीजल, ऊर्वरक और खाद्य पदार्थों की कीमतों में भारी वृद्धि से गरीब, मध्यम वर्ग और किसानों के बुरी तरह से प्रभावित होने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।"(32)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थातः-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बिहार में लाखों लोगों का जीवन प्रभावित करने वाली हर साल आने वाली बाढ़ के दौरान आपदा प्रबंधन के लिए किए गए उपायों

और आपदा राहत कोष को समय पर जारी किए जाने के उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।"(33)

प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित बातें जोड़ा जाए, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के संघीय ढांचे पर कथित हमले के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।"(34)

प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित बातें जोड़ा जाए, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बिहार और पूरे भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की खराब स्थिति, विशेष रूप से केंद्रीय सरकार द्वारा बजट में एम्स-पटना और अन्य सरकारी अस्पतालों के लिए विशेष प्रावधान तथा पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय 'विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने तथा गरीब और अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रों के लिए उच्चतर शिक्षा को सस्ता किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है । "(35)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थातः-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में नफरती अपराधों और सांप्रदायिक हिंसा की बढ़ती घटनाओं के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।"(36)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थातः-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में चीन द्वारा लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में सीमाओं पर भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ से उत्पन्न चुनौतियों और सीमा विवादों को सुलझाने के लिए कोई ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।" (37)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थातः-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में डॉलर के मुकाबले रुपये के गिरते मूल्य के चलते मुद्रास्फीति और आयातित वस्तुओं (तेल, गैस, इलेक्ट्रॉनिक्स, दवा आदि) के दाम बढ़ने तथा परिणामस्वरूप निर्यात में गिरावट और व्यापार घाटे में वृद्धि के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।"(38)

श्री लालजी वर्मा (अम्बेडकर नगर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थातः-

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण कोटे को पूरा करने में सरकार की विफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।"(87)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थातः-

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में किसानों के ऋण माफ किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।"(88)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थातः-

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में विद्युतकरघा बुनकरों को सस्ती दरों पर विद्युत उपलब्ध कराने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।"(89)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थातः-

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में उच्चतर न्यायिक सेवा आयोग की स्थापना करने और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित लोगों को उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में आरक्षण प्रदान करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।"(90)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थातः- "किंतु खेद है कि अभिभाषण में देश में नागरिकों को निःशुल्क चिकित्सा उपचार प्रदान करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।"(91)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थातः- "किंतु खेद है कि अभिभाषण में उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर जिले में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।"(92)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थातः-

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने में सरकार की विफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।"(93)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थातः- "किंतु खेद है कि अभिभाषण में उत्तर प्रदेश में अयोध्या से वाराणसी तक एक्सप्रेसवे के निर्माण के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।"(94)

SHRI VISHALDADA PRAKASHBAPU PATIL (SANGLI): I beg to move:

That at the end of the motion, the following be added, namely:-

?but regret that there is no mention in the Address about the need for a permanent solution to the recurring floods across flood-prone areas such as Sangli, which lead to massive displacement, destruction of crops, and economic distress for farmers and small businesses." (124)

That at the end of the motion, the following be added, namely:-

"but regret that there is no mention in the Address about the strengthening of the cooperative banking sector, which plays a crucial role in supporting small farmers, traders, and entrepreneurs across Maharashtra and particularly in Sangli, but is currently facing financial instability and policy neglect." (125)

That at the end of the motion, the following be added, namely:-

"but regret that there is no mention in the Address about the measures to support the sugarcane farmers particularly in Sangli, who face challenges such as rising input costs, unpredictable climate conditions, and the need for policies that ensure long-term sustainability and profitability in the sugar sector." (126)

That at the end of the motion, the following be added, namely:-

"but regret that there is no mention in the Address about the growing unemployment and the jobless growth phenomenon in the country and concerns over layoffs in the formal sector and lack of opportunities for skilled youth." (127)

That at the end of the motion, the following be added, namely:-

"but regret that there is no mention in the Address about the urgent need to control rising inflation, and falling rupee which is significantly impacting the affordability of essential commodities, burdening the middle class and poor households across India." (128)

That at the end of the motion, the following be added, namely:-

"but regret that there is no mention in the Address about the increase in incidences of paper leaks in recruitment examinations for government jobs, leading to frustration among lakhs of aspiring youth eroding faith in the system." (129)

That at the end of the motion, the following be added, namely:-

"but regret that there is no mention in the Address about the growing economic inequality in the country, with a widening wealth gap between the rich and poor, exacerbating social and economic disparities." (130)

That at the end of the motion, the following be added, namely:-

"but regret that there is no mention in the Address about the underfunding of Scheduled Caste and Scheduled Tribe welfare programs, including critical scholarships, rehabilitation schemes for manual scavengers, and initiatives aimed at reducing crimes against Dalit community." (131)

That at the end of the motion, the following be added, namely:-

"but regret that there is no mention in the Address about comprehensive measure to address India?s water crisis, including

groundwater depletion, inefficient irrigation practices, and the urgent need for large-scale rainwater harvesting initiatives." (132)

That at the end of the motion, the following be added, namely:-

"but regret that there is no mention in the Address about the inadequate budgetary allocation for climate resilience, with funding cuts in key environmental programs, lack of district-level vulnerability mapping, and insufficient focus on adaptation measures for sectors critically impacted by climate change." (133)

DR. T. SUMATHY *ALIAS* THAMIZHACHI THANGAPANDIAN (CHENNAI SOUTH): I beg to move:

That at the end of the motion, the following be added, namely:-

?but regret that there is no mention in the Address about the steps taken by the Government to curb the unprecedented rise in prices of all essential commodities." (152)

That at the end of the motion, the following be added, namely:-

"but regret that there is no mention in the Address about the alleged loss of 20 crore jobs and failure to tackle the huge unemployment problem in the country." (153)

That at the end of the motion, the following be added, namely:-

"but regret that there is no mention in the Address about failure to allocate six per cent of GDP for education." (154)

That at the end of the motion, the following be added, namely:-

"but regret that there is no mention in the Address about the failure to develop road infrastructure in Tamil Nadu and to reduce the toll rates on National Highways in Tamil Nadu." (155)

That at the end of the motion, the following be added, namely:-

"but regret that there is no mention in the Address about the need to find a solution to the row over fishing rights in the Palk Bay Strait and Gulf of Mannar and the need to provide proper protection to the fishermen from the harassment by navy of neighbouring country." (156)

That at the end of the motion, the following be added, namely:-

"but regret that there is no mention in the Address about the urgent need to discontinue NEET in the state of Tamil Nadu in view of large

scale injustice imposed on the rural poor students who do not have the wherewithal to prepare for the costly NEET exams." (157)

That at the end of the motion, the following be added, namely:-

"but regret that there is no mention in the Address about the inequitable inter-se share of tax devolution to Tamil Nadu, despite its significant contribution to the nation's GDP and tax revenues." (158)

That at the end of the motion, the following be added, namely:-

"but regret that there is no mention in the Address about ensuring equitable allocation of funds to states for climate change mitigation and disaster management, on the basis of their vulnerability to coastal and environmental hazards, and about increasing disaster relief allocations to Tamil Nadu, while ensuring equitable distribution of funds under SDRF and NDRF." (159)

That at the end of the motion, the following be added, namely:-

"but regret that there is no mention in the Address about expeditious approval and funding of the metro rail projects in Madurai and Coimbatore to meet the urban transport needs of Tamil Nadu." (160)

That at the end of the motion, the following be added, namely:-

?but regret that there is no mention in the Address about the need for immediate release of pending funds under Samagra Shiksha Abhiyan for sustaining Tamil Nadu's exemplary educational achievements." (161)

श्री नरेश चंद्र उत्तम पटेल (फतेहपुर) : अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने महामहिम राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर मुझे बोलने का मौका दिया । इस सदन पर बोलते हुए सबसे पहले मैं महाकुम्भ में हुई दु:खद घटना का स्मरण करना चाहता हूं । उन सभी श्रद्धालुओं और भक्तों को मेरी भावपूर्ण श्रद्धांजलि । उन्होंने अपने जीवन की आस्था और भक्ति के साथ पवित्र स्नान करने का संकल्प लिया था, लेकिन दुर्भाग्यवश प्रशासनिक कुप्रबंधन और लापरवाही के चलते वे काल के गाल में समा गए । यह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी, बल्कि सरकार की नाकामी का यह एक जीता-जागता उदाहरण है । महाकुम्भ, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन माना जाता है, जो लाखों-करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास का केंद्र है । यह केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं था, बल्कि भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर का प्रतीक है । जिस प्रकार की अव्यवस्था इस बार रही, वह न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि सरकार की संवेदनहीनता और प्रशासनिक कुप्रबंधन को उजागर करती है ।

मान्यवर, सरकार को क्या यह पता नहीं था कि इतने विशाल आयोजन में भारी संख्या में श्रद्धालु आएंगे? क्या योजनाएं केवल कागज में बनती हैं, जो जमीनी स्तर पर कुछ नहीं हैं? इस महाकुम्भ में बड़ी-बड़ी बातें की गईं कि हम इस तरीके का प्रबंधन कर रहे हैं, लेकिन आज तक सरकार ने महाकुम्भ में मरने वालों की सूची जारी नहीं की । हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने सदन में पहले दिन कहा था कि महाकुम्भ पर चर्चा हो । यह दुनिया का बड़ा मेला, इस मेले में इतनी बड़ी अव्यवस्था, डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार में जिस तरीके का जनता के साथ मजाक हुआ, वह घोर निन्दनीय है ।

मान्यवर, इस सरकार की असफलताओं की बहुत लंबी सूची है । शिक्षा, जो किसी राष्ट्र की बुनियाद होती है, आज शिक्षा भ्रष्टाचार की वजह से गर्त में जा चुकी है, आज हर प्रतियोगी परीक्षा मजाक बनकर रह गई है । बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में जगह-जगह पेपर्स लीक हो रहे हैं । सरकार ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का गठन बड़े-बड़े वादों के साथ किया था और कहा गया था कि यह संस्था निष्पक्षता और पारदर्शिता की नयी मिसाल कामय करेगी, लेकिन आज हालत यह है कि परीक्षा प्रारंभ होने से पहले सोशल मीडिया में पेपर लीक हो जाता है । यही सरकार की पारदर्शिता है, क्या यही डिजिटल इंडिया का सच है? नीट की परीक्षा में लाखों मेडिकल छात्रों का भविष्य तय होता है, उसमें भी बार-बार पेपर लीक की घटनाएं होती हैं ।

मान्यवर, रेलवे भर्ती परीक्षा, एसएससी या यूजीसी हो, कोई भी परीक्षा इस सरकार की अक्षमता से बच नहीं पायी है । एनटीए स्थापित करने पर सरकार ने जो बड़े-बड़े दावे किए थे, वे सभी खोखले निकलें । महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में किसानों के फसलों के मूल्य के लिए एमएसपी गारंटी का कोई जिक्र नहीं है । देश के किसान लगातार इस बात की आशा लगाए बैठे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के समय कहा था कि हम एमएसपी की गारंटी देंगे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, हम किसानों को फसलों का लाभकारी मूल्य देंगे । आज हमारे देश का किसान दर-दर की ठोकरें खा रहा है । देश के अंदर किसानों में जिस तरह की निराशा है, वह लोकतंत्र के लिए बहुत ही शर्मनाक घटना है । भारतीय जनता पार्टी के बड़े-बड़े नेता जो इस देश और प्रदेश को चलाते हैं, जब चुनाव में जाते हैं, चुनाव के समय किसानों से कहते हैं कि हम किसानों को लाभकारी मूल्य देंगे, हम किसानों को मालामाल कर देंगे, भारतीय जनता पार्टी ने किसानों की आय दोगुना करने की बात की थी । आज किसानों का देश के साथ भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से दोहरा मापदंड अपनाए हुए है, उससे हमारे लोकतंत्र को बहुत आघात पहुंचा है ।

मान्यवर, हम उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से लोक सभा के सदस्य चुन कर आए हैं । हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने अपने जमाने में किसानों के लिए खाद, बीज और कीटनाशक दवाओं का प्रबंध किया था । लेकिन आज उत्तर प्रदेश में बुआई के समय खाद

की जितनी बड़ी किल्लत हुई, डीएपी नहीं मिली, यूरिया ब्लैक में मिल रही है, किसानों को पानी नहीं मिला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया । डबल इंजन की सरकार डबल असत्य भाषण पर विश्वास करती है । आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके का काम किसानों के साथ कर रही है, हम किसान के बेटे हैं । हमारे यहां आज किसानों के साथ डबल दुख हो रहा है । हमारे जिले में और प्रदेश में छूटा जानवरों से किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं, लेकिन फसल बीमा के अंतर्गत उनको कोई लाभ नहीं मिलता है । इसका जिक्र महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी के अभिभाषण में नहीं है । किसान बीमा की दुर्घटना की शुरुआत समाजवादी पार्टी के समय में पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने की थी, पहले किसानों को कोई भी दुर्घटना बीमा का लाभ नहीं मिलता था, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किसानों को बीमा दुर्घटना के नाम पर एक लाख रुपये की राशि निर्धारित की थी, जिसे बढ़ाकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी पांच लाख रुपये कर दिया था । काफी समय बीत गया, महंगाई बढ़ती जा रही है लेकिन किसान बीमा दुर्घटना पर आज पांच लाख रुपये की राशि वही बनी हुई है, हमारी मांग है कि किसान बीमा दुर्घटना की राशि को कम से कम 15 लाख रुपये करना चाहिए ।

<u>15.09 hrs</u> (Shri Krishna Prasad Tenneti *in the Chair*)

मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम मुफ्त सिंचाई देंगे, किसानों को हम मुफ्त सिंचाई देंगे, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में मुफ्त सिंचाई नहीं है, बिजली महंगी हो गई, डीजल का दाम बढ़ गया, खाद का दाम बढ़ गया, इससे किसान परेशान है । भारतीय जनता पार्टी ने मुफ्त सिंचाई की बात करके किसानों के साथ बहुत बड़ा मजाक किया है ।

मान्यवर, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए सरकारी नलकूपों का पानी और नहरों का पानी फ्री किया था । उसी साल के बाद भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के समय कहा था कि हम किसानों के निजी नलकूपों का बिजली बिल माफ करेंगे । आज उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है, लेकिन किसानों को बिजली फ्री नहीं मिल रही है । उनके ऊपर बिजली का भार दुगुना किया जा रहा है । निजी नलकूपधारक के ऊपर बिल के ऊपर बिल लगाया जा रहा है । जिन किसानों के पास ट्यूबवेल है, वह फेल हो चुका है, लेकिन उनके ऊपर भी बिजली के बिल लगाये जा रहे हैं ।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश किसानों का प्रदेश है । अभी धान की फसल आई है, जिसका जिक्र इस अभिभाषण में नहीं है । धान की फसल में धान के किसान परेशान हैं । उनका धान लागत मूल्य से भी कम दाम में लिया जा रहा है । किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है । आज प्रदेश के अंदर जिस तरह से किसानों में निराशा है, उसका जिक्र महामहिम के अभिभाषण में नहीं है ।

मान्यवर, आज हमारे मनरेगा के मजदूर सबसे ज्यादा परेशान हैं । उनको मनरेगा की मजदूरी समय से नहीं मिलती है और न आज उनकी मजदूरी बढ़ाई गई है । आज महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है । महंगाई को रोकने के बारे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कोई ध्यान नहीं है । आज हर चीज महंगी है । उपभोक्ता और उत्पादक के बीच में असंतुलन है । उस असंतुलन की वजह से जो किसान हैं, जो कमाता है, वह आज सबसे ज्यादा परेशान है । जिस आदमी को उनकी फसल खरीदनी पड़ती है, वह भी परेशान है । उपभोक्ता और उत्पादक के बीच में असंतुलन की वजह से आज चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है । इसको हम लोग दिल्ली में देखते हैं । आज किसान अपनी फसल का लागत मूल्य नहीं पा रहा है । लेकिन, आज खाने वाले को वही महंगा मिल रहा है । यही भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि हमारे देश में रुपये की वैल्यू, हमारे देश में मुद्रा की वैल्यू लगातार घटती जा रही है । आज हमारा रुपया बहुत ही कमजोर है ।

माननीय सभापति : कृपया अब आप समाप्त कीजिए ।

श्री नरेश चंद्र उत्तम पटेल : मान्यवर, उसकी मजबूती के लिए महामहिम के अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं है । हमारे देश में विदेशी कर्ज लगातार बढ़ रहा है । विदेशी कर्ज कैसे कम हो, उसके बारे में भी महामहिम के अभिभाषण कोई जिक्र नहीं है ।

माननीय सभापति: माननीय डॉ. काकोली घोष दस्तीदार जी ।

श्री नरेश चंद्र उत्तम पटेल : मान्यवर, किसानों को दर-दर की ठोकरें न खानी पड़े, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज हमारे किसान जो पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और आदिवासी हैं, उनका रिजर्वेशन भी भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से चौपट कर दिया है । जो किसानों के बच्चे हैं, वे पिछड़े वर्ग, दलित समाज और अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने संविधान में प्रदत्त जो आरक्षण है, उस आरक्षण को खत्म करने का काम किया है । ? (व्यवधान)

माननीय सभापति: अब आप समाप्त कीजिए ।

श्री नरेश चंद्र उत्तम पटेल : मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी लगातार महिलाओं के साथ भी अन्याय करती जा रही है । मान्यवर, ?नारी शक्ति वंदन अधिनियम? लागू करने की भी बात की गई थी । ? (व्यवधान)

माननीय सभापति: माननीय डॉ. काकोली घोष दस्तीदार जी ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति: अब आप बैठ जाइए ।

श्री नरेश चंद्र उत्तम पटेल : मान्यवर, आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं ।

DR. KAKOLI GHOSH DASTIDAR (BARASAT): Sir, thank you. I stand here on behalf of All India Trinamool Congress and my leader, Ms. Mamata Banerjee, to take part in the Motion of Thanks on the speech addressed to both the Houses by Mahamahim Rashtrapati ji, Shrimati Droupadi Murmu ji. Today is Basant Panchami, so, I also express my greetings to all Members here and to all the citizens, and I wish there was a holiday for us. हम इत्मीनान से पूजा करते, लेकिन वह नहीं हुआ । I am a very religious person, a devout Hindu, but I believe and respect all religions, and that is why, like me, there were millions of Indians who were preparing for the Maha Kumbh Mela that was supposed to take place after 144 years. Some of the poor people were saving money to go and take the *maha snan* on the Mauni Amavasya. Sad to say, Mahamahim Rashtrapati ji, in her message, spent only 61 words to express her sorrow and has not condemned the death, has not given condolence message to the families of the dead.

We are very sorry for it because she has totally neglected the dead people. There is definitely a discrepancy between the number of dead bodies in the morgues as said by the doctors and the number of dead bodies or the people missing that we see. The same thing had happened in the State during the COVID-19 times. So, in this State how much ever the advertisement they did, but as far as the preparedness is concerned, disaster management is concerned, they have failed. They are giving zero because they should not be given this kind of a responsibility where they play with the lives of the common man like this.

After we go on to her speech where she mentions about the middle-class, you know the National Council of Applied Economic Research says that 30 per cent of the total population of India belongs to the middle-class. We had the Budget on the next day in which a lot of promises were made. Who is the middle-class? People who earn between Rs.2 lakh and Rs.10 lakh per year are supposed to be the middle class. But what about inflation? What about food inflation? What about support to the farmers? What about waiving of the loans for the farmers? Nothing is mentioned in the speech of *Mahamahim* Rashtrapati ji. I am sorry to say that loans of the multinationals and the billionaires have been waived by the banks but not that of the farmers. This is absolutely unwarranted in a country where

we depend on the farmers for our food. We live in the cities. We do not grow our foods. The farmers do. They toil in and out. They were sitting at the Singhu border. In the border, they were tortured, but they were not given the waivers.

I would also like to draw attention to the hon. Rashtrapati ji?s speech where she talks about teaching. She says that the number of colleges has been increased; the number of universities has been increased. But is it not an irony that there are no teachers? The number of teachers has not been increased and the amount is absolutely ridiculous. What is being taught in certain States? I do not want to name those States because there also, as in the Maha Kumbh, there is failure. In the same State, teaching is such a failure. The teachers do not know how to add nine plus thirteen, what to talk about the students.

Mahamahim Rashtrapati ji talks about the medicines where she says that some drugs have been made customs duty free. That is definitely welcome. But there are many, many other drugs which need to be made custom duty free. Also, there are certain equipment because only medicines do not help patients. Some of the equipment that are being used for the patients in different hospitals of the country are charged 300 per cent customs duty. But nothing is happening. I would just like to draw the attention of *Mahamahim* Rashtrapati ji.

* Life of a human being is not measured in years or days. Their work is the yardstick for this.*

It should be realised that the work we do, the work we do for people is more important than the statistics we give.

Here, it is said ?Housing for All?. A huge number is being promised for three-crore families with a budget of Rs.5,36,000 crore. But I would like to draw the attention of this august House and also *Mahamahim* Rashtrapati ji that more than 11 lakh families in West Bengal are suffering and spending their nights under the open sky since 2022. When these families received sanction after we applied, more than 60 teams went from the Central Government and they checked all the data. An Action Taken Report was also sent from the State of West Bengal for this money to go, the Central Government?s part of the money, to more than 11 lakh

families. It appears that there is some kind of an economic blockade or some kind of an economic betrayal for West Bengal from the Central Government.

This has not been mentioned here. This is for the Awas Yojana. We are requesting again for these people and for the common men. The poor person, who is spending with his family under the open sky, has done no mistake and he is not a political person. Why did they spite on him? It is because people of West Bengal have never voted for the Bharatiya Janata Party and they have always defeated. So, this is not the right thing to do.

15.20 hrs (Shri Jagdambika Pal *in the Chair*)

She has said that there is a multi-fold increase in the number of seats in medical colleges. Well, it has definitely increased. But sometimes, the college fees are exorbitant. She is saying that there is a neo middle-class which is coming up. There is no middle-class at all. It is because of the inflation that the middle-class is shrinking; the middle-class cannot afford to pay the bills; the middle-class cannot afford to buy the fuel; and the middle-class cannot afford to buy food. There is food inflation in the country. And the Government has done nothing to take care of the middle-class.

Ms. Mamata Banerjee, my leader, has been taking care of the people by giving them free food, free education, and free clothes. The whole country should follow her example. You beat a lot of drums when you say that the Nari Shakti Vandan Adhiniyam was passed. Yes, it was passed in this august House. But when the elections came, we did not see so many ladies coming from the Bharatiya Janata Party, neither during nomination nor being present in the House. The only political Party in the country, which has fielded women and which has more than 33 per cent women, is the All India Trinamool Congress. It is due to Ms. Mamata Banerjee. She respects women. She has brought them here. Not only here, but also, in the local bodies and in each step of the administration, she is giving respect to the women and she is bringing them to the mainstream.

Somebody might stand up from there and say that you cannot take her name as she is not the Member of the House. She is the Chief Minister

of West Bengal. She is taking care of the poor. She is taking care of the *Dalits*. She is taking care of the women. She is taking care of the children. But look at the state of affairs here where the Adivasis are neglected and all the other poor people are neglected. The Awas Yojana has not reached those people. The sanction was given in 2022 but till now, in 2025, the poor people have not received it.

In the speech, she lauds the daughters of the country by saying that they bring us medals. That is appreciable. But let me tell you that these golden girls हमारी सरताज हैं । इस पर हमें नाज है । But the hon. MP, sitting here, molested them. He was not punished. It is so shameful that his son has come back here. So, does it show that the women are respected; that the golden girls are respected; and that the sports women are respected, by this Government? So, the speech is absolutely wrongly written. I would request that when the speech is written, then they should consider what they are writing for the Mahamahim Rashtrapati ji because it is coming out from the highest Office. People are listening to her. They should not feed her with wrong information which goes against the ethos of our Constitution. Just now, the LoP was speaking about the Constitution of India. At every step, the Constitution is not respected. We must keep in mind that our Constitution forms the backbone, and our country became Independent in 1947 and not last year in 2024.

Any person can have their own religious belief. I am a devout Hindu but I respect all religions, and we celebrate all festivities. Like my leader, Ms. Mamata Banerjee says, ?*Dharmo Jar Jar, Utsav Sobar*?. Everybody can take part. So, when they did this, they should not have spoken like that. That is disrespecting the Constitution. You should not be doing it.

The Global Hunger Index puts our country at 105th rank out of 127 countries. The index is 27.3.

About child wasting, it is the highest in the world. The children of different States are not getting enough to eat. During the 2014 elections, a lot of jobs were promised. Where are those jobs now? Sir, 46 per cent of unemployment is there in the country. Out of the total population, 28 per cent of the population is between the age of 15-29 years looking for jobs and you will be astonished Sir that more the education, more the

joblessness. A graduate is more akin to get jobless than an unskilled labour. Persons, who have passed graduation, post-graduation, Ph.D., are applying for menial labour or unskilled labour. When the advertisement is coming for such jobs, they are applying because there is no job. It is like the LOP was saying that there is no projection for production and for having more production. There is a telephone Public Sector company where 48,000 people lost their jobs. Was it done just to let one private telephone communication company thrive? Those 48000 people, who lost their jobs, were working in private sector but the Government did not take care of them.

Foreign Direct Investment has entered into insurance where people keep their hard-earned money. A person gets it at the end of the day or when he is not there, his family gets it. So, you have the FDI coming into that.

You have the FDI coming into seeds. When the Seed Bill was passed, the farmers protested. Nobody listened to them. Is this a democracy where nobody listens to the common people? And you just go on passing Bills. We also protested when the common NEET was brought. It was National Eligibility Entrance Test. We requested let it happen in regional languages throughout the country because students used to study in their mother tongue and when they are applying for it in Class XI and XII standards, let them sit and write in their own language. But the Government did not listen. They have a common test for which many poor students cannot apply for the NEET. So, this also should be undone and they should be allowed to sit and write exam in their own mother tongue.

When this initiative is giving rise to digital commerce, well, it is appreciable. But do you know how many lakhs of crores of rupees have been lost by people? Either the message comes on the Whatsapp or the message comes in email or there is a phone call saying your electric bill is due, you either pay just now by pressing zero. And as soon as you press zero, all your bank accounts get empty. Lakhs of crores of rupees have been lost by people through this cybercrime. Who are these people operating this nexus or this cybercrime? It is sometimes from outside the country also. I am to understand from very reliable sources, I do not want

to quote because we are not supposed to discuss Committee things outside. We have about 500 students of IIT, different IIT engineers, trying to find out who is operating this from where, from which part of the country and which part of the world. We know some places. I do not want to say this here but they are operating like this and they are siphoning off money from people?s bank accounts. This cybercrime is taking place at a large scale. A video call from some people comes and somebody puts on the phone to talk. That picture is taken and superimposed and then, he is black-mailed. So, these things are happening. The cybercrime is destroying the peace of the country. The sanctity of the ladies of the country is being destroyed. What is the Government doing for that? So, they were not prepared before they started this online transaction. Without learning how to swim, they jumped into the pool. And that is why, people are getting this kind of messages. So, we would request that the Government should take up cybercrime very seriously and look at it, so that the people do not lose their hard-earned money.

So, we would like also to request about the Eastern side. There are eight States. Not one word was used to talk about Manipur. For one whole year, Manipur is burning. More than that, houses have burned in Manipur. Ladies have been gangraped. Children have been born in the camps, and none of our hon. Ministers, not our Prime Minister had the time.

He has time to visit the States where there is election. But he has no time to go to Manipur where our hon. Chief Minister, Shrimati Mamata Banerjee sent a team. We went there and saw how babies are in the makeshift relief camps. There is no baby food. More than 6,000 houses have been burnt. There is an ethnic war going on and there was not a single word about how many square kilometres of India is occupied by foreigners.

I do not want to name but foreign power is occupying parts of Arunachal Pradesh and parts of Ladakh. Why should we allow my motherland be occupied by foreigners and bow down to them? Do we not have the courage to stand up and protect my motherland? Thank you, Sir.

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI (THOOTHUKKUDI): Sir, I rise to speak on the Motion of Thanks on the President's Address on behalf of my

Party, the DMK. Firstly, I would like to express my grief and empathy to the families of the people who died in the stampede at Kumbh Mela. These people trusted the Union Government and the State Government and gathered there, hoping that they will protect them. But unfortunately, no one protected them.

When religion and politics merge, it is the innocent people who suffer and this is an example of that. Sadly ? I do not know whether we are waiting for the elections ? we do not even know the numbers of the people who died in the stampede. Is this not inhumane? You do not even want to allow a discussion in Parliament on this.

Sir, the President of India ended her speech saying, ?Our Bharat is a country of 140 crore people and we have diverse States, diverse regions and diverse languages.? I am happy that the President of India still believes in the diverseness of this great nation. India is a country with almost eight major religions, more than 100 ethnic groups, 700 tribes and 121 languages. As a nation, we have always celebrated this diversity and our unity is deeply rooted in this diversity.

But the Government today has chosen the politics of forced cultural assimilation and cultural elimination. The President started her speech mentioning the 75th anniversary of adoption of our Constitution. She expressed great pride in the achievements during Amrit Kaal.

She mentioned in her speech in this very House that we recently celebrated the 75th anniversary of the Indian Republic. But none of us in this House can forget that just two years ago, in this very same House, in the very first Session, a Muslim member of Parliament faced derogatory communal remarks by a colleague from the ruling party. It was a dark day, a day of dark, abysmal despair to our nation. They have divided the society into us and them and I must remind this august House that it will take ages to repair this divide.

If we just look around, we will find a decreasing number of Muslim Members in Parliament, a decreasing number of officials, bureaucrats from the SC, ST, OBC and minority communities. The President glorified India? s civilizational nationalism, a phrase increasingly used to justify a

monolithic culture. India is a living, breathing entity which has been enriched by centuries of interactions from across the world, creating a vibrant cultural tapestry.

When you talk about Indian history, according to you, it started 3,500 years ago with the Vedic age. But today, we know that the Iron Age in India has been traced to begin around 5,345 years ago. Our Chief Minister, M.K. Stalin, has proudly proclaimed to the world, based on scientific evidence validated by international labs like Beta Analytics in Florida, that Sivagalai, a small, steep, and sleepy village in the Tuticorin district, today holds within it the proof of iron smelting and usage. This is the oldest finding in India till today. The Union Government till today has not even commented about this finding, which is very important internationally. When you exclude this truth, you just not only exclude us, but you are excluding yourselves from the great legacy of Dravidian civilization.

The proponents of Hindutva ideology have this question, who is an Indian and who is not? V.D. Savarkar came up with the answer many years ago and said: ?A loyal Indian is one who is attached to the geography of India, who is born in India and whose religion has indigenous roots. A Hindu means a person who regards this land from the Indus to the Seas as his Father-land as well as his holy land.? But, let me remind this House of the words of Sardar Vallabhbhai Patel, a Congress leader, who you seem to have taken over and invoked frequently. In 1947, when it was suggested to him that India should be declared as a Hindu State, Sardar Patel replied: ?We must not forget that there are other minorities whose protection is our primary responsibility.? In 1950, he stated, ?Ours is a secular state.? I would like to underline, he said: ?Ours is a secular state, and we cannot fashion our politics in the way Pakistan is doing. Here, every Muslim should feel that he is an Indian citizen, and has equal rights as an Indian.? The Government celebrates Sardar Vallabhbhai Patel, but it disregards most of his fundamental principles. If the Government truly respects him, they should protect every citizen, honour every culture, and stop selective imposition of one ideology over the rest. Building a 3,000-crore Statue of Unity is not paying respect to him. Please understand his words and implement them. That will be a true tribute to any leader. But,

this Government ensures in every possible way that the minorities of this country do not feel comfortable. They are kept on the edge and feel like outsiders. The CAA, Triple Talaq, the Waqf Board Bill, the Uniform Civil Code, mob lynching, and state excesses are the unending examples of how you push the minorities and make them feel threatened. In August 2019, this Government revoked the autonomy of Kashmir, the only Muslim majority State in India, and made it a Union Territory. Around the same time, you passed a new amendment to the anti-terror law. This amendment ensured and gave you the right to classify individuals as terrorists, and promoters of terrorism. Under this law, hundreds of Kashmiri politicians, activists were jailed, civil liberties were suspended, and protests were banned.

A few months later CAA came. This provided a fast track to citizenship for many minority communities. The law specified that communities which could use this law were Buddhists, Christians, Hindus, Jains, Parsis and Sikhs.

These communities made it to the list. But the Muslims were omitted despite their presence in the countries where they are minorities and have been persecuted and even suffered violent attacks. In many of the BJP-ruled States, you have coined a term, ?Love Jihad?, where adult men and women are not allowed to get married to each other because they belong to different religious groups. And, your reasoning is that Hindus will become a minority in this country. India has 14 per cent Muslim population and almost 80 per cent Hindu population. Creating false narratives like this is your way of politics, but at least let people, individuals, who have a right to make a personal choice in their private lives, live a life.

We have seen, in most of the BJP-ruled States, mobs assaulting minorities while the police stand idle. I cannot even say that mobs assault them because in some States, the authorities themselves bulldoze Muslim homes and businesses. Lynchings cannot become widespread without the atmosphere of impunity which you are ready to give. The attacks on civil society groups are surging. Any voice of dissent is called anti-national.

In November 2021, the National Security Advisor, Shri Ajit Doval told the graduating class of the National Police Academy in Hyderabad that the

new frontier of war is the civil society. The National Security Advisor tells the National Police Academy in Hyderabad that the new frontier of war is the civil society. ? (*Interruptions*) Since 2015, close to 17,000 civil society organizations have been denied registration or renewal.

Next, the Christian NGOs are disproportionately losing their FCRA licenses. Out of the 2,257 NGOs which have lost their FCRA licenses, about 1,626 are affiliated with Christian social programmes. This is a targeted financial stranglehold on organizations that serve the India's most vulnerable population. The Christian community, which constitutes around 11.54 per cent of the total religious minority population, operates 72 per cent of all religious minority schools in India and over 5,000 hospitals in rural places. But still, you do not want them to help the marginalized and the underprivileged. ? (*Interruptions*) Attacks on Christian organizations and churches have escalated over the years, with Uttar Pradesh emerging as the hotspot. This Government campaigns under the banner, ?Sabka Saath?, but seems to be unable or unwilling to safeguard its minorities and the marginalized Indians.

The hon. President, in her Address, mentioned the spirit of ?Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayaas?. I got a copy of the English translation of the President's Speech. When I got the copy, I was very confident that I would be able to read through it without anybody's help or support. But I was mistaken. Even to get through one page, I needed the help of translators because this speech has been studded and sprayed liberally with Hindi and Sanskrit phrases, which happen to be the names of the schemes or the policies of the Ruling Government, which is in slogans.

So, how can you talk about ?we together? if even translations do not include us, and they are excluding us?

The President and the hon. Member who initiated the Motion of Thanks on the President?s Address from BJP also spoke about the Kashi-Tamil *Sangamam* and the Saurashtra-Tamil *Sangamam*. You remember all these only during elections. Okay, let us leave that alone. For you, Tamil seems to start in Kashi and end in Gujarat. But I would like to tell you that it is a living language.

You quoted ?Thirukkural? also. I think that only mention of Tamil Nadu or anything Tamil in the Budget was Thirukkural, nothing apart from that. Between 2014 and 2022, the Union Government has allocated Rs.74 crore for the Central Institute of Classical Tamil in Tamil Nadu whereas the allocation to the Central Sanskrit University has been Rs.1487.81 crore. We do not have staff in the Central Institute of Classical Tamil. We do not have Epigraphists to decipher Tamil inscriptions.

The President in her speech proudly proclaimed that manuscripts are being digitized. I would like to bring it to the notice of this House that the Tamil manuscripts in Tamil University, Thanjavur are being digitized with the help of the British Library in London instead of the support of the Union Government.

The Legislature, the Judiciary and the Executive are the three pillars of democracy. But this Government is undermining all three. The key democratic institutions may have formally remained in place, but the norms and practices which hold democracy have deteriorated. The V-DEM Report on democracy says that India has been downgraded to the State of electoral autocracy.

In the past 11 years, we have seen that several Bills have been brought without proper consultation with the stakeholders and they undermine the rights of the State Governments. In 1994, the Supreme Court ruling in the SR Bommai case underscored that the States were not mere extensions of the Union, rather they possess supremacy within their Constitutionally defined domain. I would like to remind the Union Government about this case and you seem to have forgotten that the States have their rights, which have been promised and secured under the Constitution of this country.

I would like to just go through a list of the Bills which were passed in this House. The Electricity (Amendment) Act, 2022 sought to allow multiple private distributors in the State-controlled power sector reducing State Governments' control over the electricity distribution. Then, the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act enabled the Union Government to auction tungsten in Arittapatti in Madurai without the consent of the Tamil Nadu Government. The Chief Minister had to bring a

Resolution in the Assembly against this, and it is only after the continuous protests of the people of Arittapatti that you did withdraw this.

The Dam Safety Act, 2021 further gave the Union Government the power over dams across States. The Forest (Conservation) Amendment Act diluted State control over forests, allowing infrastructure development in forests without State approval affecting tribal and environmental rights. Similarly, the three criminal laws, which are called the Bharatiya Nyaya Sanhita, when I asked a very senior lawyer to explain me what this Bill was about, the first thing he told me was, ?first let me get the translation, and then I will be able to explain it to you.?

The National Education Policy, which you are very, very proud of, imposes a uniform education policy disregarding the distinctive linguistic and educational priorities of the States like Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh, Kerala, and Telangana. I do not have to talk about the farm laws. The Union Government seems to have forgotten that education is under the Concurrent List and it is not in the Union List. The UGC Draft Regulations, 2025, ultimately want to centralize control over university leadership, particularly through appointment of Vice Chancellors, undermining the federalism of overriding State laws and imposing Central criteria on State University. This limits the autonomy of universities and hinders the ability to function according to regional needs. ?One nation, one election? is being brought so that during an election the issues which are important to State Governments are wiped away, are lost and the national parties can set the agenda for the election and the States do not matter.

Sir, we insist on caste census, but we have to oppose delimitation based on the Census. States which have done well, which have controlled population, which have advanced education, health, and employment, are the ones which are going to suffer. Just because we have reduced the population and just because we have been responsible States, it does not mean we have to suffer. Then once again the balance of power will become lopsided.This Government has failed its citizens even in providing basic amenities such as food, employment, education, and shelter. You keep talking about Amrit Kaal. I do not think we have even arrived at ?

acche din?, which you started with. So where is the possibility of talking about the Amrit Kaal? You are talking about protecting farmers. Do you know that 1,00,474 farmers have committed suicide between 2014 and 2022? It is because the insurance companies which collected around Rs. 57,620 crore have only given back Rs. 3,878 crore to the farmers. You have not protected the farmers. Regarding the MGNREGS workers, this Government has taken away work from rural India. This Bill was brought to ensure 100 days of employment for people who had no other means of income. But you have cut down 84.7 lakh workers from the list and this is from your own register.

The Government in its budget has reduced food subsidy by Rs. 8,000 crore. Is this Amrit Kaal? I think the LoP has spoken about youth and employment. But when you were in your campaign mode, you were talking about two crore jobs. But in the speech of the President, it has come to 10 lakh per year.

HON. CHAIRPERSON: Kindly conclude. You have already taken more than 25 minutes. Your Party?s time is only 29 minutes.

? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: She has already taken more than 25 minutes of time.

? (*Interruptions*)

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI: Sir, there was a mention about education. In an Unstarred Question, the Government has replied that 13,500 students from SC, ST, OBC communities have dropped out of Central Universities because of discrimination faced by them. ? (*Interruptions*)

It is just not the students. Professor Gopal Das from Bangalore had to write to the President of this country for justice, and in the investigation it has been confirmed that there was workplace discrimination involving the Dean and the Director. The stories of Rohit Vemulas still continue. His words ?My birth is my fatal accident? still hurts our minds.

HON. CHAIRPERSON: Kanimozhi ji, kindly conclude now.

? (*Interruptions*)

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI: Sir, I am concluding. ? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Kindly conclude now. You have already taken more than 25 minutes.

? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: The total time allotted to your Party is 29 minutes.

? (*Interruptions*)

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI: You are holding a strangled hold over the media. I think many people have spoken about how the media is being owned by some corporates who will never go against you. And, the journalists are threatened. There have been so many arrests without any rhyme or reason, and there is no protection for journalism and the media houses in this country.

In order to threaten the Opposition you have been using Income Tax, CBI, and ED, but now you have found another new way -- the *? * ? (*Interruptions*)

SHRI A. RAJA (NILGIRIS): There is one more channel. ? (*Interruptions*)

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI: In non-BJP ruled States you use your *? * to create confusion. ? (*Interruptions*) Sir, I would just like to ? (*Interruptions*) Sir, every day he is getting a ?Zero Hour?. ? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Kanimozhi ji, you cannot discuss about the conduct of the Governor and whatever you are saying ?

? (*Interruptions*)

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI: Why can I not? ? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: No, it will not be part of the record.

? (*Interruptions*)

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI: This is the Parliament. ? (*Interruptions*) Why can it not be said? ? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Mr. Raja, I think that you are aware as to what she is mentioning.

? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: No, it will not be part of the record.

? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Kindly conclude now.

? (*Interruptions*)

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI: Sir, we have seen our *?* * walk in and walk out of our Assembly insulting the State anthem and the National anthem. ? (*Interruptions*)

SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): Sir, she is not criticising. ? (*Interruptions*)

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : सर, मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर है ।? (व्यवधान)

माननीय सभापति : हो गया, हमने कह दिया है ।

? (व्यवधान)

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI: Sir, you have been using the *?* as your representatives. ? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Kindly wait for a minute. Nishikant ji has raised a Point of Order.

? (*Interruptions*)

माननीय सभापति : निशिकान्त जी, आप क्या कहना चाहते हैं?

***m48 डॉ. निशिकान्त दुबे :** सर, वे सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं । जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वे भी सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं । सबको नियम 352(5) पता है, जो हाई अथॉरिटी पर बैठे हुए लोगों के बारे में है, चाहे प्रेसीडेंट हों, चाहे गवर्नर हों, चाहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हों । लीडर ऑफ दी अपोजिशन राहुल गाँधी भी गलत बोल गए, बोलते रहे, बोलते रहे, सब ताली थपथपाते रहे, कनिमोझी जी भी वैसा ही गवर्नर के बारे में बोल रही हैं, यदि इस तरह से पार्लियामेंट चलेगा तो इस पार्लियामेंट का क्या मतलब है?? (व्यवधान)

माननीय सभापति : वह पार्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स नहीं होगा । ऑलरेडी मैंने रूलिंग दे दी है । It will not be part of the proceeding.

? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude now.

? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: All of you please take your seats.

? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Kindly conclude now. I think that your Party has only 29 minutes and you have already taken 27 minutes. How will other Members from your Party speak on this issue?

? (*Interruptions*)

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI: Sir, that is between my Party colleagues. ? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: But there is a time constraint.

? (*Interruptions*)

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI: Sir, it is between me and my colleagues. ? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please do not pass any remarks on the Chair.

? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Kindly conclude now.

? (*Interruptions*)

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI: Sir, you are depriving the States of their rights and their fiscal autonomy. I would like to say, please learn from the Dravidian Model in Tamil Nadu which is inclusive.

I would like to finish with a quote by our Chief Minister, Muthuvel Karunanidhi Stalin who said :

?The Dravidian Model does not destroy! It creates!

The Dravidian Model does not break! It repairs!

The Dravidian Model does not divide! It unites!

The Dravidian Model does not demean! It treats everyone equally!

The Dravidian Model does not exclude anyone!

Standing shoulder to shoulder It embraces everyone!"

Learn to embrace.?

This is one country. Do not destroy it.

16.00 hrs

SHRI SRIBHARAT MATHUKUMILLI (VISAKHAPATNAM): Sir, I would like to thank the hon. President for her address. I would like to focus my speech on the celebration of 75 years of our Constitution, our democracy and the Constitutional protection that we are all enjoying.

An hon. Member spoke before me about our powerful neighbour which has a lot of development happening. But is the development worth without freedom? I have studied and grown up in India. I have seen the diversity thriving in India. If we do not protect the diversity, development is not possible. Development is possible but the allegations of the Opposition

will become even more perpetuated on power and wealth being concentrated in a very few people?s hands.

Last night, I was supposed to prepare for this speech but I got really late. For some reason, I have been wanting to watch a movie, ?V for Vendetta?, last week. I first watched this movie almost 20 years ago, and it had a profound impact on me, but I still wanted to watch it again. I do not know why I watched it. As I watched the movie, the parallel to my State of Andhra Pradesh during the last five years became so clear. On 9th September, 2023, my leader, Chandrababu Naidu Garu, was arrested. Mr. Lokesh's Yuva Galam Padayatra was abruptly stopped after 229 days. He is our leader. We were all shocked.

16.01 hrs (Shri A. Raja *in the Chair*)

After less than a week, the leader of Janasena Party, Mr. Pawan Kalyan, a senior leader in our party and popular actor, Mr. Balakrishna, and Mr. Lokesh went to meet our leader, Mr. Chandrababu Naidu, in jail. Mr. Kalyan came out and announced that we are going in this together. Today, it is not about me, it is not about the TDP, it is about the future of the State of Andhra Pradesh and the future of the people of Andhra Pradesh. That went on for 52 days with him being in jail. On 31st October, he was released. And I was fortunate to be outside as he was coming out of the jail. I was standing by my car and had a vantage point. As he was greeting the people who were there to see him after so long, we were able to lock eyes. As I could see his eyes, there were tears rolling down my cheeks. All of us went to Amravati. There were leaders of the Party, the cadre, and the family. He reached there 14 hours later at 6 a.m. Someone who was in jail for 52 days, who is over 70 years of age, was still sitting in the car, not getting up and greeting people across the way wherever people were there to see him. It gave us strength to fight. Then six months later, campaigning started, elections started, 90 public meetings were held, almost three meetings every day, and all of this was not about him, it was about the future of Andhra Pradesh. I was thinking what he was feeling. His hope was to remind the world that fairness, justice, and freedom are more than just words. They are perspectives. I will be taking quotes from

the movie. At that point, he realized that the people were feeling something that he knew all along.

HON. CHAIRPERSON: Sribharat ji, please address the Chair.

SHRI SRIBHARAT MATHUKUMILLI: It was a long dialogue in the movie that really struck me. I want to paraphrase it because it appeared very true to me. I want to paraphrase what my leader was saying to the people in his address.

If you have seen nothing, if the crimes of this Government remain unknown to you, then I would suggest you allow the 13th of May to pass unmarked. But if you see what I see, if you feel as I feel, and if you would seek as I seek, then I ask you to stand beside me six months from today outside your voting booth and together we shall give them a 13th of May that shall never ever be forgotten. That is what the people have spoken. We got a historic result of winning 164 seats in the alliance with a vote share margin that was never seen in the history of Andhra Pradesh for over 40 years. But I would like to go back, Sir. What led to this moment? What led to this epiphany? In 2019, when we lost power and a new government came into force in Andhra Pradesh, we very soon realized that fear became the tool of the government; there were demolitions across the State; there were house arrests, and assets being taken away. The recent example is the Kakinada port which was taken over in a hostile manner. Fortunately, it has been reversed today.

There was a financial and psychological warfare and as the COVID-19 started, we just saw that continuing. I would like to make a quote from Macbeth: ?I dare do all that may become a man, who dares do more is none.? What does that mean? I have a responsibility to stand up and fight, but not to protect myself but for the State. There was a psychological environment where many people wanted to compromise with the Government to ensure that their assets are protected or they are protected. The University that I lead was attacked and there was an intention to coerce, but with the support of our leader, we stood strong.

As time progressed, I could see that there were many people wearing masks. If you wear a mask for too long, you forget who you are beneath it.

Many people in society, in the services, seemingly decent people, started behaving differently. Among the people who were being oppressed, I could see hate building up. It imprisoned many people. But then what I felt was that it is not about giving back that hate. I would rather die than give up. Freedom is worth dying for. These fighters, our leaders, our well-wishers across the State kept us going. All we realized is that we need an inch, an inch is all we need of hope to fight. Aiding our leader Chandrababu Naidu, we had our young leader Mr. Lokesh who started his padyatra on January 27th and continued that over 3132 kilometres. We had Mr. Pawan Kalyan fighting against the oppression of the Government and speaking up for those who did not have a voice themselves.

Finally, as we came closer to the elections, the tide started shifting and people started realizing that every action will have an equal and opposite reaction. We had our graduate MLC elections where unanimously we won all three graduate MLC elections across different regions of the State, sending a signal to the people that time has come. But as that happened, the ones in power, the more power they felt they had, the more jealous they became and that is what led to the arrest of our leader in false cases. I had to argue with some people who were supporting the Government that if there is something, they will arrest you. As I debated with a friend of mine on what is right and what is wrong, I found myself wondering that there is no absolute right and absolute wrong as we work in this world, in this Kalyug. There are some mistakes on both sides. But more than individual right and wrong, there is something that the people will collectively decide as to what is right or wrong. That is what people have shown. In Andhra Pradesh, they have given an overwhelming mandate for a change. The Opposition here in the Central Government has made many accusations against the Government that we are part of today. My reply to them is that people have decided, in spite of all these allegations, that India is in the safe hands of the NDA with the leadership of Narendra Modiji and the alliance with Telugu Desam party, Jan Sena and all other alliance partners from all over the country.

Difficult times are what tests our democracy, but people have believed in our institutions. There is a popular saying that I get reminded of. We

may have lost in 2019. So, the saying goes like this, `you can fool some people all of the time or you can fool all of the people for some time, but you cannot fool all of the people all of the time?, and I am glad that people have showed up and have given us the much-needed relief to put the State back on track. I am thankful for all the support. We have won the elections. We are here in front of you representing the Government. And I would like to come back to the Macbeth quote, ?I dare do all that may become a man; who dares do more is none.? I see an environment where people want retribution, revenge, but I feel that it is time to fulfil our responsibilities to restore balance and justice but not to go overboard. If we behave the same way that the Government before behaved, then we are disrespecting the mandate that has been given. The State needs more than that. It needs hope for our citizens, for our youth.

I would like to conclude. I do not know how I saw this movie last night. As I was speaking on the President's Address today in the Parliament, and as I have been in this journey long enough, I realized that coincidences do not happen just by chance. There is something greater at play. My takeaway is that when the intentions are good, when the intentions are pure, the universe reciprocates and I think that it is reciprocated here also with a renewed resolve. As a team we are going to work together to build a better Andhra Pradesh, to build a better India and a better democracy for all of us to thrive in.

Thank you for this opportunity. With these words, I conclude my speech.

श्री दिलेश्वर कामैत (सुपौल) : सभापति महोदय, आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर हो रही चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी है, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ।

महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी का यह तीसरा कार्यकाल चल रहा है । देश आर्थिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है । जल्द ही भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाला है । यह माननीय प्रधान मंत्री जी का संकल्प है । इसी संकल्प को पूरा करने के लक्ष्य के प्रारूप को महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने अपने अभिभाषण में देश के सामने रखा है । देश में आर्थिक काल चल रहा है । अभी हाल ही में संविधान की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है । यह हमारे राष्ट्र के लिए गौरव की बात है । महामहिम राष्ट्रपति जी ने देश की आर्थिक उन्नति का रोडमैप के साथ सरकार के कार्यों के लेखा-जोखा को सबके सामने

प्रस्तुत किया है । आज सरकार का मूल मंत्र ?सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास? परिलक्षित होता प्रतीत होता है ।

सभापति महोदय, नीति आयोग की रिपोर्ट और सरकार के प्रयास के कारण ही वर्ष 2024 तक देश में करीब 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं । यह उल्लेखनीय प्रगति है । आयुष्मान योजना के तहत पांच करोड़ परिवारों को मेडिकल सुविधाएं और 70 वर्ष से अधिक के नागरिकों को आयुष्मान योजना के तहत मिल रही मेडिकल सुविधा देना काफी सराहनीय कार्य है ।

सभापति महोदय, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना का चौथा चरण प्रारंभ हो चुका है । इसके तहत देश के कोने-कोने से सुदूर ग्रामीण इलाकों को सड़कों के द्वारा जोड़ने का काम लगभग पूरा होता जा रहा है । इसने देश के विकास में अहम योगदान देने का काम किया है ।

विश्व स्तर पर भारत का सिर ऊंचा होता जा रहा है । माननीय प्रधान मंत्री जी विश्व के अति लोकप्रिय नेता की सूची में अग्रणी पंक्ति में आ गए हैं । यह हमारे लिए और देश की जनता के लिए अति उत्साहित करने वाला क्षण है ।

सभापति महोदय, सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना का मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ । सरकार देश के अत्यंत पिछड़े इलाकों में आकांक्षी जिला योजना कार्यक्रम चला रही है । इसमें देश के 112 जिलों को लिया गया है । मेरे बिहार राज्य में इस योजना में 13 जिलों को शामिल किया गया है । इसे बढ़ा कर बिहार के सभी 38 जिलों को शामिल करने की आवश्यकता है । सरकार द्वारा 500 ब्लॉकों को आकांक्षी योजना में शामिल किया गया है, जिनमें से बिहार के 61 ब्लॉकों को शामिल किया गया है ।

इस कार्यकाल में पिछड़े इलाकों के स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, सामाजिक विकास और शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न मापदंडों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है ।

माननीय सभापति जी, महामहिम जी के अभिभाषण में ऐसे राष्ट्र के निर्माण की परिकल्पना की गई है, जो अतीत के गौरव से जुड़ा है । इसमें आधुनिकतावाद का हर स्वर्णिम अध्याय है, जो आत्मनिर्भर है और अपने मानवीय दायित्वों को पूरा करने में समर्थ है । हमारा मध्यम वर्ग भी वैभव से युक्त है ।

माननीय सभापति जी, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी के जो दूरदर्शी एवं प्रगतिशील आर्थिक नीतियां और योजनाएं हैं, वह समाज के अंतिम व्यक्ति के साथ सभी वर्गों को समानांतर एवं सार्थक लाभान्वित करती हैं । इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से हार्दिक अभिनंदन एवं आभार करता हूं ।

सभापति महोदय, मैं अपनी बातों को समाप्त करते हुए बताना चाहता हूं कि सरकार 25 करोड़ गरीब लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने में सफलता हासिल की है । इसके लिए मैं बधाई देता हूं । विकसित भारत के निर्माण के लिए देश के गरीब, युवा, नारी शक्ति और किसान कैसे सशक्त होंगे, सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है । इन्हीं

कामनाओं के साथ मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । धन्यवाद ।

श्री अरविंद गणपत सावंत (मुम्बई दक्षिण) : माननीय चेयरमैन सर, आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के अभिनंदन प्रस्ताव पर मैं अपने विचार प्रकट करने के लिए खड़ा हूं । मुझे खेद होता है कि किस तरह से आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति जी ने जो भाषण यहां रखा, मुझे नहीं लगा कि यह उनके मन की बात है । हम भी जानते हैं कि महामहिम राष्ट्रपति हों या राज्यपाल जी हों, वे जब भी भाषण करते हैं, तो उनके पास सरकार की तरफ से लिखित भाषण जाता है और वही उनको पढ़ना पड़ता है । हमें अपेक्षा थी कि महामहिम राष्ट्रपति जी कुछ अपने भी ख्याल या विचार उसमें प्रकट करेंगी, लेकिन वह नहीं हुआ । उन्होंने शुरू में ही प्रयागराज और डॉ. मनमोहन सिंह जी के बारे में संवेदना जतायी । मैं भी उसका अनुमोदन करता हूं । मैं भी बहुत गहरी संवेदना जताता हूं । खासकर प्रयागराज में जो हुआ, वह बहुत ही वेदना देने वाली दुर्घटना हुई है ।

अगर मैं मनमोहन सिंह जी के बारे में बात करूं तो इस सरकार को याद दिलाना चाहता हूं कि वर्तमान प्रधानमंत्री जी जब गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री थे, तब जीएसटी का सबसे कड़वा विरोध करने वाला कौन था तो भारतीय जनता पार्टी थी । आधार कार्ड का कड़वा विरोध करने वाला कौन था तो भारतीय जनता पार्टी थी । डॉ. मनमोहन सिंह जी ने जो सारे विचार रखे थे, उसका ही आज अवलंबन करना पड़ रहा है । इसी से हम समझ जाएं कि दूरदर्शी विजन किसे कहते हैं । हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मनमोहन सिंह जी बहुत ही विजनरी थे ।

उस वक्त पूरे विश्व में जिस तरह की व्यवस्था थी, वैसी स्थिति में भी उन्होंने भारत को संवारा था । इसकी जितनी भी सराहना की जाए, वह कम ही होगी । ये लोग भूल जाते हैं कि इन्होंने पहले क्या कहा था और आज क्या कह रहे हैं ।

सर, इन्होंने हाउसिंग फॉर ऑल के बारे में बोला है । मुझे समझ में नहीं आता है और मैं पिछले दस वर्षों से बात करते आ रहा हूं । जब भी यह विषय आता है, you know, I know and everyone knows that there is encroachment on the Government land. अब सरकार ने हमारे मुम्बई में वहां के बंदरगाह की जगह मुम्बई पोर्ट किया । वहां बहुत बड़ी झुग्गी-झोपड़ियाँ हैं । वैसी ही रेलवे की जगहों पर भी झुग्गी-झोपड़ियाँ हैं । हमारे आदरणीय शिव सेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी ने एक सपना देखा था कि हमारा कोई भी गरीब आदमी झुग्गी-झोपड़ी में नहीं रहेगा । उनको अपने हक का घर मिलेगा, इसलिए उन्होंने एसआरएस स्कीम लाई थी । उस समय स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी बनी । उसके तहत गरीबों को मुफ्त में घर दिया जाता था । वहां जो गरीब लोग बसे हुए हैं, हर बार उनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, हाउसिंग फॉर ऑल, पक्का घर, नल से पानी की बात की जाती है, लेकिन ये सब कहां है और यह कब होगा?

मेरी महामहिम राष्ट्रपति से प्रार्थना है । मैं खेद प्रगट करता हूं । आपको यह पता नहीं है कि आज भी लोग ऐसे रहते हैं । आपने किसको पक्का घर दिया? हम शहरों में रहते हैं । आप किसको पक्का घर दे रहे हैं? ये झुग्गी-झोपड़ी वाले ऐसे ही हैं । राज्य की सरकार कोई एक स्कीम बनाती है, अगर उस स्कीम से कुछ लोगों को जो केंद्र की सरकार की जमीन पर रहते हैं, उनको लाभ मिलता है तो उन्हें केंद्र सरकार लाभ नहीं देती है । वह कहती है कि यह राज्य की योजना है, हमारे केंद्र की यहां नहीं चलेगी । हमारे यहां बीडीडी चॉल है । उसका पुनर्विकास होने का जो प्रकल्प है, उसे हमारी राज्य सरकार ने लाया । शिवड़ी की बीडीडी चॉल के जो लोग हैं, उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि केंद्र सरकार की जमीन पर वह बिल्डिंग खड़ी है । इसकी अनुमति कौन देगा? सोनोवाल साहब सामने बैठे हुए हैं । यह इनकी जगह पर है । मुंबई के बंदरगाह की जगह पर है । आपको तो कुछ करना नहीं है, विन-विन सिचुएशन है । राज्य की सरकार उसे कर रही है, कोई निजी संस्था या व्यापारी नहीं कर रहा है, लेकिन आप दस वर्षों से अनुमति नहीं दे रहे हैं । हाउसिंग फॉर ऑल की चर्चा होती है । बिल्डिंग ढहने को आई, आप परमीशन नहीं देते हैं । आप लिखते हैं कि हाउसिंग फॉर ऑल । आप कहां से देंगे? यह बताइए । हम जो बोल रहे हैं, सच्चाई बोल रहे हैं । मुझे इसलिए खेद प्रगट करना पड़ता है कि महामहिम राष्ट्रपति जी को इसकी जानकारी आज भी नहीं है और आप जानकारी देना भी नहीं चाहते हैं । वह ... * आपका दिया हुआ पढ़ती हैं । मैं आगे चलकर और भी बताता हूं । ? (व्यवधान) मैंने हाल ही में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का हर निर्णय ?(व्यवधान) आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? ?(व्यवधान)

डॉ. निशिकान्त दुबे : ये राष्ट्रपति जी को ... * कह रहे हैं । इस शब्द को निकालना चाहिए । ?(व्यवधान)

SHRI ARVIND GANPAT SAWANT: Sir, I am addressing you only. किसान सम्मान योजना में आप छः हजार रुपये दे रहे हैं । ? (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: I will check the record.

? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, I will check the record. If there is anything objectionable, I will remove it.

? (*Interruptions*)

SHRI ARVIND GANPAT SAWANT: What is that? ? (*Interruptions*) Forget about the sentence, you just tell me the word. ? (*Interruptions*) I am saying that it is perfectly correct. ? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Nishikant ji, I will check the record. If there is anything objectionable, it will be removed from the record.

? (*Interruptions*)

SHRI ARVIND GANPAT SAWANT: No, Sir, I have not yielded at all. मैंने एक भी शब्द ऐसा नहीं बोला, वाक्य तो छोड़ो, शब्द भी गलत नहीं बोला है ।? (व्यवधान) अनुमति आप नहीं देते हैं । ? (व्यवधान) पक्के घर का वादा करते हो, इतना झूठा वादा करते हो ।? (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please address the Chair.

श्री अरविंद गणपत सावंत : किसान सम्मान योजना, हर कदम जो भारतीय जनता पार्टी उठाती है, वह राजनीतिक होता है, सामाजिक नहीं होता है । 12 लाख रुपये की घोषणा हुई, कोड ऑफ कंडक्ट है, यह घोषणा किसके लिए हुई? किसानों को छ: हजार रुपये और यहां 12 लाख रुपये तक इनकम टैक्स फ्री करने वाले हैं । किसानों की राशि बढ़ाइए, वह ज्यादा अच्छा होता ।

फोकस ऑन एजुकेशन, काहे का फोकस, आप क्या करते हैं? आज भी इस देश में, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, यहां बैठी हमारी बहन भी जानती हैं कि ऐसे गांव हैं जहां एक ही शिक्षक है । Quality and equality both should be maintained. आज भी एजुकेशन सिस्टम में, there is a disparity and discrimination. Both are existing. Disparity is by virtue of the education institute where it is situated. स्कूल कहां पर है, गांव में है । कोविड के समय में डिजिटल एजुकेशन चल रही थी । नेटवर्क ही नहीं मिलता था, तो गांव में वे क्या पढ़ाएंगे? एक ही टीचर है । एक ही क्लास में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ के बच्चे बैठे हैं । आज भी यह अवस्था है । आपका डॉयलॉग बड़ा अच्छा होता है । आपकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है । कथनी सुनने में बहुत अच्छी लगती है । कोई सुनेगा तो बोलेगा कि कितनी संवेदनशील सरकार है, यह बच्चों के लिए सोच रही है । आप इक्विलिटी करते हैं, सीबीएसई, आईसीएसई, इंटरनेशनल बोर्ड । हाल ही में हमारे यहां एक छोटी सी क्लिप घूम रही है । उन बच्चों से पूछा कि क्या छत्रपति शिवाजी महाराज को जानते हो? आईसीएसई के बच्चे को मालूम नहीं है । आपको पढ़ाया है, तो बोलता है कि हमारे बुक्स में नहीं है, किताबों में नहीं है । एक लड़का कहता है कि सिर्फ एक पैराग्राफ छत्रपति शिवाजी महाराज का है । यह हमारी नई जेनरेशन है, जिनको इतिहास नहीं मालूम । छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं मालूम, राणा प्रताप सिंह मालूम नहीं है, गुरू गोविंद सिंह जी मालूम नहीं है । ये आगे चलकर अपने देश को, मिट्टी को प्यार करने वाले हैं । उसको पूछा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता जी का नाम बताओ, तो उसको नहीं मालूम । This is the system. That is what is happening in education. यह जरा सोचो तो सही । हम इसे दर्द से बोल रहे हैं । मैं महामहिम राष्ट्रपति जी से कहता हूं कि जरा इस पर भी ध्यान दें तो बहुत अच्छा होगा ।

आपने 50 परसेंट पेंशन के बारे में बात की, अभी भी पुराने लोग पेंशन के लिए तड़प रहे हैं, डेढ़ हजार या बारह सौ रुपये पेंशन के रूप में मिल रही है, हम कितने सालों से

यहां बोल रहे हैं, उनकी पेंशन नहीं बढ़ रही है, आप किसको पेंशन दे रहे हैं, अभी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं? नौकरी में भर्ती कितने सालों से बंद है । आपकी कथनी और करनी में फर्क रहता है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेकर आए, आपने महिलाओं के सम्मान की बात की । ओलंपिक प्राइज वाली हमारी बहनें धरने पर बैठी थीं, आपकी तरफ से एक भी आदमी उसको देखने नहीं गया, आपकी तरफ से कोई महिला भी नहीं गयी, वहां से भगा दी गई । आपकी कथनी और करनी में फर्क है । आत्मनिर्भर भारत ने बीएसएनएल का सत्यानाश किया, आपको पता है, फाइव-जी सर्विसेज कौन देने वाला है, बीएसएनएल दे रही है, एमटीएनल दे रही है, गांव में फोर-जी सर्विस शुरू किया है, धंधा मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, मद्रास में नहीं करेंगे, गांव में करेंगे नहीं तो दोस्तों का नुकसान होगा? दोस्तों को तकलीफ होगी, अपने बच्चे को देखो, बीएसएनएल आपका बच्चा है, आज भी नहीं देख रहे हो ।

चांद पर हमारा यान गया, उसका जितना खर्च हुआ है, उससे ज्यादा खर्च मुंबई-गोवा रोड जो पनवेल से मानगांव तक है, उसमें हुआ, अभी तक रास्ता नहीं बना । इन्फ्रास्ट्रक्चर के चक्कर में प्रकृति का कितना नाश करते हो, मैट्रो रेल के लिए गोरेगांव का फॉरेस्ट बर्बाद कर दिया । क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, संवेदना वहां जताते हो, हजारों पेड़ काटते हो, तब याद नहीं आता है । विकास की बात करते हैं, विकास की परिभाषा क्या होनी चाहिए । How do you define *?vikas?*? प्रकृति का सत्यानाश करके विकास की बात करोगे । यही दुर्भाग्य है, मुंबई-गोवा रास्ता आज भी नहीं बना है । एयरपोर्ट का एक्सपैन्शन चल रहा है, चिपी एयरपोर्ट बंद है, पालघर जिले में वधावन पोर्ट के विरोध में वहां के लोगों ने आंदोलन किया, फिर भी आप पोर्ट बना रहे हो, deep in the sea, they are going to create a port. देश के इतिहास में मुंबई बंदरगाह का नाम आता है, आपने कभी सोचा कि मुंबई बंदरगाह के बारे में सोचा जाए । आदरणीय गडकरी साहब ने एक प्लॉन बनाया था, प्लॉन बनाकर सभी को बताया था, फाइल पड़ी है, कभी उस फाइल की तरफ देखो, क्यों मुंबई पर अपना रोष निकाल रहे हो, मुंबई ने क्या गुनाह किया है, क्या मुद्रा पोर्ट के लिए मुंबई बंदरगाह का विकास रोका है? मुंबई बंदरगाह का विकास क्यों नहीं करते हो । माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी को मुंबई का बंदरगाह मालूम नहीं है, लेकिन वधावन याद आया । मुंबई बंदरगाह का विकास याद नहीं आया, यही तो दुख है, खेद प्रकट करता हूं । सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास में मुंबई नहीं आता, सबका विकास में महाराष्ट्र नहीं आता, महाराष्ट्र से सारी कंपनियां लेकर गुजरात जाते हो, विकास की बात याद नहीं आती । छीन कर क्यों लेकर जाते हो, आप दस कारखाने गुजरात में खड़ा करो, , एक राज्य आगे बढ़ेगा तो मुझे बुरा नहीं लगेगा लेकिन महाराष्ट्र से छीन कर क्यों लेकर जाते हो, विश्व में सभी को पता है कि मुंबई कमर्शियल सेंटर है, इंटरनेशनल फाइनेन्शियल सर्विस सेंटर का ऑफिस मुंबई में बनने

वाला था, गिफ्ट सिटी गुजरात को दे दिया, सारे कारखाने वहां लेकर गए । यह समान विकास है, सबका साथ है, सबका विकास है, क्यों कर रहे हो?

अर्फोडेबल हेल्थ केयर, मुंबई में महानगर पालिका का बढ़िया हॉस्पिटल है, जेएस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए बच्चे तड़पते हैं । आज ऐसी हालत है कि दवा नहीं दे सकते, दवा बंद है, दवा नहीं मिल रही है, जेजे हॉस्पिटल में दवा नहीं मिल रही है, एमआरआई बंद है, सीटी स्कैन बंद है ।

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

? (*Interruptions*)

SHRI ARVIND GANPAT SAWANT: Within two minutes, I will be concluding.

HON. CHAIRPERSON: You already exceeded your time.

? (*Interruptions*)

SHRI ARVIND GANPAT SAWANT: I do understand it. I will take care of it.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude within a minute.

Arvind Sawant ji, please conclude. `

श्री अरविंद गणपत सावंत : सर, मन में बहुत सारे विषय रहते हैं । यह मुम्बई शहर की हालत है । मुम्बई शहर में महात्मा गांधी हॉस्पिटल है । वह किसी ट्रस्ट का है । किसी जमाने में वह हमारा इंडस्ट्रियल एरिया था । वह कारखानों के कामगारों के लिए बनाया गया था । अभी वह वर्करों के लिए बनाया गया है । वह अस्पताल नहीं चलता है । वहां टाटा हॉस्पिटल में बहुत भीड़ रहती है । हम बार-बार प्रार्थना करते हैं कि महात्मा गांधी हॉस्पिटल है, आप उस बिल्डिंग को ले लीजिए । उसको टाटा हॉस्पिटल को दे दीजिए । उसको आप ले लीजिए । हमें नहीं चाहिए । उसको टाटा हॉस्पिटल को दे दीजिए । देश भर के लोग टाटा कैंसर हॉस्पिटल में आते हैं । वहां जगह नहीं है । वहां जगह की कमी है । आप भी कभी वक्त निकालकर सुबह टाटा हॉस्पिटल में जाइए । जैसे स्टेशन पर भीड़ रहती है, वैसे ही वहां भीड़ रहती है । वहां चलने के लिए रास्ता नहीं रहता है । महात्मा गांधी हॉस्पिटल खाली पड़ा है । वह किसी ट्रस्ट का था, लेकिन अब सरकार का है । आप उसको लीजिए । वह लोगों के लिए उपलब्ध होगा । उससे कैंसर और हेल्थकेयर के लिए प्रोविजन होगा । आपके पास हेल्थकेयर के लिए क्या प्रोविजन है? जब मुम्बई शहर में मशीन नहीं है तो गाँव में क्या होगा । कथनी और करनी में फर्क है ।

सर, आगे मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा ।

HON. CHAIRPERSON: Arvind Sawant ji, please conclude now.

SHRI ARVIND GANPAT SAWANT: Sir, I am concluding in one sentence. सुबह हमारे माननीय विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने याद दिलाया था । मैं वापस इलेक्शन कमीशन पर आ रहा हूं । उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने वाली बात कही थी ।

मैं आगे दूसरी बात बताता हूं । हाल ही में आपने एक नियम बदल डाला । जो पराजित हुए थे, उन्होंने कहा था कि हमें काउंटिंग को देखना है । We want to see that data. उन्होंने क्या किया? इलेक्शन कमीशन ने नियम बदल डाला । नियम में मॉक पोल करने की बात की । हमने पूछा कि इतनी भीड़ शाम के पाँच बजे के बाद हुई है । आप मुझे सीसीटीवी दे दीजिए । वे हमें सीसीटीवी नहीं दे रहे हैं । यह आपका संविधान के प्रति आदर है । इसलिए, मैं खेद प्रकट करता हूं । महामहिम राष्ट्रपति जी ने जो अपना अभिभाषण प्रकट किया है, उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं । मैं सोचता हूं कि जो कुछ बोला गया था, उसके ऊपर अभी भी ध्यान नहीं है । मुम्बई बंदरगाह विकास बोर्ड आपके ?फेदर इन द कैप? में रहेगी । आप उस पर काम करेंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं । धन्यवाद ।

***m54 डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे (शिरुर) :** धन्यवाद सभापति महोदय । महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने के लिए मैं अपनी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार पार्टी की तरफ से खड़ा हूं । मैं सबसे पहले भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी के प्रति अपनी पार्टी की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा ।

सभापति महोदय, चूंकि हमारी पार्टी से दो मेम्बर बोलने वाले हैं, इसलिए मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात कहूंगा । महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में प्रयागराज में चल रही महाकुंभ की बात की । वैसे ही मिडिल क्लास की भी बहुत बात की । इस मिडिल क्लास के नजरिये से महाकुंभ क्या है? इस पर हमने कुछ पंक्तियां लिखी है । मैं वही पंक्तियां सुनाना चाहूंगा-

> ?आजकल खुद के हिन्दू होने पर, मैं कुछ ज्यादा ही गौरवान्वित महसूस कर रहा था । हालांकि, मेरे हिन्दू होने में, मेरा खुद का योगदान कुछ भी नहीं था । लेकिन, सनातन की समृद्ध परम्पराओं में मेरा अटूट विश्वास है । वैसे भी देशप्रेमी कहलवाने के लिए हिन्दुत्व का प्रदर्शन हो, यह आज का राजनीतिक माहौल है । महाकुंभ में सनातन के विराट वैश्विक अनुभव के साथ पाप धोने का अनोखा अवसर था, इसीलिए लाखों श्रद्धालुओं की तरह, मैं भी उस दिन प्रयागराज महाकुंभ में था । दिल्ली से आती यमुना में चुनावी जुमलों का प्रभाव था, बिहार जाने वाली धारा में बजट का कुछ ज्यादा ही बहाव था । लेकिन, लुप्त रही सरस्वती मइया, क्योंकि शायद आज की राजनीति में सद्-सद् विवेक का थोड़ा सा अभाव था । धन्य हो गंगा मइया, जिसने सारे पापों के साथ सभी को अपनाया । महंगाई बेरोजगारी और तमाम विफलताओं को किसी ने आस्था की चादर के आड़ छुपा दिया । उसी आस्था के साथ डुबकी लेने वाला मैं यह देखकर हैरान रह गया । मुझसे भी गहरे पानी में कोई लगतार गोते खा रहा था । अनजाना नहीं था, जाना-पहचाना था वह, वह मेरे देश का रुपया था ।

नजरअंदाज करते हुए मैंने खुद को समझाया, चिंता की कोई बात नहीं है,
अर्थव्यवस्था तो 5वें पायदान पर है, तभी कानों में फुसफुसाई गंगा मैया,
पर कैपिटा जीडीपी में बालक हम 141वें स्थान पर हैं ।
लेकिन यह सब सोचने की मुझे क्या जरूरत है,
मैं तो एक साधारण-सा मिडिल क्लॉस हूं,
जो बजट में टैक्स रिबेट देखकर खुश होता हूं,
लेकिन रोजमर्रा की चीजों पर 5 से 18 प्रतिशत जीएसटी भरता हूं ।
चप्पल, कपड़े, खाना, साबुन, खाद, यहां तक कि कफन, शर्म आनी चाहिए,
कोई भी चीज नहीं छूटी है, दर्द तो होता है,
लेकिन जख्म नहीं दिखता, इनडॉयरेक्ट टैक्स, जीएसटी की यही तो खूबी है ।
वैसे हेल्थ और एजुकेशन सेस भी मुझसे ही वसूला जाता है,
लेकिन पढ़ाई के लिए प्राइवेट स्कूल और इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है,
खुद की गाड़ी पर जीएसटी और रोड टैक्स भी भरता हूं,
लेकिन गड्ढे, टोल और पेट्रोल सेस से कहां राहत पाता हूं ।
महंगाई तो बढ़ती है लगातार, तुलना में सैलरी नहीं बढ़ती है,
लेकिन कहां शिकायत कर पाता हूं,
लोकल ट्रेनों में लटकता हूं, ट्रैफिक जाम में फंसता हूं,
मानो प्रीमियम और ईएमआई चुकाने के लिए मैं जीता हूं ।
ईएमआई से याद आया कि पिछली बार चुका नहीं पाया, तो बैंक मेरे दरवाजे पर आया था,
उसी बैंक से करोड़ों की ऋण माफी लेने वाला पूंजीपति कुछ दिन पहले ही शाही स्नान कर चुका था । गुस्सा तो आता है, पर कर भी क्या सकता हूं,
ज्यादा से ज्यादा ताव में सोशल मीडिया पर लिख देता हूं ।
क्योंकि मैं हूं ही कौन, मेरा वजूद क्या है, मैं एक साधारण-सा मिडिल क्लॉस हूं,
लेकिन विचारों की इस श्रृंखला को तोड़ अगली डुबकी लेने ही वाला था,
तभी कानों पर शोर आया कि पुण्य की आस में आया हर कोई, जिंदगी की सांस के लिए भागता नजर आया ।
भगदड़ में हाथ से हाथ छूट गए, अपनों से अपने बिछड़ गए,
सपने सारे बिखर गए, इंसानों तले इंसान कुचल गए ।
जहां सजा था आस्था का उत्सव, वहीं अब मौत का तांडव उफान पर था,
लेकिन प्रशासन लाशों से ज्यादा अपनी नाकामी और विफलता को ढकने में तत्पर था ।

कितने खोए, कितने मरे, कितने लापता हुए, लोगों के साथ सरकारी आंकड़ा भी गायब था,
शासन, प्रशासन, मीडिया, हर कोई चुप्पी साधे शायद किसी के लिए मानवता से ज्यादा यह इवेंट होना जरूरी थी ।
मानो महाकुंभ की आस्था की आड़ में, सत्ता की लालसा मचल रही थी,
गंगा किनारे इंसानों के बाद, अब इंसानियत कुचल रही थी ।
थर्रायी गंगा मैया फिर संभलकर बोली, किनारे पर लाशों के अंबार नए नहीं हैं मेरे लिए,
पाप तो धो दूंगी तुम्हारे, लेकिन यह वचन देना होगा कि इस सत्ता की लालसा में एक दिन लोकतंत्र भी लाश न बन जाए, ध्यान रखना होगा तुम्हे, भारत के भविष्य के लिए ।
भावभीनी नजरों से मैंने आखिरी डुबकी लगाई,
पापों का तो पता नहीं, अंधभक्ति की पट्टी जरूर खुल गई,
धन्य हो गंगा मैया, जिसने भावनाओं से बढ़कर जिम्मेदारी की जोत जलाई,
एक मिडिल क्लॉस को उसके भारतीय होने के कर्तव्य की याद दिलाई ।

धन्यवाद, जय हिन्द ।

श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे (मावल) : माननीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी और प्रयागराज कुंभ में दिवंगत श्रद्धालुओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं ।

महोदय, महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण का मैं अपनी पार्टी शिवसेना की ओर से समर्थन करता हूं । यह अभिभाषण हमारे देश के लिए एक दिशा दिखाने वाला दस्तावेज है । माननीय राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार के कामकाज का एक आईना है । माननीय पंतप्रधान मोदी जी के नेतृत्व में सरकार द्वारा बीते दस साल से ज्यादा समय में देश की हुई प्रगति का पूरा रूप माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण में रखा गया है । मैंने विपक्ष के माननीय नेता राहुल गांधी जी का भी भाषण सुना है । उन्होंने जो भी आरोप लगाए हैं या जो बातें रखी हैं, मैं सदन के माध्यम से उनसे कहना चाहता हूं कि अगर उनके पास कुछ भी दस्तावेज हों तो सदन के पटल पर रखने चाहिए । सदन के विपक्ष के नेता के रूप में अपनी बात कहते हुए उन्होंने जो-जो बातें कहीं हैं, कुछ देश के सीमावर्ती भागों की बात कही है और कुछ देशों का उल्लेख यहां पर किया और उनका नाम लिया है, लेकिन मैं उन देशों का नाम नहीं लेना चाहता हूं । एक जिम्मेदार विपक्षी नेता होने के नाते उन्होंने जो-जो आरोप लगाए हैं, उनका तथ्य सदन के पटल पर रखना आवश्यक है । विपक्षी नेता अपनी बात कहकर मीडिया में आते हैं, जिससे देश की प्रतिमा मलिन होने की संभावना है ।

माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण में सबसे पहले ?प्रधानमंत्री आवास योजना? की सफलता का उल्लेख हुआ है । ?प्रधानमंत्री आवास योजना? गरीबों के लिए एक क्रांतिकारी कदम है, जिससे लाखों गरीब लोगों को पक्के घर मिल सकते हैं । बेहतर निगरानी में वित्तीय समर्थन के साथ इस वर्ष करीब तीन लाख घर गरीब लोगों को देने की बात अभिभाषण में रखी गयी है । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज भी देश में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं, जिनके पास सरकारी दस्तावेज नहीं है, जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, जिनके पास वोटर कार्ड नहीं है । जो बड़े शहरों में रास्ते के किनारे रहते हैं, उनको दस्तावेज देकर उनके सपनो के घर का प्रश्न हल करने की बात रखता हूं । पंतप्रधान योजना में जो लाभार्थी है, उस लाभार्थी को कुछ रकम भरनी पड़ती है, लेकिन जो गरीब है, वह उस रकम को भर नहीं सकता है और बैंक भी सहायता नहीं करते हैं तो बैंकों को भी सूचित करना चाहिए कि गरीब लोगों को आवास दिलाने में सहायता करने की आवश्यकता है ।

हमारे देश में कृषि एक मुख्य साधन है । इस कारण कृषि के क्षेत्र में सरकार उल्लेखनीय कार्य कर रही है । हमारी सरकार किसानों की उपज और उचित मूल्य दिलाने के लिए सहायता कर रही है । सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मजबूती लाने के लिए अन्नदाता को सशक्त बना रही है । हमारे देश और पूरी दुनिया में शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है । गांव से शहरों की ओर जनसंख्या बढ़ रही है । आधुनिक विकास कार्यों के कारण कृषि योग्य भूमि लगातार घट रही है । इसके साथ ही साथ शहरीकरण से प्रदूषण की समस्या बढ़ती जा रही है ।

पर्यावरण प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है । जमीन कम होने के कारण किसान मजबूरी में पलायन कर रहा है । इस पर भी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है । देश की अर्थव्यवस्था अगले तीन-चार वर्ष में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है । मजबूत नीतियों, निवेश, डिजिटल क्रांति और आत्मनिर्भरता के साथ भारत ने केवल जीडीपी के मामले में वैश्विक नेतृत्व और नवाचार में भी अपना स्थान मजबूत किया है । यह गर्व का विषय है ।

आर्थिक क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रही हमारे देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर हमारा देश बढ़ रहा है । मेक इन इंडिया, पीएलआई स्कीम, डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सरकार ने विनिर्माण और स्टार्टअप को बढ़ावा दिया है । यह उपलब्धियां माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में पिछले दस सालों में हो रही हैं । इन नीतियों और प्रगतिशील दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप अपने तीसरे कार्यकाल में सरकार ने तीन गुना गति से काम किया है, जो हमारे देशवासियों की प्रगति और प्रतिबद्धता को दर्शाता है । इसलिए माननीय प्रधान मंत्री और उनके मंत्रिमंडल के सभी मंत्रीगण का मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं ।

माननीय सभापति महोदय, जम्मू-कश्मीर हमारे देश का अभिन्न हिस्सा है । लेकिन पिछली सरकारों ने इसके विकास कार्यों पर ध्यान नहीं दिया । जबकि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू-कश्मीर लगातार विकास के पथ पर बढ़ रहा है । इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में उधमपुर-बारामुला-श्रीनगर रेल परियोजना का पूरा होना एक ऐतिहासिक कदम है । यह परियोजना कश्मीर को शेष भारत से जोड़ेगी । इससे पर्यटन, व्यापार, रोजगार के नये अवसर पैदा होंगे । कश्मीर में निरंतर विकास हो रहा है ।

अनुच्छेद 370 को हटाने पर विपक्ष के कई नेताओं ने इसे अलग मुद्दा बनाकर देश में अलग सा माहौल बनाने की कोशिश की थी । लेकिन जिस जम्मू-कश्मीर में युवा पत्थरबाजी करते थे, उसकी समृद्धि के लिए सरकार कदम उठा रही है । ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि विकास बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है । माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कृषि पर सरकार काम कर रही है ।

माननीय सभापति महोदय, सरकार द्वारा पिछले दस साल में की गयी प्रगति और देश के पूरे विकास हेतु प्रगति पथ पर है । सरकार के निर्णयों में लोक सभा और विधान सभाओं में महिलाओं को 33 परसेंट आरक्षण, वक्फ बोर्ड और एक देश, एक चुनाव शामिल है । ये निर्णय प्रशासनिक सुधारों और पारदर्शिता की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा । मध्यम वर्ग देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होता है । इसलिए सरकार ने मध्यम वर्ग की जरूरतों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं । इसमें आवास योजनाएं, रोजगार सृजन और जीवनयापन के कई सारे प्रयास शामिल हैं इसके साथ ही साथ आयुष्मान भारत योजना के तहत 70 वर्ष की आयु से अधिक 6 करोड़ नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा देने का निर्णय लिया है जो हमारे बुजुर्गों के प्रति सरकार की संवेदना को दर्शाता है ।

आर्थिक क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है । इस क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए केन्द्र सरकार ने क्रेडिट गारंटी योजना और ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट हब की पहल शुरू की है । एमएसएमई क्षेत्र में क्रेडिट गारंटी योजना और ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट हब के माध्यम से व्यापार को प्रोत्साहन दिया है । यह कदम देश को सशक्त बनाने में सहायक सिद्ध हो रहा है । वित्तीय वर्ष 2023-24 में इस योजना के लिए फंड में वृद्धि की गयी है ।

जब कोविड-19 महामारी ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया था, तब माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में आए इस संकट का प्रभावी रूप से सामना किया गया था । लॉकडाउन, वैश्विक अभियान और अन्य स्वास्थ्य योजनाओं द्वारा मोदी सरकार ने भारत को मजबूत रखने का संकल्प लिया था । स्वास्थ्य हमारे लिए एक महत्वपूर्ण विषय है और देश का हर नागरिक स्वस्थ रहे, उसके लिए माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी द्वारा देश भर में स्वास्थ्य योजनाओं के तहत 1.75 लाख आरोग्य मंदिर स्थापित करने का भी एक बड़ा निर्णय लिया गया था ।

अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जम्मू-कश्मीर की परिस्थिति में सुधार हुआ है । माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने जो भी कदम उठाए हैं, वे देश की समृद्धि, सुरक्षा और विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं । हम सबको मिलकर इन उपलब्धियों की सराहना करनी चाहिए और राष्ट्र के उज्ज्वल भविष्य के लिए कदम बढ़ाने चाहिए । हमारी सरकार ने प्रगति के नए आयाम स्थापित किए हैं। यह अभिभाषण हमारे देश के सुनहरे भविष्य का पूर्ण रूप प्रस्तुत करता है । मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का समर्थन करता हूँ ।

***m56 डॉ. फग्गन सिंह कुलस्ते (मंडला) :** माननीय सभापति जी, मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का समर्थन करते हुए एक बात कहना चाहता हूँ । हमारे कांग्रेस के मित्रों ने भारत की महामहिम राष्ट्रपति जी के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया था, वह सबको पता है । इनके द्वारा अभद्र टिप्पणी की गई थी, वह भी एक आदिवासी महिला पर की गई थी, जो इस देश के लिए अच्छी बात नहीं है । इनको स्वयं विचार करना चाहिए कि अगर हाउस के अंदर एक माननीय सदस्य देश की राष्ट्रपति के लिए ऐसा व्यवहार करते हैं तो वह बहुत ही अशोभनीय होता है । जहां तक महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का सवाल है तो मैं देख रहा था कि कई ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय, जो कि सरकार द्वारा किए गए हैं तथा उनको लेकर महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हुआ । आज देश में गरीब और गरीब कल्याण की योजनाओं का जिक्र हुआ है । आज हमारे कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि पिछले समय लगभग 4 करोड़ लोगों के पास घर नहीं होते थे । आज आवास योजना के तहत 4 करोड़ घर बनाए गए हैं । अभी पिछले बजट के दौरान तीन करोड़ घरों का और एलॉटमेंट किया गया था ।

आप सोच सकते हैं कि लगभग 7 करोड़ मकान गरीबों के लिए बनेंगे । यह हमारे देश के लिए और गरीबों के लिए उत्साहजनक बात है । इसके बारे में हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी अपने भाषण में उल्लेख करती है तो हमें गर्व होता है । आज जनजातीय समाज के लोग, 5 करोड़ ऐसे लोग हैं, जिनके लिए ?धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान? प्रारंभ हुआ है । इसके अंदर 80 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है ।

महामहिम राष्ट्रपति जी ने इस योजना के बारे में अपने भाषण में उल्लेख किया है । मुझे लगता है कि इसके बारे में कभी सरकार के संज्ञान में, अगर पुरानी सरकारों के बारे में या कांग्रेस सरकार के बारे में कहा जाए तो कभी भी इस देश के जनजातीय लोगों के बारे में नहीं सोचा गया । आज पीएम-जनमन योजना है, जिसके तहत हमारे देश में 75 ऐसी प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं, जिन्हें सरकार ने विशेष जनजाति का दर्जा दिया है । उनकी 50 परसेंट की आबादी है और उनमें भी लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं तथा 75 विशेष जनजाति समुदाय के लोग हैं ।

आप छत्तीसगढ़, बस्तर में देखिए । मध्य प्रदेश में बैगा जनजाति और सहरिया जनजाति है । जारवा जनजाति के लोग हैं ।?(व्यवधान) देश भर में ऐसी अनेक जनजातियां हैं । इसके लिए सरकार ने क्या किया है, मैं यह बता सकता हूं ।

हमारी सरकार बनने के बाद पहली बार वर्ष 2002 में 16 जिलों में उनको जनजाति का स्टेटस दिया गया । अभी हम ने और चार जिलों को शामिल किया है । राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इन सभी बातों का उल्लेख हुआ है । मैं नेता प्रतिपक्ष का भाषण सुन रहा था कि देश को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए । शायद उनको पता नहीं है । जब अटल जी की सरकार थी, तो उस समय पहली बार देश में आईटी के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ । यहां पर पूर्वोत्तर के कई माननीय सदस्यगण हैं । हम लोग वर्षों से देख रहे हैं कि उन परिवारों से वर्षों से उनका कोई संबंध नहीं था । आज हम पूर्वोत्तर क्षेत्र के बारे में कह सकते हैं कि देश में बहुत बड़ा परिवर्तन और विशेष कर पूर्वोत्तर क्षेत्र के भाइयों और बहनों के लिए किया गया है, उसका उल्लेख इसमें किया गया है । महामहिम राष्ट्रपति जी के भाषण में नए-नए इनिशिटिव्स लिए गए हैं । इसीलिए नेता प्रतिपक्ष जी क्या कहते हैं, उनकी सोच क्या है, मैं यह नहीं कह सकता हूं, परंतु आज वास्तव में नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में यह देश उन ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है । हमने यह उस समय से देखा है ।

आज मैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में कांग्रेस के मित्रों को बताना चाहता हूं कि जिस समय अटल बिहारी जी हमारे प्रधानमंत्री थे, पहली बार एनडीए की सरकार बनी थी, जब इस योजना को लाँच किया गया, तो वे हमेशा कहते थे कि यह भारत, ग्रामीण भारत है, गांवों का भारत है । यह टाइटल हुआ करता था । जब उस समय निर्णय हुआ तो उस समय की सरकार ने एक-एक गांव को पक्की सड़क से जोड़ने का फैसला किया । यह पहले भी हो सकता था ।

हम गांव की गरीबी के बारे में बात करते हैं । अभी हमारे साथियों ने कहा कि उस गरीबी से उबरने के लिए हमारे पास क्या-क्या मापदंड हो सकते हैं, हम देश में कौन-कौन सा फार्मूला अपना सकते हैं, इसके बारे में चर्चा नहीं होती है । आज मैं कह सकता हूं कि नरेन्द्र भाई मोदी जी की सरकार बनने के बाद मैंने वर्ष 2014 में हेल्थ सेक्टर को देखा है । यहां पर हेल्थ सेक्टर के बारे में बहुत उल्लेख किया गया है । हम ने उस समय मोदी जी के नेतृत्व में प्रयास किया । आज मेडिकल के क्षेत्र में सीटों की वृद्धि हुई है । हमारे देश में एमबीबीएस के लिए 50 हजार सीट्स होती थीं । वर्ष 2014 के बाद वर्ष 2015-16 में हमने एमबीबीएस के लिए लगभग 75000 सीट्स की वृद्धि की है । हमने पीजी के लिए 25 हजार सीट्स की वृद्धि की है । आज हम इनको निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं । आज भी हमारे देश में जनजाति क्षेत्र हैं, जनजाति जिले हैं । देश के उन जिलों को भी कवर करने का प्रयास इसके अंदर किया गया है । आप राष्ट्रपति जी की सोच को देखिए, उनके भाषण को देखिए । मैं गर्व के साथ कहता हूं कि इस प्रकार के प्रयास का उल्लेख हमारे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में हुआ है ।

मुझे याद है कि जब आयुष्मान भारत योजना की घोषणा हुई । प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ने यह घोषणा की तो हमारा टारगेट था कि इसका लाभ 50 करोड़ लोगों को मिलेगा । आज धीरे-धीरे लगभग पूरे देश में, अपवाद स्वरूप कुछ प्रदेशों को छोड़ दें तो पूरे देश में 75 से 80 प्रतिशत लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं ।

17.00 hrs

पहले हम रेलवे के मामलों को लेकर लोगों से मिलते थे, माननीय प्रधान मंत्री जी से मिलते थे तो बहुत प्रयास करने के बाद ही रेलवे लाइन मिलती थी । आज मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि देश में रेलवे के क्षेत्र में अमान परिवर्तन के काम हो रहे हैं जैसे अमृत भारत मिशन, नमो भारत ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन । अब फास्ट ट्रेनों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है । विकसित भारत के विज़न में जनभागीदारी का सामूहिक समर्थन, देश की आर्थिक उन्नति का रोड मैप तैयार होना, डिजिटल क्रांति के रूप में टेक्नोलॉजी की ताकत और आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर का आधार शामिल है । महामहिम राष्ट्रपति जी ने अभिभाषण में इस देश के विज़न को सामने रखते हुए सब बातों का उल्लेख किया है । विपक्ष के नेता कह रहे थे कि देश के बारे में विज़न नहीं है । मैं कहना चाहता हूं कि यह बहुत बड़ा लक्ष्य है और देश उंचाइयों तक जा रहा है, आगे बढ़ रहा है ।

सभापति जी, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से अगर हम भारत को देखें तो हम 11वें नंबर पर थे और अब हम पांचवें नंबर पर हैं । भारत आने वाले समय में आर्थिक दृष्टि से दुनिया में तीसरे नंबर पर होगा । इस अभिभाषण में आने वाले समय में, वर्ष 2047 में विकसित भारत की बड़ी कल्पना की गई है । पिछले दिनों हमने देश की आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया था । अब देश की आजादी के 75 साल पूरे हो गए हैं और हमने इसी हाउस में इस विषय पर चर्चा भी की थी । मुझे कहते हुए खुशी होती है कि महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में सारी बातों का उल्लेख किया गया है । माननीय प्रधान मंत्री जी ने नारा दिया ? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास । इस मंत्र को ध्यान में रखते हुए इस देश के अंदर सरकार काम कर रही है और इसी विज़न को महामहिम राष्ट्रपति जी ने मेंशन किया है ।

मैं उज्ज्वला योजना के बारे में बताना चाहता हूं । दस करोड़ गैस कनैक्शन्स और 80 करोड़ जरूरतमंदों को नि:शुल्क राशन देने का बहुत बड़ा विज़न है । यह अभिभाषण देश की और माननीय प्रधान मंत्री जी की सोच को दर्शाता है । कोविड जैसे संकट के समय हमने देश के लोगों को, गरीबों को उबारने के लिए बहुत बड़े विज़न को सामने रखकर काम को आगे बढ़ाया और अब 80 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिल रहा है । महामहिम राष्ट्रपति जी ने अभिभाषण में इसका भी उल्लेख किया गया है ।

हम ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं । हम देखते हैं कि जितने औषधि केंद्र हैं, वहां 80 परसेंट सब्सिडी मिल रही है । इससे गरीब लोगों को सुविधाओं का लाभ मिल रहा है । औषधि केंद्र चाहे किसी अस्पताल के सामने हो, चाहे किसी कस्बे में हो, चाहे किसी गांव में

हो, लगातार वृद्धि हो रही है । छोटे और गरीब लोगों का जीवन स्वास्थ्य लाभ की दृष्टि से सुरक्षित हो, इसके लिए सरकार विज़न को लेकर आगे बढ़ रही है । महामहिम राष्ट्रपति जी ने अभिभाषण में इसका भी उल्लेख किया है जबकि वास्तव में यह देश के लिए और देशवासियों के लिए चुनौती थी ।

पिछली लोक सभा में आप सब लोगों ने आरक्षण के बारे में माननीय प्रधान मंत्री जी का विज़न देखा था । उनका विज़न था कि लोक सभा, विधान सभा में 33 परसेंट महिलाओं का रिजर्वेशन हो । वर्ष 2026 के बाद जब डिमिलिमिटेशन होगा, उस समय हमारी बहुत बहनें इस हाउस में आएंगी । इतना बड़ा संकल्प कोई कभी ले नहीं सकता था । हमने पिछले दिनों देखा था कि हाउस में बिल फाड़ दिया गया था ।उस समय हमने इस प्रकार की घटनाएं देखी हैं । आज मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता होती है कि भारत के राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस प्रकार के निर्णयों को मेन्शन किया गया है । मैं एसएचजी के बारे में कहना चाहता हूं कि हमारे स्वयं सहायता समूह देश भर में काम करते हैं । वे बहुत बड़ी संख्या में हैं । मुझे याद है कि वर्ष 2014 के पहले देश में 1 करोड़ 34 लाख बहनें एसएचजी के अंदर काम करती थीं । वर्ष 2014 के बाद आप देखिये कि आज 10 करोड़ महिलाएं एसएचजी के अंदर हैं । उनका समावेश हुआ है । नारी शक्ति वंदन अधिनियम के द्वारा हमारी बहनों के लिए लोक सभा और विधान सभाओं के अंदर आरक्षण का प्रावधान इसी को ध्यान में रखकर किया है । हमारी बहनों का जो सशक्तिकरण है, आज यह धीरे-धीरे इतना आगे बढ़ रहा है ।

आपको यह याद होगा कि 9 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि बैंक लिंकेज के माध्यम से वितरित की गई है । यह कितना बड़ा एमाउंट है । मैं एक बात और कहूंगा । उनकी जो रिकवरी है, आज पूरे देश में देखेंगे कि कई ऐसे फ्रॉड केस होते हैं, परंतु बैंकों ने जो ग्रांट दी है, उनका 99 परसेंट बहनों ने ईमानदारी के साथ उसका परिचय देश के अंदर दिया है । बैंकों का विश्वास जागा है । यह बहुत बड़ा काम एसएचजी के अंदर हुआ है । एक करोड़ 15 लाख से अधिक लखपति दीदी की कल्पना इसके अंदर हुई है । मैंने पिछले दिनों देखा है कि महिला राष्ट्रपति होने के कारण इस विजन को उन्होंने अपने सामने रखा है और हमारे कॉन्स्टीट्यूशन में इसका उल्लेख बार-बार हुआ है । वास्तव में अगर हम इस प्रकार की योजनाओं के बारे में, कार्यक्रमों के बारे में, महिलाओं के बारे में, उनके सशक्तिकरण के बारे में देखेंगे तो बहुत बड़े विजन के साथ यह देश आगे बढ़ रहा है । मैं राष्ट्रपति जी को बधाई देना चाहता हूं । आज हमारी बहनों के बारे में, ड्रोन दीदी के बारे में, पूरे देश में एग्रीकल्चर सेक्टर में देखिये कि पिछले दशक में मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसी पहल से युवाओं को रोजगार देने की बात की गई है । आज मैं कह सकता हूं और मुझे बहुत स्थानों पर जाने का अवसर मिला है । जो शिक्षित बेरोजगार लोग हैं, चाहे वह व्यवसाय की दृष्टि से हो, चाहे सरकारी सेवाओं के अंदर हो, ?बी? और ?सी? ग्रेड के अंदर हो, लगभग 10 लाख लोगों

को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार देने का फैसला सरकार ने किया है । आज हम उसका भी कहीं न कहीं उल्लेख करते हैं और उसके कारण देश में परिवर्तन का वातावरण दिख रहा है ।

एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम और ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट हब्स सभी प्रकार के उद्योगों को बढ़ा दे रहे हैं । मुझे याद है कि इस भाषण के अंदर इस बात का उल्लेख किया गया है और थोड़ा सा बजट का भी उल्लेख करूं तो पहली बार एससी, एसटी के लिए एमएसएमई के अंदर इसका उल्लेख हुआ है और उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई है । इससे पहले यह कभी नहीं हुआ था । यह जो विजन है, मैं राष्ट्रपति जी को बधाई देना चाहता हूं कि छोटे-छोटे अनेक तरह के जो व्यवसाय हैं, उद्योग हैं, हम डिजिटाइज करने का काम कर रहे हैं । मैंने एक बहुत बड़े विजन टेक्नोलॉजी के बारे में प्रारंभ में उल्लेख किया था । 5जी सर्विस की शुरुआत इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है । हम टेलीकॉम के क्षेत्र में कितने तरह के उदाहरण देख सकते हैं । मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है और मैं महामहिम राष्ट्रपति जी को बधाई देना चाहता हूं कि हमने ऐसे क्षेत्र को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है । आज देश का कोई भी ऐसा क्षेत्र, राज्य, चाहे वह यूनियन टेरिटरी हो, चाहे राज्य सरकारों के अंदर हो, आज हमारी ग्राम पंचायतों तक पहुंच बढ़ी है । आज इसका ही उदाहरण हैं कि ई-पंचायतें हैं । एक समय ऐसा भी होता था कि हमारे देश के ही पूर्व प्रधान मंत्री कहते थे कि हम यहां से 100 रुपये भेजते हैं तो गांव में 15 रुपये पहुंचते हैं ।

आज इसका ही उदाहरण है कि ई-पंचायतें हैं । एक समय ऐसा भी होता था, जैसा कि पूर्व प्रधानमंत्री कहते थे कि हम एक सौ रुपए यहाँ से भेजते हैं, तो गांवों में 15 रुपए ही पहुंचते हैं । आज डीबीटी के माध्यम से एक प्रत्यक्ष उदाहरण देख सकते हैं कि ऐसे करोड़ों लोग हैं, गांव के गरीब लोग हैं, मजदूर हैं, जो पंचायतों और ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर काम करते हैं । आज इसमें उनके बारे में इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है । आज इसमें पारदर्शिता है । यही कारण है, इस पारदर्शिता के कारण हमारा जो मैकेनिज्म डेवलप हुआ है, वह सरकार की इच्छाशक्ति को प्रमाणित करता है ।

माननीय सभापति जी, मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि वे इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक बेहतर जीवन, देश को एक नयी पहचान देना अपने-आप में ही देश को एक नया आत्मविश्वास देता है । बीते दशक में, भारत ने वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के कई माइलस्टोन तय किये । ये इसके उदाहरण हैं । आज हम भारत के बारे में सोचते हैं, हमने देखा है कि वास्तव में, अगर हम कहें, तो कुछ समय पहले लोगों की क्या स्थिति थी, राज्य सरकारों की क्या स्थिति थी । हमने देखा है कि आज कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए क्या काम किये गये हैं, चाहे हाइवेज़ हों, रेलवेज़ हों, एयरपोर्ट्स हों, एयर सर्विसेज हों या बंदरगाह हों । आज एक बहुत बड़ा सेक्टर लॉजिस्टिक्स है । इस क्षेत्र में, आज इसका बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है । इसके कारण हमारे व्यवसाय, अनेक लोगों को काम और रोज़गार के अवसर प्राप्त होते हैं ।

माननीय सभापति, यह हमारे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विज़न है । मेट्रो के क्षेत्र में लोगों ने कभी कल्पना नहीं की होगी, लेकिन आज धीरे-धीरे देश में मेट्रो का कितना नेटवर्क बढ़ा है । इस क्षेत्र में, यह दुनिया का तीसरा बड़ा देश बन गया है । आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे देश में मेट्रो का जितना विस्तार हुआ है, वह इच्छाशक्ति के कारण ही हुआ है । इसी इच्छाशक्ति के कारण आज हम इस मुकाम तक पहुंच पा रहे हैं । अभी कुछ दिन पहले राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन के बारे में कहा गया था । देश में लोगों को टीबी मुक्त करने का निर्णय लिया गया था । विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार ने इसके लिए एक अभियान प्रारंभ किया है । इस पर हमने फोकस किया है । सरकार ने इस बात पर चिन्ता जाहिर की है । माननीय राष्ट्रपति जी ने इसके अन्दर उसका उल्लेख किया है । उन्होंने सभी देशवासियों और सभी माननीय सांसदों से भी कहा है कि प्रधानमंत्री जी ने टीबी मुक्त भारत की कल्पना की है । इसलिए इसके लिए एक बहुत बड़ा संकल्प लिया गया है, माता-बहनों के लिए संकल्प लिया गया है । मैंने कहा कि आने वाले समय में, अगर हम देखें तो हम इसको और ज्यादा आगे बढ़ा सकते हैं । कई क्षेत्रों के अन्दर टीबी मुक्त भारत की कल्पना कर सकते हैं, जहाँ सिकल सेल एनीमिया जैसी परम्परागत बीमारी होती है । ऐसे कई क्षेत्र हैं, जैसे आदिवासी क्षेत्र हैं, जनजातीय क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्र हैं, जहाँ इसका कितना बड़ा दुष्प्रभाव है । आज इसके लिए इतना बड़ा कदम उठाया गया है । इसके लिए स्पेशल बजट का प्रॉविज़न करना है, इसके लिए विशेष अभियान चलाना है । इसलिए मैं कह सकता हूँ कि माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इसका उल्लेख किया गया है । यह अपने-आप में एक गर्व करने वाली बात है ।

माननीय सभापति जी, मैं मध्य प्रदेश में, अपने क्षेत्र में, सिंचाई के लिए विशेषकर बाबा साहब अम्बेडकर जी के विज़न पर चलते हुए देश के सूखाग्रस्त इलाकों में सिंचाई और पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री जी ने ?नल-जल योजना? प्रारम्भ किया है । यह जो पानी का संकट है, हमारे पास इसका सोर्स कम है, इसलिए हमारे सामने यही एक विकल्प है कि बड़ी नदियों को जोड़कर, जैसे माननीय अटल जी ने उस समय इस योजना को प्रारम्भ किया था, आज हम इसको फलीभूत होते हुए देख रहे हैं । आज इस विज़न से किसान के खेतों को भी पानी मिलेगा, आम जनता को भी पीने के लिए पानी मिलेगा । इसलिए जल-जीवन मिशन को पूरा करने का लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री ने रखा है । मुझे यह भी कहते हुए प्रसन्नता है कि उन क्षेत्रों के अन्दर ऐतिहासिक रिवर लिंकिंग परियोजनाओं का, विशेष रूप से 44 हजार करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाली केन-बेतवा लिंक परियोजना शुरू की गई है । मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूँ । उनका विज़न देखिए । माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में इस विज़न के बारे में उल्लेख किया है ।

महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में इस विजन का उल्लेख किया है । हमारी संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चम्बल लिंक परियोजना राजस्थान, मध्य प्रदेश में

सिंचाई और पीने के पानी के लिए आज इसकी जरूरत है । आज इतने बड़े विजन के साथ कोई ऐसा सेक्टर बाकी नहीं है । आज मुझे एक बात और कहनी है । मैं महामहिम राष्ट्रपति जी को बधाई देना चाहता हूँ कि सरकार के प्रयासों का सबसे अधिक लाभ देश में हमारे दलितों, पिछड़ों और आदिवासी समाज को मिला है । आजादी के दशकों बाद भी हमारे जनजाति समाज, आदिवासी समाज की जो उपेक्षा हो रही थी, राष्ट्रपति जी ने कहा है कि मेरी सरकार ने उसको प्राथमिकता दी है । हमारे कांग्रेस के मित्रों ने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के समय जो टिप्पणी की, वह उचित नहीं है । पीएम जन-मन योजना का मैंने प्रारंभ में उल्लेख किया था । आज देश में उन क्षेत्रों के अंदर प्रावधान किया गया है । 470 से अधिक एकलव्य आदर्श विद्यालय खोले गए हैं । वर्ष 1999 में इस योजना को प्रारंभ किया गया था । इसके पहले शिक्षा के क्षेत्र में, खास तौर से ट्राइबल लोगों की शिक्षा के लिए ऐसा कोई विजन नहीं था । शिक्षा की गुणवत्ता पर पहले कभी विचार नहीं हुआ । उस समय ऐसे 100 आवासीय विद्यालय प्रारम्भ किए गए । आज ऐसे 470 एकलव्य विद्यालय हमारे देश के अंदर खोले गए हैं । इनमें क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है । इसके लिए स्पेशल प्लान प्रधानमंत्री जी ने किया है । मुझे खुशी है कि आज हमारे सवा लाख आदिवासी बच्चों को स्कूली शिक्षा दी जा रही है । पिछले 10 वर्षों में तीस नए मेडिकल कॉलेज खास तौर से आदिवासी क्षेत्रों में खोले गए हैं । यह अपने आप में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी फैसला सरकार ने किया है । हमारे ट्राइबल क्षेत्रों के अंदर तीस नए मेडिकल कालेज खोलना, पहले हम लोग सोचते थे, देखते थे कि इसके लिए कितनी बार सरकारों को कहना पड़ता था, विभाग को कहना पड़ता था, परन्तु आज अपने आप में इस बहुत बड़े चैलेंज को सरकार ने स्वीकार किया है । भगवान बिरसा मुंडा जी की 125वीं जयंती को पूरे देश में जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है । मुझे याद है कि जब यह निर्णय सरकार ने किया, पूरे देश भर में सम्मान के साथ भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती और जनजातीय गौरव वर्ष में कार्यक्रम हुए । भगवान बिरसा मुंडा जी देश के वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, हमारे जनजातीय समाज के पहले ऐसे आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए, जो वास्तव में जंगल के अधिकार को दिलाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़े । आज जो यह वन अधिकार का कानून बना है, इसके माध्यम से चाहे वह सामूहिक दावे हों, चाहे व्यक्तिगत हों, बहुत बड़ी संख्या में आज हमारे जनजातीय क्षेत्रों के भाई-बहनों और जो भी व्यक्ति वहाँ उन क्षेत्रों के अंदर रह रहा है, उस कानून के अंदर यह भी प्रावधान है कि किसी को बेदखल नहीं किया जाएगा । इस प्रकार के प्रावधान इसके अंदर किए गए हैं । पूर्वोत्तर क्षेत्रों के बारे में मैंने कहा, पर्यटन की दृष्टि से, हमारे नॉर्थ-ईस्ट के भाई-बहनों की भावनाओं को ध्यान में रखकर हमारी भारत सरकार ने, पूर्वोत्तर के अंदर जो गैप था, इस गैप को भरने का काम सरकार ने किया है ।

महोदय, वास्तव में यह काम सरकार की इच्छा शक्ति के कारण हुआ है । हमारे पूर्व क्षेत्र के भाई-बहनों के लिए सरकार योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है । मैं

महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को इस बात के लिए भी बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जम्मू-कश्मीर का भी जिक्र किया । मैं केवल एक बात जोड़ना चाहता हूं कि वहां रिजर्वेशन की कोई व्यवस्था नहीं है । धारा 370 हटने के साथ 35-ए भी हटाया गया । मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि प्रधान मंत्री जी ने बहुत क्रांतिकारी कदम उठाया है और मुझे उम्मीद है कि इन धाराओं का हटाने का पूरा लाभ हमारे जम्मू-कश्मीर के लोगों को मिलेगा ।

महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जिन छोटी-छोटी चीजों का उल्लेख किया गया है, जिन्हें किसी ने छूने का भी कभी प्रयास नहीं किया, परन्तु इन सबका समावेश उन्होंने अपने भाषण में किया है । इसके लिए मैं राष्ट्रपति जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं । मैं देश के प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को भी बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने इस विजन को पूरी ईमानदारी के साथ जन-जन तक पहुंचाने का काम किया है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

***m57 श्री राजेश वर्मा (खगड़िया) :** सभापति जी, आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के ऊपर हो रही चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया और साथ ही साथ मैं महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा देश को दिए गए संबोधन के लिए अपनी लोक जन शक्ति पार्टी (रामविलास) अपने नेता चिराग पासवान जी, हमारे प्रदेश बिहार और अपनी लोक सभा खगड़िया की जनता की तरफ से महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी का कोटि-कोटि धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं ।

महोदय, राष्ट्रपति का अभिभाषण एक संवैधानिक दायित्व है और इस दायित्व की जिम्मेदारी की ताकत उन्हें बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर जी का संविधान देता है । जिस तरीके से महामहिम राष्ट्रपति महोदया को प्रत्येक वर्ष सरकार क्या काम कर रही है, इसे देश के समक्ष रखना होता है और जिस खूबसूरती से महामहिम राष्ट्रपति जी ने सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए पूरे देश के हर वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए चाहे वह किसानों की बात हो, चाहे युवाओं की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे दलित वंचितों की बात हो, चाहे बुजुर्गों की बात हो, सभी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपना संबोधन देश के सामने रखा था । महोदय, मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि जब एक महिला होने के बावजूद और विपक्ष में वरिष्ठ सदस्य होने के बावजूद एक महिला राष्ट्रपति पर ऐसा कमेंट पास करना कि वह पुअर थिंग है, वह बोरिंग है और आज जिस तरीके से लीडर ऑफ ओपोजिशन ने इस बात को कहा कि राष्ट्रपति का अभिभाषण प्रत्येक साल एक जैसा ही होता है । मैं आपके माध्यम से लीडर ऑफ ओपोजिशन को बताना चाहता हूं कि राष्ट्रपति का अभिभाषण योजनाएं प्रत्येक वर्ष कमोवेश वही होती हैं । अंतर केवल आंकड़ों में होता है इसलिए आंकड़ों पर ध्यान दिया जाए, न कि योजनाओं के नाम पर ध्यान देने की जरूरत है । मैं आपके माध्यम से जो विपक्ष बार-बार कहता है कि सरकार ? सबके साथ सबके विश्वास? की बात करती है, तो कहां ऐसा काम हो रहा है । मैं आपके

माध्यम से विपक्ष के उन सभी साथियों का ध्यान हर एक मुद्दे पर ध्यान केंद्रित कराना चाहता हूं कि किस तरीके से यह सरकार सभी को एक साथ लेकर चल रही है । जिस तरीके से 5,36,000 करोड़ रुपये प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत सरकार नए आवासों को बनाने के लिए खर्च कर रही है और आने वाले इस कार्यकाल में लगभग तीन करोड़ नए आवास यह सरकार बनाने का काम करेगी ।

सभापति महोदय, हम लोगों ने अपने खगड़िया लोक सभा संसदीय क्षेत्र में भी चुनावों के वक्त सैकड़ों घरों को जलते हुए देखा है, जो कच्चे मकान थे । हम लोगों को भी इस बात की ललक थी कि सरकार की इस योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा मेरी कंस्टीट्युन्सी को मिले । यह कहते हुए गर्व होता है कि इस कार्यकाल में मेरी कंस्टीट्युन्सी में लगभग 40,000 नए घरों की स्वीकृति मिली है और यह देन हमारी इस एनडीए सरकार की है ।

महोदय, लोग कहते हैं कि सरकार कैसे ध्यान रख रही है तो मैं बताना चाहता हूं कि आयुष्मान कार्ड योजना के तहत आज लगभग 55 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिल रहा है । पहले कभी किसी गरीब परिवार के घर में किसी को कोई गम्भीर बीमारी होती थी तो उसके घर के जेवर गिरवी रख दिए जाते थे, उसका घर गिरवी रख दिया जाता था और बड़े-बड़े लोग बड़े ब्याज दरों पर उन्हें पैसे देते थे और उनका शोषण करते थे । पर, माननीय प्रधान मंत्री जी की यह सोच है कि आयुष्मान कार्ड योजना के तहत आज उन 55 करोड़ लोगों को सुगम, सुलभ और नि:शुल्क इलाज मिल पा रहा है ।

सभापति महोदय, हमारी यह सरकार युवाओं के लिए कैसे काम कर रही है तो आपके माध्यम से मैं विपक्ष के हमारे साथियों को यह बताना चाहता हूं कि एक करोड़ युवाओं को मल्टीनेशनल कम्पनीज़ में इंटर्नशिप दिलाने के लिए सरकार ने पूरी तरह से प्लान किया है और आने वाले समय में सरकार सभी एक करोड़ नौजवान युवा साथियों को इंटर्नशिप कराने का काम करेगी ।

महोदय, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन कैनेडी ने कहा था, ?American roads are not good because America is rich, but America is rich because American roads are good?. मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि इसी विचारधारा के साथ हमारी सरकार भी काम कर रही है । यदि हम लोग आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहते हैं, यदि हम लोग अपने प्रदेश को, अपने जिले को सम्पन्न देखना चाहते हैं, तो इसके लिए रोड कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है । यह कहते हुए गर्व होता है कि हमारी सरकार ने प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 70,000 करोड़ रुपये की स्वीकृति देने का काम किया है, जिसे महामहिम राष्ट्रपति जी ने भी अपने अभिभाषण में कहा है । जहां यह सरकार एक तरफ सड़क मार्ग से एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश को जोड़ने का काम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ यह सरकार 71 अमृत भारत और वन्दे भारत ट्रेनों के माध्यम से रेल मार्ग से भी लोगों को जोड़ने का काम कर रही है ।

विपक्ष किस तरह से किसानों की बात करता है, हमारी सरकार में ही किसानों को तीन लाख रुपये के क्रेडिट कार्ड देने का काम किया गया और उसको अब बढ़ाकर पाँच लाख रुपये तक के क्रेडिट कार्ड लोन की स्कीम को लागू करने का काम किया गया है ।

विपक्ष दलितों की बात करता है और बार-बार इस बात को कहता है कि यह दलित विरोधी सरकार है । इसी सरकार ने एस.सी., एस.टी. की महिलाओं को बिना किसी कोलैट्रल के पाँच लाख रुपये तक के लोन्स देने का काम किया है ।

आम लोगों की आवाज़ को अपनी आवाज़ बनाकर सरकार ने 12 लाख रुपये तक की आय वाले लोगों की आय को टैक्स-फ्री करने का काम किया है । यह जो एक बड़ा निर्णय हमारी सरकार ने लिया है, इसके लिए मैं सरकार का तहे दिल से आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं ।

17.28 hrs (Shrimati Sandhya Ray *in the Chair*)

महोदया, स्वच्छ भारत अभियान के तहत इसी सरकार ने 12 करोड़ शौचालय बनाने का काम किया । उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ घरों तक गैस कनेक्शंस पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया । यह कहते हुए गर्व होता है कि आज लगभग 80 करोड़ लोगों को राशन उपलब्ध कराने का काम यह सरकार कर रही है । विपक्ष के जो साथी यह बार-बार कहते हैं कि यह सरकार कहां ?सबका साथ, सबका विकास? की बात करती है तो हम बात नहीं करते हैं, बल्कि हमारी सरकार काम करती है और सरकार ने यह करके दिखाया है । इसी का नतीजा है कि आज एक बड़ी आबादी गरीबी रेखा से ऊपर उठकर इस सरकार पर अपना विश्वास दिखा रही है । हमारी सरकार ?रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म? की विचारधारा के साथ निरंतर काम करने का काम कर रही है ।

सभापति महोदया, इसके साथ-साथ आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं बिहार से आता हूं । पिछले दो बजट से, जब-जब बजट में बिहार के लिए थोड़ी योजनाएं भी चलायी जाती हैं तो विपक्ष के लोग शोर मचाकर कहते हैं कि यह बजट तो बिहार का बजट था, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, मैंने पिछली दफा भी यह कहा था कि आप बिहार के प्रति अपना रुख सकारात्मक रखिए, क्योंकि ऐसा शायद ही कोई प्रदेश होगा और शायद ही ऐसे बड़े कारखाने होंगे, जहां उन कारखानों को चलाने में अगर किसी का मूलभूत योगदान है, और यदि आप वहां जाकर देखेंगे तो वहां आपको कोई न कोई बिहारी ही मिलेगा । इसलिए बिहार के प्रति आप अपने रुख को सकारात्मक रखिए ।

दिल्ली में अपने आपको ईमानदार कहने वाले एक नेता ने अभी कुछ ही दिन पहले ही बिहारियों के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था ।

हम लोग बस यही कहना चाहते हैं कि यह बदलता हुआ बिहार है । जिस तरीके से केंद्र सरकार, राज्य सरकार, एनडीए की सरकार ने बिहार को लगातार सहयोग देने का काम किया है, उसके लिए हम लोग जहां एक तरफ कोटि-कोटि उनको धन्यवाद देते हैं, वहीं दूसरी तरफ यह विश्वास दिलाते हैं कि यह बदलता हुआ बिहार आने वाले वक्त में खुद

से रोज़गार भी सृजन करेगा, उद्योग भी सृजन करेगा, साथ ही, आर्थिक रूप से धीरे-धीरे अपने आप को मज़बूत कर के बिहार और बिहार की अस्मिता को बचाने का संकल्प भी हरेक बिहारी लेगा । मैं अंत में बस यही कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ, बिहारियों के लिए कहना चाहता हूँ कि हम पत्थर पर लिखी इबादत हैं, शीशे से कब तक हमको तोड़ोगे? मिटने वाले हम नाम नहीं, तुम बिहार को कब तक रोकोगे?

बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री उज्ज्वल रमण सिंह (इलाहाबाद) : सभापति महोदया, आपने मुझे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए आपका धन्यवाद । मैं राष्ट्रपति महोदया को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर को नमन कर के अपने अभिभाषण की शुरूआत की और जो लोग इसको एक फैशन बताते थे, आज कहीं न कहीं यह साबित कर दिया कि बाबा साहब भीम राव अंबेडकर का नाम लेना फैशन नहीं, बल्कि हर भारतीय की आस्था है । उस महान आदमी, जिसने भारत का शानदार संविधान दिया, आज हम सब लोग उनके विचारों को बचाने के लिए, भारत के संविधान को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं । हमें फख्र है कि हमारे नेता विपक्ष राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे । हमने बाबा साहब का अपमान न सहा है, न सहेंगे और सौ बार नहीं हज़ार बार संविधान हाथ में लेते रहेंगे । हम सब मिल कर यह कहना चाहते हैं कि भारतवासियों के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात नहीं है कि माननीय राष्ट्रपति जी ने बाबा साहब भीम राव अंबेडकर के नाम से अपने अभिभाषण की शुरूआत की ।

महोदया, मैं इलाहबाद से चुनकर आता हूँ । वहां पर कुंभ मेला का आयोजन किया जा रहा है । मैं सबसे पहले उन श्रद्धालुओं को, जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, उनकी स्मृतियों को नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ । मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जो लोग कुंभ मेला, अर्ध कुंभ और कुंभ को नहीं जानते कि कुंभ की असली आस्था गांव में है । भक्ति के रंग में रंगल गांव देखा । धर्म में, कर्म में सनल गांव देखा । अगल में, बगल में सगल गांव देखा । अमावस्या नहाय चलल गांव देखा । मौनी अमावस्या का नहान कैलाश गौतम जी ने अपनी कविता के माध्यम से चरितार्थ किया है । मौनी अमावस्या में लाखों-करोड़ों लोग आए हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा था कि दस करोड़ लोग नहान के लिए आएंगे । अगर कोई सामान्य आदमी भी अपने घर में व्यवस्था करता है, किसी को न्योता देता है, बुलाता है तो उसके खाने-पीने और रहने की व्यवस्था करता है । लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने उन श्रद्धालुओं को, जो आम श्रद्धालु आए थे, उनकी व्यवस्था नहीं की । वे 30-30 किलोमीटर पैदल चल कर गए । गंगा के स्नान के लिए जिस आस्था के साथ गए, मैं कहना चाहता हूँ कि उनके लिए न शौचालय की व्यवस्था थी, न पानी पीने की व्यवस्था थी, न उनके रहने की व्यवस्था थी । इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप कभी जा कर देखें, मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि कभी कुंभ मेले में जा कर

देखिए तो वहां का माहौल कैसा है । उल्लास और उमंग का माहौल था, जब लोग 27, 28 और 29 तारीख को पैदल चलते हुए जा रहे थे । उल्लास और उमंग का माहौल था । जो हमारे तंबू और कनात लगाए गए, वे तंबू कनात नहीं थे । मैं कविता के माध्यम से कहना चाहता हूँ:-

?अजर हो गया, अमर हो गया है, शहर तंबुओं का शहर हो गया है ।
महाकुंभ की आस्थाओं में डूबा यह यह लाखों-करोड़ों का घर हो गया है ।?

इस तरीके से महाकुंभ का हमारा नगर बसा । उस नगर में सरकार ने जिस तरीके की व्यवस्था की, उसमें कहीं क्राउड मैनेजमेंट नहीं था । कहने को कहा गया कि 144 सालों बाद संजोग बना, जब अमृतपान करने के लिए लोगों को आपने बुलाया ।

आज तक बुलाया नहीं जाता था । पहली बार उत्तर प्रदेश की सरकार ने बुलाया और बुलाने के बाद व्यवस्था राम भरोसे छोड़ दी । वहां तीन जगह भगदड़ हुई । मैं कहना चाहता हूं कि आज तक उत्तर प्रदेश की सरकार यह बतलाने को तैयार नहीं कि कितनी जगहों पर भगदड़ हुई, कितने लोग मारे गए । आज तक हम लोगों को उनका नाम नहीं बताया जा रहा है । कितने लोग अपने लोगों से बिछड़ गए, लेकिन उनका नाम नहीं बताया जा रहा है । कितनी गाड़ियाँ लावारिस खड़ी हैं । मैं कहना चाहता हूं कि इसका मुख्य कारण क्या था । इस घटना का मुख्य कारण था, पॉन्टून के जो तीस ब्रिजेज बने हुए थे, 27 तारीख से तीस के तीस ब्रिज, 15 आने के और 15 जाने के, सारे के सारे ब्रिजेज को बंद कर दिया गया । एक ही मार्ग से आना था, एक ही मार्ग से जाना था । इस कारण यह व्यवस्था खराब हुई ।

महोदया, मैं कहना चाहता हूं कि जब आदमी इतनी दूर से चल कर आएगा, वह 20-20, 30-30 किलोमीटर दूर से चल कर आएगा, तो वह उसी रेती में जा कर सो जाएगा । एक तरफ सोते हुए लोग और दूसरी तरफ चलता हुआ जन सैलाब । कहीं न कहीं जिला प्रशासन, कहीं न कहीं मेला प्रशासन, कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन फेल हो गया । उत्तर प्रदेश की सरकार के दावे खोखले साबित हुए और इतनी बड़ी दुर्घटना घटित हो गई । मैं कहना चाहता हूं कि यह वीआईपी मेला नहीं था, यह आम श्रद्धालुओं का मेला है । यह आम श्रद्धालुओं का महाकुंभ है । लेकिन, जिस तरह से वीआईपी लोगों की हूटर लगी गाड़ियां, सायरन बजाती हुई गााड़ियाँ, उसमें संतों की वाणी खो गई । कहीं न कहीं संतों की आवाज दब गई और हूटर एवं सायरन में लोग दौड़ते चले गए । अगर इस दुर्घटना के प्रमुख कारणों की जांच होगी तो एक बहुत बड़ा कारण है, जिस तरह से वीआईपी लोगों की दौड़ लगी थी, वीआईपी लोगों के चिंता थी, अपनी फोटो खिंचवाने की, फोटो ऑप्र्चुनिटी लेने की । सरकार की चिंता थी, इवेंट मैनेजमेंट कराने की, अपनी ब्रांडिंग कराने की, लेकिन यह वह जगह नहीं थी ।

माननीय अधिष्ठाता महोदया, मैं कहना चाहता हूं कि यह वह जगह नहीं थी । यहां आस्था का समुद्र था । लोग उस आस्था और विश्वास के साथ आए कि अब अमृत वर्षा

होगी, उस अमृत का पान करेंगे, लेकिन हजारों लोग मर गए । आपने देखा होगा, वह दृश्य देखे होंगे कि किस तरीके से जेसीबी लगा कर लोगों का समान उठाकर फिकवाया गया । आज भी कूड़े के ढेर में लाशें मिल रही हैं । लोग उठाने को तैयार नहीं हैं, लेकिन जबरदस्ती पुलिस वाले मार-मार कर लाशें उठवा रहे हैं । मैं कहना चाहता हूं कि इसकी गहनता से जांच हो, इसकी गहराइयों से जांच हो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो । इसके लिए जो लोग जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो । यह मैं आपसे कहना चाहता हूं । मैंने प्रैस और टेलीफोन के माध्यम से पहले ही सचेत किया था कि मकर सक्रांति के बाद मौनी अमावस्या के दिन चार गुना ज्यादा लोग आएंगे । वहां चार गुना ज्यादा लोग आए, लेकिन सरकार ने मेरी बात को अनदेखा कर दिया । हमारी बात को सरकार ने अनसूना कर दिया । कहीं न कहीं वीआईपी के पीछे मेला प्रशासन, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन भागता गया । वीआईपी लोगों ने उनको काम नहीं करने दिया । रोज के रोज फोटो खिंचवाने की होड़ लगी रही । मैं कहना चाहता हूं कि इस मेले में भ्रष्टाचार भी हुआ । शाल की लकड़ी का 300 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ । पहले यह सरकार से सरकार को जाता था । अब चुने हुए कुछ चिन्हित ठेकेदारों को यह काम दिया गया । खराब लकड़िया दी गईं और अंत में पुल बन कर तैयार हुआ । इसकी वजह से यह बड़ी दुघर्टना हुई । आज यह घटना आप सब के सामने है । आज भी आंकड़े छुपाए जा रहे हैं । जो लोग मरे हैं, उनका नाम नहीं बताया जा रहा है । इसलिए, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं और जेपीसी की मांग करता हूं । इस संसदीय समिति के सभी सांसद वहां जाएं । वे वहां जाकर देखें कि यह दुर्व्यवस्था क्या है, अव्यवस्था क्या है? मैं एक कविता के माध्यम से कहना चाहता हूं-

झूठ के सैलाब में सच के किनारे बह गए,
चांद की झूठी तरफदारी में तारे रह गए,
पूछिए मत कौन दोषी है, गिरावट का यहां,
मुल्क के मजबूत पाए सबसे पहले ढह गए ।

महोदया, यह हालात प्रयागराज का है । आज प्रयागराज के लोग पीड़ा में हैं । वे आंसुओं से रो रहे हैं । जो मायूसी छाई हुई है, उसकी जवाबदारी और गुनाहगार कौन है, इसे हम उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार से जानना चाहता हैं । इन सरकारों ने इतने पहले आयोजन की व्यवस्था की । उन्होंने कहा कि मेट्रो बनेगा, गंगा एक्सप्रेस-वे बनेगा, सिक्स-लेन ब्रिज बनेगा, लेकिन आज एक भी चीज बन कर तैयार नहीं है ।

यह है केंद्र सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की विफलता । एक भी मजबूत काम नहीं हो पाया, एक भी ढांचागत काम नहीं हो पाया, जिससे क्राउड मैनेजमेंट की बेहतर व्यवस्था हो । अगर दुर्घटना हुई थी, उसके इवैक्युएशन की कोई तैयारी नहीं थी । रात डेढ़ बजे घटना हुई, उसके बाद दूसरी घटना झूंसी में साढ़े पांच बजे की है, लेकिन प्रदेश की सरकार उसको मानने को तैयार नहीं है । मैं कहना चाहता हूं कि इसकी जांच जेपीसी के

द्वारा नहीं होगी, तो दूध का दूध, पानी का पानी नहीं होगा । लोग कहते हैं कि जो लोग मरे, उनको मोक्ष प्राप्त हो गया । इससे बड़ी हास्यास्पद बात क्या हो सकती है? गरीब की मौत का मजाक अगर उड़ाया जा रहा है, तो इस सरकार के द्वारा उड़ाया जा रहा है । कोई सरकारी व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त नहीं हुआ, कोई बड़ा व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त नहीं हुआ । गरीब किसान मरा, वहां गरीब किसान ने अपना दम तोड़ा, जिनकी लाशों की गिनती करने को आप तैयार नहीं हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या था बताओ उनका पाप? हादसे, नाकामियों, गलतियों के बाद भी थपथपाते दिख रहे अभी भी अपनी पीठ आप । इतनी नाकामियों के बाद भी आप अपनी पीठ थपथपा रहे हो । मैं कहना चाहता हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए ।

महोदया, जो नेता विरोधी दल ने संशोधन का प्रस्ताव रखा है, मैं उससे अपने को संबद्ध करना चाहता हूं । आज बेरोजगारी की दर 8 पर्सेंट से बढ़कर 8.3 पर्सेंट हो गई । इसका जिक्र राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में नहीं है । आधी हकीकत, आधा फसाना । राष्ट्रपति जी ने जो अभिभाषण दिया, उसमें सरकारी पूंजीगत में पिछले 6 महीने में 37 पर्सेंट रह गया, जो पिछले वर्ष 49 पर्सेंट था । कहीं पर राष्ट्रपति जी ने उन बातों, उन तथ्यों को छिपाया जो देश को जानना चाहिए । वर्ष 2004 से 2014 तक डॉलर की कीमत क्या थी? वर्ष 2003 में 46.5 रुपये और वर्ष 2013 में 56.50 पैसे थी, यानी 10 सालों में 10 रुपये की बढ़ोत्तरी । पिछले 12 सालों में 30 रुपये की बढ़ोत्तरी डॉलर की कीमत में हुई । देश की इज्जत घटी है या देश की इज्जत बढ़ी है, इसका फैसला सदन को करना पड़ेगा ।

मैं आपके माध्यम से राष्ट्रपति जी को कहना चाहता हूं कि देश की इज्जत लगातार गिरती जा रही है, लेकिन सरकार इसको अनदेखा कर रही है । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आदमी की इन्कम नहीं तो इन्कम टैक्स में आप कमी करते हैं । आज डॉ. मनमोहन सिंह जैसे अर्थशास्त्री की जरूरत थी, जिन्होंने दीर्घकालिक नीतियां बनाकर देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने का काम किया । आज इस सरकार के पास डॉ. मनमोहन सिंह जैसा व्यक्तित्व नहीं है । आज इस सरकार के पास ऐसा कोई नेता नहीं, जो आर्थिक नीतियां बना सके ।

आज आप कहते हैं कि तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में इसके बारे में कहा है । तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में अगर आप देखें तो प्रति व्यक्ति आय हमारी कहां है? आप प्रति व्यक्ति आय को देखें तो हमारी प्रति व्यक्ति आय 2,480 अमेरिकी डॉलर है । अगर हमें वर्ष 2047 तक विकसित देश बनाना है तो 12,500 डॉलर हमारी प्रति व्यक्ति आय होनी चाहिए । अगर हम पांच गुना भी इसको बढ़ा दें, तब भी हम वहां तक नहीं पहुंच सकते । आज हमारी जीडीपी की ग्रोथ 5.6 पर्सेंट है । 6.5 पर्सेंट के हिसाब से भी अगर हम जीडीपी की ग्रोथ ले जाएं तब भी हम 12,500 डॉलर तक नहीं पहुंच सकते । आज भारत कहां विकसित हो रहा है? हमारे यहां एक बड़ोखर न्याय पंचायत है, वहां पानी पीने की व्यवस्था नहीं है । शंकरगढ़ न्याय पंचायत हमारे यहां

टाउन एरिया है, वहां गर्मी में लोग पानी को तरस जाते हैं । मांडा ब्लॉक में परोध इलाका है, वहां सिंचाई के पानी की व्यवस्था नहीं है । आप कौन सा विकसित भारत बनाना चाहते हैं? ऐसा विकसित भारत, जहां अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है । प्रति व्यक्ति आय हमारी बढ़ती नहीं, गांव में पानी मिलता नहीं, सिंचाई के पानी की व्यवस्था नहीं । मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि आज देश के हालात अच्छे नहीं हैं ।

राष्ट्रपति महोदया को सही जानकारी न देकर कहीं न कहीं दिगभ्रमित किया गया, सही बात नहीं बताई गयी । मैं गालिब के शेर के साथ अपनी बात खत्म करना चाहूंगा ।

तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूट जाना
कि ख़ुशी से मर न जाते अगर एतिबार होता

यह गालिब ने कहा है, इस सरकार का रवैया ऐसा है । जिस तरीके से कुंभ में अव्यवस्थाओं का हाल रहा, जिस तरीके से अर्थव्यवस्था का हाल है, पूरे देश का हाल है, इस पर सरकार को सोचना चाहिए । सरकार को सोच कर फैसला करना चाहिए कि अगर हम लोगों ने दीर्घकालिक नीतियां नहीं बनायीं, अभी कुछ साथी कह रहे थे कि कुंभ मेले में कहीं न कहीं साजिश है, षडयंत्र है । हर जगह आपको साजिश और षडयंत्र नजर आता है । आप अपने अंदर झांककर देखिए कि क्या कमियां थीं । कमियों को दूर करने का प्रयास कीजिए । आज पूरा प्रयागराज रो रहा है, प्रयागराज के लोग आज रो रहे हैं, इसलिए रो रहे हैं कि सरकार ने झूठे वादे किए थे कि हम भव्य तरीके से कुम्भ का आयोजन करेंगे, उसको करने में नाकाम रहे हैं इसलिए आपको देश से माफी मांगनी चाहिए । उत्तर प्रदेश सरकार और केन्द्र सरकार को जिसने लोगों को न्योता दिया, लेकिन सही तरीके से व्यवस्था नहीं की । इतनी बड़ी दुर्घटना अभी तक नहीं हुई । पूरा देश इसका संज्ञान लें, इस पर कोई न कोई कार्रवाई होनी चाहिए ।

SHRI SUNIL DATTATREYA TATKARE (RAIGAD): Hon?ble Madam Chairperson, today I rise to support and welcome the motion of thanks on the President?s Address. I am thankful for giving me this opportunity to speak. I also pay homage to Hon?ble Ex Prime Minister of India Shri Manmohan Singhji on behalf of my party NCP.

Madam, I am really pained to listen the speeches of opposition party leaders on the motion of thanks on President?s Address. I would like to thank our Hon?ble Prime Minister Shri Narendra Modi for upholding the democratic values enshrined in our constitution written by Dr. Babasaheb Ambedkar. Our Prime Minister was present in the House to listen leader of opposition and other opposition party leaders. But, unfortunately, the

opposition leaders showed the hatred towards our Prime Minister and crores of people have witnessed it.

Hon?ble President of India delivered her speech but later she was referred as poor lady by opposition leaders. Today, I want to protest against the treatment given by opposition leader to our President who belongs to a tribal community.

After independence, Shri Pandit Jawaharlal Nehru became the Prime Minister of India thrice since 1952. But, Smt. Indira Gandhi failed to secure power in continuation and could not become Prime Minister thrice. People of India have elected Prime Minister Narendra Modi for the third continuous term this time. Congress Party is still languishing in despair and disappointment.

Today, our party leaders are talking about One Nation-One Election. This is not a new concept. After independence, we used to hold National and State Assembly election at same time. But, this was disrupted in 1971 when Bangladesh came into existence Congress Party ruling at centre used to dismiss the State Government?s ruled by Opposition Parties.

I know about the policies and actions of Congress Party very well. How they behaved with Shri Sharad Pawarji you also know. Therefore, we have taken this decision to join NDA after knowing the reality of Congress Party.

In the year 1980, Choudhary Charan Singh Government had there at centre which was supported by Congress Party. Eventually they withdrew the support and mid-term Elections had to take place and Congress Party was responsible for it.

In the year 1989, when Shri V.P. Singh came to power but he had to resign after Mandal Commission Report implementation. Then, Shri Chandrashekhar Government came to power and Congress Party extended its outside support to it. Then, Congress Party again withdrew the support on petty issue and this country had to face midterm polls.

There is a provision of five-year term for Lok Sabha and State Assemblies in our constitution but, our country had to face many mid-term elections just because of Congress Party and today, they are talking about constitution. Later, in the year 1991, P.V. Narsimha Rao Government came

to power and continued for six long years. Even the Pulod Government, under the Chief Minister ship of Shri Sharad Pawar, was also dismissed by Congress Party when he opposed the leadership of Sanjay Gandhi.

Today, we need ?One Nation-One Election?, but, they are opposing it intentionally out of fear and insecurity. So, now it is clear that the Congress Party and its coalition partners in Maharashtra have not still been recovered of the shock and setback they received in assembly elections.

You secured a victory in Lok Sabha Elections and that time, you did not care for EVM, voter list, numbers of vote etc. You preached about a fake narrative of threat to our constitution throughout the country. I have been elected to this 18th Lok Sabha and I am proud of it. During Assembly Elections in Maharashtra, there were many contenders for the post of CM from Mahavikas Aghadi but, our CM Shri Eknath Shinde, Devendra Fadanvis and Ajitdada Pawar took some revolutionary decisions and faced the elections in a victorious way.*

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, मैं आपसे कहना चाहती हूं कि आप या तो अंग्रेजी भाषा में बोलिए या हिन्दी भाषा में बोलिए, क्योंकि कुछ तकनीकी दिक्कत है ।

SHRI SUNIL DATTATREY TATKARE: Yes, I can speak in English. That is not the matter, but the way in which the Leader of Opposition has insulted the people of Maharashtra?s mandate has made me decide to speak in Marathi.

It is pertinent to mention here that our Hon?ble Prime Minister came to visit the Raigad Fort of Chhatrapati Shivaji Maharaj twice. No other Prime Minister of India ever visited this place.

माननीय सभापति : आप हिन्दी या अंग्रेजी भाषा में अपनी बात रखिए ।

SHRI SUNIL DATTATREY TATKARE: The people of Maharashtra have given the mandate to the NDA. Still, the frustration of these people has not gone. Hence, the LoP has said so. Therefore, I am expressing my views in Marathi. I may please be allowed to speak in Marathi because all our Maharashtrians are just looking at my speech here.

*Somebody told here that all the voters from Himachal Pradesh were shifted to Maharashtra. But, this is not true Madam, I have been elected

from Raigad Lok Sabha Constituency once again and I have scored 50,000 more votes this time.*

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, कुछ तकनीकी खराबी है, इसलिए आप हिन्दी या अंग्रेजी भाषा में बोलिए ।

श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे : महोदया, मैं एक मिसाल देना चाहता हूं । I just wanted to give an example from my Raigad Parliamentary constituency. My Raigad Parliamentary constituency consists of four Assembly constituencies, namely Pen, Alibag, Shrivardhan and Mahad, and neighbouring Dapoli and Bhangar.

I just wanted to quote the figure of voters. Total voters in Pen were 3,01,427; in Alibag it was 2,93,832; in Shrivardhan -- from where my daughter got elected -- it was 2,59,822; and in Mahad it was 2,81,721.

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, आप हिन्दी या अंग्रेजी भाषा में बोलिए, क्योंकि कुछ तकनीकी खराबी है ।

SHRI SUNIL DATTATREY TATKARE: In Pen Assembly Constituency in Assembly election voting done was 3,07,979. Nearly, 6,000 votes were increased as the Election Commission had conducted a Special Drive to increase the votes for those who had completed 18 years. Hence, only 5,000 votes were increased in the Assembly constituency.

My daughter?s constituency, from where Mr. A. R. Antulay happened to be the Chief Minister of Maharashtra, he was the founder when Indira ji had formed the Indian National Congress. He was the General Secretary at that time and at the end of his political career I know who has done what. So, I do not want to say anything about it. In her constituency the voting was 2,65,286.

18.00 hrs

There was an increase of 6000 votes. महाराष्ट्र का निर्माण वर्ष 1960 में हुआ था । स्वर्गीय चव्हाण साहब मंगल कलश शिवाजी पार्क के ऐतिहासिक पार्क में लेकर गए थे । वर्ष 1962 से लेकर वर्ष 1967, वर्ष 1972, वर्ष 1978, वर्ष 1980, वर्ष 1984, वर्ष 1990, वर्ष 1995, वर्ष 1999, वर्ष 2004, वर्ष 2009, वर्ष 2014, वर्ष 2019 तक ? (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, एक मिनट रुकिए माननीय सदस्यों, मेरे पास एक लंबी सूची है । अत: सभा की सहमति हो तो सभा की कार्यवाही 10 बजे तक के लिए बढ़ा दी जाए ।

अनेक माननीय सदस्य : हां ।

SHRI SUNIL DATTATREY TATKARE: Though the Congress was the single largest party in the State, such kind of alliance never got a glorious victory with a huge figure of votes in Maharashtra but this is the first time in the history, the people of Maharashtra have given such a glorious mandate to NDA in Maharashtra. They are still in a dilemma. They cannot digest the election result. That is why they are making allegations against the Election Commission and the EVM machine. When they won with the same EVM machine, that was a mandate of the people, and when they lost miserably, they said it is an EVM game.

माननीय सभापति : प्लीज, अपनी बात कंप्लीट कीजिए ।

? (*Interruptions*)

SHRI SUNIL DATTATREY TATKARE: No, that is not true.

Today, we are standing tall on our own and not because of Congress Party. We strengthened our party, so please do not try to teach us.

I have been in politics for the last 40 years. So, please do not teach me. Our Prime Minister Narendra Modi is a world class leader and he belongs to OBC category. I also belong to a very small OBC community. I am an only member of my party. I am thankful to Hon?ble Home Minister Shri Amitbhai Shah for nominating me as a Chairman of Petroleum and Natural Gas Committee.

You are saying that trade, business, industries and major projects have been shifted to Gujarat but Shri Narendra Modi ji has sanctioned a mega Refinery project in Maharashtra and you were opposing it.

It is going to provide employment to the unemployed youths of Konkan Region. You have been rejected by people of Maharashtra as you have committed a sin of opposing it.

Lastly, I would like to congratulate our President of India and Prime Minister Shri Narendra Modi too for taking India on the path of overall and inclusive progress. Very soon, we are going to become the third largest economy in the world. But, the opposition parties are not happy with it.

I would also like to mention here that there is no threat to our constitution because it is eternal. Our Prime Minister relentlessly trying to strengthen our country through our constitution.

Once again, I support the motion of thanks on the President?s Address and conclude.

Jai Hind.

Jai Maharashtra.*

श्री वीरेन्द्र सिंह (चन्दौली) : धन्यवाद अधिष्ठाता महोदय, मैं वीरेन्द्र सिंह, सांसद, लोक सभा क्षेत्र चंदौली, उत्तर प्रदेश, समाजवादी पार्टी की तरफ से महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा सदन में दिए गए अभिभाषण पर कुछ सुझाव और संशोधन रखने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

महोदया, हमने पूरी तन्मयता से महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण को सुना । उनके अभिभाषण में यह होना चाहिए था कि देश किस दिशा में और किस तरीके से प्रगति करेगा । लेकिन अफसोस है कि केवल पुरानी बातों को दोहराने के अलावा महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में बहुत कुछ देखने को नहीं मिला । महामहिम राष्ट्रपति ने किसानों की आय कैसे बढ़े, इस संदर्भ में अपने अभिभाषण में पूरी तरह से खुलासा नहीं किया । इस देश के किसान की आमदनी को कैसे बढ़ाया जाएगा, इसकी कोई ठोस योजना उनके अभिभाषण में नहीं थी । किसानों के द्वारा उपयोग की जाने वाली खाद, बीज, दवाइयां कैसे सस्ती मिलें, कृषि यंत्रों पर जीएसटी कैसे कम हो, जिससे किसानों को लाभ मिल सके । किसानों द्वारा लिए गए ऋण से कैसे माफी मिलेगी, इसका कोई जिक्र उनके अभिभाषण में नहीं था । सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो बटाईदार किसान हैं, जो बड़े किसानों से जमीन ठेके पर लेकर खेती करते हैं और दैवीय आपदा और तमाम कारणों से उनकी फसलें नष्ट हो जाती हैं । लेकिन इस सरकार के पास उनको राहत देने के लिए कोई उपाय अभिभाषण में नहीं था । मैं मांग करता हूं कि बटाईदार कृषि मजदूर हैं, उनकी भलाई के लिए, चाहे बीमा का सवाल हो, चाहे किसान की खेती करते समय मृत्यु का सवाल हो, उनके परिवार के भरण-पोषण को सरकार गंभीरता से ले । उनके लिए कोई ठोस योजना सरकार को बनानी चाहिए ।

महामहिम राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कुंभ में मृतक श्रद्धालुओं के प्रति संवेदना तो व्यक्त की लेकिन तमाम ऐसे श्रद्धालु जो अपने घरों से पुण्य की प्राप्ति के लिए प्रयागराज गए थे, लेकिन आज भी हजारों की संख्या में वे लापता हैं, उनके परिजन परेशान हैं और उनकी कोई सुधि यह सरकार नहीं ले पा रही है और न ही उनकी कोई खोज हो पा रही है । मैं बनारस का रहने वाला हूं । हमारे बनारस के सांसद इस देश के प्रधान मंत्री हैं, लेकिन अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि करीब हजारों-लाखों की संख्या में बसों के जरिए करोड़ों ऐसे श्रद्धालु थे जो प्रयागराज से लौटकर काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए आते थे । आस-पास के जिलों से स्नान करने के लिए और बाबा के दर्शन के लिए घरों से चले थे, वे करीब तीस घंटे तक रिंग रोड पर इंतजार करते रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश की असंवेदनशील सरकार ने उनकी कोई सुधि ली । उनके खाने-पीने और बच्चों के लिए दूध का इंतजाम भी नहीं किया, जिसके कारण हमारी माताओं-बहनों को बहुत ही बुरी

स्थिति में समय गुजारना पड़ा । यह सरकार इतनी असंवैदनशील है कि वह इसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहती है और न ही उनके बारे में कोई सुधि लेना चाहती है ।

सभापति महोदया, मैं जनपद चंदौली से आता हूँ । जनपद चंदौली आज से 27 वर्ष पूर्व बनारस का अंग हुआ करता था । 27 वर्ष पूर्व उसे अलग जनपद के रूप में स्थापित किया गया, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे जनपद चंदौली में न तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, न न्यायालय भवन है, न वहां पर अधिवक्ताओं के बैठने के लिए जगह है, न वहां से आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है और न ही वहां के स्टेशनों पर कोई ट्रेन रुकती है । इसलिए मजदूर और किसानों को बड़ी कठिनाई और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ।

सभापति महोदया, आप जानती हैं कि जनपद चंदौली आकांक्षी जिले में चयनित हुआ है । माननीय प्रधान मंत्री जी ने हमारे जिले को विशेष जिले का दर्जा दिया है । हमारे जनपद का आधे से ज्यादा क्षेत्र वनवासी और आदिवासी बहुल का है । आप सब जानते हैं कि आदिवासी और वनवासी क्षेत्रों में खेल के प्रति तमाम प्रतिभाएं उन लोगों में छिपी रहती है, लेकिन संसाधन के अभाव में उनकी प्रतिभाएं देश के काम नहीं आती हैं । मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि उसका ध्यान मेरे जिले की तरफ आए और उन लोगों की प्रतिभा का निखार हो । उन्हें चिह्नित किया जाए और वहां पर उनके लिए एक अच्छा सा स्टेडियम बनाया जाए, ताकि वे देश में अपनी सेवाएं दे सकें और देश का नाम भी रोशन कर सकें । सन् 1947 में जब यह देश आजाद हुआ तो खाद्यान्न की कमी को दूर करने के लिए हरित क्रांति की योजना लाई गई और जनपद चंदौली में जितने भी क्षेत्र हैं, वहां पर नहरों का जाल, पम्प, कैनाल आदि बनाए गए । वे उसी समय बनाए गए थे, लेकिन अफसोस की बात है कि आज तक उन नहरों की मरम्मत नहीं हुई है । उन नहरों की हालत बहुत जर्जर है । उस जर्जर हालत में सिंचाई ठीक तरह से नहीं हो पाती है । हमारा देश कृषि प्रधान देश है, लेकिन किसानों की स्थिति बहुत खराब है ।

मैं सरकार का ध्यान स्वास्थ्य के क्षेत्र की तरफ भी आकर्षित करना चाहता हूँ । हमारे जनपद में एक बाबा कीनाराम मेडिकल कॉलेज है, लेकिन अफसोस की बात है कि न तो वहां पर अस्पताल है, न ही योग्य डॉक्टर्स हैं और न ही किसी तरीके से इलाज होता है । वहां 80-80 किलोमीटर दूर तक ग्रामीण क्षेत्र है । वहां आकस्मिक इलाज की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण उनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है ।

मैं माननीय सड़क परिवहन मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बड़ी-बड़ी सड़कों की घोषणाएं तो की हैं, लेकिन जनपद चंदौली से कोई सड़क नहीं जाती है । मैं सरकार से मांग करता हूँ कि कृषि पर आधारित उद्योग यदि वहां पर लगाए जाएं, एक गन्ना चीनी मिल लगाई जाए तो निश्चित रूप से किसानों को उससे लाभ होगा और नौजवानों को रोजगार भी मिल सकेगा ।

मैं सदन का ध्यान एक और विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई में हमारा जनपद वाराणसी पिसता जा रहा है, क्योंकि बनारस से होकर एक भी एक्सप्रेस वे नहीं गुजरता है । वहां गोरखपुर के लिए लिंक रोड बनी है । हर जगह के लिए एक्सप्रेस वे बना है, लेकिन बनारस जनपद, जो कि प्रधान मंत्री जी का क्षेत्र है, वहां से कोई एक्सप्रेस वे का लिंक नहीं बना है । मैं मांग करता हूँ कि बनारस को अयोध्या से जोड़ने के लिए एक ग्रीन रोड, एक्सप्रेस वे का निर्माण करवाया जाए, ताकि जो श्रद्धालु बनारस आएं, उनको उसका लाभ मिल सके और पर्यटन को भी बढ़ावा मिल सके ।

मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ । मैंने जितनी भी बातें कही हैं, वे जनहित की बातें हैं और माननीय मंत्री जी सरकार के द्वारा इन मुद्दों पर काम करेंगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ ।

SHRI E. T. MOHAMMED BASHEER (MALAPPURAM): Thank you very much, Madam. On behalf of my party, Indian Union Muslim League, and on my own behalf, I express my *shradhanjali* for the sadful demise of a large number of brothers, sisters and kids.

Coming to the Motion of Thanks, there is nothing substantial in this. It is superficial and far away from the Indian reality. Most of the points are reproduced from the websites of the various Departments. There is nothing important in it. As far as development is concerned, there is a definition in the speech which I would like to reproduce, and I quote:

> ?Development is truly meaningful when its benefits reach the person standing at the last rung of society.?

It is a correct definition. But I would like to ask whether there is any kind of honesty in your saying. There is nothing like that. I understand that even though we have said so many things, we have forgotten the ill fate of the downtrodden section and the marginalised section of the society. When we are measuring the wealth, the progress, and the prosperity, we are aiming at the upper class, the multinationals and things like that. Poor people, who are living below the poverty line, have not been considered properly in that. Regarding Emergency also, you have given an emphasis. You are saying about 1975 in your speech. You have said about Emergency. But you have conveniently forgotten that undeclared emergency is continuing in this country during your period. That is happening. I do not want to go into the details of it.

Similarly, what is happening in the country now? The entire democracy is at the doldrums. Take the example of the Parliament. This House is having a glorious tradition. Unfortunately, what is happening? Law-making in this House has become a mockery. That is for victimisation. That kind of thing is going on. Similarly, the Executive is in a deplorable condition. Judiciary also is moving like that. There is a lot of criticism about the credibility of the Judiciary also. Similar is the case with the freedom of expression, freedom of the media. All these things are condemnable; that is what is happening in our country now.

My complaint is small one. You have not even mentioned a single word, a single sentence about the minorities in this country. Why have you forgotten them? What is their ill fate? You have to realise what is happening in this country. Legislations are made against them. For them only, legislations are coming. There are many examples. I do not go into it. What is happening? The topmost leaders in this country have been put in jails just before the election by fabricating stories against them. That is happening. Similarly, activists, environmental activists, student leaders, media persons and cultural leaders were put behind the bar without any reason, for political reason only. Is it not a shame for this country? There are these kinds of things which should be curtailed.

There are atrocities against the minorities. What is happening in this country? They are demolishing the houses. People are thrown to streets. In North India, that is happening. In UP, that is happening. Nobody is there to question this. Similarly, in the name of cow protection, how many people are killed in this country? There is nobody to question it. You are saying wonderful things. But this country is getting a bad shape. It is going from bad to worse. Those kinds of things are going on. In seven States in the country, they have made their own legislation. What is anti-conversion? There is a provision in the Indian Constitution, Article 25. When that is there, what is the *locus standi* of the States, except with the BJP?s blessing, to have this kind of a legislation. Those kinds of things are going on. Actually, the Government is watching as a silent spectator. All these kinds of things are going on. They are not reacting.

Why is it so? That is with the blessing of the Ruling Party.

Madam, I do not want to go into the details. Now, I come to Waqf Act. What is this for? The Waqf Act is only to victimise the minorities. There is nothing more than that. The Home Minister has already declared that the Government will go for Uniform Civil Code and that kind of things. You are talking about unity. It has been mentioned in the speech. But instead of unity, you are developing enmity in this country. You have to realise one thing that in this country, you are taking a partisan attitude. It is a very sad thing.

I am quoting from the President?s Address. It says, ?A significant measure of ?Viksit Bharat? is balanced development of the country. No region should feel left behind in the journey of progress?. It is a beautiful sentence. But is there any iota of truth in dealing with all these things? You have no moral right to talk about the unity.

HON. CHAIRPERSON : Please conclude.

SHRI E. T. MOHAMMED BASHEER : Madam, I am concluding.

When you are talking about balanced development and when you are distributing the wealth, programmes, projects, etc., are you giving justice? There also there is a partisan attitude. I would like to say one thing. In the southern end of India, there is a beautiful place; a tiny place; a green State, which is Kerala. That is my own home State. Are you aware of it? Your plans; the speech of the hon. President; and your Budget, are totally ignoring the State. I express my vehement objection to this negative stand taken against Kerala.

Madam, now, I am going to conclude. We have to understand one thing. Towards the end, I would like to say one more thing which is about Haj. I met the hon. Minister, who is the incharge of Haj. Calicut is the biggest embarkation point for Haj. After U.P., Calicut is the biggest embarkation point. Cochin, Kannur and Kozhikode are embarkation points. The flight charge at Kozhikode is above Rs. 40,000. What is the justification? They are going for a good thing. They are victimised. You have to find out a solution for that. I met the hon. Minister. I am really thankful to him. He had given me a sympathetic response.

What I am saying is that there may be politics; there may be ideas; there may be ideologies; and there may be a fight over an ideology, but

justice should be ensured. That is what is lagging behind in this country now.

Through you, Madam, I once again request that justice should be given. The minorities are denied justice. There must be justification for these kinds of activities also. There should not be a denial of justice.

With these few words, I conclude.

Thank you very much.

DR. ANGOMCHA BIMOL AKOIJAM (INNER MANIPUR): Thank you, Madam Chairperson for the time and for allowing me to take part in this discussion on the hon. President?s Address in this House.

Very honestly speaking, I was expecting the President?s speech to mention something on Manipur because I thought that the Government will outline through her speech the steps being taken by the Government of India to deal with the issues and this tragedy that we have been witnessing in my home State. But call it arrogance or a reflection of a peculiar form of ?*Rastriya Chetna*? followed by the Ruling Party, they have chosen to remain silent in an effort to make the crisis invisible to the rest of the country as well as to the globe. So, I expect, Madam Chairperson, to give me a little more time than the usual so that I can register the pain and anguish of the people of my State, in particular, and those fellow countrymen who are worried about the happenings in my home State. It is my sincere appeal to you. Please do give me some extra time.

The President?s speech says that the Government is trying to take along all these people; an inclusive and an all-encompassing approach based on the principle enshrined in the Constitution.

But the fact of the matter is this Government and their ideological moorings clearly do not believe in inclusive politics. I say this for one reason not only for what has happened vis-à-vis with the Manipur crisis and the manner in which the Government of India have responded but also generally the manner in which they have tinkered the Constitution principles and the manner in which they have imagined this nation to be. Their attitude and response to Manipur is nothing but a specific form of reflection of their general conception of what this nation is all about.

Then, we start with a particular tinkering that this Government has done which we do not see. Babasaheb Ambedkar said we have this document now but how we inject flesh and blood to the soul, to this document, is what matters through our practice, what has been happening since the last ten years. Like all liberal Constitutions, we have this beautiful phrase in our Preamble called ?We the people? and this ?We the people? is like old liberal Constitution that conceptualized the population. The nation has a stratified population. But this Government is pushing for a kind of imagination of a nation which is cultural and organic in nature. When the Prime Minister took over in 2014, he has said that on many occasions across many platforms in the West, in UK, UAE, Netherlands or in various meetings in this country. He invoked a very familiar phrase that we have seen in the Nazi Germany in the 1920s and 1930s, that is, *Blut-und-Boden ?*Blood and the soil?. He said in his speech in Wimble as well as in Netherland or UAE or in my part of the world in Silchar. He asks whether one should be given emphasis on the colour of the passport or the colour of the blood or in our relation to the soil. This invocation of the blood and the soil is what the Nazis have shouted in the 1920s and 1930s. It is these conceptions of the people of this country that lead to various exclusions. So, there is no surprise that today we have a party which swears by nationalist ethos and you have none of the Members from the Muslim communities which constitute 15 per cent of the population. That is the reflection of that imagination of the nation. It is a similar kind of an exclusion that you have continued through your response through the crisis in Manipur.

Allow me to cite four specific issues that tell you that the crisis in Manipur is not an isolated issue. Its gravity is such that it is a national crisis. Let me explain the four specific issues. Under the Indian Constitution, we have the State Government and the Assembly which has been reduced to a farce. We had the shortest Assembly session in August 2023 which barely lasted less than half an hour. Instead of discussing the crisis, the Assembly was cut short. The Government of Manipur openly claims that its power has been shrivelled by the Union Government. We do not know who is in charge of this State of Manipur. The leaders of the

Government in the State say that the police did not report to the hon. CM and the Home Minister. To whom are they reporting then? And the appointment of big officials to deal with law and order, such as the Chairman of the Unified Command which takes care of the security and law and order situation and coordinates with the various security agencies, has been done away and they appointed some ex-bureaucrat from the Centre.

For instance, the CM says that some part of Manipur is under my command and some part of the State is under the command of the Union Home Minister. Can you tell the Chief Minister of Maharashtra that Mumbai is under my control and the rest of Maharashtra is under the control of the Union Government? That is an illegal subversion of the Constitutional mechanism and democracy in this country in the 75 years of our experience. That is the subversion that we have experienced. We do not realize this. The Chief Minister orders something. The Central Security Forces refuses to obey the order.

There are images where the Central Armed Police Forces stopped the Manipur Police from responding to armed attacks on innocent villagers. We witnessed this complete chaos in the 75th year of our Constitution on which we have been given lectures in this House as well. It is a reality which is happening in Manipur. But who cares?

You have sent 60,000 plus troops there. Under whose command those troops are working? If Article 355 or Article 365 has been invoked, where is the written document? There is nothing of that kind. So, it is an extra constitutional subversion of the Constitution of our country in a State called Manipur. The Indian state has become nothing but a ... * in the State of Manipur.

Madam Chairperson, have you ever seen elected Members being beaten up publicly in this country and the country thinks that constitutional order is in order in Manipur? The dignity of the elected Members, the authority of the Assembly ? everything has been subverted by this Union Government in collusion with their satraps who are running the show on

their behalf in Imphal. Please keep in mind that this is a complete subversion of a constitutional order on the 75th year of our Constitution.

Incidentally, this has happened not for the first time in Manipur. When the Constitution was adopted 75 years ago, we had an Assembly of our own and a constitutional monarchy which was bulldozed on 15th October, 1949. That insult should be bygone and we should look forward. But the manner in which the crisis has been handled and the contemptuous manner in which this has not been talked about even in our hon. President?s Address is making us to remember that humiliation once more as we are trying to look forward. This is the most saddening and unfortunate part as we are celebrating the 75th year of our Constitution.

When Babasaheb Ambedkar was asked, which Article in the Constitution do you think is the most important one? He pointed out Article 32 and said that this Article is the soul and the heart of the Constitution ? (*Interruptions*) Madam, I have seen people getting more time. Please give me two or three minutes more.

Habeas Corpus under Article 32 is one of the legal rights which the citizens have. But in the most secured place in Manipur, the Red Shield Division, 57 Mountain Division, an army garrison, a civilian, called Laishram Kamal Babu, disappeared without a trace since last November. The Defence Minister kept quiet; the Army Chief kept quiet. How secured are the people of Manipur even when you are not secured in the military garrison, the biggest army headquarters, 57 Mountain Division in the State of Manipur? Who will answer this?

I am elected by my people and I am supposed to voice in this House as a part of a democratic culture, as a part of a constitutional scheme of things. Now, how do I speak? People have been killed. Children and women have been assaulted. We have seen the situation of hostage. Women and children were not only taken hostage but they were killed in cold blooded manner and in a most gruesome manner in Jiribam including an 8-month-old infant. The post-mortem report is a chilling reminder. People have been killed in gruesome manner throughout this 21-month-old crisis. This kind of hostage and killing has never happened.

I, as an MP, cannot go to some parts of Manipur. Where is my right to free movement which comes under Article 19? People are not able to go everywhere. The Chief Minister himself cannot go to certain places. Some MLAs belonging to tribal groups cannot come and attend the Assembly and we think that Article 19 is working in the State of Manipur and we are celebrating 75th year of the Constitution! Where is Article 19?

Madam Chairperson, there are still thousands and thousands of people in relief camps. Partition is a living reality in the State of Manipur and we think the constitutional order is intact in the State of Manipur!

I have been hearing our ministers and leaders saying that Kukis and Meiteis should talk to each other. Have you ever heard, when the communal violence happens, Hindus and Muslims should talk to each other? It is the responsibility of the State. First, you should rein in the violence. The authority of the Indian State has been challenged by armed groups. Many of them have been propped up by the Indian security agencies, as many observers have pointed out. Many of these Kuki armed groups are under Suspension of Operations (SoO). They have been propped up by Indian security forces, and, unfortunately, on media you see BJP entering into an understanding with them to win elections. Now, they are playing havoc. They are running wild.

Similarly, in the valley areas, there are armed groups which are reportedly nurtured by political leadership from the Ruling Party. This is where the Government wanted to keep silent. The Government does not want the rest of the country to know about this. Hindus and Muslim conflict in India was a product of a colonial process during the Britishers time. It is not inherent in our country. Many scholars have written this. The Government should not essentialize this conflict. It is a part of a colonial State process. Unfortunately, while we are talking about decolonization, and trying to change the law created by the British, we are talking like the Britishers saying that this is an essential conflict between the Hindu just like the Britishers have done as if the Kukis and the Meiteis have an essentialized conflict. It is a product of a State process. We need to decolonize our mind.

Last but not least, we talk about progress and development in Viksit Bharat. I must inform the House that the highest inflation rate in the country today is in the State of Manipur. All the small-scale, medium, micro-entrepreneurs have shut down. We are losing investment. People are losing jobs. In unemployment rate, Manipur is among the top five States in this country. We talk about the Eastern States. Many of the Eastern States including Andaman are in the list of the top ten States where most of the people are unemployed in this country. You are not talking about this economic crisis. There is no relief, tax or otherwise. You are trying to push it under the carpet as if nothing has happened.

Despite all this, you know what happened. People are not able to travel because of this communal violence. The flight fare is soaring to the sky. They are looting the tragedy-stricken people. A flight fare from Delhi to Kolkata is around Rs. 6,000, which is a two-and-a-half hours journey, but a flight from Imphal to Kolkata is around Rs. 13,000 or Rs.14,000. It has been going on for the last 20 months. The Government of India is not interested in that.

The Government thinks that we are talking about Manipur as if it is an exception. I want to end with this remark. The Danish philosophers have reminded us. Søren Kierkegaard said: ?If you want to understand the general, pick up an exceptional, true exception. Because the exception will explain the general as well as the exception itself.? If you want to understand what this country is and how it is imagined, how this constitution is working, and how it is being lied to the rest of the country, take Manipur as an exceptional case. The moment we are honest about it; the Government will be able to answer. We think that alienation of the North-East people will be okay, but the Government should check how the youth are asking about the relationship between India and Manipur because of this crisis. It is a danger written on the wall, and I draw the attention of all our Members cutting across party lines to please respond. We need a JPC to inquire into this crisis and do justice to the people of the State of Manipur.

Thank you, Madam Chairperson.

SHRI BALASHOWRY VALLABHANENI (MACHILIPATNAM): Madam, thank you for giving me an opportunity to extend my thanks to the President of India for her Address.

It was indeed a pleasure to listen to her speech. The hon. President spoke at length about the collective achievements of the Government during the last one decade, and has given a roadmap of what is going to happen in the coming years. I, on behalf of my party under the leadership of Shri Pawan Kalyan garu, strongly believe that hon. President?s speech is a visionary blueprint of the country?s path towards building a Viksit Bharat.

The hon. President has highlighted various initiatives, programmes and schemes of the Government. This Government is committed to give ? Housing for All?, particularly poor and economically weaker sections of this society with Rs. 5 lakh crore plus budget for the scheme.

Madam, it is one of the great initiatives taken by the NDA Government through which many families have been benefited till date. The NDA Government will continue to run this programme.

Madam, the financial assistance to our entrepreneurs through MUDRA scheme have been increased to Rs. 20 lakh from Rs. 10 lakh. As we all know with rising population, unemployment is becoming one big concern in the country. With such schemes, more and more youth are attracted to become self-sufficient.

Madam, I only wish to focus on two issues. The first is, interlinking of rivers. Firstly, I would like to speak regarding the Godavari-Banakacherla Interlinking of River Project. In Para 19 of her Address, the hon. President has mentioned about the importance of interlinking of rivers. As we all know, water is a big concern for every State, particularly drinking water and irrigation water. There is a drought like situation in many States during summers. This has to be taken up very seriously and immediately. The hon. President has rightly mentioned about it in her speech.

Madam, I come from Andhra Pradesh, and we have understood its importance. One such interlinking project in Andhra Pradesh also needs to be taken up. This would provide irrigation to new ayacut of three lakh hectares, stabilizing 9.1 lakh hectares of area. Importantly, it will provide

drinking water to 80 lakh people of Uttarandhra and Rayalaseema districts, and 20 TMC water for industrial use. This project links Godavari and Krishna rivers and gives immense benefits.

Madam, this interlinking is needed, because Krishna River does not have reliable inflows due to excessive use by upstream States and full utilization by the Krishna Basin States. But Godavari has reliable inflow, and it is very unfortunate that nearly 3000 TMC of average water flows into the sea every year. It means, 3000 TMC of water is going waste, which is unacceptable. So, to address the irrigation and drinking water needs of the whole State of Andhra Pradesh, Krishna Delta, Uttarandhra and Rayalaseema, the Government of Andhra Pradesh has proposed to divert Godavari flood waters of 200 TMC at 2 TMC per day from Polavaram to Banakacherla regulator to overcome drought in the State. The project is proposed in three Phases. One is, Godavari River to Krishna River; second is from Krishna River to Bollapalle Reservoir; and the third is from Bollapalle Reservoir to Banakacherla Regulator. The cost of the project is estimated to be Rs. 80,000 crore. Andhra Pradesh has successfully linked Vamsadhara and Nagavali Rivers, and now there is a need to take up the Godavari-Banakacherla Link Project.

The hon. Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri Chandrababu Naidu, and the hon. Deputy Chief Minister, Shri Pawan Kalyan Garu discussed about this project with the Minister concerned in the Government of Andhra Pradesh. So, I appeal to the hon. Prime Minister and the hon. Finance Minister to approve this Project and provide required funds in the form of grant to complete this project which would make Andhra Pradesh drought-proof State in the country.

Madam, secondly, I would like to talk about cyclones which occur more often in Andhra Pradesh. My entire Lok Sabha Constituency of Machilipatnam in Krishna district is prone to floods, and cyclones have become the order of the day.

I still remember the 1977 Super Cyclone, which hit Diviseema and devastated the entire Krishna delta region. Thousands of people lost their lives and properties. Whatever cyclone shelters are there, they are old and have got damaged. Therefore, I appeal to the hon. Prime Minister, who is

also the Chairman of the NDMA, to get the new cyclone shelters constructed in Machilipatnam and Diviseema regions. It will help the people of those areas.

Finally, before I conclude, I would extend my thanks to our leader Shri Pawan Kalyan Garu and every *karyakarta* of my Jansena Party to walk over the NDA *mantra* ? *Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Prayas.* I believe that we will definitely achieve our dream of *Viksit Bharat*.

Thank you, Madam. Namaskar.

SHRIMATI MALVIKA DEVI (KALAHANDI): Thank you, Madam, for giving me an opportunity to speak on the Motion of Thanks on the President's Address. Today I would like to begin my speech by saying that I come from Odisha from where our hon. President comes. वे ओड़िशा की लड़की हैं, ट्राइबल कम्युनिटी की लड़की हैं, भारत की लड़की हैं । I just feel one thing that whenever we say something against anybody, it is not that you are raising a finger only at a person, a lady, but you are actually questioning 140 crore Indians, which is not right because she has come and really worked hard and has reached a position which is the highest position in the country. We should be respecting her for that, looking up to her for that. She has come from adverse situations and shown the world where she is today. She is respected all over the world. It is sad that people in our own country, in our own Parliament are not showing the same respect that the world shows her today.

I would also like to say that the enthusiasm with which she started her speech is the same enthusiasm with which she ended the speech, speaking for one hour. For one hour, our hon. President spoke about all the development works that happened in 10 years after 2014. अगर ये सब काम वर्ष 2014 से पहले हुए होते तो यह उनकी स्पीच में आता, पर कुछ हुआ ही नहीं था, तो वर्ष 2014 के बाद जितने काम हुए, उनको बार-बार दोहराना जरूरी है । अगर कोई गौर से सुने, तभी पता चलेगा कि नम्बर्स बदल रहे हैं, नम्बर्स बढ़ रहे हैं । जीडीपी बढ़ रहा है । भारत का सब कुछ बढ़ रहा है, पर काश कि सब यह बात समझ पाते और सोच सकते!

Modi ji's dream of *Viksit Bharat*, which was never a dream for anybody before 2014, is a dream today, and it is a dream which is being fulfilled in every aspect of the world. अगर हम प्रधान मंत्री आवास योजना की बात

करें, an amount of Rs.5,36,000 crore has been allocated in it. अगर हम पी.एम. किसान सम्मान निधि स्कीम की बात करें, an amount of Rs.41,000 crore has been given to it in the recent months.

स्मॉल ऑन्त्रप्रेन्योर्स के लिए मुद्रा स्कीम जो पहले 10 लाख रुपये की थी, वह अब बढ़ कर 20 लाख रुपये हो गयी है । पर, हम इन सब चीजों पर क्यों नहीं गौर करते? इसलिए हमारी राष्ट्रपति जी के लिए जरूरी है कि वे हमें बार-बार यह याद दिलाएं कि यह सब काम भारत में हो रहा है ।

In Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, an amount of Rs.70,000 crore has been spent to connect about 25,000 habitations. This kind of work has never happened before. A total of 71 Vande Bharat, Amrit Bharat, Namo Bharat trains have been started. Out of the new 71 Vande Bharat trains that have just been started, एक वन्दे भारत ट्रेन मेरे कालाहांडी में स्टार्ट हुई है, जो खरिअर रोड से केसिंगा जाती है । वे दो स्टेशंस मेरे ही ओड़िशा में हैं । ?विकसित भारत? का सपना पूरा हो रहा है । We are living in a world where we are going to see *Viksit Bharat*, Modiji's dream of Viksit Bharat.

मैं ओड़िशा से हूं, जहां पहले लोग शौचालय के लिए बाहर जाते थे, पर आज वहां पर भी बाथरूम्स हैं । वहां लेडीज़ जाती हैं । उनका आज ध्यान रखा जा रहा है ।

हमारे प्रधान मंत्री जी ही केवल एक ऐसे आदमी हैं, जो गरीब, महिला और किसानों के बारे में सोचते हैं । उन्होंने सबके बारे में सोच कर ही काम किया है, सिर्फ अपने बारे में सोच कर अपने परिवार के बारे में सोच कर काम नहीं किया है । उड़ान स्कीम जो ओडिशा में भी है, कालाहांडी में भी है, केसिंगा में है, उत्काला में है, आज 1.5 करोड़ लोग उड़ान योजना के तहत हवाई यात्रा कर पा रहे हैं । जन औषधी केंद्र खुले हैं । नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में 91 लाख सेल्फ हैल्प ग्रुप्स को एम्पलॉयमेंट मिला है । नारी शक्ति वंदन अधिनियम की वजह से आज हम सब महिलाएं लोक सभा में हैं और हम अपनी बात को आगे रख पा रही हैं । ड्रोन दीदी योजना से सब लोगों को फायदा हुआ है । चाहे वह ड्रोन दीदी हो, चाहे वह जेट फ्लाइट्स की पायलट हों, आज लेडीज़ यहां से ले कर वहां तक पहुंची हैं, क्योंकि प्रधान मंत्री जी यह चाहते हैं । वे चाहते हैं कि पूरा भारत विकसित बने । सभी क्षेत्र विकसित हों । 10 लाख परमानेंट जॉब्स दी गयी हैं । One crore youth is being provided hands on experience with real kind of work environment. 1.5 लाख स्टार्टअप्स किए गए हैं । खेलो इंडिया टार्गेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, ये कुछ चीज़े हैं, जो मोदी जी ने की हैं । बहुत सारी चीजें हैं, जिनके बारे में मैं नहीं बोलूंगी, नहीं तो शायद कोई बोले कि आपकी स्पीच बहुत बोरिंग है ।

10 हज़ार से ज्यादा अटल टिंकरिंग लैब्स, रिसर्च फाउंडेशंस, 10 हज़ार करोड़ रुपये हमारी विज्ञान धारा योजना पर खर्चा किये गये हैं । आर्टिफिशल इंटेलिजेंस, इंडियन एआई मिशन के बारे में बात हो रही है । बायो इथ्री पॉलिसी को किया गया है, जो बायो को बूस्ट करती है । वन नेशन वन टैक्स ? जीएसटी लाया गया है । मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया आगे बढ़ रहा है । आज कई चीज़ों पर मेड इन इंडिया लिखा जाता है, क्योंकि सबने ग्लोबली हमें पहचाना है । We have been recognised globally, which is a very big thing for us today. Earlier, we only imported and there was nothing which said, ?Made in India?, but today we have products which say, ? Made in India?. There is launch of 5G services in India along side other leading nations. More than 50 per cent of the world?s real-time digital transactions now take place in India.

Hon. Members, the first deep water mega port at Vadhavan worth Rs. 76,000 crore has been approved. An amount of Rs. 28,000 crore has been approved to establish 12 industrial nodes. There are Metro projects in Delhi, Pune, and everywhere. The Metro network has now crossed the milestone of 1,000 kilometres. The Government is providing affordable, accessible, and quality healthcare to everybody. There are about 1,75,000 Ayushman Arogya *mandirs*. Several cancer drugs have been exempted from customs duty. Nine crore women have been screened for cervical cancer. As regards TB eradication, TB was a big problem in Odisha, especially in Kalahandi. I am very happy to say that मोदी जी जिस हिसाब से टीबी इरैडिकेशन पर काम कर रहे हैं, वह पहले कभी नहीं हुआ ।

In 2023-24, India achieved a record production of 332 million ton of food grains. The Minimum Support Price for Kharif and Rabi has gone up. Rice, wheat, pulses, oilseeds, all have tripled. The release of 109 climate-resilient bio-fortified, high yielding advanced crops have been done. There is packaging for ensuring availability of DAP for everyone. Mission Mausam has been launched. The Government has undertaken initiatives to preserve tribal heritage. This year, 150th birth anniversary of Bhagwan Birsa Munda, which was only known in Odisha earlier, is now being celebrated across the country as Janjatiya Gaurav Varsh. ये सब छोटी बातें नहीं है । ये बहुत बड़ी बातें हैं, जो मोदी जर के कार्यकाल में ही मुमकिन हुई हैं । After the abrogation of Article 370, Jammu & Kashmir is facing new life today.

इलेक्शंस नहीं हो सकते, यह नहीं हो सकता है, वह नहीं हो सकता, यह सब कहा गया । आज जम्मू-कश्मीर में सब कुछ हो पा रहा है । वह भी मोदी जी का ही सपना था ।

One crore diyang ID cards have been given. Namaste yojana has been launched. We are strengthening self-reliance, self-employment by establishing a defence industrial corridor. There is Atal tunnel, Sela tunnel, and Sonamarg tunnel. Elimination of left-wing extremism has also begun.

Our Bharat is a country of 140 crore people. We have diverse States, diverse regions, diverse languages, yet as one nation we have only one identity. We are Bhartiyas. We are Bharat*vasis*.

मैं केवल एक चीज बोलूंगी । आज हम सबने एलओपी की स्पीच सुनी । हममें से कोई नहीं बोलेगा कि वह बोरिंग स्पीच थी, क्योंकि वह हमारे लिए एंटरटेनिंग थी । हमने सुना और हमने सुना ही सुना, क्योंकि हमें लगा कि शायद हम चाइना में हैं, इंडिया में नहीं । मैं केवल एक ही चीज पूछना चाहूंगी । जब आप चाइना पर इतना रिसर्च करके आ सकते हैं तो थोड़ी सी रिसर्च हमारे भारत पर भी कर लेते तो हम सबका भला होता ।

लास्ट में, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि जिस हिसाब से हमारे ऑनरेबल प्रेसीडेंट ने स्पीच दी, उसे सब लोगों ने सुना । आज पूरे भारत को हमारे प्रेसीडेंट ने बताया कि दस सालों में कैसे काम किया जाता है और किसने करके दिखाया है । वह काम आगे भी वैसे ही होगा । धन्यवाद ।

We heard the best speech from our President, and a Vote of Thanks to her for her speech -- thank you, Madam!

DR. KALANIDHI VEERASWAMY (CHENNAI NORTH): Madam, thank you very much for giving me an opportunity to speak on the Motion of Thanks on the President's Address.

Madam, we all know it is customary. Though it is her Address, we know it is not her views and it is the views of the Government which has prepared the speech for her. So, whatever comments or criticisms are made, it can be understood that it is not made against the hon. President and it is against the Government which has prepared this draft for her. ? (*Interruptions*)

I cannot hear you. Anyway, let me continue with this. Actually, I am surprised that not many senior Ministers are here to listen to what the Opposition has to speak. This has been the problem where anytime when the Opposition Members are raising some issues, neither is it answered nor is it reflected upon.

Coming to the speech, the first point that the President has spoken is about the 75th Anniversary of adoption of our Constitution. In that we are talking so much about the Constitution, but it is sad to note the 17th Lok Sabha and the 18th Lok Sabha have not had a Deputy Speaker. The Deputy Speaker is a Constitutionally-provided post, which has to be filled. This Government, in the first paragraph itself, have broken the Constitution. They have made it a ... * thing that they do not have the confidence in having even a Member from one of your allies like TDP or JD(U) to be made the Deputy Speaker. So, I hope that the Government will look into this and make sure that a Deputy Speaker is appointed for the Lok Sabha.

The next paragraph talks about the Mahakumbh. Everybody is talking about the Mahakumbh, which happens once in 144 years. And it is very sad to note that so many deaths have happened. So far, what has been reported is 30 deaths and 60 people injured. But we are suspicious of these news articles because whenever a major calamity of this extent happens in this country, we expect the Home Minister to come and give a statement in this House to mention what exactly has happened and what measures have been taken for relief and for support of the people over there, and what safety measures are taken to ensure that it does not happen again in the future. Actually, I am sad that this Government has not bothered about it. Though they claim themselves to be a Hindutva Party, they do not care about the people who have died over there.

The next point that they are talking about is ?housing for all?. When they are talking about ?housing for all? the Government says that the Union Government is providing funds for ?housing for all?. But actually, if you look into the amount of money which has been sanctioned, most of the amount which has been sanctioned is from the State Governments. The State Governments are the ones which are doing it. If you note the amount which has been allocated, the funds are not being utilised because only in southern States or developed States these funds are fully utilised and most of the other States are not utilising it, and these funds are totally wasted.

The Government is also talking so much about trains -- the Vande Bharat and so many other trains that this Government has launched. Earlier, in my speech I had spoken when I was talking about Chandrayan, I had said that we can always boast saying that we are the first nation to land in the south pole of the moon, but you have to take into account that development of a nation is not based only on one particular event. So, you also have to see how many accidents are happening in these trains. We see in the news, of late, every month there is some kind of an incident like there is a derailment or there is a collision where we are losing so many lives and the Government has been mum about that. Usually, in the earlier years we have noticed that when some major calamity happens, the Minister concerned takes responsibility for it and steps down. But here, we are not even bothered about the loss of lives and we continue as if nothing has happened though hundreds of people lose their lives.

We are comparing ourselves with developed nations like Japan. They are running something called ?Bullet Train? which they have been doing it for several decades.

19.00 hrs

Not even a single instance of fatality or minor crash has ever happened. I hope the Government would be able to achieve something like that so that we can call ourselves a developed nation.

The hon. Prime Minister constantly talks about Viksit Bharat. I would like to understand what they mean by ?Viksit Bharat?. The economic criteria for a ?developed nation? is that you have to have a per capita income of 15,000 US dollars. Though China has achieved a per capita income of 6,500 US dollars, it is not considered as a developed nation. We are at a paltry amount of 2,500 US dollars and the Government says that we are going to achieve the target of five trillion dollars by 2030. Even if you achieve five trillion dollars, your per capita income will only be 3,250 US dollars. When you are talking about this, I cannot understand how the Government can say that they are working towards a Viksit Bharat.

The hon. Prime Minister is always mentioning ?Make in India?. When you say ?Make in India?, you can only become a manufacturing hub. The present requirement for the whole world is to think in your own country, to

be able to think and come out with some kind of intellectual properties. If you look at the largest companies which are performing well, if you look at the amount of development and growth that has happened in the developed nations, it is not because they are manufacturing goods in their own country. Most of the manufactured goods have been exported by countries like China, Indonesia, India, and Vietnam. The developed nations are developing things like Facebook, Instagram, and Twitter which generate a lot more revenue. So, I hope the country will focus on developing artificial intelligence and making sure that we will be able to achieve heights of growth by 15 per cent or 20 per cent. Unless you do that, we can never dream of becoming a developed India in the next 100 years also.

Madam, our hon. Chief Minister has brought out a book called ? Antiquity of Iron? which is translated in Tamil ? ?Irumbin Thonmai?. This pushes the Iron Age back to 3,450 BC. I am surprised that the hon. Prime Minister has not even mentioned this in any of his social media accounts like Twitter etc. There was also no mention of it in the President's Address. This is something which is not a proud moment for Tamils alone. It is a proud moment for the whole of India that the Iron Age started in India. It started in Tamil Nadu. The archaeologists world over are looking at us with awe. They are so shocked to know that it was our technology in 3,450 BC when we could smelt iron. This is sad that it is not being appreciated and acknowledged by the hon. Prime Minister. I hope that the Government passes a resolution over here congratulating the archaeologists and all the people who are involved in getting this happening.

Madam, if you look at China and India, China has an economy of almost 18 trillion dollars or more. We are still struggling to achieve five trillion dollars and you are talking about making India ?Atmanirbhar Bharat?, where you want to make everything here. But sadly in the last 10 years, our trade deficit was 600 billion US dollars where you have lost out the amount of money which could have made India export surplus. We could have been trade positive, but that has not been achieved in the last 10 years. I hope this country focuses on ensuring that we are a trade surplus country. The hon. President in the last line of her Address told that

this is a country of 140 crore people, but the Government is not behaving in such a way. The Government has ensured that the minorities, the Dalits and the other communities, are oppressed. You are treating us as though India has only 60 crore people and you are neglecting all of them. I am hoping that you will be able to rectify that. There is a Muslim community of 20 crore people. When the Government is talking about bulldozers, they are pushing those people into a brink where you are inciting their emotions, which is not healthy for this nation. I hope the Government will stop this.

डॉ. राजकुमार सांगवान (बागपत) : सभापति महोदया, आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, धन्यवाद । राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में भारत की विकास यात्रा, सरकार की नीतियों, देश के भविष्य के लिए उठाए गए ठोस कदमों की चर्चा की । उन्होंने भारत को एक मजबूत, आत्मनिर्भर और समृद्ध राष्ट्र बनाने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाया । राष्ट्रपति जी ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने, विकासशील से विकसित राष्ट्र बनाने की यात्रा पर जोर दिया ।

उन्होंने बताया कि सरकार का प्रयास न केवल आर्थिक प्रगति बल्कि देशवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में भी कारगर है । अभिभाषण में बताया गया कि डिजिटल इंडिया अभियान के जरिए सरकारी सेवाओं को सरल और पारदर्शी बनाया गया है । विकास के हर पहलू को डिजिटलीकरण से जोड़ा गया है, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच की खाई कम हो रही है । सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाएं युवाओं को रोजगार और नए अवसर प्रदान करने में सहायक है । स्टार्ट-अप इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे अभियानों ने देश में नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा दिया है । किसानों की स्थिति सुधारने और कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों पर चर्चा की गई । आधुनिक कृषि तकनीकों, सिंचाई की बेहतर सुविधा और फसल बीमा योजना के जरिए किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया । राष्ट्रपति जी ने यह भी बताया कि वर्तमान सरकार रिफार्म, परफार्म और ट्रांसफार्म के सिद्धांत पर काम कर रही है । यह न केवल प्रशासनिक कार्यों को कुशल बना रहा है, बल्कि वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ा रहा है । भारत ने हरित ऊर्जा और सतत् विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया हैं, ये नीतियां भारत को न केवल ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगा बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी अह्म भूमिका निभाएंगी ।

सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है, जिससे लाखों सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, यह कदम आर्थिक सशक्तीकरण और कर्मचारियों के कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण है । महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बजट अभिभाषण में आत्मनिर्भर भारत, आर्थिक सुधार, सामाजिक समावेश और वैश्विक नेतृत्व को मजबूत

करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है । यह सरकार की दूरदर्शिता, प्रतिबद्धता और नीतिगत स्थिरता को दर्शाता है । यह अभिभाषण भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा ।

महोदया, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, कई माननीय सदस्यों ने महाकुम्भ की चर्चा की । जो हादसा वहां पर हुआ, उस पर महामहिम राष्ट्रपति जी ने दुख व्यक्त किया है, जिनकी जानें गई हैं, उनके प्रति शोक-संवेदनाएं व्यक्त की गई हैं, जो घायल हुए हैं, सरकार उनका उपचार भी करा रही है । मैं इसलिए इसकी चर्चा कर रहा हूं क्योंकि कुछ माननीय सदस्यों ने हादसे की बात रखी है, वर्ष 1954 में कुंभ में हादसा हुआ तो हजारों लोगों की जान चली गई, उस समय की सरकार ने पूरी घटना छिपाने का काम किया और लाशों को इकट्ठा करके जलाने का काम किया था, जो बड़ा अशोभनीय काम था । 1989 में भी ऐसी ही घटना घटी, जिसमें सैंकड़ों लोगों की जान चली गई । वर्ष 2013 में जिनकी सरकार थी, वहां पर भी कुंभ में अनेकों श्रद्धालुओं की जान चली गई, लेकिन सरकार ने जरा भी संवेदना व्यक्त नहीं की थी ।

आज प्रदेश की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ जी जिस तरीके से महाकुम्भ का आयोजन सफलतापूर्वक सम्पन्न करा रहे हैं, रात-दिन चिंता कर रहे हैं, वहां पर हर श्रद्धालु को स्नान करने का अवसर मिले, उनके रहने और खाने-पीने, आने-जाने की सुविधा मिले, हर प्रकार के प्रबंधन पर खुद मोनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं । जो घटना घटी, उसके लिए सरकार ने जांच आयोग का गठन किया है, सारी बातें सामने आएंगी, इससे पता चलेगा कि इसके पीछे कौन लोग हैं ।

मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करना चाहता हूं कि महाकुम्भ हमारी आस्था का पर्व है, लोग गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करने जाते हैं । सरकार द्वारा उठाए गए कदम और प्रबंधन के साथ हमें खड़ा होना चाहिए । श्रद्धालु लोग वहां स्नान करने जा रहे हैं, उनके साथ कोई गंभीर घटना न घटे और उनकी कुशलतापूर्वक स्नान करने, रहने, आने-जाने की सारी व्यवस्था सम्पन्न हो ।

हम सरकार के फैसले के साथ खड़े रहें, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के फैसले के साथ खड़े रहें, ऐसी कोशिश हमें करनी चाहिए । मुझे इस बात की तकलीफ है कि वर्ष 1820 में, वर्ष 1840 में और वर्ष 1854 में भी ऐसी घटना घटी थी । उस समय अंग्रेजी हुकूमत थी । उस समय भी घटनाएं घटी थीं । ये हादसे हैं । मेरा बागपत लोक सभा क्षेत्र है । उसी दिन एक घटना मेरे बागपत लोक सभा क्षेत्र में घटी थी । उस दिन जैन समाज का धार्मिक आयोजन था । उस आयोजन में लाखों की भीड़ नहीं थी । लेकिन, घटना घटी और 10 लोगों की जान चली गई तथा 70-80 लोग घायल हुए थे । प्रदेश की सरकार ने तत्काल उसका संज्ञान लिया था । जो घायल लोग थे, उनको बड़े अस्पतालों में, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ में उपचार करवाया । चूंकि बागपत जनपद में कोई बड़ा अस्पताल

नहीं था । सरकार उसके प्रति गंभीर थी । जिनकी जान चली गई, सरकार ने उन परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की और उनकी आर्थिक मदद करने की भी घोषणा की ।

आज हमारी प्रदेश की सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी हमारे महाकुंभ को सकुशल संपन्न कराने में पूरी मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं । प्रयागराज के महाकुंभ में जितनी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गए हैं, आज तक के इतिहास में जब भी कुंभ का मेला लगा है, किसी भी सरकार के मुखिया ने वहां इतनी बार जाने का काम नहीं किया है । आज आप उन्हीं पर सवाल उठाने का काम कर रहे हैं । मैं तो फिर आग्रह करूंग कि यह समय ऐसा नहीं है कि आप आलोचना करें । यह समय ऐसा है कि जिनकी जान गई है, उनके साथ हम खड़े रहें और उनको संबल प्रदान करें । जो घायल हुए हैं, उनके उपचार के लिए हम ईश्वर से दुआएं करें कि वे ठीक हों । हमारा जो महापर्व है, स्नान का पर्व है, महाकुंभ है, जो आस्था से जुड़ा है, वह सकुशल संपन्न हो । हम सरकार के साथ मजबूती के साथ खड़े रहें । यह वह समय है । इसके लिए मैं सभी से आग्रह करूंगा ।

अंत में, मैं महामहिम राष्ट्रपति जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राष्ट्र को विकसित भारत बनाने के प्रयासों की चर्चा की और उनके प्रयासों की सराहना की ।

आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री आगा सैय्यद रूहुल्लाह मेहदी (श्रीनगर) : धन्यवाद सभापति महोदया । मेरे पास वक्त ज्यादा नहीं है । मेरे पास समय कम है, इसलिए मैं प्वाइंट पर आ जाता हूं । जब मैंने एक पैराग्राफ को सुना और पढ़ा तो मुझे हैरत हुई । पेज नम्बर-19 में, प्रेसिडेंशियल एड्रेस में जम्मू-कश्मीर के हवाले से जिक्र किया गया और यह बताया गया कि अनुच्छेद-370 हटाने के बाद वहां पर पार्लियामेंट इलेक्शन और असेम्बली इलेक्शन हुआ । मुझे ताज्जुब है कि कैसे इस मुल्क को बेवकूफ बनाया जाता है । जम्मू-कश्मीर में असेम्बली का इलेक्शन और पार्लियामेंट का इलेक्शन पहली बार नहीं हुआ है । अनुच्छेद-370 के रहते हुए भी होता था । आपने नाजायज तरीके से अनुच्छेद-370 को हटाया और उसके बाद भी इलेक्शन हुआ । अनुच्छेद-370 के दौरान भी लोगों ने जम्हूरियत पर यकीन दिखाया था और जम्हूरियत के जरिए अपने फैसले किए । अनुच्छेद-370 को हटाने के बाद भी लोगों ने जम्हूरियत के जरिए जवाब दिया । वहां इलेक्शन होना कोई पहली बार नहीं है, कोई खास बात नहीं है । इलेक्शन इससे पहले भी हुए हैं, आज भी होते हैं और आगे भी होते रहेंगे । जो चीज बतानी चाहिए थी, वह प्रेसिडेंशियल एड्रेस में नहीं बताई गई कि जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद-370 हटाने से क्या नुकसान हुए और अनुच्छेद-370 के होने से क्या फायदे थे । जो बात मुल्क को नहीं बताई नहीं जाती है, जो बात इस ऐवान को नहीं बताई जाती है, जो बात प्रेसिडेंशियल एड्रेस में होनी चाहिए थी, उसका जिक्र नहीं हुआ । मैं कुछ प्वाइंट्स की तरफ इशारा करूंगा, जिनके बारे में बात होनी चाहिए थी । हकीकत यह है कि आप

अनुच्छेद-370 के होते हुए और अनुच्छेद-370 के हटने के बाद ह्यूमेन डेवलपमेंट इंडेक्स उठाकर देखें, अनुच्छेद-370 के होते हुए जम्मू-कश्मीर कोई पिछड़ा हुआ राज्य नहीं था और पसमांदा रियासत नहीं थी । अनुच्छेद-370 के होते हुए ह्यूमेन डेवलपमेंट इंडेक्स में जम्मू-कश्मीर का शुमार छठे रियासत के रूप में होता था । अगर आप बीजेपी गवर्न्ड रियासतों से कंपेयर करेंगे तो बिल-ख़ुसूस आपकी मख्सूस और खास रियासत जो गुजरात है, जम्मू-कश्मीर का ह्यूमेन डेवलपमेंट इंडेक्स अनुच्छेद-370 रहते हुए 0.712 था, वहीं गुजरात का 0.677 था, जो जम्मू-कश्मीर से कम था । हरियाणा का 0.702 था, जो जम्मू-कश्मीर से कम था । उत्तर प्रदेश का उससे भी कम 0.596 था । मध्य प्रदेश का जम्मू-कश्मीर से बहुत ज्यादा कम 0.606 था । बिहार का 0.76 था । काश उस तरफ भी तवज्जो दी गई होती है । आप जम्मू-कश्मीर पर तोहमतें लगाते हैं, जबकि हकीकत कुछ और है ।

जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 के होते हुए इन सब रियासतों से, जिसमें गुजरात भी शामिल है, वह बहुत ज्यादा बेहतर था ।

गरीबी दर है, जिसका यहां पर जिक्र नहीं हुआ है, जो बताया जाना चाहिए था, इस मुल्क का जो आखिरी सर्वे हुआ था, जम्मू-कश्मीर में 10.3 प्रतिशत गरीबी दर थी, जो कि गुजरात से कहीं ज्यादा बेहतर है । गुजरात में गरीबी दर 16.6 प्रतिशत है, उत्तर प्रदेश में 29.4 प्रतिशत गरीबी दर है, मध्य प्रदेश में 31.7 प्रतिशत गरीबी दर है, बिहार में 33.7 प्रतिशत गरीबी दर है । जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 के होते हुए वहां की गरीबी दर सिर्फ और सिर्फ 10.3 प्रतिशत थी । आप यह बताना भूल गए हैं । आप इस मुल्क को बेवकूफ बनाते हैं । आप इस मुल्क को मिसलीड करते हैं ।

अगर मैं जीवन प्रत्याशा की बात करूं । वर्ष 2009 से 2016 के दौरान इस मुल्क में जो सर्वे हुआ था, अगर आप तुलना करेंगे, तो जम्मू-कश्मीर में जीवन प्रत्याशा की जो दर थी, वह 73.5 थी । गुजरात में उससे कम यानी 68.5 थी । गुजरात की तुलना में जम्मू-कश्मीर में जीवन प्रत्याशा ज्यादा थी । हरियाणा में जीवन प्रत्याशा 69.4 है, उत्तर प्रदेश में जीवन प्रत्याशा 60.3 है, मध्य प्रदेश में जीवन प्रत्याशा 60.2 है, बिहार में जीवन प्रत्याशा 68 है । इन सबके मुकाबले जम्मू-कश्मीर में जीवन प्रत्याशा सबसे ज्यादा थी, वहां 73.5 थी ।

अगर मैं एजुकेशन के हवाले की बात करूं, तो मैं एक ही इंडीकेटर की बात करूंगा । ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो फॉर हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन में जो लोग दाखिला लेते थे या एनरोल करते थे, जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 के होते हुए इन सब रियासतों से सबसे ज्यादा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो थी । अनुच्छेद 370 के होते हुए जम्मू-कश्मीर में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 30.9 प्रतिशत थी । जम्मू-कश्मीर की तुलना में गुजरात में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बहुत कम थी, यानी 20.4 थी । जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 के होते हुए हायर एजुकेशन में आबादी की ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 31 प्रतिशत थी ।

गुजरात में उससे बहुत कम यानी 20 प्रतिशत थी । हरियाणा में 29.4 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में 25.8 प्रतिशत, मध्य प्रदेश में 22.6 प्रतिशत और बिहार में सिर्फ और सिर्फ 14 प्रतिशत है । यह हालत जम्मू-कश्मीर की थी ।

कश्मीर जिस राह पर था, अगर मैं इन्कम की बात करूं, मैं ज्यादा इंडेक्सेज़ में नहीं जाऊंगा । मैंने गरीबी दर की बात कही है । जम्मू-कश्मीर गुजरात से भी बेहतर था, हरियाणा से भी बेहतर था, उत्तर प्रदेश से भी बेहतर था, मध्य प्रदेश से भी बेहतर था और बिहार से भी बेहतर था ।? (व्यवधान)

महोदया, मैं सिर्फ दो मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा । मुझे पता है कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है । पोस्ट एब्रोगेशन का डेटा है । एक ही इंडीकेटर है । जब जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 था, तो ये सारे इंडीकेटर्स थे, जो यहां पर बताया नहीं गया है । अगर पोस्ट एब्रोगेशन का एक ही इंडीकेटर उठाकर देंखें, चूंकि मेरे पास वक्त नहीं है, तो ऐसी रियासतों में जहां पर ये इंडीकेटर्स थे, आज जो रोजगार दर है, वह 32 प्रतिशत पर पहुंचा है । हमने पहली बार देखा है । अनुच्छेद 370 को हटाने का यह नतीजा है ।

अनुच्छेद 370 हटाने के बाद यह बताया गया है, मुल्क को बेवकूफ बनाने की कोशिश की गई है कि चुनाव हुए हैं । उससे पहले भी चुनाव होते थे । यह नहीं बताया गया है कि चुनाव के जरिए वहां के लोगों ने क्या पैगाम दिया है । उन्होंने चुनाव के जरिए पैगाम दिया है, वहां की विधान सभा में रिजोल्यूशन पास हुआ है । न सिर्फ अनुच्छेद 370 है, बल्कि संविधान के जरिए जम्मू-कश्मीर को सन् 1953 से पहले जो स्टेटस मिला हुआ था, विधान सभा ने वह रिजोल्यूशन पास किया है । हमें तब तक यह स्टेटस कबूल नहीं है, जब तक उस स्टेटस को बहाल न किया जाए ।? (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, आप अपनी बात पूरी करिए ।

श्री आगा सैय्यद रूहुल्लाह मेहदी : महोदया, हालांकि मेरी वह ख्वाहिश नहीं है, सिर्फ स्टेटहुड बहाल किया जाए ।? (व्यवधान) मगर विधान सभा के जरिए ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जो आपके उन वादों पर उम्मीद लगाए हुए हैं, आपने यहां पर स्टेटहुड की बहाली के हवाले से वादे किए हैं, आपने सुप्रीम कोर्ट में वादे किए हैं, आप वे वादे कब पूरा करेंगे? आप रिजोल्यूशन पर कब अमल करेंगे? सन् 1953 से पहले जम्मू-कश्मीर का जो स्टेटस था, एक दिन इस मुल्क को उसको वापस करना पड़ेगा ।? (व्यवधान)

महोदया, पूरे मुल्क में मुसलमानों की जो हालत है, आप उस हालत के बारे में यहां पर जिक्र करना भूल गए हैं । सुबह एलओपी ने एआई रिवॉल्यूशन का जिक्र किया है, विजन के बारे में बताया है । उस विजन के साथ ओबीसीज़ को जोड़ा गया, उनको जोड़ना भी चाहिए, पिछड़ों को जोड़ा गया, जोड़ना भी चाहिए, लेकिन आप मुसलमानों को जोड़ना भूल गए ।? (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, आप अपनी बात पूरी करिए ।

श्री आगा सैय्यद रूहुल्लाह मेहदी : क्या सिर्फ मुसलमान इसलिए हैं, ताकि उनको बीजेपी से डराकर चुनावों में वोट्स हासिल किए जाएं । मैं यह बताना चाहूंगा कि यह गलतफहमी पालना बंद कर दीजिए । मुसलमान किसी से डरने वाला नहीं है । न तो वह बीजेपी से डरता है, न ही किसी और से डरता है । अगर वह डरता है, तो सिर्फ और सिर्फ इसी बात से डरता है कि आरएसएस और बीजेपी ने जिस तरह का रवैया अपनाया है ।? (व्यवधान)

डॉ. आलोक कुमार सुमन (गोपालगंज) : सभापति महोदया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने के लिए मौका दिया । ? (व्यवधान)

महोदया, राष्ट्रपति जी के विज़नरी अभिभाषण ने हम सब एवं 140 देशवासियों का मार्गदर्शन किया है । इसमें आर्थिक सुधार, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्वास्थ्य सेवा में प्रगति, शिक्षा, डिजिटल, इकोनॉमी, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रामीण विकास से लेकर अंतरिक्ष तक हर पहलू को रेखांकित किया गया है । राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में वर्ष 2047 का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें देश को विकसित भारत बनना है । आज सरकार के प्रयास से भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है । पिछले दस सालों के रिकॉर्ड का अध्ययन करने से पता चलता है कि विश्व की अर्थव्यवस्था में 35 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जबकि भारत की अर्थव्यवस्था 90 प्रतिशत तक बढ़ी है । यह एक सस्टेन ग्रोथ है, जिसको देश ने हासिल किया है । वर्तमान सरकार के कारण भविष्य में भी सस्टेन ग्रोथ बनी रहेगी ।

महोदया, माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में रिफॉर्म, परफॉर्म एवं ट्रांसफॉर्म की बात की गई है, ताकि गुड गवर्नेंस को मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जा सके । सरकार के प्रयास से ही 25 करोड़ देशवासियों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया गया है और आज नियो मिडिल क्लास के रूप में जिंदगी जी रहे हैं तथा आगे बढ़ रहे हैं । सरकार ने तीन करोड़ नए घर गरीबों के लिए, यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा और कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक लाख करोड़ रुपये दिए गए हैं । देश में सौ से ज्यादा वैराइटीज़ के बीज बांटे गए हैं । आज देश विश्व में सबसे बड़ा दूध, दाल और मसालों का उत्पादन करने वाला देश बन गया है । चार करोड़ युवाओं को डायरेक्ट बेनिफिट देने के लिए दो लाख करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है । पहले अधिकतम युवाओं को मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए विदेश में जाना पड़ता था, लेकिन सरकार ने एक लाख नई सीट्स बढ़ाई हैं, जिससे अब 1 लाख 80 हजार एमबीबीएस और एमडी की सीट्स हो गई हैं । 15 अगस्त, 2024 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह घोषणा की थी कि आने वाले पांच सालों में 75 हजार और सीटों को मेडिकल सेक्टर में जोड़ा जाएगा । इससे हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर में हम विश्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभा पायेंगे । जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछले वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाया गया । यह भारत देश का ही इनिशिएटिव था । विश्व में हम

सबसे बड़े मिलेट्स उत्पादन करने वाले देशों में शामिल है । यह माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व का परिणाम है कि हम विश्व के फूड बास्केट के रूप में तैयार हो रहे हैं और मेड इन इंडिया का भोजन विश्व की हर टेबल पर मिले, यह संभव हो रहा है ।

महोदया, माननीय राष्ट्रपति जी के संबोधन में जी-20 के सफलतापूर्वक समापन की भी चर्चा की गई है । देश में ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव का सपोर्ट सभी पार्टिसिपेटेड देशों ने किया । देश ने वर्ष 2030 तक 5 मिलियन टन्स उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है । इसके साथ ही वर्ष 2030 तक ही 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करने का लक्ष्य रखा गया है । यह एक सराहनीय कदम है । आउटसोर्सिंग ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स या कंसल्टेटिव सर्विसेज़ में एससी, एसटी और ओबीसी के पार्टिसिपेशन के लिए सरकार कृत संकल्पित है । इसके साथ ही अगर इसमें नियमावली बना दी जाती है तो दलित आदिवासी और नियो मिडिल क्लास के उत्थान में और गतिशीलता आएगी । आज भारत ने 17 टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में काफी हद तक कई गोल्स को पूरा कर लिया है या पूरा करने के नजदीक है । यह देश की सामर्थ्य दिखता है । माननीय राष्ट्रपति जी के संबोधन में उड़ान स्कीम के तहत डेढ़ करोड़ लोगों का सपना पूरा हुआ है । हमारे संसदीय क्षेत्र गोपालगंज के हथुआ मंडल में सबेया एयरपोर्ट, जो उड़ान योजना में शामिल है, उसके कार्य को कराने के लिए सरकार क्रियाशील है । मेरा आग्रह है कि उसमें गतिशीलता प्रदान की जाती है तो पूरे देश के आम नागरिक का सपना साकार होगा । गोपालगंज के डेढ़ से दो लाख लोग विदेश में रहते हैं ।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को अपना समर्थन देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं । धन्यवाद ।

SHRI S. VENKATESAN (MADURAI): Hon. Chairperson, Vanakkam. Although India constitutes 20 per cent of the population of the world, it has only a share of 2 per cent in the world trade. India?s share is just 4.6 per cent in Services sector and 1.5 per cent in International tourists? arrival. We are the reason for this backwardness. DeepSeek AI of China has made an impact worldwide recently. Even countries like USA have started taking actions aimed at overcoming the impact of DeepSeek AI. But what are we doing in India? The Director of a very reputed institution of higher learning, IIT-Chennai talks about drinking cow urine everyday as it has medicinal values. There are such people spreading the fake practices of science and medicine. You talk very high about ?One Nation One Tax?. One per cent of the population has 40 percent of the income. If you levy adequate tax on this 1 percent super rich, there is no need to levy tax on the rest of 99 percent of our population. But on whose side you stand is very much

visible from your actions. Where is One Tax? You are levying three types of taxes for just a Popcorn. If popcorn is not pre-packaged, 5 percent GST is levied. If Popcorn is pre-packaged and labelled in a carton box, then the GST rate is 12 per cent and caramelised Popcorn has a GST of 18 per cent. Friends, while talking on the President?s Address I must say that this Government is ignoring the needs, rights and pride of the Tamil Nadu government. The Union Government claims that they have created a metro rail network for 1000 kilometres in the country and India is the third nation to have such a big network of metro rail. But only a metro rail network of 54 kilometres is operational in Tamil Nadu. We have metro rail network in 5 cities of Uttar Pradesh. We have metro rail network in 4 cities of Maharashtra and 2 cities of Gujarat. We have metro rail connectivity in 2 cities of Madhya Pradesh. But we have metro rail only in one city of Tamil Nadu, i.e. Chennai spreading over just 54 kilometres. Where is the metro rail network for Madurai? Where is the metro rail network for Coimbatore? Tamil Nadu government has been raising these questions time and again. We also raise this question in this august House. But the Union government has failed to answer these questions till now. It refuses to allocate adequate funds for metro rail expansion in Tamil Nadu. At the same time, we can say one thing with pride in this august House. We the Hon. MPs from Tamil Nadu are here standing with pride in this House after upsetting your conspiracy relating to Tungsten mining. Hon. Chief Minister of Tamil Nadu passed a resolution in the State Assembly of Tamil Nadu against Tungsten mining. We even passed resolutions in all the Panchayat Unions and local bodies of Melur in Tamil Nadu against Tungsten mining. Even then the Union Minister issued statements not once or twice but thrice saying that the Union Government will not give up Tungsten mining activities. But we never gave up. After organising non-stop agitations for 77 days we have come up victorious now. After this victory of ours, the Hon. Union Minister says that the people of this area can sleep peacefully. It is true that people of this area will have peaceful sleep. But actually who disturbed their sleep? You are the ones who disturbed their peace and sleep. After cancelling the Tungsten mining activities, hon. Union Minister now says that the people of that area can hereafter sleep peacefully. But

who gave this suffering to them? It is none other than you. That is why people through their non-stop agitations have forced you to withdraw Tungsten mining activities. But what do you say in hon. President?s Address? You mentioned in the Address that the private sector will be allowed to get into mining activities of rare mineral wealth. After taking away one piece of meal, you are giving them a feast rather. This is in favour of the private companies. We saved one Arittapatti from mining activities. But you say that you will create many number of such Arittappatis. I want to raise another important issue here. As mentioned with great pride by our hon. Member of Parliament of Tuticorin, the legacy of iron technology in history is very worth-mentioning. Qutub Minar in Delhi is a rust-free Iron Pillar. Use of iron in Kohinoor temple and iron pillar of Thar are examples of attraction for the great legacy of India in the world history. Now another prideful aspect has been added to the glory of this legacy. The era of iron technology, as announced by hon. Chief Minister of Tamil Nadu, dates back to 5300 years. This is an important message to the world history that there was use of iron and its technology in Tamil Nadu almost 5300 years ago. Below the Vindhyas at the time when copper was only in use, iron has been into use particularly in Tamil Nadu. There existed a knowledge based society in Tamil Nadu who rationally approached the nature and created their life and wealth. I want to make a request to the hon. Speaker of Lok Sabha. Lok Sabha Secretariat has informed that there will be a special screening of an animation film on Ramayana in the Parliament House complex exclusively for the MPs. I say that you can very well screen this animation film on Ramayana. But prior to that I humbly request in this august House that you have to screen the documentary film produced by Tamil Nadu on the finding of existence of iron technology in Tamil Nadu about 5300 years ago. Similarly, Governors are making the rights of the State Government a question mark. They think themselves as kings of a small kingdom. Even after the hon. Courts have pronounced on the functioning Governors within the limits of the Constitution, they do not pay heed to such directions. One cannot become a king by just wearing the dress of a king. He can only become an actor in a drama. How can we make him understand this truth? Governors are

questioning about the rights of the Legislatures and make frequent walk out from the Legislative Assemblies. If we elected members of this House walk out of this House then it can be called as ?walk out?. How can it be called a ?walk out? when anyone and everyone coming to this House walks out. The people of Tamil Nadu are not knowing as to how one can wipe out his ignorance as he thinks that he has all powers. I wish to say in this august House once again. Hon. President has mentioned about classical language. I wish to humbly state here that what transpired during the debates in the constituent assembly during the framing of our Constitution. There was a long debate that took place in the Constituent Assembly on how to name the post of hon. President. When many MPs said that particularly that position should be called as ?Rashtrapati?, hon. Ambedkar mentioned that it should be mentioned as ?President of India? as he was writing the Constitution in English. He refused to mention as ? Rashtrapati? in the Constitution. He further said that it will be written in English and one can translate it in their respective mother tongue later. This was the statement of Dr. Ambedkar. But when we celebrated the 75th year of adoption of the Indian Constitution, in this very House, in the Joint Session of Parliament, hon. President read out the Preamble in Hindi. As we were waiting for hon. President to read the Preamble in English, it was read in Hindi by the hon. President. We the MPs from non-Hindi speaking constituencies were totally shocked to see this. This was a challenge to the democracy of India. I want to categorically stress that if you want to bring this House under the control of one particular language, the representatives of other major languages in this House would never ever allow.

Thank you. Vanakkam.

***m70 श्री वरुण चौधरी (अम्बाला) :** सभापति महोदया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको मैं धन्यवाद देता हूँ ।

हमें गर्व है कि हम भारत देश के नागरिक हैं । हमें बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी पर गर्व है, जिनके माध्यम से हमें बराबरी का अधिकार मिला है । हमें पीड़ा होती है, जब देश की मौजूदा सरकार देश की समस्याओं को सुलझाने की जगह लोगों का ध्यान भटकाने का काम करती है । वर्ष 2014 में महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कहा गया था कि श्रेष्ठ भारत बनाया जाएगा ।

उसमें श्रेष्ठ भारत का संकल्प लिया गया है और वर्ष 2019 में नए भारत के निर्माण की बात की गई है और अब विकसित भारत की बात की जा रही है । उस नए भारत का क्या हुआ, उसके निर्माण का क्या हुआ, श्रेष्ठ भारत के निर्माण का क्या हुआ, कुछ नहीं । विकसित भारत का रोड मैप आज तक भी नहीं बताया गया है, सार्वजनिक नहीं किया गया है कि क्या हो जाएगा, क्या मानदंड हैं कि कब यह मान लिया जाएगा कि भारत विकसित हो गया? फिर स्व-घोषित अमृतकाल आ जाता है कि अमृत काल आ गया है । फिर विश्व गुरु की बात की जाती है । कई साथी कहते हैं कि विश्व गुरु बन गए, कई साथी कहते हैं कि नहीं, अभी विश्व गुरु बनना है और चेले देशों का कोई नाम नहीं लेता । ये चेले देश कौन हैं, उनका पंजीकरण कहां हो रहा है, कौन पंजीकरण कर रहा है, कौन सा विभाग है जो चेले देशों का पंजीकरण कर रहा है और क्या शर्तें हैं, क्या नियम हैं कि जो चेले देशों को अपनाने होंगे? केवल और केवल ध्यान भटकाने की बातें हैं - कहीं धर्म के नाम पर, कहीं जाति के नाम पर । ये हालात हैं कि 80 करोड़ से भी अधिक भारतवासी अपना भोजन तक अर्जित नहीं कर पा रहे हैं । यह हालत हमारे देश की है । विश्व के सबसे अधिक कुपोषित बच्चे आज हमारे भारत देश के अंदर हैं जो हमारे देश के भविष्य हैं । वेस्टिंग रेट 18.7 प्रतिशत है । जीडीपी पर कैपिटा में हमारे देश का स्थान 188 देशों में से 140वां है । ये हमारे हालात हैं । युवा देश छोड़कर जा रहे हैं, नशा बढ़ रहा है, महिलाएं अपने-आप को सुरक्षित नहीं महसूस करती हैं, पूरे विश्व में सड़क हादसों में सबसे अधिक मौतें भारत देश में होती हैं, किसानों को सड़कों पर रोका गया है, दीवारें खड़ी की जाती हैं, कोई सुनवाई नहीं, ना महंगाई पर बात है, ना बेरोजगारी पर, मणिपुर जाने तक का समय नहीं मिलता है । एक देश - एक टैक्स की बात की गई थी । एक देश - एक टैक्स, लेकिन भारतवासी अभी तक कंफ्यूजन में हैं, अस्पष्टता यह है कि उस एक टैक्स का नाम इनकम टैक्स है, जीएसटी है, कॉरपोरेट टैक्स है, एक्साइज है, वैट है, या क्या इसका नाम है? देशवासियों के साथ झूठ बोला जाता है ।

वंदे भारत ट्रेन की बात हुई, अमृत भारत ट्रेन की बात हुई, पर पैसेंजर भारत ट्रेन कहां है, जिसके माध्यम से देश के आम आदमी एक जगह से दूसरे जगह जाते थे । पैसेंजर ट्रेनों को बंद कर दिया गया । गरीब आदमी किसी माध्यम से, उन ट्रेनों के माध्यम से अपनी आजीविका कमाते थे, लेकिन अब वे कहीं नहीं जा सकते हैं और अपनी आजीविका भी नहीं कमा सकते हैं ।

भारत देश का विकास भारत देश के राज्यों के माध्यम से हो सकता है, लेकिन उनके हालात क्या हैं? राजकोषीय घाटा बढ़ता जा रहा है, देनदारी बढ़ती जा रही है और हालात ऐसे ही चलते रहे तो वर्ष 2047 तक हमारा भारत कर्ज भरा भारत बन जाएगा और उस कर्ज को उतारने की जिम्मेदारी आने वाली पीढ़ियों की बन जाएगी । आने वाली पीढ़ियां को यह मिलेगा, इतना कर्ज होगा कि उन्हें उतारना भी मुश्किल हो जाएगा ।

आज भारत देश में देशवासियों की ही सुनवाई नहीं हो रही है । एक साल से अधिक समय हो गया है, किसानों को सड़कों पर रोका हुआ है । विश्व में कहीं भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि सड़कों और नेशनल हाईवेज़ पर दीवारें खड़ी कर दी गई हों, कीलें लगा दी गई हों । भारत देश के अंदर ही भारत देश के नागरिक आ और जा नहीं सकते, उनकी कहीं सुनवाई नहीं है, वे देश की राजधानी में नहीं आ सकते ।

महोदया, शंभु बार्डर एक साल से बंद है, किसान परेशान हैं क्योंकि उन्हें रोका हुआ है । कर्मचारी और व्यापारी परेशान हैं क्योंकि व्यापार ठप हो गया है, लेकिन इनकी सुनवाई करने के लिए सरकार के पास कोई समय नहीं है । कहां व्यस्त है? मैं जानना चाहता हूं कि कितने विकसित देशों के नागरिकों ने भारत देश की नागरिकता ली है? हमें इसका पता तो चले । अब तो ये हालात पैदा हो गए कि हमारे देश के नागरिक देश छोड़कर जा रहे हैं । यह शर्म की बात है । उनको क्यों मजबूरन देश छोड़कर जाना पड़ रहा है?

महोदया, प्रति वर्ष दो करोड़ नौकरियां देने की बात हुई थी और इस अभिभाषण में दो साल में दस लाख नौकरियां देकर पीठ थपथपाई जा रही है । स्वच्छ भारत किसे देखने को मिल रहा है? यह कहां है? पैसा खर्च हो रहा है लेकिन स्वच्छता अभी-भी कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है । अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए कोई कार्यक्रम नहीं है, कुछ नहीं है । यह बताया गया कि बुनियादी ढांचे का बजट लगभग दो लाख करोड़ रुपये था जो 10 सालों में अब 11 लाख करोड़ रुपये हो गया है । एमपीलैड स्कीम का पैसा वर्ष 2011 से वहीं का वहीं खड़ा है, 15 साल होने को हैं, पांच करोड़ रुपये ही है । संसद सदस्य कहीं भी जाते हैं तो लोग खुश होते हैं कि चुने हुए नुमाइंदे हमारे बीच पहुंचे हैं । उन्हें अपने क्षेत्र के सांसद से उम्मीद होती है कि अब गांव या वार्ड की तरक्की के लिए या आधारभूत संरचना बनाने के लिए कुछ देकर जाएंगे, लेकिन यह अमाउंट इतना कम होता है कि कुछ भी नहीं हो पाता है । इसे क्यों नहीं बढ़ाया जाता? बहुत से माननीय सदस्यों ने बार-बार कहा है कि इसे बढ़ाया जाए, इसे क्यों नहीं बढ़ाया जाता? आप सीपीडब्ल्यूडी के रेट्स देखिए कि वर्ष 2011 में कंस्ट्रक्शन का क्या रेट था? लेबर का क्या रेट था? 15 साल बीत चुके हैं, आप देखिए कि आज क्या रेट है? आप सीपीडब्ल्यूडी के रेट्स ही देख लीजिए ।

मेरी आपके माध्यम से यही प्रार्थना है, यही आग्रह है कि देश की सरकार देशवासियों की सुनवाई करे, उनकी समस्याओं का समाधान करे, उनका ध्यान भटकाने का काम न करे । आपका बहुत धन्यवाद । जय भीम, जय हिंद ।

***m71 श्री सौमित्र खान (बिष्णुपुर) :** भारत माता की जय । मैं कांग्रेस और कांग्रेस साथियों से पूछना चाहता हूं कि आप लोग किसके साथ हैं? अगर आप मुस्लिम्स के पक्ष में हैं तो डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जी जब राष्ट्रपति बन रहे थे, उस समय आपने विरोध किया । दलित समाज से रामनाथ कोविंद जी के राष्ट्रपति बनने के समय आपने विरोध

किया । हमने भारत माता को नहीं देखा लेकिन महामहिम राष्ट्रपति जी की चेयर पर भारत माता की बेटी बैठीं तो उसका भी आप लोगों ने विरोध किया । आप विरोध करते-करते कहां पहुंच गए? यह आप लोगों को सोचना चाहिए । आप लोग किसी के नहीं हैं । पहले आप कहते थे कि हमने बहुत कुछ किया । मैं वर्ष 2014 में सांसद बनकर आया था, फाइनेंस मिनिस्टर बोल रहे थे, आप कह रहे थे कि गरीबों को कैसे डिजिटल पेमेंट होगी । ऑटो चलाने वाला कैसे पेमेंट लेगा, यह तो एकदम फ्लाप हो जाएगा । यह बोला गया था । तब मैं पहली बार सांसद बनकर आया था, लेकिन आज लग रहा है कि सबसे ज्यादा डिजिटल पेमेंट यही लोग यूज करते हैं । किसान, खेत मजदूर, ऑटो वाले, सब्जी वाले, ग्रॉसरी वाले लोग ही इसे यूज करते हैं ।

आप लोग बोलते हैं कि हमने विकास देखा नहीं है । अभी हमारे एक माननीय सदस्य बोल रहे थे कि विकास तो हुआ नहीं । अरे, आपने चश्मा पहना है या आपकी आंखें बंद हैं, किसी को मालूम नहीं है । ? (व्यवधान) आप मुम्बई जाएंगे तो आपको सागरमाला का प्रोजेक्ट दिखाई देगा । आप यहां से इलाहाबाद चले जाइये । आपको कितना अच्छा रास्ता दिखाई देगा । आप कहीं भी जाइये । इतना अच्छा काम हुआ है कि आप कन्याकुमारी से कश्मीर तक बाय रोड जा पाएंगे । जो महाकुम्भ हो रहा है, इस पर भी टिप्पणी हो रही है । कांग्रेस वालों ने और उसके सहयोगी ने, एक दुर्गा मंदिर बनाने के लिए पुलिस वाले बंद कर देते हैं, काकोली जी बहुत कुछ बोल रही थीं । दुर्गा मंदिर बनने के लिए जो हाइट होती है, वहां दो लाख लोग जमा हुए थे, उसने काम बंद कर दिया । यहां पर 20 करोड़ आदमी महाकुम्भ में आ रहे हैं । आप इस पर ध्यान दीजिए । टिप्पणी करने का काम नहीं है, बल्कि काम को आगे लेकर जाइये ।

आज बसंत पंचमी है । जो बंगाली दिल्ली में रहते हैं, पूरे देश में बसंत पंचमी की पूजा होती है । आज शर्म की बात है कि यहां पर तृणमूल कांग्रेस के 29 सांसद हैं । वहां पर सरस्वती की पूजा को बंद कर दिया, उस पर किसी ने नहीं बोला । जोगेश चंद्र चौधरी कॉलेज में सरस्वती पूजा को बंद कर दिया और पुलिस को लेकर पूजा करनी पड़ रही है । यह कितने शर्म की बात है?

मैं पश्चिम बंगाल से आता हूं । मैंने देखा है कि डेवलपमेंट क्या होता है? मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के बारे में कभी सोचा नहीं था । आज मोदी जी के समय में कोलकाता में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट हुआ है । हम लोग हावड़ा से एयरपोर्ट तक जा पाएंगे । सिलिगुडी से सिक्किम तक आप नेशनल हाईवे से बाय रोड जा सकते हैं । सेन्ट्रल गवर्नमेंट का हर जगह काम होता है ।

पश्चिम बंगाल में गरीबों का जो घर होता है, उनका भी वे पैसा चोरी करते हैं । उस महिला का सम्मान नहीं है । आरजी कर अस्पताल में एक डॉक्टर महिला के ऊपर अत्याचार हुआ, रेप हुआ, फिर भी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इसको डेथ पैनल्टी नहीं होगी । यहां पर शर्म की बात बोल रहे हैं । हर दिन पश्चिम बंगाल में महिलाओं का रेप हो

रहा है । आज पूरे भारत में देखिए कि कितना अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है । प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार आज इतना अच्छा काम कर रही है । आज उड़ान स्कीम के तहत डेढ़ करोड़ पैसेंजर्स फ्लाइट्स से जा रहे हैं । आज माय भारत पोर्टल में, आत्मनिर्भर भारत में, स्टार्ट-अप इंडिया में कितने सारे लोग बिजनेस का काम कर रहे हैं । मैं आज सिर्फ यही बोलूंगा कि आज हम लोग काम कर रहे हैं ।

मैं भारत माता की बेटी राष्ट्रपति महोदया का तो समर्थन करता ही हूं, साथ ही इस पार्लियामेंट से मेरी रिक्वैस्ट है कि बांग्लादेश के बॉर्डर को बंद कीजिए । उसे बंद करने के लिए मैंने छ: महीने पहले भी बोला था और आज भी बोल रहा हूं । आप उस बॉर्डर को बंद कीजिए, नहीं तो वहां से काफी रोहिंग्या दिल्ली में आ रहे हैं और नक्सली काम कर रहे हैं । ये लोग पूरे देश को खराब कर रहे हैं, लेकिन इनको देखने वाला कोई नहीं है । आज वहां पर तृणमूल कांग्रेस रोहिंग्या को रहने के लिए जमीन दे रही है । इससे यह देश सुरक्षित नहीं रहेगा । अगर इस देश को सुरक्षित करना है तो सबसे पहले बांग्लादेश के पूरे बॉर्डर को सील करना चाहिए । जितने भी रोहिंग्या दूसरे देश से यहां पर आए हैं, उनको पहले बाहर कीजिए । सीएए लागू हुआ है, मैं भी चाहता हूं कि एनआरसी हो जाए, क्योंकि हमारा देश एक सुरक्षित देश होना चाहिए । हम रोड्स पर तब चलेंगे, जब हम बचे रहेंगे । आप लोग बोलते हैं कि भाजपा के कार्यकाल में मुस्लिम सुरक्षित नहीं हैं । 80 करोड़ लोगों को राशन मिलता है, उसमें हम हिन्दू-मुस्लिम नहीं देखते हैं । आज आप केरल में चले जाइये, पश्चिम बंगाल के मालदा में चले जाइए, वहां पर हिन्दू को ओपन थ्रेट मिलती है कि उनको हिंदुत्व नहीं करने देंगे, सनातनी को खत्म कर देंगे । आप वहां पर जाकर देखिये । फिर आप लोग बोलेंगे ।

मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि भारत माता की बेटी को, जिस तरह से हमारी सरकार चल रही है, मोदी जी की सरकार चल रही है, इतने अच्छे काम हो रहे हैं, हमें इनको आगे लेकर जाना है । हमें इसलिए आगे लेकर जाना है, क्योंकि हमारी महिलाएं सुरक्षित हैं, देश सुरक्षित है । पूरे वर्ल्ड में भारत का सम्मान है, एक पहचान है ।

भारत माता की जय । जय श्री राम ।

***m72 श्री राजा राम सिंह (काराकाट) :** माननीय सभापति महोदया, माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया गया है, मैं उसके खिलाफ में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ ।

सबसे पहले महाकुम्भ में जिन लोगों की मौतें हुई हैं, मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ । यह लगातार हो रहा है । पिछले दिनों, मध्य प्रदेश, गुजरात में धार्मिक आयोजनों के दौरान सैकड़ों लोगों की मौत हुई । इसलिए ऐसा लग रहा है कि जैसे सरकार ने एक रणनीति बना ली है कि भगदड़ होगा, तो माना जाएगा कि देश में बड़ी आस्था है । एक रणनीति के तहत ये चीजें हो रही हैं । यह बहुत ही चिन्ताजनक है । पिछली बार सदन में संविधान पर बहस चल रही थी । प्रधानमंत्री जी काफी तैयारी के साथ आए थे और अम्बेडकर जी के

पक्ष में कैसे हमारी पार्टी रही है और नेहरू जी ने कैसी अवमानना की थी, उन्होंने विस्तार से इसकी चर्चा की थी । लेकिन राज्य सभा जाते-जाते दिल की बात जुबाँ पर आई । कहा गया कि क्या कहते हो, अम्बेडकर-अम्बेडकर । यह बात सेकेंड नम्बर की कुर्सी पर बैठने वाले एक मंत्री ने कही थी । जुबान नहीं फिसली थी, असल में दिल की बात जुबाँ पर आ गई, तो पूरी पोल खुल गयी ।

मैं कहना चाहता हूँ कि देश में 13 महीने तक किसान आन्दोलन हुआ, जिसमें साढ़े सात सौ किसान मर गये । सरकार को इसी सदन में पारित हुए कानूनों को वापस लेना पड़ा । इसके बावजूद, अभी एक दूसरे रास्ते से, सरकार एनपीएफएएम (नैशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑन एग्रीकल्चर मार्केटिंग) के नाम से एक नयी पॉलिसी लाने जा रही है, जिसके तहत उन्हीं कानूनों को छद्म रूप से लागू करने की कोशिश है । इससे किसानों की मार्केटिंग पर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को हावी कर देना है । किसानों की खेती को कारपोरेट फार्मिंग के रूप में तब्दील कर देना है । इस तरह से, मल्टी नेशनल कम्पनियों को भारतीय कृषि बाजार पर हावी कर देना है । उसमें न तो पीडीएस (जन वितरण प्रणाली) के तहत अनाज देने की गारंटी की बात की गई है और न ही किसानों को एमएसपी देने की बात की गई है । बात हो रही है कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं, वे कर्ज में डूब रहे हैं, इससे उनको बचाने के लिए स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप उनको सी-2 प्लस 50 परसेंट देना होगा । लेकिन सरकार अपने छुपे हुए इरादे को बार-बार विभिन्न तरीके से लाने से बाज नहीं आ रही है । मैं यह कहना चाहूंगा कि इसे रोकना पड़ेगा ।

महोदया, मैं अपने क्षेत्र से संबंधित कुछ मांगों को रखना चाहूंगा । बिहार में अभी जो राशि गई, बिहार के कुछ सांसदों ने कहा कि सरकार बिहार के लिए बहुत कुछ कर रही है । आज तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है । पिछड़े हुए राज्य के नाते जो पैसे वहाँ जा रहे हैं, वे पिछड़े और दलितों तक कहाँ पहुंच रहे हैं? जब नीतीश बाबू इंडिया गठबंधन के साथ थे, तो पिछले साल एक सर्वे हुआ था, जिससे पता चला कि 34 परसेंट लोग ऐसे हैं, जिनकी आमदनी छ: हजार रुपए प्रति माह से भी कम है । 10 हजार रुपए की आमदनी वाले 63 परसेंट लोग हैं । यह सवाल उठा है कि जो पैसे जा रहे हैं, वे कहाँ जा रहे हैं? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए ।

19.53 hrs (Shri Dilip Saikia *in the Chair*)

सोन नहर अंग्रेजी राज में बना था, जिसकी लगातार उपेक्षा की जा रही है । बिहार की कृषि अर्थव्यवस्था और देश की कृषि अर्थव्यवस्था में उसका काफी योगदान है । इंद्रपुरी डैम की माँग पुरानी है, उसे आप पूरा करें । सोन नहर का आधुनिकीकरण कीजिए । औरंगाबाद-बिहटा रेल लाइन, डिहरी-जपला रेल लाइन, डिहरी-बलिया नई रेल लाइन का निर्माण कराया जाए । दाऊदनगर और डिहरी में हर जगह पर प्रशासन की सुविधा की माँग हो रही है, इसे जिला बनाने की बात है । सुअरा हवाई अड्डा का निर्माण और दुधैला, डेहरी में मेडिकल कॉलेजों को ठीक करने और नये मेडिकल कॉलेजेज बनाने की बात है ।

सोन नहर में सुपर बिजली ग्रिड बनाने की बात है । इसके साथ-साथ अंत में मैं यह बात कहूँगा । अभी एक बात हो रही थी कि सत्ताधारी दल बीजेपी अपने को बहुत संस्कार वाला दल कहती है । आपका संस्कार हाथरस में कहाँ गया था, अभी-अभी कुम्भ में आपका संस्कार कहाँ गया था । मरने के बाद परिवार वालों को लाश दी जाती है कि वे उसका दाह कर्म करें, लेकिन दलितों, आम नागरिकों के साथ यह सरकार क्या कर रही है, यह सरकार लाश छिपाने में लगी हुई है । जो डबल इंजन की सरकार डबल बुलडोजर बनकर कल मुसलमानों के घर तोड़ रही थी, आज उसने जेसीबी को लाश छिपाने में लगाया हुआ है । यही उसका काम बन गया है । हम कहना चाहते हैं कि संस्कार की बात आपके मुँह से शोभा नहीं देती है । जो आप तमिल काशी संगमम् पर पीठ ठोक रहे हैं कि देखिए हम सांस्कृतिक एकता के पक्ष में खड़े हैं, आप क्या खड़े होंगे, आपने तो इसी सदन से, आपने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया कि सेतु समुद्रम नाम की कोई चीज नहीं थी, राम-रावण युद्ध कभी हुआ ही नहीं, इसलिए ये बेकार की बातें हैं । यह सुप्रीम कोर्ट में आप ही की पुरानी सरकार ने एफिडेविट देकर कहा है । जहाँ पर कॉरपोरेट हितों से मामला टकराता है, वहाँ पर आस्था की बात पीछे छूट जाती है । इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि यह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद नहीं है, यह मतलब की बात है । अपने स्वार्थ में जो आपको सूट करता है, उसको आप लागू करते हैं । आप कॉरपोरेट हितों का संरक्षण करते हैं । कॉरपोरेट धीरे-धीरे विकास के ऐसे मॉडल पर ले जा रहे हैं कि वे 50 लाख रुपये के पेड़ काटने का ठेका लेते हैं और तीन करोड़ रुपये के पेड़ काट लेते हैं । पूरे खनिज को बर्बाद करके छोड़ दे रहे हैं । पर्यावरण संकट में है । इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इस मॉडल को रोकिए, यह भारत के विकास का रास्ता नहीं है । आप अपनी पीठ अपने आप मत थपथपाते रहिए । यह भारत को विनाश की तरफ ले जा रहा है । हमारा पर्यावरण संकट में पड़ रहा है और खेती चौपट हो रही है ।

महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद ।

***m73 डॉ. राज कुमार चब्बेवाल (होशियारपुर) :** महोदय, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने जो संसद के समक्ष अभिभाषण दिया, उस पर मुझे बोलने का मौका दिया । मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि यह मेरी मेडेन स्पीच है और यदि आप मुझे एक-दो मिनट का अतिरिक्त समय दे देंगे तो मैं आपका आभारी रहूँगा ।

उन्होंने अपने अभिभाषण में कहा कि हमारे लोकतंत्र को जो 75 वर्ष हुए हैं, जो 26 जनवरी को हमने सेलिब्रेट किया, हमारा देश गणतंत्र बना, उस पर माननीय राष्ट्रपति जी ने बात की । मुझे गर्व है कि बाबा साहेब भीम राव अंबेडकर, जो ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने संविधान को प्रारूप दिया, मुझे बड़ा खेद और दुख होता है कि लोक सभा के चुनाव के पहले बीजेपी के कुछ लीडर्स के स्टेटमेंट्स आ रहे थे । कर्नाटक के एक्स एमपी, अयोध्या के एक्स एमपी, बीजेपी के नागपुर से कैंडिडेट, उनकी स्टेटमेंट्स आयीं कि अगर

दो तिहाई सीटें बीजेपी को मिल जाएं, 400 सीटें मिल जाएं तो संविधान खत्म कर देंगे, संविधान बदल देंगे । वही बात जब दोबारा सदन में उठी, माननीय मंत्री जी ने जो बोला कि मान्यवर, अब यह फैशन हो गया है, अंबेडकर, अंबेडकर, अंबेडकर, अंबेडकर, अंबेडकर, अंबेडकर, यदि इतनी बार भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता । यह बात उनकी मनोवृत्ति को दर्शाती है । यह बात बीजेपी की मनोवृत्ति को प्रकट करती है । इसके विपरीत अगले दिन ऐसा षड़यंत्र रचा गया कि उस पर चर्चा करने का, उस पर बोलने का भी मौका नहीं दिया गया ।

20.00 hrs

महोदय, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू दलित समाज से यदि राष्ट्रपति बनी हैं तो बाबा भीम राव अम्बेडकर साहब जी की कृपा से बनी हैं । मैं आम आदमी पार्टी से हूं और मैं अपने पंजाब के मुख्य मंत्री जो पहले लोक सभा से सांसद रहे हैं, उन्होंने पंजाब में ऐसा काम किया है जो मेरे खयाल से पूरे देश में, यहां तक कि पार्लियामेंट में भी वह काम नहीं हुआ । वह काम यह है कि एडवोकेट जनरल आफिस में पंजाब सरकार ने रिजर्वेशन दी है । यह रिजर्वेशन केवल पंजाब में है और देश के अंदर कहीं भी नहीं है । मैं विनती करता हूं कि इसे देश के अन्य राज्यों में और केंद्र सरकार में भी लागू करना चाहिए । आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में दलित विद्यार्थियों को विदेशों में मुफ्त शिक्षा देने की बात की है और बाबा साहब के सपनों को साकार करने का काम किया है । मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ी सोच है ।

महोदय, मैं सुबह श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी को सुन रहा था । वे बहुत चिंतित दिखाई दिए । उन्होंने देश की बात नहीं कही, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बात नहीं की लेकिन उन्होंने दिल्ली के बारे में लगातार बोला कि हमने यह किया, हमने वह किया । सच्चाई यह है कि इसी पार्लियामेंट में नेशनल केपिटल टेरिटरी एक्ट में जो अमेंडमेंट वर्ष 2023 में हुई, उसमें दिल्ली के चुने हुए विधायकों की और चुनी हुई सरकार की सारी पावर्स एलजी को दे दी । लोकतंत्र की इससे बड़ी हत्या और क्या हो सकती है? इसके बावजूद मुझे उनके भाषण से यही लगा कि यहां से दिल्ली के लिए प्रचार हो रहा है और वे दिल्ली के लिए डरे हुए हैं । वे दिल्ली की विकास क्रांति से परेशान हैं । दिल्ली की आम आदमी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं, उनकी गारंटियों से वे परेशान हैं । यह जो ?गारंटी? शब्द ईज़ाद किया है, वह सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने किया और बाद में आपने उसे अपना लिया । बात यह है कि गारंटी की बात आपने जरूर की है लेकिन कभी गारंटी दी नहीं । दिल्ली में मुफ्त बिजली पानी मिल रहा है, मुफ्त शिक्षा मिल रही है, मुफ्त दवाई मिल रही है, मुफ्त पढ़ाई हो रही है और महिलाओं का सफर फ्री हो रहा है, इससे ये परेशान हैं । मुझे ये सुबह बहुत परेशान दिखे और इससे भी ज्यादा परेशानी तब हुई जब उन्होंने यह पढ़ा कि यहां महिलाओं के लिए 2100 रुपये महीना हो रहा है और सबसे ज्यादा उन्होंने ओफेंडेड महसूस किया जब पुजारियों और ग्रंथियों को 18000 रुपया देने का वायदा

किया । इस बात पर उन्होंने महसूस किया कि हमारा एजेंडा तो आम आदमी पार्टी ने ले लिया है ।

महोदय, हमारे सुप्रीमो की मैं प्रशंसा करूंगा कि वे मानते हैं कि यमुना का काम थोड़ा रहता है और उसे हमें करना है । मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि यहां इतने बजट पेश हुए, क्या कभी किसी ने बोला है कि हमारा ग्रोथ रेट कम है और हमें इसे ऊपर करना है । हमारा कर्ज 205 लाख करोड़ रुपये हो गया है, हमें उसे कम करना है ।

महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया और मैं बिधूड़ी जी को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 8 फरवरी को दिल्ली में आम आदमी पार्टी की ही सरकार बनेगी ।

एडवोकेट चन्द्र शेखर (नगीना) : सभापति जी, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर आपने मुझे अपनी कहने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं । मैं जातिगत जनगणना से अपनी बात शुरू करूंगा, जिसकी देश को जरूरत है, क्योंकि जनगणना होगी तो आंकड़े आएंगे और आंकड़े आएंगे तो बजट सही तरह से लोगों तक पहुंच पाएगा और लोगों को फायदा पहुंचेगा । अयोध्या में तीन दिन तक पुलिस ने कार्रवाई नहीं की और इसका खामियाजा एक बेटी को अन्याय के रूप में उठाना पड़ा और मुख्य मंत्री जी यहां खड़े होकर राजनीतिक स्पीच में उस बेटी के अपमान का तमाशा बना रहे थे, यह बहुत दुखदायी है ।

इसके साथ-साथ कुम्भ में जिनकी जान गयी, उनको मैं श्रद्धांजलि देता हूं और आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से कहता हूं कि वे उनकी सूची दे दें तो सभी लोगों तक मुआवजा पहुंच जाए । यह बहुत अच्छी बात है ।

सर, मुझे देश भर की सरकारों को एक आईना दिखाना है । बागपत के एक बच्चे जितेन्द्र को न्याय नहीं मिला, उसने इसी पार्लियामेंट के सामने आत्महत्या कर ली ।

परभणी में बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ा गया । वहां सोमनाथ सूर्यवंशी को पुलिस ने मार दिया ।

पंजाब में अमृतसर में बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा का किस तरह से अपमान किया गया? गोरखपुर में दो दलित बच्चों की हत्या हुई । सूरत में एक दलित बच्ची को फीस न चुका पाने के कारण अपमानित किया गया । उसने आत्महत्या कर ली । झुंझुनू, राजस्थान में दोबारा मटकी छूने पर पिटाई की गयी । जम्मू के कठुआ में एक नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया । सहारनपुर में भू माफियाओं ने देवबंद में श्मशान की भूमि पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की, गोलीबारी की । आजमगढ़ में सूरज की हत्या हुई और पुलिस अपराधियों को बचाने का काम कर रही है ।

सर, पहले एस.सी., एस.टी. को जमीन मिलती थी । कई सरकारों ने उसे पट्टे के रूप में दी । उन जमीनों को पहले तो दबंगों ने कब्जा करके रखा और अब उन जमीनों

को सरकार भी छीन रही है । शहर में रहने वाले एस.सी., एस.टी. को आवासीय पट्टा दिया जाना चाहिए । आज़ादी के 75 सालों के बाद भी उनके पास घर नहीं है ।

एस.सी., एस.टी. के बच्चों को स्कॉलरशिप्स दी जाती थीं । केन्द्र और राज्य के बीच आपसी विवाद है कि 60 प्रतिशत आप देंगे, 40 प्रतिशत हम देंगे । इस चक्कर में कई बार उनके बीच स्कॉलरशिप्स समय पर नहीं पहुंच पाती हैं । इससे उनकी मानसिक प्रताड़ना होती है । उन्हें स्कूल और कॉलेज प्रशासन परेशान करता है । इसलिए मेरी राय है कि ज़ीरो बैलेंस पर उन बच्चों की एडमिशन करायी जाए । अगर सरकार कुछ करना चाहती है तो उन बच्चों का कुछ फायदा हो जाए ।

सर, देश भर में बहुत सारे छात्रावास बने हैं, लेकिन उन छात्रावासों की स्थिति वैसी ही जर्जर है, जैसी हमारे स्कूलों की है । उन छात्रावासों का जीर्णोद्धार कराया जाए, उनके रखरखाव का ख्याल रखा जाए, क्योंकि वहां देश का भविष्य तैयार हो रहा है । ऐसी ही हालत स्कूलों की है ।

सर, मैं उत्तर प्रदेश के नगीना क्षेत्र से आता हूं । वहां के स्कूल ऐसे हैं कि किसी भी दिन वे गिर जाएंगे और उससे बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा । उसे कोई पूछने वाला नहीं है ।

सर, ओबीसी समुदाय की बात की जाए । अब वक्त आ गया है कि ओबीसी समुदाय को विधान सभा और लोक सभा में आरक्षण मिलना चाहिए, जिससे यहां लोक सभा में और सभी राज्यों की विधान सभाओं में उनकी पर्याप्त संख्या आ पाए । यह सामाजिक समानता की दिशा में एक जरूरी कदम है । ओबीसी को भी एस.सी.. एस.टी. की तरह प्रोमोशन में रिज़र्वेशन मिले । ओबीसी आरक्षण में जो क्रीमी लेयर जोड़ा गया है, वह असंवैधानिक है । उसको खत्म किया जाए । सरकारी स्वायत्त संस्थानों में भी सरकारी विभागों के समतुल्य पदों को चिह्नित किया जाए तथा उनकी समतुल्यता स्थापित की जाए, ताकि इन संस्थानों में कार्यरत ओबीसी कर्मचारियों के बच्चों को भी आरक्षण का लाभ मिल जाए ।

सर, आज पत्रकार सुरक्षित नहीं हैं । भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने पर पत्रकार मुकेश चन्द्राकर की हत्या की गयी । इस स्थिति में कौन पत्रकार ईमानदारी के साथ पत्रकारिता करेगा?

किसानों को एमएसपी की कोई लीगल गारंटी नहीं है । डल्लेबाल जी एक बड़े किसान हैं । वे 69 दिनों से आमरण अनशन पर हैं । क्या पता किसी दिन उनकी जान चली जाए, सरकार को उनकी बातों को संज्ञान में लेना चाहिए ।

सर, माइनॉरिटीज़ की बात करूंगा, धार्मिक आस्था की बात है । हम तो सभी का सम्मान करते हैं क्योंकि हमने शपथ ली है । हम संविधान को मानने वाले लोग हैं । बड़ौत में भगवान आदिनाथ निर्वाण लड्डू पर्व के दौरान दुर्घटना हुई । उसमें 8 श्रद्धालुओं की जान चली गयी । उसमें 75 घायल हैं । सरकार ने इसका संज्ञान नहीं लिया । अयोध्या की

तरह उनको भी मुआवजा दे देते तो उनमे मन में भी माइनॉरिटी होने की जो पीड़ा है, वह खत्म हो जाती ।

न्यायालय द्वारा आदेश पारित होने के बावजूद भी जैन समाज को जैन महातीर्थ गिरनार, जूनागढ़, गुजरात में पूजा करने से रोका जा रहा है, जो उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है ।

बरेली में सार्वजनिक रूप से हज़रत पैगम्बर मोहम्मद साहब के खिलाफ सार्वजनिक अपमानित गाने चलाए गए । क्या मुसलमानों की धार्मिक आस्था का सम्मान नहीं होना चाहिए? आज़ादी में उनका भी तो योगदान है । इन अपराधियों को किसका संरक्षण प्राप्त है कि वे खुले आम इस तरह के गाने बजाकर अपमानित कर रहे हैं ।

सर, संभल की हिंसा में अब तक 74 लोगों की गिरफ्तारी हुई है । वहां के मुस्लिम डर के साये में हैं । सरकार बेगुनाहों की गिरफ्तारी बंद करे ।

सर, महाराष्ट्र में चन्द्रपुर जिला है । वहां मैं अभी गया था । वहां के चिमुर तालुका में ताडोबा फॉरेस्ट में संघारामगिरी पहाड़ पर एक बहुत पुराना बौद्ध स्थल है । वहां बौद्ध भिक्षुओं के लिए सरकार बिजली नहीं देती, उनके लिए रास्ता नहीं देती । उनकी बहुत बुरी हालत है । यह उनकी धार्मिक आस्था का सवाल है ।

तथागत बुद्ध की ज्ञान स्थली होने के कारण बोध गया, जो बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है, इस स्थल पर अवैध कब्जा हटा कर उसे बौद्ध धर्म के अनुयायियों को सौंपा जाए । उनके मन में बहुत चिंता है । वहां देश-विदेश से बहुत लोग आते हैं । इससे हमारे देश की छवि भी खराब हो रही है ।

महोदय, अभी 12 फरवरी को सतगुरु रविदास जी महाराज की जयन्ती है और 14 अप्रैल को बाबा साहेब अम्बेडकर की जयन्ती है । 11 अप्रैल को राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले की जयन्ती है । इनको मानने वाले लोग एक कार्यक्रम करना चाहते हैं । अभी जिस विचार की सरकार है, वे तो कोई भी कार्यक्रम कर लेते हैं, लेकिन अगर ये कोई कार्यक्रम करना चाहते हैं तो इनको कोई छूट नहीं है और इन्हें इसकी कोई परमिशन नहीं दी जाती है ।

मैं अंत में थोड़ा सा और कहूंगा, सरकार से मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकारी पैसे पर एक ही धर्म का अधिकार है? दूसरे धर्म के धार्मिक आयोजनों का क्या होगा? अभी कुंभ में आपने 7.5 हज़ार करोड़ रुपये खर्च किए हैं । आप रविदास जयंती पर कितना खर्च करेंगे? 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडर जयंती होती है, जिनकी जय-जयकार होती है, उनकी जयंती पर कितना खर्च करेंगे? उनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए आप क्या सहयोग करेंगे? यह सवाल बहुत बड़ा है । मुझे आपके माध्यम से सरकारों से कहना है कि क्या इस देश से दलितों, मुसलमानों, पिछड़ों और आदिवासियों को सरकार निकाल देना चाहती है? जिस तरह से उनके अधिकारों को, स्कॉलरशिप को, उनकी पढ़ाई को रोका जा रहा है और हेल्थ सैक्टर में कोई पैसा नहीं खर्च हो रहा है । क्या उनको निकाल कर इस देश को एक ऐसा देश बनाना चाहते हैं, जहां कुछ ही धर्म के लोग रहेंगे? सर, मैं

यह कहना चाहता हूँ कि देश सबका है और अगर सरकार यह तय कर के बैठ गई कि वह दलितों, मुसलमानों, पिछड़ों और आदिवासियों को निकाल देगी तो यह संभव नहीं है । इतनी बड़ी आबादी है । हम अंबेडकरवादी लोग उनके पक्ष में खड़े हैं क्योंकि हमने शपथ ली है कि हम हर व्यक्ति का संरक्षण करेंगे ।

सर, मैं आपके माध्यम से सरकार को चेतावनी के तौर पर कहना चाहता हूँ कि सरकार अपनी इस आदत में सुधार करे, वर्ना इसके परिणाम सड़कों पर बहुत भारी होंगे । अगर मुसलमानों को, दलितों को आप लोग निकालने के बारे में सोचेंगे और उनकी धार्मिक आस्था का अपमान करेंगे तो यह हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे ।

सर, अंत में अपनी बात को समाप्त करते हुए मैं यह कहना चाहता हूँ कि सरकार सभी का ध्यान रखे और उनमें भी गरीबों का ज्यादा ध्यान रखे, क्योंकि अभी जेब कटाई हुई, प्रयागराज का 2800 रुपये का टिकट है, कुंभ की वजह से कुछ दिनों से 56,000 रुपये का हो गया था । मैंने मंत्री जी से कहा, तब जा कर उन्होंने संज्ञान लिया, तब आधे रेट हुए हैं । मैं इसलिए कह रहा हूँ कि धर्म के नाम पर धंधा और लूट नहीं होनी चाहिए । इसकी जिम्मेदारी सरकार की है । धन्यवाद ।

***m75 श्री गणेश सिंह (सतना) :** सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदया का आभार एवं धन्यवाद प्रकट करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से उन्होंने हमारी सरकार द्वारा पिछले दस वर्षों में किए गए हर क्षेत्र में विकास कार्यों का उल्लेख किया तथा भविष्य में, यानि वर्ष 2047 तक, जब देश आजादी की 100वीं वर्षगांठ मनाएगा, उन लक्ष्यों का जो देश हित एवं राष्ट्र हित में संकल्प लिया है, संसद के सामने रखा है, उसकी मैं तहेदिल से प्रशंसा करता हूँ और पुन: उनका आभार प्रकट करता हूँ ।

महोदय, सबसे पहले तो उन्होंने भारत की सनातन एवं सांस्कृतिक परंपरा के तहत ऐतिहासिक महाकुंभ की सराहना की । वहीं मौनी अमावस्या के दिन हुए हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया । अभी दो माह पहले हमने संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ मनाई है और कुछ दिन पहले ही भारतीय गणतंत्र ने 75 वर्षों की यात्रा भी पूरी की है । यह अवसर लोकतंत्र की जननी के रूप में भारत के गौरव को नई ऊंचाई देगा । भारत की विकास यात्रा के इस अमृत काल को आज मेरी सरकार अभूतपूर्व उपलब्धियों के माध्यम से नई ऊर्जा दे रही है । तीसरे कार्यकाल में तीन गुना तेज़ गति से काम हो रहा है । आज देश बड़े निर्णयों और नितियों को असाधारण गति से लागू होते देख रहा है । लेकिन दुर्भाग्य है और दुख भी होता है कि कांग्रेस की एक बहुत बड़ी नेता, जो कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष रही हैं, वे महामहिम राष्ट्रपति जी को ? * कहती हैं । यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है । महामहिम राष्ट्रपति जनजातीय समाज से हैं और 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही हैं । इस नाते भी उनका अपमान हुआ । नारी समाज का अपमान हुआ और राष्ट्रपति पद का अपमान हुआ है । इस तरह से उन्होंने जो राष्ट्रपति जी के बारे में कहा है, मैं तो

आज सभा के माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि वे माफी मांगे, सार्वजनिक रूप से माफी मांगे ।

देश प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तेज़ गति से बदल रहा है । जहां एक ओर देश की अर्थव्यवस्था दुनिया में तीसरे स्थान पर पहुंचने के लिए तैयारी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ देश में पीएम-गतिशक्ति योजना के माध्यम से अधोसंरचना के विकास के कार्य जम्मू-कश्मीर से ले कर कन्याकुमारी तक और कच्छ से ले कर कोहिमा तक, बिना किसी भेदभाव के, बिना कोई पक्षपात के किए जा रहे हैं ।

देश की सबसे बड़ी चुनौती गरीबी है । यह चुनौती आज की नहीं है, बल्कि देश की आजादी के बाद से ही रही है । पिछले दस वर्षों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में आजादी के बाद पहली बार गरीबी पर काबू पाने का काम शुरू हुआ । जहां एक तरफ उनकी बुनियादी जरुरतें पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, मुफ्त में अनाज योजना, हर घर में बिजली योजना, हर घर में खाना पकाने के लिए रसोई गैस योजना, बीमारी के लिए पाँच लाख रुपये का आयुष्मान कार्ड योजना और हमारी माँ, बहन, बेटियों के सम्मान में निशुल्क रसोई गैस दी गई है । इसी तरह से 12 करोड़ से ज्यादा घरों में माँ, बहन और बेटियों के सम्मान के लिए शौचालय बनाया गया है । ये काम बहुत छोटे-छोटे थे, लेकिन उनको देश की आजादी के बाद वर्षों तक इंतजार करना पड़ा । जब नरेन्द्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इन सारे कामों को पूरा किया । 10 सालों में मोदी जी ने 4 करोड़ गरीबों के घर बना दिए । अभी 3 करोड़ और नए घर बनाने का उन्होंने संकल्प ले लिया है । 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त में खाद्यान्न दिया गया है । जो गरीब हमेशा रोटी की चिंता करता था, उनको रोटी की चिंता से मुक्त कराया । आज 50 करोड़ों लोगों को पाँच लाख रुपये का मुफ्त में इलाज किया जा रहा है । अब 70 साल से अधिक के जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं, उनको भी इस सुविधा के साथ जोड़ने का काम शुरू कर दिया गया है । हमारे मध्य प्रदेश की सरकार और वहां के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी ने आयुष्मान के जितने कार्डधारी हैं, उन सबको नि:शुल्क एम्बुलेंस और एयर एम्बुलेंस की सुविधा प्रदान की है । 10 करोड़ घरों में नि:शुल्क रसोई गैस सिलेंडर दिए गए हैं । 12 करोड़ घरों में बहन-बेटियों के सम्मान में शौचालय बना है । 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा की सीमा से बाहर पहली बाहर आए हैं । आजादी की इतिहास में पहली बार देखा गया कि इतनी बड़ी संख्या में लोग गरीबी रेखा की सीमा से ऊंचे उठे हैं । पीएम गति शक्ति योजना के तहत चल रहे जो अधोसंरचना के कार्य हैं, उसमें तेजी लाने के लिए 11 करोड़ रुपये का फिर से एक नया प्रावधान हुआ है । आज देश में सड़कों का जाल बिछा हुआ है । जो लोग कहते थे कि देश में कुछ नहीं हुआ । आज वे सचमुच में जब अपने आत्मा पर हाथ रखकर बोलेंगे तो देखेंगे कि राष्ट्रीय राजमार्ग कहां नहीं बने है । कहां गांव में सड़के नहीं बनी है । सब जगह सड़कें बनी हैं । रेल यात्रा में आधुनिक सुविधाएं दी जा रही हैं । विश्वस्तरीय रेलवे स्टेशन बन रहे हैं । आज बंदे भारत ट्रेन चल रही है । नमो भारत ट्रेन चल रही हैं । इन

सभी ट्रेनों का उत्पादन भी यहीं हो रहा है, जो पहले कभी नही होता था । 100 हवाई अड्डों को क्षेत्रीय उड़ान सेवा में शामिल किया गया । उनमें से बहुत सारे हवाई अड्डे बन कर तैयार हो गए हैं । मेरे लोक सभा क्षेत्र सतना का हवाई अड्डा भी बनकर तैयार है । यह लोकार्पण की स्थिति में आ चुका है । वहां से हवाई परिचालन का इंतजार है ।

महोदय, आज मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से मांग करूंगा कि सतना हवाई अड्डे की लंबाई बढ़ाई जाए । वहां रात की लैंडिंग की सुविधा भी दी जाए । हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है । आज 100 से अधिक औद्योगिक पार्क बनाने की घोषणा की जा रही है । यह एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए जबरदस्त काम है । इससे नए रोजगार सृजित हो सकते हैं । इससे हमारे युवाओं को रोजगार मिल सकता है । बैंकों के साथ उनका टाइ-अप हो ताकि उनको अधिक से अधिक लोन मिल सके ।

महोदय, दुर्गम क्षेत्रों में जो ब्रिजेज बने हैं, वे अद्भूत हैं । दुनिया की सबसे बड़ी सुरंग और केबल ब्रिज कश्मीर में बनी है । अभी कश्मीर के हमारे साथी कह रहे थे कि वहां कुछ भी काम नहीं हुआ है । नॉर्थ-ईस्ट के जितने भी प्रदेश हैं, उन सभी में एयर कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी के साथ जोड़ा जा रहा है । जो नदी जोड़ो अभियान था, यह अटल जी की कल्पना थी । यह बाबा साहब अंबेडकर जी की भी कल्पना थी । उसका सबसे पहला काम हमारे मध्य प्रदेश में हुआ । वहां केन-बेतवा योजना का काम 44 हजार करोड़ रुपये की लागत से शुरू हो चुका है और दो नए प्रोजेक्ट्स भी लिए गए है । एक पार्वती-काली सिंध परियोजना है और दूसरा, पोलावरम सिंचाई परियोजना है । इसके लिए 12 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है । मेडिकल की 75 हजार सीटें बढ़ाई जा रही है । आज खेल विश्वविद्यालय बना है । कृषि अनुसंधान विश्वविद्यालय बने हैं । नए एम्स खोले जा रहे हैं । कई जगह आईआईटी खोले जा रहे हैं । अभी त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की भी स्थापना हो रही है । अभी हमारे गृह मंत्री जी ने इस बिल को इंट्रोड्यूस किया है ।

महोदय, नई शिक्षा नीति में हमारे 13 देशी भाषाओं के माध्यम से पढ़ाई होगी । प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का चौथा चरण भी ले लिया गया है । इसमें 25 हजार नए गांव जोड़े जाएंगे । धन धान्य योजना के माध्यम से जहां कृषि का उत्पादन कम है, उनको शामिल किया गया है । देश के अति पिछड़े आकांक्षी जिलों में बहुत तेज गति से विकास के काम चल रहे हैं । ढाई लाख पंचायतों में ऑप्टिकल लाइन बिछा कर डिजिटल बनाने का काम हुआ है । 1000 किलोमीटर से अधिक मेट्रो ट्रेन की रूट तैयार हो गई है । यह दुनिया में दूसरे नंबर पर है । 100 औद्योगिक पार्क बनाए जा रहे हैं ।

आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार जो सरकार काम कर रही है, वह अद्भूत है । यह सभी क्षेत्रों में हो रहा है ।

युवाओं को पांच सौ कंपनियों में इंटर्नशिप दिए जाने का भी लक्ष्य निर्धारित हुआ है । मेधावी छात्रों के लिए विद्या लक्ष्मी योजना शुरू हो रही है । आज लगभग 10 करोड़

महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं और 9 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का बैंक का ट्रांजैक्शन उनके लिए हुआ है । लगभग 1.15 करोड़ दीदियां लखपति बन चुकी हैं । दीदियां ड्रोन चला रही हैं । आज बेटियां लड़ाकू विमान चला रही हैं, सेना में भर्ती हो रही हैं, कॉरपोरेट कंपनीज़ में नियुक्त हो रही हैं । देश के युवा स्टार्ट अप से लेकर स्पेस फील्ड में देश का नाम रोशन कर रहे हैं । ?माई भारत? पोर्टल के जरिए लाखों युवा जुड़ रहे हैं । पिछले एक दशक में ?मेक इन इंडिया?, ?स्टार्ट अप इंडिया?, ?स्टैंडर्ड इंडिया?, ? डिजिटल इंडिया? जैसी पहल से युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए गए । पिछले दो वर्षों में हमारी सरकार ने दस लाख स्थायी नौकरियां दीं । प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार के तीसरे कार्यकाल में मुद्रा ऋण भी बढ़ाया गया ।

जो लोग कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ, वे शायद पुराने जमाने के लोग हैं । आज भारत बोल रहा है, गली-गली से आवाज आ रही है । देश में डिजिटल क्रांति हुई है । जो जूता सिलने वाला है, जो सब्जी बेचने वाला है, जो चाट की दुकान लगाने वाला है, जो चाय बेचता है, वह भी डिजिटल पेमेंट ले रहा है । यह किसी ने सोचा नहीं था । पूर्व वित्त मंत्री जब यहां के सांसद थे, तब कहते थे कि यह हमारे देश में संभव ही नहीं है । वे कांग्रेस के वित्त मंत्री थे । आज वह सब कुछ सम्भव हो चुका है । भारत में 50 पर्सेंट से ज्यादा लेन-देन डिजिटल हो चुका है । छोटे दुकानदारों का इसमें सबसे बड़ा विश्वास जुड़ा हुआ है । आज आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर से नागरिकों का बेहतर जीवन हुआ है । पिछले दशक में भारत ने जो कार्य किए हैं, उनमें कई तो माइलस्टोन बन चुके हैं । हमारा भारत सबसे बड़ा दूध, दाल और मसाले का उत्पादक देश बन चुका है ।

सभापति जी, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के आठवें वेतन आयोग का गठन हुआ है । इसकी सराहना हो रही है । 12 लाख रुपये तक जिनकी इनकम है, वे टैक्स से मुक्त हुए हैं । हमारे यहां डेढ़ करोड़ लोग हवाई यात्रायें कर रहे हैं, उसको चार करोड़ तक ले जाने का संकल्प है । प्रधान मंत्री जी का जो मंत्र है, ?सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास?, इस मंत्र का सिर्फ एक ही लक्ष्य है विकसित भारत का निर्माण । नेता प्रतिपक्ष पिछड़ों के लिए बड़े घड़ियाली आंसू बहा रहे थे । वे शायद भूल गए कि वे जो बात कह रहे हैं, जब उनकी सरकार वर्ष 2011 में थी, मैं तब भी सांसद था और वे भी सांसद थे । उस समय पर उनके सहयोगी साथी, आरजेडी के, जेडीयू के, इवेन भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा था कि जातीय गणना करा दो । उस समय पर सरकार पीछे हट गई और नहीं करा पाई । आज वे उनके लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं । आज जो भी पिछड़े वर्गों के लोगों को मिला है, चाहे वह नीट परीक्षा में, चाहे वह केंद्रीय विद्यालय में, चाहे वह सैनिक स्कूल में, चाहे नवोदय विद्यालय में बच्चों को जो आरक्षण मिला है, वह प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने दिया, पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मोदी जी ने दिया और क्रीमी लेयर का दायरा मोदी जी ने बढ़ाया । नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि पिछड़ों के लिए कुछ नहीं हुआ । इसके लिए अगर कोई जवाबदार है तो वे खुद हैं । हमारे देश के

प्रधान मंत्री स्वयं पिछड़ी जाति के हैं । आज उनके नेतृत्व को दुनिया सराह रही है । आज वे पूरे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं । सबका साथ, सबका विकास उन्होंने सिर्फ कहा ही नहीं, उसको जमीन में उतारकर दिखा दिया । विपक्ष के साथियों को यह तकलीफ हो रही है । प्रयागराज में जो महाकुम्भ हो रहा है, इसकी सफलता को देखकर विपक्ष के लोगों को बहुत परेशानी हो रही है । वहां पर इतनी सारी जो व्यवस्था हुई है, उसको पूरी दुनिया सराह रही है । जो व्यक्ति वहां जाते हैं, उनकी जुबान से उसकी प्रशंसा निकलती है । यह सनातन संत का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन है, जो 140 वर्षों के बाद हो रहा है ।

प्रधान मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश प्रगति कर रहा है । इसमें देश के सभी नागरिकों का साथ जुड़ा हुआ है । उनकी सरकार के कोई काम भेदभावपूर्ण नहीं हैं, सब पक्षपात रहित है । मैं एक बार फिर से कहूंगा कि भारत विकसित देश बनने जा रहा है, आप सब लोग उनके साथ चलें और देश की तरक्की में भागीदार बनें । मैं एक बार फिर राष्ट्रपति जी को बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं । उन्होंने जो अभिभाषण किया, मैं उसके समर्थन में अपनी बात रख रहा हूं और हृदय से बहुत-बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूं ।

SHRIMATI PRATIBHA SURESH DHANORKAR (CHANDRAPUR): Hon?ble Chairperson, thank you, I rise to express my views on the motion of thanks on President?s Address. In the President?s Address there was a mention about the extension of PMAY. But I am sorry to say that the Aid under this scheme has not been released yet and it is always distributed very late. The monetary assistance given is very meager in rural area in comparison to urban area.

In the President?s Address, there was a mention about distribution of property cards for ownership rights. But, in my district, the farmers who have been doing farming for generations, still have not received permanent ownership rights. We must think about how would they get the benefits of this scheme?

There was a mention about the Government?s focus on education and employment for youths in President?s Address, but the Modi Government?s promise to provide 2 crore jobs proved to be fake and baseless. The youths are continuously registering their names on Rojgar Portal, but they are not getting the jobs. This government has registered a record of the highest unemployability during its tenure of last 10 years.

This government has started the trains like Vande Bharat, Amrit Bharat and Namo Bharat from various places, but no new trains from the

tribal district of Chandrapur have been started. So, it is my request to the Government to restart the trains for Pune and Mumbai which were discontinued during Corona Pandemic.

Hon?ble President has mentioned about the Digital India. We can see that cybercrimes are increasing day by day. These cyber criminals are fooling the people at large, but no concrete action is being taken against these criminals.

Hon?ble President of India talked about the pensionary benefits to the employees, but the old pension scheme is not being implemented for the State Government employees of Maharashtra. It is very important to them and that is why the Central Government needs to take a concrete decision in this regard.

Our President talked about Nari Shakti Vandan, but in our Maharashtra there is an urgent need to implement ?Shakti law?. We have been repeatedly requesting the Union Government in this connection but nothing has been done in this regard. If you really want to grant equal rights to women, it is necessary to implement this law.

The Union Government took the credit for crop insurance scheme, but it is now more than a year, the crop insurance benefits have not been credited to farmer?s account. This issue of MSP is also still pending. The MSP has not been declared by the Union Government but it is very important for farmers survival.

In the President?s Address, it is talked about air connectivity and new airports. In my Chandrapur district, it was proposed to construct a new airport at Murti, but it is still a distant dream. My district is a mineral rich district with deposits of iron ore. A steel hub is there. In the adjoining district of Gadchiroli, Surjagarh Mega Project is there. Many coalfields are located in my district and hence, air connectivity is very much needed there.

Many goals were set about modern and self-reliant farming in President?s Address, but in reality, the story is totally different. No relief and assistance was given to the poor and needy farmers when they faced natural calamities like, unseasonal rains and hailstorming, floods and

draught. They neither received crop insurance benefits nor the loan waiver relief. We, as Government, must stand with them in distress.

The Union Government has spent crores of rupees under Amrit Yojna to provide tap water. We have also spent the same amount of rupees under Jal Jiwan Mission, but it has provided no benefits for irrigation and drinking water facilities. If we are spending this much of public money, then the positive results should also be delivered to the people.

Sir, I have also served Maharashtra Assembly as an MLA for five years term and today I am an MP here. But the Government is providing only Rs 5 crore under MPLADS Fund. It should be increased up to Rs.30 to 40 crore, so that more developmental works can be done for lacs of people.

This President?s Address depicts only the hollow promises made by the Modi Government and hence I register my protest. I oppose this motion of thanks on the President?s Address.

SHRI BALYA MAMA SURESH GOPINATH MHATRE (BHIWANDI): Hon. Chairperson, thank you. I am speaking in this august House today for the first time after the oath taking ceremony. I am really thankful to Hon. Shri Sharadchandra ji Pawar for his blessings, due to which I have been elected as an M.P., Lok Sabha.

I am also thankful to Supriyatai Sule. Before, I start my speech, I want to make it clear that I would like to focus on my State Maharashtra and my Lok Sabha Constituency Bhiwandi.

Sir, we all are well aware that the maximum tax collection is generated from Maharashtra. But, as you know, every time Maharashtra is ignored and injustice is done to Maharashtra State. Today, at Centre as well as at State, BJP is in power but still nothing has been changed. Out of total tax collection, at least 50% funds should be given to our State. But unfortunately, it is not more than 10-15% and I register my protest against this injustice.

Secondly, bullet train route is passing through my Lok Sabha constituency. Its car shed is also situated in my constituency. Sir, thousands of crores have been spent for this project. But there are cases

of corruption in this Mega project. I have talked to collector and SP. This is a dream project of Modiji and I would like to congratulate Modiji.

There are rampant cases of improper valuation of lands and structures related to this project. They are changing the valuation of the construction every year and in this way, they have minted money. These corruption cases must be unearthed. You should look into it properly and you would come to know how they are doing corruption in bullet train project.

Late Nana Shankarsheth is regarded as a pioneer of railway system in India. He was born in Murbad. But this Murbad Tehsil is waiting for railway connectivity. In the year 2022-23, the railway line project worth Rs. 864 crore was sanctioned. But it needed Rs. 1300 crore for land acquisition to complete this project. Still, this amount has not been sanctioned. I would like to request the Union Government to sanction this fund to complete this Rail project. By completing this project in Murbad, we can pay homage to Nana Shankarsheth.

On one hand, we are talking about bullet train, but on the other hand, we are ignoring the basic facilities to railway passengers. At many railway stations like Washind, Asangaon, Adgaon, Badlapur, no basic amenities like, benches, toilets and sheds are available there. I request railway administration to provide these facilities to the middle-class railway passengers.

You talked about farmers? welfare. But this Government is doing nothing for farmers. It is completely ignoring the issues like doubling the farmers? income, increasing the farm yield and MSP. We know that the number of farmers suicide cases is highest in India. The geographical condition is different in Maharashtra.

So, it is Government?s duty to support these farmers in this condition. Government should also try to change these geographical conditions following the other countries in the world.

Recently, there was a Kumbh Mela and a historic event took place at Prayagraj after 144 years. We cannot make arrangement for such a huge gathering within 2-3 months? time. It takes years together for preparation.

Many people have been died there due to stampede. I pay my homage to them but, who is responsible for this?

The Government school?s condition is very pathetic. All schools should be made digital. The school students should get free medical treatment. If we care for better health and education, it would definitely help to build our country?s future.

There were no law and order in Beed and Parbhani districts of Maharashtra and same kind of situation is developing in my Bhiwandi region too. There is one notorious criminal in my Lok Sabha Constituency. He has committed all kinds of crimes like murders, attempt to murder etc. But he is still going scot-free and nobody dares to arrest him.

Lastly, I would like to request to increase the MPLADS fund.

You heard me patiently. I am really thankful to you.

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : सभापति जी, मैं ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स की तरफ से अनाउंसमेंट के लिए खड़ा हुआ हूं ।

A dinner has been arranged for the Members in MP Dining Hall, First Floor, Parliament House. आप डिनर 8 बजे के बाद से ले सकते हैं ।

श्री पुष्पेंद्र सरोज (कौशाम्बी) : सभापति महोदय, आपने मुझे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं । मेरी यह मेडेन स्पीच है और आज मैं बड़े गर्व और सम्मान के साथ कौशाम्बी की जनता को दिल से बधाई देने के लिए यहां खड़ा हूं, जिन्होंने इस देश के इतिहास में मुझ सबसे नौजवान सांसद को चुनने का गौरव दिया । उनका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सर, सबसे पहले माननीय राष्ट्रपति जी ने महाकुम्भ में हुई स्टैम्पीड में जो श्रद्धालु मरे, उनके प्रति संवेदना व्यक्त की, मैं उनका धन्यवाद देता हूं । सदन के माध्यम से पूरा देश उनसे जानना चाहता है कि सरकार के द्वारा दिए गए आंकड़े, जो 30 या 40 हैं, क्या माननीय राष्ट्रपति जी ने उनके प्रति ही संवेदना व्यक्त की है या 700 से ज्यादा जमीनी आंकड़े, जिनको सरकार पेश नहीं कर रही है, उनके प्रति भी संवेदना व्यक्त की है? मैं राष्ट्रपति द्वारा दिए गए अभिभाषण के महत्वपूर्ण बिंदुओं को रखना चाहूंगा, जिनमें उन्होंने कहा है कि सेवा, सुशासन, समृद्धि और गर्व के स्तम्भों पर देश का दृष्टिकोण रखा है, लेकिन पिछले साल की हकीकत को नजदीक से देखें तो यह दावा असली अनुभवों से बिल्कुल अलग दिखाई पड़ता है । सत्ता में सरकार का कम मार्जिन से जीत पाना यह स्पष्ट करता है कि देश के लोगों की सरकार के प्रति बढ़ती निराशा एक सच्चाई है । अगर यह

सरकार सच में सेवा और सुशासन का प्रतीक होती तो भारत की जनता इसे जोरदार समर्थन देती, लेकिन मतदाता का स्पष्ट संदेश इस सरकार को यह है कि अब वे परिवर्तन चाहते हैं ।

Sir, within the first year of this third-term Government, the Government has trampled upon the spirit of the Constitution by introducing controversial legislations like the Waqf Bill and the Constitution (One Hundred and Twenty?Ninth Amendment) Bill, 2024 and the Union Territories Laws (Amendment) Bill, 2024

The Waqf Bill marked as a step towards empowerment and modernisation is in reality a direct assault on the secular fabric of our nation. It is yet another attempt to tighten Government?s control over the religious and cultural traditions of the Muslim community, undermining their autonomy in the name of religion.

Meanwhile, the proposal for ?One-Nation, One-Election? poses an existential threat to India's federal structure. It is nothing more than an attempt to centralize power, diminish the political, economic and social autonomy of the States. Even today, the States are struggling under an unfair fiscal arrangement, particularly after the introduction of the GST. The Centre's political agenda has overshadowed the rightful allocation of tax revenues, pushing many States into financial distress, forcing them into debt rather than empowering them with their due resources. This Government claims to uphold the Constitution, but its action speaks otherwise. It is our duty to call out these contradictions and defend the very principles that define India's democracy.

सभापति महोदय, सरकार खुद को गरीब का रखवाला कहती है, गरीब कल्याण, ? सबका साथ, सबका विकास? जैसे स्लोगन्स देती है, लेकिन असली सच्चाई सबसे परे नहीं है । ये लोग गरीबों का भला करने का वादा तो जरूर करते हैं, लेकिन देश में इनकम इनइक्वेलिटी और बढ़ती चली जा रही है ।

ऑक्सफेम रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ एक परसेंट अमीर लोग इस देश की 40 प्रतिशत से ज्यादा सम्पत्ति को कंट्रोल करते हैं, बाकी गरीब लोग कहीं के नहीं बचे हैं । अर्बन एरियाज में युवा बेरोजगारी 23 प्रतिशत से ज्यादा हो गयी है । अगर हम रूरल इंडिया की बात करें तो मनरेगा का बजट 30 प्रतिशत से ज्यादा कम कर दिया गया है । इससे हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं ।

सर, विश्वगुरू भारत । विश्वगुरू भारत का दुर्भाग्य यह है कि गरीब अन्न योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है । लेकिन भारत के 75 परसेंट मजदूरों के पास कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है । चाइल्ड मालन्यूट्रिशन 35 प्रतिशत से ज्यादा हो चुका है । एक अलार्मिंग सिचुएशन इस देश के रूरल इंडिया में पनप रही है । इसके बावजूद सरकार का ध्यान बड़े-बड़े इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाने में है । महंगे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और कोरपोरेट टैक्स पर है, जबकि गरीब अपनी हालात से खुद लड़ने को मजबूर है । यह डिसकनेक्ट छोटे व्यापारियों के साथ भी क्लीयरली दिखायी देता है, जो देश की इकोनॉमी का बैकबोन कहे जाते हैं । उनका भी बुरा हाल है । बड़ी कम्पनीज़ बिना किसी रुकावट के एक्सपैंड कर रही हैं, लेकिन छोटे दुकानदार और व्यापारी सरकार की अनदेखी का शिकार हो रहे हैं । सरकार फाइनैंशियल इनक्लूजन और लोन्स प्रमोट करने की बात तो करती है, लेकिन उसमें लोगों को नहीं जोड़ती है । अगर हम बनारस की बात करें, जो कि माननीय प्रधान मंत्री जी का क्षेत्र है तो वहां 40 साल से ज्यादा बीएचयू के पास काम कर रहे छोटे-मोटे दुकानदारों को हटा दिया गया, सिर्फ वीआईपी कॉनवॉयज़ के लिए, ? * इन व्यापारियों को फेक स्कीम्स और खोखले वायदे नहीं चाहिए, उनको अपना काम बिना डर के करना है और उनको अपना अधिकार चाहिए ।

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण) : सर, यह उचित नहीं है कि ?*

HON. CHAIRPERSON: Expunge the unparliamentary words.

श्री पुष्पेंद्र सरोज : लेकिन यह प्रधान मंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, जिसके बारे में मैं बोल रहा था और यह हकीकत है ।

माननीय सभापति : वह रिकॉर्ड में नहीं जाएगा ।

श्री पुष्पेंद्र सरोज : उन व्यापारियों को फेक स्कीम्स नहीं चाहिए, उनको अपना हक और अधिकार चाहिए । जो लोग इकोनॉमी का फाउंडेशन कहे जाते हैं, उन्हीं को सरकार इज्जत नहीं देती है तो इसका मतलब क्लीयर है कि सरकार सिर्फ अमीरों के लिए काम कर रही है, जबकि गरीबों के लिए सिर्फ कोरे वायदे कर रही है ।

सरकार प्राउडली फार्मर्स को अन्नदाता कहती है । फाइनैंस मिनिस्टर ने सदन में खड़े होकर फार्मर्स को अन्नदाता कहा, लेकिन उनकी पॉलिसीज़ उनको सिर्फ धोखा दे रही है । वर्ष 2024 की बात करें तो फार्मर्स के प्रोटेस्ट फिर से देखने को मिले जिसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस, लोन वेवर, रेज़िंग इनपुट कॉस्ट और डिलेयड पेमेंट्स के प्रोमिसिस पूरे न होने की वजह से सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं । एमएसपी की लीगल गारंटी का अब तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है । जिस वजह से किसान अपनी फसल उसके असली दाम से बहुत कम प्राइस पर बेचने को मजबूर है । फार्मर्स सूसाइड एक और बड़ी प्रॉब्लम है । वर्ष 2023 में 10000 से ज्यादा फार्मर्स और लेबरर्स ने सूसाइड की थी जो एग्रीकल्चर सेक्टर की असलियत दिखाता है । लोन वेवर का जो वादा किया गया था, वह सिर्फ डॉक्यूमेंट्स तक सीमित रहा और असली रिलीफ मिलना अब तक मुश्किल है ।

इसके अलावा डीएपी और यूरिया जैसी जरूरी फर्टिलाइजर्स की शॉर्टेज ने किसानों की दिक्कत और बाधा को बढ़ा दिया है । लेकिन सेंटर और स्टेट दोनों क्राइसिस को एक्सैप्ट करने के लिए तैयार नहीं है । अगर उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की मैं बात करूं, गन्ना बेल्ट की बात करूं तो सरकार ने नये सीजन के लिए अब तक शुगर केन प्राइस डिक्लेयर नहीं किया है । जिस वजह से फार्मर्स अपनी इनकम और फाइनैंशियल प्लानिंग को लेकर अधर में हैं । गन्ना मिलों के द्वारा टाइम पर पैसा न देना एक पुरानी प्रॉब्लम है, जिस वजह से फार्मर्स को मजबूरन और ज्यादा कर्ज लेना पड़ता है जिससे सूसाइड रेट और बढ़ते हैं । जब महामहिम राष्ट्रपति यह कहती हैं कि यह सरकार फार्मर्स को सही दाम और उनके इनकम बढ़ाने के लिए काम कर रही है तो यह जमीनी हकीकत से बिलकुल ओपोजिट लगता है । वर्ष 2020 का किसान आंदोलन एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम्प्ल है कि किस तरह से फार्मर्स को सरकार के अंगेस्ट प्रोटेस्ट करना पड़ा ताकि उनका हक और अधिकार उनको मिल जाए । लेकिन अभी भी एमएसपी की गारंटी, लोन रिलीफ, क्लाइमेट प्रोटेक्शन और फेयर मार्किट एक्सेस जैसे कोर इश्यूज़ पर सरकार सीरियस नहीं है ।

माननीय सभापति : प्लीज, अपनी बात समाप्त कीजिए ।

श्री पुष्पेंद्र सरोज : सर, दो मिनट और दीजिए ।

माननीय सभापति : नहीं-नहीं, आप समाप्त कीजिए ।

श्री पुष्पेंद्र सरोज : सर, सरकार के वायदे असली रियलिटी से बहुत दूर हैं । क्राइम अंगेस्ट विमन की बात की जाती है । यह सरकार नारी शक्ति की बात करती है । Yet its action tells a different story, one of neglect injustice and apathy towards the safety and dignity of women in India. While grand speeches celebrate women-led development, the ground reality exposes a disturbing contradiction. Crime against women has surged alarmingly with over 4.5 lakh cases reported in 2024 alone. Sexual violence, domestic abuse, and workplace harassment remain rampant and yet conviction rates remain abysmally low. The horrific incidents in Manipur where women were paraded naked and assaulted shook the nation?s conscience, and yet this Government remained silent for 77 days.

We have demanded it so many times in the Parliament, but the Government is yet to speak on Manipur.

HON. CHAIRPERSON : Please conclude now.

SHRI PUSHPENDRA SAROJ : The Government boasts about youth empowerment. यूथ हमारी सोसायटी का बहुत बड़ा सैक्शन है । Unemployment is soaring, and the unemployment rate is at more than eight per cent as of December, 2024. Nearly, 35.6 million people are jobless and yet the

Government's negligence continues. UPPSC, RO, ARO exams were cancelled due to paper leak triggering widespread protest. This is not an isolated incident. We have seen multiple such incidents where the students and people in Prayagraj were beaten up because of their protests. This has been happening in the entire country.

We have also seen protests like Agnipath in 2022 where frustrated youth were stripped of stable career opportunities. ? (*Interruptions*)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, प्लीज कनक्लूड कीजिए ।

? (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: The next speaker is Shri Abhay Kumar Sinha. Please start your speech.

? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: No. Shri Abhay Kumar Sinha ji, please start your speech.

? (*Interruptions*)

श्री पुष्पेंद्र सरोज : सर, मुझे एक मिनट दे दीजिए । मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है । ? (व्यवधान) सर, मैं आज मुसलमान और शेड्यूल कास्ट के खिलाफ बढ़ते हुए अत्याचार, भेदभाव और हेट स्पीच पर बात करने के लिए खड़ा हुआ हूँ । उत्तर प्रदेश और दूसरे बीजेपी शासित राज्यों में कावड़ यात्रा के दौरान मुस्लिम रेस्टोरेंट मालिक को अपना नाम डिस्प्ले करने पर मजबूर किया गया । ? (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, आप महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलिए ।

? (व्यवधान)

श्री पुष्पेंद्र सरोज : सर, मैं दलित समाज से आता हूँ । मैं जब इलेक्शन लड़ने के लिए गया तो मेरे हाथों से पर्चा नहीं लिया गया । आज यह समाज की हालत है, क्योंकि मैं दलित समाज से आता हूँ । मैं लास्ट में इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमने हिंदुस्तान की बहुत बात की, आत्मनिर्भर हिंदुस्तान हो गया, विकसित भारत हो गया, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमें वह भारत चाहिए, जहां सब चैन, अमन और प्यार से रहे ।

सभापति महोदय, मैं चार पंक्तियों से अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ :-

?वतन को संवारने के लिए मोहब्बत की किताब होनी चाहिए,
मुल्क के अंदर अपने दिलों में अपना संविधान होना चाहिए,
हो मस्जिदों में वेद का उच्चारण,
अमन की खातिर हिंदुस्तान में मोहब्बत बेहिसाब होनी चाहिए ।?

श्री अभय कुमार सिन्हा (औरंगाबाद) : सभापति महोदय, आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर प्रदान किया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और मैं धन्यवाद प्रस्ताव के विपक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ ।

सभापति महोदय, मैं अपनी पार्टी के सम्मानित नेता और समाजवाद के पुरोधा परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को, बिहार के लिए नई रोशनी की किरण, भाई तेजस्वी यादव जी को और औरंगाबाद लोक सभा के सभी मतदाताओं को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें इस तरह का अवसर प्रदान किया है ।

सभापति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने अपने अभिभाषण में एक से बढ़कर एक सुनहरे सपने दिखाने का काम किया है, लेकिन हकीकत में जनता को क्या मिला? जनता के हाथ आया ? आश्वासन, वादे और वर्ष 2047 के सपने । ये वर्ष 2047 के लिए सपने दिखाने का काम कर रहे हैं ।

सभापति महोदय, महाकुंभ की भगदड़ में श्रद्धालुओं की मौत पर मैं गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ और मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि महाकुंभ की भगदड़ सरकार की प्रशासनिक कुव्यवस्था का महायज्ञ था । सब कुछ कंट्रोल में है, फिर भी भगदड़ मच जाती है ।

महोदय, चाहे वे स्टेशंस हों, अस्पताल हों या रोजगार के कार्यालय हों, वहां भगदड़ मच जाती है । इन्होंने आस्था को इवेंट बनाने का काम किया है । मैं निश्चित तौर पर कर सकता हूं कि इन्होंने आस्था को इवेंट बनाने का काम कुंभ में किया है और इवेंट के बहाने वहां पर श्रद्धालुओं की भीड़ तो जुटा ली गई लेकिन कुव्यवस्था के कारण अनेकों श्रद्धालुओं ने अपनी जान गवां दीं । मैं निश्चित तौर पर कहना चाहूंगा कि सरकार उसका संज्ञान ले और जिन श्रद्धालुओं की मौतें हुई हैं, उनका आकलन करके कम से कम एक करोड़ रुपए का मुआवजा प्रत्येक परिवार को दें । आप इवेंट कर रहे हैं, आस्था को इवेंट के रूप में मना रहे हैं, आप करोड़ों रुपए कमा रहे हैं लेकिन श्रद्धालु अपनी जान गंवा रहे हैं । ?(व्यवधान)

महोदय, हम यह जरूर कहना चाहेंगे कि आप हमारे गार्जियन हैं । हम लोग सदन में नए-नए आए हैं । आप लोग हमारे सीनियर्स हैं । हमें आप लोगों का संरक्षण मिलना चाहिए । हम चाहेंगे कि जो बातें हैं, वे सामने आएं ।

महोदय, सरकार कहती है कि अर्थव्यवस्था फल-फूल रही है लेकिन जनता की जेब खाली हो रही है । बेरोजगारी आठ परसेंट से बढ़कर 8.3 परसेंट हो गई है । महोदय, हम निश्चित तौर पर कहना चाहेंगे कि आप वर्ष 2014 में 2 करोड़ नौकरी देने का झांसा देकर के आए थे, लेकिन आज हमारे युवा रोजगार के लिए दर-दर भटक रहे हैं और यह सरकार वर्ष 2047 का सपना दिखाने में मग्न है ।

महोदय, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत 6000 रुपए प्रत्येक साल किसानों को दिए जा रहे हैं और ये 12 लाख रुपए इनकम की उम्मीद कर रहे हैं । ये हर किसान को छ: हजार रुपए खाते में दे रहे हैं और 12 लाख रुपए इनकम की उम्मीद कर रहे हैं । ये आधी आबादी को पांच किलोग्राम राशन फ्री में दे रहे हैं और ये 12 लाख रुपए इनकम की उम्मीद लगाए बैठे हैं । महोदय, यह किस तरह की सरकार है? आप कहते हैं कि आधी आबादी गरीबी रेखा से नीचे हैं, हम उन्हें पांच किलोग्राम अनाज दे रहे हैं । मैं मानता हूं कि आप 5 किलोग्राम अनाज दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वे 75-80 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करते हैं और आप उनकी गाढ़ी कमाई से जीएसटी वसूल लेते हैं । अगर आप रियल में गरीबी उन्मूलन के लिए काम कर रहे हैं तो उन 80 करोड़ लोगों को आप जीएसटी फ्री का एक अकाउंट बनाकर कार्ड बांटने का काम कीजिए, तब मैं समझूंगा कि आप जो 5 किलोग्राम अनाज दे रहे हैं, वह सही है । आप जीएसटी के लिए एक फ्री कार्ड बांट दीजिए । आपके पास सारा आकलन किया हुआ है ।

महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि बिहार का नाम महामहिम के अभिभाषण में बड़े ही जोर-शोर से गूंजा । इस बजट में भी वायदों का कटोरा मिला । कोई विशेष आर्थिक पैकेज की इसके पहले घोषणा हुई? कोई ठोस निवेश नहीं, बस चुनावी भाषणों जैसी घोषणाएं हुई हैं । हमारे माननीय अभिभावक यहां बैठे हुए हैं । हम उनका सम्मान करते हैं । हमें याद है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए हमारे माननीय अभिभावक, हम सभी लोगों ने, बिहार के तमाम लोगों ने हस्ताक्षर अभियान चला करके, पटना से यहां आकर हस्ताक्षर की कॉपी महामहिम महोदया को सौंपी थी । हम माननीय अभिभावक से कहेंगे कि आप सत्ता में है और यह पूरा देश जान रहा है कि आज यह जो केंद्र की सरकार है, वह बिहार की बैसाखी के सहारे है । हम चाहेंगे कि आप बिहार के हित के लिए, अगर आप बिहार को आगे ले जाना चाहते हैं तो आप इस सरकार से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएं ।

21.00 hrs

मैं तब जाकर समझूंगा कि आप बिहार के हित की बात कर रहे हैं । इसे विशेष राज्य का दर्जा मिले ताकि निवेश बढ़े ।

मैं एक बात और कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा, हम इशारा समझ गए हैं । हाईवे 139 पटना से विक्रम, अरवल, औरंगाबाद होते हुए हरिहरगंज, झारखंड से जुड़ेगा । यह हाईवे फोर-लेन बना हुआ है । इससे पहले सदन में माननीय मंत्री जी ने कहा था कि बहुत जल्द इसका डीपीआर बना देंगे, इसके निर्माण का काम शुरू हो । गया इंटरनेशनल पैलेस ज्ञान स्थली है और मोक्ष की भी धरती है । गया में दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय है । मैंने पहले भी सदन में प्रस्ताव रखा था कि केंद्रीय विश्वविद्यालय का नाम बौद्ध धर्म के सबसे बड़े प्रचारक अशोक सम्राट के नाम पर नामकरण किया जाए । गया में मेट्रो लाइन का काम होना है, यहां मेट्रो चलनी है, इसका विस्तार केंद्रीय विश्वविद्यालय तक विस्तार

किया जाए । झारखंड में कुटकू डैम का फाटक कई वर्षों से लंबित है, इसे लगाने का काम किया जाए । हड़ियाही सिंचाई परियोजना को जल्द से जल्द चालू कराया जाए ।

21.02 hrs (Shri Krishna Prasad Tenneti *in the Chair*)

महोदय, जातीय जनगणना तो नहीं करा रहे हैं, कम से कम जनगणना तो करा लीजिए । जनगणना को कितने साल हो गए? आप मत कराइए जातीय जनगणना । माननीय अभिभावक यहां बैठे हैं, महागठबंधन की सरकार बनी, बिहार में जातीय जनगणना हुई और गणना के अनुसार, आबादी के अनुसार, आरक्षण देने का काम किया गया । नौवीं अनुसूची में शामिल करना चाहा, नहीं हुए, आप ही लोगों ने रिट दायर करके फिर बंद कराया । हम आपसे आग्रह करते हैं कि जातीय जनगणना तो नहीं करा रहे लेकिन कम से कम जनगणना तो करा लीजिए ।

सभापति जी, आपने मुझे इस अवसर पर बोलने का मौका प्रदान किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, बहुत-बहुत प्रणाम ।

डॉ. इन्द्रा हांग सुब्बा (सिक्किम) : मैं आज महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं । मैं सिक्किम राज्य से रिप्रेजेंट करता हूं । सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना और अब 50 साल पूरे हो गए हैं । भारत देश को गणतंत्र बने 75 साल हो चुके हैं । वर्ष 1975 से अब तक भारत देश ने सिक्किम के लिए धारा 371एफ का पूर्ण समर्थन किया है और इसे अंतर्गत सिक्किमवासियों की सुरक्षा निहित की गई है । हमें पूरा विश्वावस है कि भविष्य में धारा 371एफ के अंतर्गत सिक्किमवासी सुरक्षित रहेंगे ।

महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर देश की प्रगति और उन्नति के विषय में बातें कही गई हैं । सबसे पहली बात है कि किसी भी देश की प्रगति शिक्षा नीति पर निर्भर करती है । देश के युवाओं को कितनी शिक्षा मिली है और किसी भी देश का कोई भी राज्य क्यों न हो, शिक्षा में किस तरह की प्रगति हुई है, यह बहुत महत्वपूर्ण है ।

जहां तक सिक्किम की बात है, वर्ष 1975 में राज्य बनने के बाद आज तक 50 सालों में बहुत प्रगति हुई है । वर्ष 1971 में सिक्किम में 17 परसेंट ही लिटरेसी रेट था, लेकिन आज लेटेस्ट वर्ष 2011 का सेंसस कंसीडर करें तो यहां 82 परसेंट लिटरेसी रेट है । अगर वर्ष 2024 में देखेंगे तो इससे भी ज्यादा है । सिक्किम ने बहुत सारी कठिनाइयों के बावजूद भी लिटरेसी रेट और शिक्षा में बहुत प्रगति की है । सिक्किम को केवल एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी वर्ष 2007 में मिली और एक एनआईटी वर्ष 2010 में मिला । सिक्किम में कोई आईआईटी नहीं है, सिक्किम में कोई आईआईएम नहीं है । फिर भी सिक्किम के युवाओं ने देश की उन्नति में अपनी भागीदारी लेने का प्रयास किया है । यहां पर जैसे क्वांटम मिशन की बात की गई । अभी न्यूक्लियर मिशन की बात की गई है । इसका जितना भी रिसर्च है, रिसर्च के लिए जितना भी अनुदान दिया जाता है, सिक्किम जैसे छोटे राज्य ऑटोमैटिकली एक्सक्लूड हो जाते हैं, क्योंकि जितना भी अनुदान है, जितने भी ग्रांट्स हैं, रिसर्च के लिए जितना भी बजट रखा जाता है, वह आईआईटी, आईआईएम, आईआईएससी को बोल

कर रखा जाता है । इसी सेंटेंस से स्टेट पूरी तरह से एक्सक्लूड हो जाता है । एट लीस्ट एनआईटी बोल दिया होता या अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी बोल दिया होता तो शायद सिक्किम भी इनक्लूड होता । मैं भारत सरकार से यही निवेदन करता हूं कि इसमें सिक्किम को भी इनक्लूड करने की कोशिश करें ।

आप जानते हैं कि सिक्किम इस देश का पहला ऑर्गेनिक राज्य है । प्रधान मंत्री जी ने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स लागू किए हैं । मैं यही रिक्वैस्ट करना चाहता हूं कि सिक्किम को आर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग हब बनाया जा सकता है । अगर इसमें भारत सरकार विचार करें तो मुझे लगता है कि ऑर्गेनिक प्रोड्यूसेस और ऑर्गेनिक प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स में भी सिक्किम लीड कर सकता है, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस रहा है । आज भी हम ऑर्गेनिक की प्रेक्टिस कर रहे हैं । आज सिक्किम को 50 साल हुए हैं । वर्ष 1975 में जब सिक्किम इंडिया में 22वें स्टेट के रूप में मर्ज हुआ था, तब भूटिया, लेप्चा और नेपाली सिक्किमवासी थे, सब एक साथ भारत में मर्ज हुए थे । लेकिन उस टाइम भूटिया, लेप्चा को शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा दे दिया गया । वर्ष 2003 में लिंबू और तमांग कम्युनिटी को ट्राइबल का दर्जा दे दिया गया, लेकिन आज तक भी 12 लेफ्ट आउट कम्युनिटीज़, जो नेपाली स्पीकिंग पॉपुलेशन है, उनमें से 12 कम्युनिटीज़ को आज तक भी ट्राइबल का दर्जा नहीं मिला है । मैं भारत सरकार से रिक्वैस्ट करता हूं कि सरकार इसमें विचार करें । जिसको मिला है, जैसे भूटिया, लेप्चा की अपनी सीट रिजर्व्ड है, लेकिन लिंबू और तमांग जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स कम्युनिटी हैं, उनको आज तक भी अपनी सीट नहीं मिली है । इसमें आर्टिकल 332 और 371(एफ) दोनों का वायलेशन हुआ है । वर्ष 2003 से लेकर आज तक भी रिजर्वेशन नहीं हो पाया है । मैं इसके लिए भी भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि इस इश्यु को एट लीस्ट 50 ईयर्स ऑफ स्टेटहुड में, सिक्किम के हर सेक्शन को न्याय देने के लिए इन मुद्दों को भारत सरकार कंसीडर करें और सिक्किमवासियों को न्याय दें ।

हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं । यह बहुत ही बड़ा विजन है । हम जानते हैं कि मेक इन इंडिया के तहत ही हम भारत देश को आगे ले जा सकते हैं । सिक्किम जैसे जो छोटे स्टेट्स हैं और हिमालयन राज्य में जो स्टेट्स हैं, ये इस वजह से एक्सक्लूडेड हैं कि वहां पर सही तरह से कनेक्टिविटी हो नहीं पाई है । हम जानते हैं कि रेलवे का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है । हम सरकार को धन्यवाद देते हैं कि वर्ष 2026 तक संचालन होने का वचन दिया है और हम पूरी आशा करते हैं कि वह संचालन हो । लेकिन उसके बावजूद भी एनएच 10, जो सिक्किम को कनेक्ट करता है, अभी इसकी जो हालत है, अगर आप सिक्किम जाएंगे और जो भी रिसेंटली सिक्किम गए होंगे, सब को पता है कि एनएच 10 की हालत आज भी बिल्कुल खराब है । इसको सही कनेक्टिविटी न देने की वजह से सिक्किम भी मेक इन इंडिया प्रोग्राम से कहीं न कहीं एक्सक्लूडेड है । मैं भारत सरकार से यह निवेदन करता हूं कि जो कनेक्टिविटी सिक्किम के लिए बननी चाहिए, इसमें पूरी तरह

से सहयोग करें । सिक्किम सरकार भी इस कनेक्टिविटी को आगे ले जाने के लिए पूरा काम कर रही है । ? (व्यवधान) सर, मैं कनक्लूड कर रहा हूं ।

हिमालयन रीजन्स के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि जो नॉर्थ सिक्किम है, सिक्किम में नॉर्थ सिक्किम, वेस्ट सिक्किम सहित तीन इंटरनैशनल बॉर्डर्स हैं । एक भूटान से लगा है, एक नेपाल से लगा है और एक चाइना से लगा है । इन बॉडर्स पर जाने के लिए जितने भी रोड्स हैं, इनमें नॉर्थ सिक्किम जाने वाला रोड आज तक ठीक से कनेक्ट नहीं हो पाया है । हमने डिफेन्स मिनिस्टर साहब से भी मिलकर इसके लिए रिक्वेस्ट किया है । आज मैं इस सदन में भी यह बात रखना चाहता हूँ कि अगर हम नैशनल इंट्रेस्ट को कोर में रखते हैं और नैशनल सिक्युरिटी को हम सीरियसली कंसीडर करते हैं, तो नॉर्थ सिक्किम और वेस्ट सिक्किम की नेपाल बॉर्डर की ओर जाने वाली जो सड़कें हैं, उनको ठीक करना बहुत जरूरी है ।

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

SHRI SANJAY UTTAMRAO DESHMUKH (YAVATMAL-WASHIM): Hon. Chairman, thank you. Through the President?s Address, this Government talked only about tall promises and assurances, but if we look at the actions of this Government closely, we will find them completely baseless, misguiding and without any substance. Today, we can see that the unemployment rate is at the highest level in our country. Inflation has brought an ill effect on the people. The number of farmers suicides is increasing day by day. Crimes against women are also increasing. No employment opportunities are being provided to the youth and the Government of the day is busy with making only hollow promises and misleading slogans.

Chairman Sir, this Government declared many mega schemes like Make in India, startup India, Digital India, but in vein. These Schemes proved to be bogus and formed only the part of Government?s advertisement and propaganda policy. Even today the MSME sector is struggling for its existence.

This Government promised to generate employment but, unfortunately no vacancies are being filled. On the contrary, Government is pushing for privatization.

In my Lok Sabha Constituency, Yavatmal-Washim, many students are still unemployed even after taking higher education. Farmers?

children are looking for jobs in cities but it is of no use. This Government talked about development of trade and industry but the industrial units are shutting down. There is a depression in manufacturing sector and hence it stops new investments.

India is an agriculture dominated country and farmer is a backbone of our economy. But, they continue to suffer and their condition is deteriorating day by day. The concept of MSP is on the paper only. The benefits of crop insurance scheme are not being provided to farmers. And these debt ridden farmers had to commit suicide because that is the only option left for them.

These farmers desperately need the MSP, loan waiver and a long term agriculture policy. If you look at the number of farmers? suicide cases, you can easily understand that the agriculture policies of this Government have been failed completely.

In Yavatmal district, 1,91,326 farmers suffered the losses over the 1,76,600 hectare of land due to heavy rains. But still dues of approximately Rs. 214 crore are pending. The farmers did not receive a single penny.

In Amravati Division, at many places like Amravati, Akola, and Buldhana, the standing crops were washed away completely and the farmers had to suffer heavy losses.

Around, Rs. 386 crore are still lying with Maharashtra Government. But it did not distribute it till date.

In Washim District, there were also huge losses due to heavy downpour. But this district was not included under the Scheme. Farmers suffered losses, but they were not included in Government list.

In the President?s Address, the Government talked about Jal Jiwan Mission Scheme and also made tall claims. Through the ?Har Ghar Jal? Scheme, it is claimed to provide tap water to every household. But the situation in my Lok Sabha Constituency is totally different. They never check ground realities because people in rural area still roam here and there to fetch water. This Government also talked about interlinking of rivers project. In Vidarbha region they are making tall promises.

Vainganga and Nalganga rivers interlinking project is really a visionary project, but an injustice done to Washim district because this district is excluded. This is an aspirational, backward and drought ridden district. If this project is a life changing project, for the Vidarbha region, then why Washim district is ignored completely?

In Pusad Tehsil, the people of 42 villages, are searching for water endlessly. During summer, they had to suffer a lot even for a single drop of water. The people of Mahapathar area are urging the Government to kindly look into it sympathetically. Water is needed for drinking and irrigation purposes. Availability of water can change everything in this region. Why this Govt. is giving step motherly treatment to the people of Washim district?

The Union Government should consider the problem of unemployed and educated youth of this country seriously. Do not indulge only in sloganeering. You should know about the ground reality and actual problems of the people at large. You cannot run this country only by false propaganda and marketing tactics. Your advertising skills would not help you in long run.

So, face the reality and know what is happening actually. This country can be run only by honesty, truthfulness and democratic values.

Thank you.

DR. THOL THIRUMAAVALAVAN (CHIDAMBARAM): Hon Chairman, Vanakkam. I sincerely thank you for giving me this Opportunity to speak on the Motion of Thanks to the Hon President?s Address. We can say that the Hon President?s Address can be called as a prelude the General Budget. It is so natural that the Hon President?s Address remains a prelude announcing the aspects of the forthcoming Budget in advance.

I should say that both the Hon President?s Address and Budget are not boosting our confidence. I am pained to state that the Hon President?s Address is very disappointing for the marginalised sections of the people including the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, minorities and OBCs. I want to pinpoint several aspects of the President?s Speech here. Hon President has taken pride for having rescued about 25 Crore people from

poverty. But we still have Crores of people suffering in poverty and facing difficulties due to price rise.

I am left with sadness in mind to ask whether or not Hon President is aware of this? Hon President has also stated with pride that 3 Crore new houses would be built by the Government. Madam President has made a repetition of several announcements that were uttered by her during the previous Joint Session of Parliament. One such announcement pertains to the construction of Houses under PM Awas Yojana. Last time, as much as Rs 54,500 Crore was allocated for this Scheme and only Rs 32,400 Crore was spent by the Government. The spending was cut almost to half of the total allocation of this Scheme. The Government did not spend Rs 22,100 Crore allocated for this Housing Scheme. As a result this Scheme could not be completed in several places. Many such works are incomplete. Funds allocated are spent without reaching completion. People have not been given constructed Houses as the targets were not achieved. This is a matter of great concern.

I request you to ponder over this. Union Government allocates 1 lakh and 20 thousand for constructing one Unit. Remaining 40 per cent has to be borne by the State Government which comes to Rs 70,000. Whereas the State Government gives an additional Rs 50,000 matching the grant of Union Government and makes its contribution as Rs 1,20,000 per unit. Along with this under MGNREGA Scheme, Rs 27,000 is also allocated by the State Government.

I want to ask you that how a House measuring 280 sq. ft. can be constructed with just a meagre amount of Rs 2 lakh and 67 thousand. That is why I say this President?s Address seems very ornamental and very disappointing. If we take for instance, at least Rs 2500 is required for constructing one sq. ft., Rs 5 lakh would be required for constructing a House in an area of 280 sq. ft. Kalaignar Dream House Scheme in Tamil Nadu provides Rs 5 lakh for constructing a House as this was implemented successfully by the Hon Chief Minister of Tamil Nadu. The State Government has taken up this responsibility. I therefore urge that at least Rs 5 lakh should be allocated for the PM Awas Yojana for construction of Houses besides monitoring at all levels of its execution.

Next important point I wish to raise is about the SC and ST Sub-Plan. We have separate Sub-Plans for SCs and STs. As per the population of pour country, 15 percent of the funds are to be allocated to the welfare of SCs and 7.5 percent of funds for the welfare of STs. This forms the basis of these Sub-Plans. Our total spending is of Rs 50 lakh and 65 thousand. This was announced by the Government. If we calculate 15 percent of this amount. It comes to Rs 7, 59,081 Crore. This is the justifiable amount of allocation. But only 1, 68,478 Crore was allocated to the welfare of SCs. By this reduced allocation, the Union Government takes away the share of Rs 5, 91,000 Crore, almost 6 lakh Crore. This amount they do not want to allocate or spend for the welfare of SCs. This is against the interests of the people belonging to SC community. Similarly the STs are also ignored.

I will conclude by saying an important thing. Pre-matric and Post-matric Scholarships are being provided to the students belonging to SCs, STs and minorities. During the previous Budget, Rs 6, 360 Crore was allocated for this.

But Rs 7, 60 Crore remained unspent. There is inadequate or very less allocation of funds made for Overseas Scholarships for such students. This is not doing justice to the students belonging to these communities. Particularly druing the pervious Budget, there was an allocation of Rs 326 Crore for the pre-matric scholarships meant for the minority students. That too, out of this Rs 326 Crore only as little as Rs 90 Crore was spent for this purpose. Now they have reduced this allocation for Pre-matric scholarships to just Rs 195 Crore. As regards Post-matric Scholarships, as against the allocation of Rs 1, 145 Crore during previous Budget, only Rs 344 Crore could be spent by this Government. Even that allocation has been reduced now to Rs 413.9 Crore for providing Post-matric Scholarships. This has seen a drastic reduction of almost Rs 700 Crore.

I must say that this will lead to a planned destruction of denying education to minorities and it may be seen as a worst conspiracy to keep them in darkness. I therefore want to say that this Hon President?s Address is just ornamental and appreciative of BJP Government in power and nothing is visionary. I urge that this Government should think of

uplifting the common masses including SCs, STs, OBCs and Minorities. Thank you.

श्री राजकुमार रोत (बांसवाड़ा) : सभापति महोदय, आज आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के ऊपर बोलने का जो अवसर प्रदान किया, उसके लिए आपका धन्यवाद, जोहार ।

महोदय, एक तरफ हम और पूरा देश, विशेषकर जो सत्ताधारी लोग हैं, हम इस बात की खुशी मना रहे हैं कि हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया एक आदिवासी समुदाय से आती हैं और इसके साथ ही वे एक महिला हैं । लेकिन, वर्तमान में देखा गया है कि पूरे देश में अगर कोई सबसे ज्यादा पीड़ित है, अगर किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो वह आदिवासी समुदाय है और महिलाएं हैं । आज मणिपुर का उदाहरण देख लें ।

हम यह कह रहे हैं कि हमारे देश की महामहिम उस समुदाय से हैं, हमें भी खुशी है, लेकिन दूसरी तरफ इस बात की तकलीफ है कि देश में आदिवासी समुदाय के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है और महिलाओं के साथ भी सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं । इसका ताजा उदाहरण मणिपुर का देख लीजिए । राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के अन्दर देख लीजिए । विकास के नाम पर आदिवासियों को विस्थापित किया जा रहा है । एक दौर था, जब आज़ादी के बाद इस देश की आम जनता ने, गरीब ने, आदिवासी ने यह राहत की साँस ली थी कि अब ?अच्छे दिन? आएंगे, उज्ज्वल भविष्य होगा । हमने उस दौर को देखा है, जब आज से 20-25 साल पहले आदिवासी गरीब दलित व्यक्ति अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए जमीन और जेवरात को गिरवी रखता था, लेकिन आज वह इतना मजबूर हो गया है कि कई इलाकों में यह देखा गया है कि आदिवासी समुदाय अपनी बहन-बेटियों या अपने छोटे बच्चों को गिरवी रख रहा है ।

हमारे राजस्थान में आज ?डबल इंजन? की सरकार है । कोटड़ा, राजस्थान में आए दिन घटनाएं हो रही हैं । इन पहाड़ों में आदिवासी समुदाय की कैसी हालत हो गयी है? सरकार की योजनाएं कागजों में ही रहती हैं, वे धरातल तक नहीं पहुंच पाती हैं । कई ऐसी घटनाएं सामने आयी हैं, जिसमें इन परिवारों ने अपने नाबालिग बच्चों को गिरवी रखा है । गुजरात के अंदर कई इलाकों में यह घटना सामने आयी है । यह एक छोटा-मोटा आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह सैकड़ों में है और हम यहां बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं ।

माननीय सभापति महोदय, आज हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं । हमारे बड़े-बुजुर्ग भी यह कहा करते थे कि बच्चे को अपने पैरों पर खड़े होना सिखाना है, यानी कि उसको आत्मनिर्भर बनाना है, लेकिन आज देखा गया है कि देश की आम जनता कम आत्मनिर्भर होती जा रही है और ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि वे किसी न किसी पर निर्भर होते जा रहे हैं । विशेषकर आदिवासी, दलित और पिछड़े वर्गों में यह देखा गया है ।

माननीय सभापति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में आदिवासी इलाकों में 30 मेडिकल कॉलेजों की बात हुई । यह अच्छी बात है । हम भी चाहते हैं, लेकिन धरातल पर इन मेडिकल कॉलेजों की स्थिति क्या है? कई ऐसे केस आए हैं । एक केस आया कि एक महिला डिलीवरी के लिए उस मेडिकल कॉलेज में गयी । वह सोनोग्राफी के लिए चिट्ठी लिखवा रही है और उसका नम्बर एक महीने के बाद आ रहा था । तब तक तो बच्चा पैदा हो गया और बच्चे का नामकरण भी हो गया । कई ऐसे केसेज सामने आए । कुछ समय पहले हमारे डूंगरपुर का एक केस आया था, जिसमें एक व्यक्ति इलाज के लिए गया । उसका नम्बर एक महीने के बाद आया और तब तक उसका अंतिम संस्कार हो गया था । यह स्थिति बनी हुई है, मतलब कि धरातल पर पी.एच.सी., सी.एच.सी. से भी बदतर स्थिति मेडिकल कॉलेजों की बन गयी है । अगर आप वहां जाएंगे तो आपको यह दिखेगा । मैं खुद एक सांसद हूं । मैंने अपने संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा, डूंगरपुर में कई विजिट किए हैं । वहां जाने को मेरा ज़मीर नहीं मानता है, क्योंकि वहां ऐसी हालत बनी हुई है । वहां लोग पड़े रहते हैं । उनका नम्बर नहीं आता है । उनकी जांच नहीं हो पा रही है । हम चाहते हैं कि जो योजनाएं हैं, उनको धरातल पर इम्प्लीमेंट किया जाए ।

माननीय सभापति महोदय, आयुष्मान कार्ड की बात की गयी । यह बहुत अच्छी बात है । यह होना चाहिए । लेकिन, पिछले दो-तीन सालों में देश में ऐसे कई किस्से आए हैं, जिसमें दवाई के पैसे न मिलने से वह अपने परिवार का पालन नहीं कर पाया, उनका इलाज नहीं करा पाया और इसलिए उसने आत्महत्या कर ली ।

माननीय सभापति महोदय, बिरसा मुंडा जी के लिए जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया । इसकी घोषणा हुई । हम भी इसका स्वागत करते हैं । लेकिन, सिर्फ घोषणा होने से, मनाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि यह सोचना पड़ेगा कि बिरसा मुंडा जी क्या चाहते थे, उनके विचार क्या थे, उनके उद्देश्य क्या थे, इन पर हमें काम करने की जरूरत है । वे जल, जंगल, जमीन की बात करते थे । ?अबुआ दिशुम अबुआ राज? की बात करके वे गए थे, लेकिन आज क्या हो रहा है? आज जल, जंगल और जमीन उद्योगपतियों को भेंट में दिए जा रहे हैं और वहां पर खत्म किया जा रहा है । बिरसा मुंडा जी के उपदेशों पर जाना पड़ेगा, उनके विचारों पर जाना पड़ेगा, सिर्फ जनजातीय गौरव दिवस मनाने से काम नहीं चलेगा ।

माननीय सभापति महोदय, जनगणना को लेकर अभी एक बात सामने आई । मुझे एक बात समझ में नहीं आई, यह मैं नहीं बोल रहा हूं, यह देश की आम जनता बोल रही है, जो विवेकशील है । वह यह बोल रही है कि सरकार और मीडिया के पास कुम्भ में कितने लोगों ने डुबकी लगाई, उसका आंकड़ा है, लेकिन कितने लोग मरे हैं, उसका आंकड़ा नहीं है ।

30-35 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई, वह आंकड़ा है, लेकिन मरे कितने लोग हैं, घायल कितने हैं, किस राज्य से कितने लोग हैं, यह आंकड़ा अभी तक सामने नहीं आ

पाया है ।

माननीय सभापति महोदय, जल-जीवन मिशन की बात हुई । जल-जीवन मिशन से हमें भी लगा कुछ काम तो अच्छा होगा । लेकिन मैंने इसी सदन में क्वेश्चन लगा कर उत्तर निकलवाया है कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर, मैं अपने संसदीय क्षेत्र की बात करूं, जल-जीवन मिशन में जैसे हमारा जिला प्रतापगढ़ है, वहां तीस प्रतिशत उपलब्धियां प्राप्त हुईं । उदयपुर में 31 प्रतिशत, डूंगरपुर में 27 प्रतिशत और बांसवाड़ा में 24 प्रतिशत घरों तक नल पहुंचाने के लिए अभी तक टारगेट ट्राइबल इलाके के अंदर हुआ है । वह भी कागज़ों पर है, धरातल पर स्थिति कुछ और है ।

माननीय सभापति महोदय, हमारे वहां पर कडाणा बैकवॉटर इसी सरकार में सैंक्शन कराया गया था, लेकिन आज तक उसका वर्क ऑर्डर नहीं गया है ।

सर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह देश तब महत्वपूर्ण या मज़बूत रहेगा, जब इस देश में प्रत्येक धर्म और प्रत्येक जाति के अंदर भाईचारा रहेगा । राजस्थान के अंदर धर्मांतरण को ले कर एक विधेयक आया । हम शांति से रहना चाहते हैं । हम नहीं चाहते कि एक आदिवासी को दूसरे आदिवासी से लड़ाया जाए ।

सर, हकीकत यह है, मैं यह ऑथेंटिक आंकड़े के साथ बोल रहा हूँ कि जिस सरकारी स्कूल के अंदर आज से दस साल पहले दो सौ बच्चे पढ़ रहे थे, उसी स्कूल में आज पचास बच्चे पढ़ रहे हैं । ट्राइबल इलाके के अंदर तीन-तीन क्लास के बच्चे एक रूम में बैठ रहे हैं । उनको किस क्वालिटी की एजुकेशन मिल पाएगी? मैं आपके माध्यम से सरकार से यही अनुरोध करना चाहूंगा कि हमें कुछ नहीं मिले तो चलेगा । गरीब आदिवासी और दलित को अच्छी एजुकेशन और अच्छी हेल्थ मिलनी चाहिए, वह अपने आप सारी चीज़ें कर लेगा ।

इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद और आभार ।

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Thank you, Sir, for giving me this opportunity. I stand to oppose the Motion of Thanks on the President?s Address.

Sir, I start by putting to this House how the foreign policy of our country has been compromised from what its traditional position has been. Take the case of Palestine. About 61,709 Palestinians have been killed, and about 1,11,588 have been injured. India is a party to Genocide Convention. The Genocide Convention says that anyone who is party to the Genocide Convention must contribute to ensure that it prohibits from contributing to genocide and also requires to take steps to prevent it.

Sir, not a single hospital is there in Gaza. This country, this great nation of mine had constructed two floors of a library in a university. Those

universities and that library has been finished. You have 1.2 million people being made homeless, deliberate starvation has happened, and people do not have access to drinking water. And, what do we see now? We have heard the Prime Minister saying, ?Stop the war in Ukraine.? Where is my Prime Minister; where is this Government? Why are they keeping quiet on this genocide which is being perpetrated on the Palestinians? What has been the traditional stance of our country, from Mahatma Gandhi up to all the Prime Ministers? Why can we not oppose genocide? We are a party to Genocide Convention. I am warning this Government that when the genocide history of Gaza will be written, this Prime Minister will also be on the list of accomplices. I demand from the Government that let this Government, let our country take the responsibility of constructing the health sector in Gaza, invite more Palestinians to India on scholarship; let them rebuild Gaza. We cannot be a party. How can we allow arms to be exported to Israel? An Indian ship was stopped in Spain. We are signatory to this Genocide Convention.

How will history remember us? With what face can we face the world?

Secondly, Sir, India's moral voice is dead in Palestine. It is completely dead.

With regard to China, the Army Chief in an interview to an English newspaper ruled out any troop cut along LAC. He said, ?no troop normalization can happen?. Why are we back to business as usual? Mansarovar Yatra will start, direct flights will start, visas will be issued, and Chinese investments will be welcomed with open arms. Can we patrol those 25 patrolling points which we have lost? Can we go and patrol in the buffer zones of Galwan, Pangong Tsu, Gogra, Hot Spring and Kailash? No. We have lost 2,000 square kilometres of land, and it is back to business with China! I strongly condemn this step which this Government is taking in the fear of China.

Now, let us come to USA. A Pew Research Study says that 7.25 lakh unauthorized immigrant Indians are in USA, and about 18,000 are in the final list for removal. Are we going to accept all these 7.25 lakh people? Are we going to accept these 18,000 people who are in the final

list for removal? How many aircraft do you require? You would require about 300 aircraft. Can this Government imagine the loss of remittance? What will be their employment over here? They have no policy.

Sir, with respect to Bangladesh, I would like to say that we are destroying our relationship with Bangladesh for the sake of one person. When will my Prime Minister meet his counterpart in Bangladesh? I fear that we will be out of the game. When I say the term ?game?, the Government understands that.

So far as minorities are concerned, I would submit that in 2023-24, out of a budgetary allocation of Rs.3,000 crore, an amount of Rs.2,064 crore was surrendered by the Ministry of Minority Affairs. For the last about 10-11 years, I have been consistently demanding that the Pre-Metric, Post-Metric and Merit cum-Means Scholarships should be made demand-driven because only Rs.2,000 crore are required. Because of its not being demand-driven, you have thousands of Muslim students who are out of education. There have been empirical studies like the Kundu Committee which said that the reason for Muslim out-of-school children is financial wherewithal. You are not interested to ensure that Muslim children study.

My community has the highest illiteracy rate in women. Out of 100 students, I have only three graduates. You are after Jamia Millia; you are after AMU and you have cut down the funding for Madarsas. Yes, you do not read. You have cut down the money on Madarsas also. I mean, if you read, you will know it. Why can you not do it, Sir?

Then, I would ask you to come to Mustafabad and Okhla and see. You have the Mount Everest of garbage which is being dumped right inside the Muslim area. Why? Because it is a Muslim area. Then, you have this person who was given birth politically through surrogacy by an institute which has an allegiance to the person who wrote ?We, or Our Nationhood Defined? and ?Bunch of Thoughts?. That person day in and day out lies and lies. His start and end points are lies only. But what I am hearing from the ground, which I have seen, a pure, organic Muslim leadership will emerge on Wednesday.

Sir, I am cautioning and warning this Government. If you bring in and make a Waqf law in the present form, which will be a violation of

Articles 25, 26 and 14, it will lead to social instability in this country. It has been rejected by the entire Muslim community. No waqf property will be left. Nothing will be left, I say. If you want to make India a Viksit Bharat, we also want a Viksit Bharat. Do you want to take this country back into the early 80s and 90s? It will be your responsibility because as a proud Indian Muslim, I will not lose an inch of my Masjid. Forget about a Masjid, I will not lose an inch of my *dargah*. I will not allow that.

We will no more come and give a diplomatic talk over here. This is the House where I have to stand up and say honestly on behalf of my community, which says that we are proud Indians, that it is my property, not given by anyone. You cannot snatch it away from me. Waqf is a form of worship for me.

Sir, let me talk about unemployment. Youth unemployment has increased to 45 per cent. I will give you an example. At Mumbai airport, for about 1800 jobs, 15,000 graduates turned up.

I must congratulate the Prime Minister. In Bihar and UP, train stations overflow with aspirants every time there is an exam for a Government job. In public sector, in oil and gas sector, 15,000 jobs have been lost even though their revenue doubled. Central PSUs eliminated 2.7 lakh jobs over the past decade. During April-August 2024, 11,500 MSMEs have been shut down. Employment in manufacturing sector fell from 12.6 per cent in 2011-12 to 11.4 per cent in 2022-23.

Sir, in conclusion, I would like to say this. What is the Government showing us? I really feel pity for the allies of NDA. Despite the fact that they are 240 in number, they are irrelevant now. You can take something here and there but what about the country at large? What about the youth of this country? The only nation in the world which has demographic dividend is India. This Government has failed to uplift the youth. That is why, on the grounds which I have submitted, I oppose the Motion of Thanks on the President?s Address.

Thank you.

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : सभापति महोदय, धन्यवाद । माननीय स्पीकर साहब ने 115(1) में एक डायरेक्शन दिया और लीडर ऑफ दी अपोजीशन को यह कहा कि जब आप कोई चीज बोल रहे हैं तो उसको ऑथेंटिकेट करिए । राष्ट्रपति अभिभाषण में 6 ऐसे

पॉइंट्स हैं, जिनके समर्थन में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । मुझे लगता है कि इस पूरे पार्लियामेंट का जो बनने का उद्देश्य है, कौल एंड शकधर कहता है कि लीडर ऑफ दी अपोजीशन ऐसा होना चाहिए जिसको पार्लियामेंट्री स्किल के बारे में, रूल के बारे में, कंट्री के बारे में, देश के प्रधान मंत्री के बारे में, देश की स्वतंत्रता के बारे में, सॉवरेनिटी के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए । मैं बड़े दु:खी मन से यह बात बोलने जा रहा हूं कि वर्षों बाद, यह मेरा चौथा टर्म है, इस चौथे टर्म में मुझे पहली बार एक ऐसा लीडर ऑफ दी अपोजिशन दिखाई दे रहा है, जो दुनिया में भारत कैसे कमजोर हो, देश के कैसे टुकड़े हों, किस तरह की विदेशी ताकतों के साथ मिलकर यहां की सोसाइटी को बरगलाया जाए, गलत बयानी की जाए और इस पार्लियामेंट में जो हमें आर्टिकल 105 में फ्री एंड फेयर डिस्कशन का अधिकार मिला हुआ है, उस फोरम का मिसयूज करके पूरे देश को गुमराह किया जाए, ऐसी सोच वाला है । मेरा आपके माध्यम से विपक्ष के नेता पर आरोप भी है और उनको चैलेंज भी है और आपसे आग्रह भी है कि मैं जितनी बातें कह रहा हूं, उन सबको मैं ऑथेंटिकेट करूंगा और यदि राहुल गांधी जी में, लीडर ऑफ दी अपोजिशन में हिम्मत है तो वे सारी बातों को ऑथेंटिकेट करें, नहीं तो वे ऑन दी फ्लोर ऑफ दी हाउस इस्तीफा दें ।

उन्होंने 6 ऐसे पॉइंट्स कहे, मैं उन 6 विषयों को आपके सामने और पूरे देश को बताना चाहता हूं । सबसे पहले उन्होंने कहा कि ?This phone is not made in India. This phone is assembled in India.? ऐसे करके उन्होंने फोन दिखाया । अपने दिल से जानिए पराए दिल का हाल । कांग्रेस ने इस देश को किस तरह से विदेशियों के हाथों में गिरवी रख दिया । मैं यह कहानी बताना चाहता हूं । मैं यह पेपर लेकर आया हूं । जब चिदम्बरम जी इस देश के वित्त मंत्री थे, इस देश के कॉमर्स मिनिस्टर थे, वर्ष 1996-97 में इंटरनेशनल टेलीकॉम एग्रीमेंट, आईटीए-1, यह पूरे देश को जानने का सवाल है । आईटीए-1 में उस वक्त केवल 14 कंट्रीज़ सिगनेट्री थीं । पूरी दुनिया में 195 कंट्रीज़ हैं । चाइना उसका सिगनेट्री नहीं था, उसका पार्ट नहीं था, लेकिन इस देश को बेचने के लिए जो साफ्टवेयर, हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक टॉयज़, ये सब जो पूरी दुनिया में मैनुफैक्चरर बनाते थे, यूरोपियन यूनियन के दबाव में उस सरकार ने और तत्कालीन वित्त मंत्री ने पैसे लेकर उस एग्रीमेंट को साइन कर दिया । आईटीए-1 में क्या साइन किया? यह कहा कि आप कोई भी कंपोनेंट लेकर आ जाओ, हार्डवेयर का, इलेक्ट्रॉनिक का, टॉय का, कोई भी कंपोनेंट लेकर आ जाओ, उस पर जीरो परसेंट ड्यूटी लगेगी ।

जब आपने उस एग्रीमेंट को साइन कर लिया तो धीरे-धीरे करके सभी चीजों पर जीरो परसेंट ड्यूटी हो गया । टॉय में हम नम्बर वन हुआ करते थे लेकिन खिलौने सभी चीनी आ गए, मोबाइल चीनी आ गया, इसके इक्विपमेंट्स चीनी आ गए । आपने जब देश को बेच दिया । रोपा पेड़ बबूल का तो आम कहां से होय । आपने देश को बेच दिया, देश को गिरवी रख दिया ।

वर्ष 2014 के बाद जब इस देश में माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि हम मेक इन इंडिया को आगे करेंगे, देश में मैन्युफ्रैक्चरिंग सेक्टर आगे जाएगा, सारी टेलीकॉम कंपनियों को कहा, आज असेम्बलिंग हो रही है । वर्ष 2015 आईटीए-॥ आया, इसको साइन करना है, माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेश पर आईटीए-॥ का सदस्य आज तक हम नहीं बने, यही कारण है कि हम आज इस मोबाइल के नम्बर वन मैन्युफ्रैक्चरर्स हैं । आप ऑथेन्टिक करो, आप एआई की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को मैन्युफ्रैक्चरिंग समझा रहे हो, प्रोडक्शन समझा रहे हो, कन्ज्यूमर्स समझा रहे हो । आपने देश को गिरवी रखा, आपने देश को बेचा, यदि आपके पास प्रमाण है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहां के मैन्यूफ्रैक्चरिंग सेक्टर को नहीं बढ़ाया है, चीन को उन्होंने बैन नहीं किया । चीन को यदि हम कम्पटीशन नहीं दे रहे हैं तो आप ऑथेटिंकट करो, नहीं तो आप देश से माफी मांगो कि आपने माननीय प्रधानमंत्री जी के इमेज को खराब किया ।

दूसरा, बार्डर का सवाल है । मैं कई किताबों को कोट करके आया हूं, वैसे राजीव रंजन सिंह जी बहुत कह रहे थे, चौकीदार वाला बात कहा और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से भाग गये, ऐसे ही भगोड़ा है, झूठ बोलने की आदत है, कभी झूठ बोल दिया, कभी दबाव आ गया तो वापस ले लेते हैं । इस देश के बार्डर और सैनिकों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट बात कही, क्या बात कहा । माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनें, 140 करोड़ लोगों का विश्वास माननीय प्रधानमंत्री जी पर है इसीलिए वह तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं । दुनिया के फोरम पर वह जाते हैं, रूस-यूक्रेन वार हो रहा हो या यूरोपियन यूनियन में परेशानी हो रही हो, चाहे इजराइल में परेशानी हो रही हो, फिलिस्तीन में परेशानी हो रही हो, पूरी दुनिया भारत की तरफ देखती है, लेकिन यह किसने पैदा किया ।

आचार्य कृपलानी कांग्रेस के बड़े नेता थे, उनकी पत्नी सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी बनीं, कांग्रेस पार्टी से आचार्य कृपलानी ने इस्तीफा क्यों दिया? यह देश को जानने वाला सवाल है, जब पंचशील समझौते पर हिन्दी चीनी भाई-भाई के नाम पर पंचशील एग्रीमेंट साइन करने का विचार किया तो आचार्य कृपलानी ने कांग्रेस पार्टी में उसका विरोध किया । उन्होंने कहा कि आप देश को बेच रहे हो, आप तिब्बत को उसके साथ जाने के लिए मजबूर कर रहे हो । हमारे ऊपर एक दुश्मन को पैदा कर रहे हो, यह चलने वाला नहीं है, एक दिन चीन हमारे ऊपर अटैक करेगा । इस गांधी परिवार ने नेहरू जी के नेतृत्व में आचार्य कृपलानी को ही कांग्रेस पार्टी से बाहर कर दिया ।

जब इन्होंने यह बात कही कि प्रधानमंत्री जी कुछ बोलते हैं और आर्मी के चीफ या सेना के जवान कुछ अलग बात बोलते हैं । मैं कोट कर रहा हूं, उस वक्त के फील्ड मार्शल रार्बट्स थे, उन्होंने कहा कि पंचशील सिद्धांत के बाद चीन हमारे ऊपर अटैक करेगा और हमारी आर्मी इतनी मजबूत नहीं है कि हम उसका मुकाबला कर पाएं । जब यह स्टेटमेंट बाहर आया तो इसी फ्लोर पर नेहरू जी ने कहा कि आर्मी के लोग गलत बयानी कर रहे हैं । मुझे अपने देश पर भरोसा है, मेरे पास इतनी सेना की ताकत है कि हम किसी भी देश

का मुकाबला कर सकते हैं, चीन की क्या बात है? यह उनका स्टेटमेंट वर्ष 1960 का इसी फ्लोर ऑफ द हाउस में दिया हुआ है । मैं उसी को कोट कर रहा हूं । वर्ष 1961 में फील्ड माशर्ल करियप्पा जी रिटायर हो रहे थे, उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का फर्क है कि मैं सैनिकों को मरते हुए नहीं देख पाया, मैं उसके पहले ही रिटायर हो गया ।

जो वर्ष 1962 में हुआ, वह पूरी दुनिया जानती है । उसके बाद क्या हुआ? लगातार हम चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट में लगे हुए हैं । मैं एक पेपर लेकर आया हूं । वर्ष 1981 में राहुल गांधी जी की दादी इंदिरा गांधी जी ने एक एग्रीमेंट साइन किया था । जब उस एग्रीमेंट को साइन किया था, उस वक्त चाइना के वित्त मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर और ऑर्मी डिफेंस मिनिस्टर हुआंग हुआ थे । हुआंग हुआ और इंदिरा गांधी के बीच में वर्ष 1981 में समझौता हुआ था । वर्ष 1981 से लेकर वर्ष 1987 तक इनके पिताजी भी इस देश के प्रधानमंत्री बन गए थे । हमने चाइना के साथ बाइलैटरल जमीन के लिए, बॉर्डर के लिए लगातार आठ बार मीटिंग की, जो फेल हो गयी । यदि चाइना ने नेहरू जी से जमीन नहीं ली थी तो इंदिरा गांधी जी ने वह कमेटी क्यों बनाई थी? राजीव गांधी जी ने वह कमेटी क्यों बनाई थी? आपने वर्ष 1981 से वर्ष 1987 तक आठ बार मीटिंग क्यों की? आप चाइना को पूरा का पूरा अक्साई चीन से लेकर पाकिस्तान, जो आपने बनाया, मैं उस पर नहीं जाता, आपने सेना को घुसने दिया, आप लद्दाख तक पहुंच गए, आप अरुणाचल तक पहुंच गए, आपने तिब्बत को देकर हमारे माथे पर चाइना को बैठा दिया । आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण एक बॉर्डर डिस्प्यूट रिजॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है । माननीय जयशंकर जी ने यही बयान दिया था कि वे हमारे साथ बाइलैटरल टॉक में हैं । जहां लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल था, वहां पर दोनों सेना चली गई है । इस प्रधानमंत्री जी की जिस मजबूती के कारण आज चाइना पूरी दुनिया में परेशान नजर आ रहा है, आप उस प्रधानमंत्री जी को प्रेज करने के बदले, पूरे देश में उनकी वाहवाही करने के बदले ऐसी बातें कर रहे हैं । आपने चाहे वह नेहरू जी की समस्या हो, इंदिरा जी की समस्या हो या राजीव गांधी जी की समस्या हो, उस समस्या को चूंकि आप रिजॉल्व नहीं कर पाए, आपने चाइना को माथे पर बैठा दिया । आज माननीय प्रधानमंत्री जी उसको रिजॉल्व कर देंगे तो आपका सारा विषय खत्म हो जाएगा, क्योंकि चाइना के साथ आपका एग्रीमेंट है । चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी ने क्या एग्रीमेंट किया है, वह आज तक पूरी दुनिया को नहीं पता है । आप चाइना के एजेंट के तौर पर बैठे हुए हैं, इसी कारण माननीय प्रधानमंत्री जी को बदनाम करने के लिए, देश को गुमराह करने के लिए आप यह बात कह रहे हैं । आप फ्लोर ऑफ द हाउस माफी मांगिए और इन चीजों को ऑथेंटिकेट कीजिए ।

सर, उन्होंने तीसरी बात जयशंकर जी के बारे में और अमेरिका के बारे में कही है कि जयशंकर जी लगातार जाते रहे कि माननीय प्रधानमंत्री जी कैसे ट्रंप से मिलें । आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं । आपने कम्प्यूटर की बात की है । हम लोग अटल जी का 100 वां साल मना रहे हैं । आपने अटल जी को भी कोट किया है । मैं उनका

बयान लेकर आया हूं । उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने यह कहा था कि कम्प्यूटर का कोई बहुत बड़ा प्रभाव हमारे समाज में नहीं पड़ेगा । यही छोटा सा स्टेटमेंट है । यही बात उन्होंने भी कही है । यह फैक्ट है । कम्प्यूटर का हमारे समाज में क्या इम्पैक्ट पड़ा? आज अमेरिका में भी, सॉफ्टवेयर में भारत के लोग ही मजबूत हैं । हमारा स्किल पावर पूरी दुनिया में आगे है । उन्होंने यही बात कही थी कि इससे रोजगार नहीं जाएगा, इससे रोजगार बढेगा । आप उस मृतात्मा, देश के ऐसे प्रधानमंत्री, जिनके बारे में आज भी पूरी दुनिया गर्व करती है, हम गर्व करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के वे प्रधानमंत्री थे, आप उनको भी नहीं छोड़ते हैं । आज आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी फरवरी में जा रहे हैं, कम्प्यूटर हमारे यहां वर्ष 1987-88 में आया था, जबकि अमेरिका में कम्प्यूटर 1960 के दशक में आया था । यूके में कम्प्यूटर 1960 के दशक में आया था । तीस साल बाद आप कम्प्यूटर लाते हैं ।

कोरोना की वैक्सीन में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने दुनिया को दिखाया कि हम दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वैक्सीन बना सकते हैं और हमने बनाया । आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी दुनिया को दिखाया कि जितना आप आगे होने की बात करते हैं, उससे ज्यादा हम हैं । अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के कहने पर अश्विनी वैष्णव जी का बयान आया है कि जो चाइना का डीपसीक है, उसको हम छ: महीने के अंदर समाप्त कर देंगे और हम उससे बढ़िया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाएंगे । डाटा हमारे पास है, मैन्युफैक्चरिंग हमारे पास है, बुद्धि हमारे पास है, लेकिन आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि अमेरिका में जयशंकर जी गए ।

मैं पूरे हाउस की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं । 27 जनवरी, 2025 को व्हाइट हाऊस का जो स्टेटमेंट है, मैं उसको पढ़ना चाहता हूं । वे कहते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री से बात की है । व्हाइट हाउस का स्टेटमेंट है, देश का स्टेटमेंट नहीं है । वे यह कहते हैं कि हम भारत के साथ और भारत के प्रधानमंत्री के साथ अच्छे संबंध रखना चाहते हैं । हमने उनको इन्वाइट किया है । यदि जयशंकर जी ने यह काम किया होता, तो क्या व्हाइट हाउस पर भी भारत सरकार का इतना अधिकार है कि वे जो चाहें, वह स्टेटमेंट दे दें? यदि यह अधिकार जयशंकर जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण व्हाइट हाउस पर भी है, तो इस देश को गर्व करना चाहिए कि हमने व्हाइट हाउस को भी कंट्रोल कर लिया है । लेकिन फिर मैं कहूंगा कि समस्या कहां है, समस्या यह है कि अमेरिका से इनके पूरे परिवार के साथ संबंध खराब रहे हैं ।

अभी मैं सन् 1971, 1972 और 1973 की सीआईए की रिपोर्ट्स देख रहा था । वह यह कह रही है कि भारत की इकोनॉमी रसातल में जा रही है, यह पाकिस्तान को अटैक करके एक्सटेंशन के मोड में जाना चाहती है, लेकिन इसका अपना कुछ नहीं है, यह रूस के साथ मिलकर जाना चाहते हैं और हम भारत को बैन करेंगे । सन् 1971-72 की सीआईए की जो रिपोर्ट है, मैं आपको बताऊं कि इंदिरा जी को सन् 1982 में रोनाल्ड

रीगन से माफी मांगनी पड़ी थी । आप उस परिवार के आदमी हो । मैं नहीं बोलना चाहता था, मैं मुंह नहीं खोलना चाहता था, लेकिन सन् 1982 में इंदिरा जी ने अमेरिका जाकर रोनाल्ड रीगन से माफी मांगी कि जो हो गया, सो हो गया, हमको माफ कर दीजिए । एक वह देश था और आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह देश है कि ट्रंप खुद से फोन करते हैं और ट्रंप पूरे व्हाइट हाउस को बताते हैं कि हमने उनको बुलाया है, हम उनके साथ अच्छे संबंध रखना चाहते हैं । देश कहां चला गया और आप कहां खड़े हो?

मेरा तीसरा सवाल है, इन्होंने महाराष्ट्र चुनाव की बात कही । चौथा, इन्होंने इलेक्शन कमिश्नर के अपाइंटमेंट की बात कही । मैंने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देखा है । सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने कहा है कि इलेक्शन कमिश्नर का जो अपाइंटमेंट है, वह ट्रांसपैरेंट नहीं है । आज सुप्रीम कोर्ट में केस दायर हुआ, तो यह जजमेंट आया और यह भी कहा गया कि मैं यह टेंपरेरी जजमेंट दे रहा हूं, लेकिन पार्लियामेंट को यह अधिकार है कि वह कानून बनाए । कानून कैसे बनाना है? इसी पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया कि कौन-कौन लोग होंगे और इलेक्शन कमिश्नर का अपाइंटमेंट कैसे होगा, लेकिन मैं जो महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं कि आपने चुनाव आयोग पर इतने आरोप लगाए हैं ।

एम. एस. गिल मुख्य चुनाव आयुक्त थे । वह रिटायर हुए, कांग्रेस पार्टी के सदस्य हो गए और राज्य सभा के मेंबर हो गए । देश में स्पोर्ट्स मंत्रालय के मंत्री बन गए । नवीन चावला जी हैं, मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं, अभी उनकी मृत्यु हुई है, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि जो विदेशी लॉबी है, उन्होंने मदर टेरेसा पर बहुत अच्छी किताब लिखी थी । सोरोस के साथ जो लॉबी गांधी परिवार की मदद करती है और जो देश के टुकड़े-टुकड़े करना चाहती है, वह उस लॉबी के सबसे बड़े समर्थक थे । जो सेक्रेटरी एम्पैनल नहीं था, मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, उसको जबरदस्ती सेक्रेटरी एम्पैनल कराया और सीधे मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया गया ।

यदि आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हम कानून चेंज करके लाएं और उसमें आप भी बैठेंगे, हम पैनल देंगे, तो इसके पहले तो आपने कभी भी लीडर ऑफ द अपोजिशन को नहीं पूछा था । जब वर्ष 2014 तक आपकी सरकार रही है, मैं राहुल गांधी जी, पूरी कांग्रेस पार्टी और पूरे विपक्ष को चैलेंज करता हूं कि क्या आपने मुख्य चुनाव आयुक्त के अपाइंटमेंट में एक बार भी किसी विपक्ष के आदमी से कंसल्ट किया है? सन् 1950 से लेकर 2014 तक आप अपने चपरासी को, कार्यकर्ता को, आपने जिसको चाहा, उसको चुनाव आयुक्त बना दिया । 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को । आज हम ट्रांसपैरेंसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं । कुछ ऐसी ताकतें हैं, जो भारत के लोकतंत्र को कमजोर करना चाहती हैं, आपने उन ताकतों के साथ मिलकर पूरे के पूरे महाराष्ट्र चुनाव का हिसाब-किताब दे दिया । मैं कुछ सीटें लेकर आया हूं । मैं दो-चार मिनट्स में अपनी बात समाप्त कर दूंगा ।

22.00 hrs

माननीय सभापति : आप बैठिए । मैं आपको मौका दूंगा । इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए वक्ताओं की लंबी सूची है । अगर सभा की अनुमति हो तो सभा की कार्यवाही 11 बजे तक बढ़ा दी जाए ।

अनेक माननीय सदस्य : हां ।

डॉ. निशिकान्त दुबे : सभापति महोदय, महाराष्ट्र इलेक्शन में कहा गया कि सभी ईवीएम पर आ जाइए, ईवीएम पर आ जाइए, लेकिन ईवीएम कौन लाया? क्या ईवीएम हम लेकर आए? जब मैं वर्ष 2009 में पहली बार सांसद बना तो ईवीएम से ही जीत कर आया था । जब आपकी सरकार ईवीएम से बनी तो इसका मतलब है कि आप ईवीएम में चोरी करते थे । आप देश को बताइए कि ईवीएम मैनिपुलेट होती है और नवीन चावला के माध्यम से आपने मैनिपुलेट की, एमएस गिल के माध्यम से अपने मैनिपुलेट की । आप माफी मांगिए । यदि आप माफी मांगते हो तो शायद इसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी चर्चा कर सकते हैं । ईवीएम तो आप ही लेकर आए हैं । अपने जनता के मन में डेमोक्रेसी के खिलाफ, महाराष्ट्र के रिजल्ट के खिलाफ बोला और महाराष्ट्र की जनता का अपमान किया तथा मेनडेट का अपमान किया । उसका हिसाब-किताब कौन देगा?

सभापति महोदय, मैं केवल कुछ सीटों के बारे में आंकड़े पढ़ना चाहता हूं । अकोला वेस्ट सीट पर 18000 वोट बढ़े । ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली है कि 1000 से लेकर 70000 तक वोट किसी-किसी विधानसभा में बढ़े हैं । अकोला वेस्ट में 18000 वोट बढ़े, लेकिन जीता कौन ? कांग्रेस, नागपुर वेस्ट में 22000 वोट बढ़े, लेकिन जीता कौन ? कांग्रेस, नागपुर नॉर्थ में 23000 वोट बढ़े, लेकिन जीता कौन ? कांग्रेस, यवतमाल में 13000 वोट बढ़े, लेकिन जीता कौन ? कांग्रेस, मालेगांव में 40000 वोट बढ़े, लेकिन जीता कौन - ओवैसी साहब की पार्टी, धानुआ में 17000 वोट बढ़े, लेकिन सीपीएम जीती, भिवंडी में 40000 वोट बढ़े, लेकिन समाजवादी पार्टी जीती, मुंबई नॉर्थ में 41000 वोट बढ़े, लेकिन एनसीपी शरद पवार जी की पार्टी जीती । आप यह समझिए कि विधानसभावाइज सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ चुनाव जीती हैं । आप किस तरह की बातें करते हो? हम लोक सभा में वहां पर कम सीटें लाए तो उछलने लगे कि जनता आपके खिलाफ है । जब आज हम जीत गए तो डेमोक्रेसी और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आप जनता को गुमराह कर रहे हो । आप टुकड़े-टुकड़े गैंग के सरदार हो और उस टुकड़े-टुकड़े गैंग की इस देश को टुकड़े-टुकड़े करने की जो साजिश है, वह आप कर रहे हैं । आप ऑथेंटिकेट कीजिए कि आपने गलती की है और आप गलत बात बोल रहे हैं ।

सर, मैं अपने अंतिम पॉइंट को बोलना चाहता हूं । जातिगत जनगणना हो और ओबीसी को अधिकार मिले, एससी को अधिकार मिले, एसटी को अधिकार मिले, इससे कोई भी आदमी परहेज नहीं करता है । तेलंगाना की जनगणना हाउस के लिए आई है । माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहां पर कहा और यह देश को जानने वाला सवाल है, खासकर, पिछड़ों और अति पिछड़ों को जानने का सवाल है । इस देश में 27 परसेंट रिजर्वेशन

इसलिए मिला है कि ओबीसी की पापुलेशन 54 परसेंट है । तेलंगाना की रिपोर्ट आई है और सभापति महोदय वह आपके बगल का पड़ोसी राज्य है, वह कह रहा है कि 46 परसेंट ओबीसी है । इस तरह से क्या होगा? वे ओबीसी में मुसलमानों को जोड़ रहे हैं । माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब तक मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूं और भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता है, वह ओबीसी के आरक्षण को बैक डोर से कभी मुसलमानों के पास नहीं जाने देगा । यह जो वोट बैंक की राजनीति है, ये वोट बैंक की राजनीति यही करने के लिए प्रेरित कर रही है । आप जिस पिछड़े की बात कर रहे हो, उस पिछड़े का सबसे बड़ा नेतृत्वकर्ता माननीय प्रधानमंत्री खुद सामने बैठे हैं । क्या आपको यह दिखाई नहीं दिया कि ओबीसी इस देश का प्रधानमंत्री है? ललन जी, मनमोहन सिंह जी की अभी डेथ हुई है । उनको वह भी नहीं दिखा कि माइनोरिटी के आधार पर दस साल मनमोहन सिंह जी एक माइनोरिटी इस देश के प्रधानमंत्री थे ।

श्रीमती द्रौपदी मुर्मु जी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की महिला, इस देश की राष्ट्रपति हैं । श्री रामनाथ कोविंद, शेड्यूल्ड कास्ट से हैं और इस देश के राष्ट्रपति हुए । आप किस तरह की बात करते हो । आप बिजनेसमैन की बात करते हो । आज ही अखबार में बड़ी-बड़ी तुलसी तांती की ऐड छपी । तुलसी तांती कौन है? शेड्यूल्ड कास्ट से नहीं हैं? टाटा एक पारसी हैं और क्या माइनोरिटी से नहीं हैं? क्या अडाणी जी जैन नहीं हैं? वेदांता के अनिल अग्रवाल साहब क्या ओबीसी नहीं हैं? हमारे राज्य से आते हैं और हमारे यहां तो मारवाड़ी भी ओबीसी हैं । आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? जिस आदमी को न कुछ अता है, न पता है । इनको लिखकर देने वाले जो स्क्रिप्ट राइटर हैं, वे भी किस बियाबान में रहते हैं, क्योंकि जब इटली से लिखवाकर आओगे, सोरोस से जब लिखवाकर आओगे तो इस देश के टुकड़े कैसे किए जाएं, इसके अलावा आपके पास कोई विषय नहीं हैं । मैं कनक्लूड करते हुए आपके माध्यम से यह आग्रह करता हूं कि इन छ: पॉइंट्स को वे ऑथोन्टिकेट करें, नहीं तो स्पीकर के डायरेक्शन के खिलाफ उनके ऊपर प्रिवलेज की कार्यवाही हो और उनको इस पार्लियामेंट से बाहर कीजिए, तभी यह देश बचेगा । आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत ।

संसदीय कार्य मंत्री; तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री किरेन रिजिजू) : सर, आज जब लीडर ऑफ ओपोजिशन बोल रहे थे तो माननीय स्पीकर ने खुद चार बार दोहराया कि जो बात लीडर ऑफ ओपोजिशन रख रहे हैं, उसको ऑथोन्टिकेट करें । लेकिन लीडर ऑफ ओपोजिशन बोलकर चले गए । उन्होंने जो मुद्दे रखे हैं, निशिकांत जी ने अभी जो मुद्दे रखे हैं, मैं इसी बात पर बल देना चाहता हूं कि इस संसद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए लीडर ऑफ ओपोजिशन बहुत रिस्पोंसिबिलिटी वाला पोस्ट है । इसलिए जो भी तर्क रखे, भविष्य में भी कोई भी नेता प्रतिपक्ष होगा तो बात को गंभीरता से रखेगा । यह प्रक्रिया हमेशा चलती रहनी चाहिए । अगर हम आज श्रीमान राहुल गांधी जी को छूट देंगे तो कल को कोई भी नेता प्रतिपक्ष यहां कोई भी बात बोलकर चले जाएंगे, ऐसा तो बिलकुल नहीं होना चाहिए ।

इसलिए जिन छ: पॉइंट्स को रखा गया है, उनको ऑथोन्टिकेट जरूर करना चाहिए । अन्यथा जो उचित कार्यवाही है, वह चेयर की ओर से की जानी चाहिए । इसी बात को लेकर मैं दो पॉइंट सदन के सामने रखना चाहता हूं । एक तो चीन के प्रवक्ता से भी ज्यादा चीन की तारीफ आज नेता प्रतिपक्ष ने सदन में की । भारत की संसद में चीन का इतना गुणगान किया गया कि मैंने आज तक जिंदगी में इतना सुना नहीं है । ? (व्यवधान) दूसरी बात, नेता प्रतिपक्ष उसी पार्टी से आता है, इसीलिए मैं कह रहा हूं वर्ष 1959 में और 1962 में जितनी जमीन हमारे देश की जमीन, चाहे वह लद्दाख में हो या अरुणाचल प्रदेश में हो या कहीं भी हो । ? (व्यवधान)

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): The hon. Minister is misleading the House. ? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Let him speak. Please sit down. You will be given a chance.

? (*Interruptions*)

श्री किरेन रिजिजू : वर्ष 1959 और 1962 में चीन ने जितनी जमीन कब्जा की है, उसके लिए श्रीमान राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए ।? (व्यवधान) उसके परिवार के ही, उनके नाना जी उस समय प्रधान मंत्री थे । इसलिए मैं आज यह मांग करना चाहता हूं । ? (व्यवधान)

SHRI KODIKUNNIL SURESH : He is misleading the House. ? (*Interruptions*) Sir, how are you allowing him to speak? ? (*Interruptions*)

श्री किरेन रिजिजू : सुरेश जी, आप सीनियर मैम्बर हैं और आप आठ बार चुनाव जीतकर आए हैं । ? (व्यवधान) आप राहुल गांधी जी को समझा दीजिए ।? (व्यवधान) राहुल गांधी जी यहां बोलकर चले गए हैं, लेकिन आप उनको समझा दीजिए कि यह भारत की संसद है और इस देश की संसद में हम भारत का अपमान नहीं सह सकते हैं । ? (व्यवधान)

SHRI SASIKANTH SENTHIL (TIRUVALLUR): You are misleading the House. ? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Now, Shri Sasikanth Senthil.

SHRI SASIKANTH SENTHIL (TIRUVALLUR): Hon. Chairperson, Sir, first of all, I would like to thank the hon. Member, who spoke before me, for giving his acceptance speech for the allegations that the LoP has made. Yes, he gave justification why they are doing it. तब हुआ तो हम भी करेंगे, हम भी करेंगे । That is the whole point.

So, in fact, inadvertently, he has justified and he has accepted what the hon. LoP has said, and he just could not say anything else. So, that

means that on the Floor of the House, there is an hon. Member who is accepting everything that the LoP has alleged.

Now, I come to the President?s Address. I come from Tamil Nadu where our great leader Periyar once said, and I quote:

?yaar solli irunthalum, yenge padichu irunthalum, naane sonnalum, un buddhikkum podhu arivukkum porunthatha ethaiyum nambadhe.?

It translates to ?do not believe anything that does not match your intelligence and commonsense?. No matter who says it or where you read it or even if I say, we are not going to read the entire President?s Address because we are bored of this; our country is completely bored of this rhetoric Address. It is just a wish list, laundry list and nothing else. There is no vision. There is nothing which has talked about the macro-economic condition. I am not saying this without any reasoning. It appears that the Government has mastered this art of grand announcements where statistics are cherry-picked and brushed under the carpet. This is what is happening. I am not saying this without any reason.

Sir, what is the biggest problem? Getting jobs is the biggest problem. Where is the employment? There is no employment. Did even a word occur in the President?s Address about the employment? Unemployment is around 45 per cent. In 2014, I remember the Prime Minister?s speech where he used to say ?अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे ।? हम दो करोड़ जॉब्स दे देंगे । Where are those two crore jobs? आपने 20 लाख जॉब्स भी प्रोड्यूस नहीं की है ।

Let us come to GDP. They said that GDP will just grow at the lightning speed. It is seven per cent or 7. 5 per cent. 7.5 परसेंट कहां पर है? Even in your term, it has fallen down to 6.4 per cent. In this quarter, it is 5.4 per cent. Why do they not speak about these things? Even in the worst times, during Manmohan Singh Ji?s period, the average GDP was 7.6 per cent. That is the growth we had. You do not talk about all these things.

Let us come to the real people of this country. What has happened to their wages? Wages have either stagnated or declined. In fact, we are now running 39 per cent of our GDP. Now, these are all macro-economic things. There is no discussion about these things.

Now, I come to the issue of household savings. People used to save in our country. That is our mainstay. The household savings are low in 50 years. There are no savings happening. The entire macroeconomic situation is in a very bad shape.

Now, I will come to BJP?s economic policy. जब हम बच्चे थे we used to read about Robinhood. Robinhood used to steal from the rich and give it to the poor. Now, the BJP?s economic policy is reverse of what Robinhood?s policy was. They steal from the poor and give to the rich. They are so friendly; they are so understanding of their friends that in the last five or in the last ten years, they have waived Rs. 9.9 lakh crore of loans that too from our Public Sector Banks. Now, where does this money come from? It is the tax-payers? money. So, the fastest thing, which is actually happening, is the vanishing of the tax- payers? money in this regime or maybe, the fastest thing happening is the inflation which is happening in this regime. That is the only fastest thing which is happening.

In the Budget, there was a huge thing about the tax rebate which they have given. I just checked the numbers. This year, they had collected around Rs. 12 lakh crore from direct tax, that is income tax. Now, for next year, they are projecting that they are going to collect Rs. 14.38 lakh crore. I just cannot understand it. If that is such a great rebate, how is your tax income growing and that too from individual tax-payers?

Sir, 57 per cent of the tax is being taken away from individual tax-payers. In the case of corporates, a very nice approach is followed. Nothing should pain them. In fact, it is a very charitable Government. They actually donate a lot only to the people who are in the boardrooms and they steal from the people on the ground.

Let us come to the issue of farmers. They said that by 2022, they will double their income. What have they done? They have doubled the debt of the farmers.

Sir, regarding Kisan Credit Card, this Government is the biggest loan giving Government we have ever seen. The biggest programme for farmers is the Kisan Credit Card. किसान क्रेडिट कार्ड पर अभी तक दो लाख लोन था और अभी पांच लाख लोन हो गया । You have doubled the debt of the farmers. That is exactly what he did.

When the farmers demanded MSP, you just barricaded them, lathi-charged them and used tear gas on them. In fact, one of the Members today was talking about how Mr. Modi, the Prime Minister, instructed his army ?गोली चलाओ, गोली चलाओ ।? I think he instructed his security forces to फार्मर्स पर गोली चलाओ । That is what is happening.

They do not have any concern for our farmers. Sir, not only the farmers, the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, women ? everybody is in big trouble in this country.

Sir, today we talked about the Drone Didi Scheme. I verified as to what the Drone Didi Scheme is. I cannot understand what this Drone Didi Scheme is. They have given drones to women. We have seen women in the rural areas. Just by doing some PR exercise does not work. In fact, 60 per cent of these drones do not have enough battery which can run for ten minutes and all the drones are landed.

In fact, our LOP has talked about it. If the government has a little bit of concern, a little bit of common sense, it will understand what the LOP is saying and create a vision for this country rather than going back to the history of Shri Motilal Nehru and his father. Come to reality, Sir! The youngsters of this country want to know about the policy for their future. That is exactly what they want.

Regarding federalism, I want to state that this is a Union of States. I come from Tamil Nadu. I wonder whether this Government even thinks that we are part of this country. They talk about Kashi Tamil Sangamam. Who has asked for Kashi Tamil Sangamam? Did we ask for it? Did anybody in Tamil Nadu ask for it? We do not want Kashi Tamil Sangamam. We want you to respect our Sangam. Did you respect our Sangam?

Today, by our own Archaeological Department, we have found that the Iron Age dates back to 5000 BC in Tamil Nadu. Did you speak about it? Did you even bother about the culture of this country? Did you even bother about this country? So, the whole point is, you want to run your narrative and want to forget everything.

Sir, Tamil Nadu has been requesting Rs. 6,675 crore for disaster relief and Rs. 2,152 crore for Samagra Shiksha Abhiyan. They have not paid the

salaries of our teachers. They have made our children sit without paying the salaries of our teachers. Why are you talking about federal system?

Sir, I want to conclude by saying only one thing. This country is not made by big rulers or ruling class. This country is made by the working class, the oppressed section of this country, the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the OBCs of this country. We are not going to sit and listen to all these things.

Sir, I will also tell you one thing that when the concept of *achchhe din* got faded out, they came with this new idea of Amrit Kaal. When this concept got faded out, they have come out with a new idea of Viksit Bharat. Investors are running from this country. Maybe they should add one more Viksit and make it Viksit Viksit Bharat to make sure that the economy is alright.

Finally, I conclude by saying the most irritating thing for them ? Ambedkar, Ambedkar, Ambedkar, Ambedkar, Ambedkar, Ambedkar. Thank you, Sir.

श्री रामप्रीत मंडल (झंझारपुर) : आदरणीय सभापति महोदय, आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी है, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं ।

महोदय, माननीय प्रधानमंत्री श्री नेरन्द्र मोदी जी के कार्यकाल में देश में स्वर्णिम युग चल रहा है । देश में बहुमुखी विकास हो रहा है । गरीबों, पिछडो, दलितों एवं वंचितो वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए काम हो रहा है ।

महोदय, सरकार की सभी योजनाओं का लाभ आम जनता को समान रूप से मिल रहा है । हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के सारे संकल्प पूरे हो रहे हैं । देश को माननीय प्रधानमंत्री जी पर गर्व है कि उनका मूल मंत्र "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास" पूरे विश्व में प्रचारित किया जा रहा है और सफल हो रहा है । मैं अपने विश्व प्रिय प्रधानमंत्री जी का अभिनन्दन करता हूं । ऐसे महान नेता धरती पर सदियों में पैदा होते है । यह मेरा सौभाग्य है कि मैं पिछले 6 वर्षों से उनके साथ सदन में कार्य कर रहा हूं । आज विश्व में भारत की अपनी अलग पहचान बनी है । विश्व के प्रमुख राजनेताओं से इनका आत्मीय संबंध बढ़ा है । यह देश के लिए गौरव की बात है ।

महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी का सह तीसरा कार्यकाल प्रारम्भ हुआ है और सरकार भी तीन गुणा तेजी से काम कर रही है, इसका परिणाम होगा कि भारत जल्द ही विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यस्था वाला देश बनने जा रहा है । यह एक अभूतपूर्व उपलब्धी होगी ।

आदणीय महोदय, देश में सभी के लिए आवास के उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो काम हो रहा है, वह सराहनीय कदम है । हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा स्वामित्व योजना इस दिशा में अगला कदम है ।

महोदय, सरकार नई दिशा नीति लागू कर चुकी है । इससे युवाओं की शिक्षा और उनके लिए रोजगार के नए अवसर मिलेंगे । शिक्षा के इस आधुनिक युग में मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरे संसदीय क्षेत्र झंझारपुर, बिहार में आजादी के 75 वर्षों के बाद एक भी केन्द्रीय विद्यालय नहीं है । इसके लिए में पिछले कार्यकाल से ही प्रयासरत हूं, किन्तु अभी तक यह मामला केन्द्र सरकार के पास लम्बित है । आशा है कि माननीय शिक्षा मंत्री इस ओर जल्द से जल्द कदम उठाने का काम करेंगे और मधुबनी के झंझारपुर में केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना की स्वीकृति प्रदान करने का प्रयास करेंगे ।

महोदय, सीतामढ़ी से जयनगर, लदनियां, लौकहा-लौकही, निर्मली, सुपौल जिला, सहरसा जिला को जोड़ने वाली रेल परियोजना के लिए वर्ष 2004 में उस समय के रेल मंत्री, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में माननीय नीतीश कुमार जी थे, उन्होंने यह प्रस्ताव लाया, लेकिन अभी तक माननीय के द्वारा उस पर विचार नहीं किया गया है । मेरा सरकार से अनुरोध है इस क्षेत्र के आर्थिक व सामाजिक विकास की दृष्टि से इस परियोजना को जल्द से जल्द पूर्ण कराने का काम करेंगे । मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी का कृषि आधारित बिहार राज्य में केसीसी की सीमा तीन लाख से पांच लाख किए जाने पर संपूर्ण बिहार की तरफ से धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं ।

आदरणीय महोदय, सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि योजना से देश भर में मात्र तीन करोड़ किसानों को ही लाभ दिया जा रहा है, इसे बढ़ाने की आवश्यकता है क्योंकि काफी संख्या में जरूरतमंद लाभार्थी इस योजना से वंचित हैं । मेरा कहना है कि उन्हें भी सामान रूप से लाभ मिलना चाहिए । इस योजना की समीक्षा करना अति आवश्यक हो गया है ।

महोदय, देश के विकास में हमारे किसानों का ही महत्वपूर्ण योगदान है । आज देश की अर्थव्यवस्था तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है, यह किसानों की बदौलत ही संभव हो पा रहा है किन्तु देश के किसान अभी भी खुशहाल नहीं हैं उनकी स्थिति दयनीय बनी हुई है । सरकार प्रयासरत है किन्तु अपेक्षित परिणाम नहीं आ रहे हैं । आज एमएसपी पर सरकार का फोकस है किन्तु अभी भी हमारे किसान भाई आंदोलन करने के लिए मजबूर हैं । यह दुर्दशा क्यों है? इस दिशा में सरकार को विचार करना चाहिए ।

आज हमारे किसान 332 मिलियन टन अनाज पैदा कर रहे हैं, यह देश के लिए गर्व की बात है । हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा दूध, दालों और मसालों का उत्पादक है, फिर भी देश में किसानों की आय को दो गुना करने का जो लक्ष्य सरकार ने रखा है वह भी पूरा नहीं हो पा रहा है । मेरे संसदीय क्षेत्र में एक एग्रीकल्चर कॉलेज की अति आवश्यकता है ।

मेरा क्षेत्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है । खेतीबाड़ी ही वहां के लोगों का मुख्य स्रोत है । अतः माननीय कृषि मंत्री जी इस ओर जरूर ध्यान देने का काम करें और मेरे संसदीय क्षेत्र में एक कृषि महाविद्यालय की स्थापना की मंजूरी देने का काम करें । मैं इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ ।

किसान के पसीने की अब कद्र हो रही है,
धरती माँ की गोद फिर से हरी हो रही है ।
सरकार के फैसले नई रोशनी ला रहे हैं,
अन्नदाता के सपने हकीकत बनते जा रहे है ।

जय हिन्द, जय जवान, जय किसान जय विज्ञान ।

श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील (सांगली) : माननीय सभापति जी, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का मौका देने लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

सरकार ने महामहिम राष्ट्रपति जी को अच्छी बातें पढ़ने का अवसर दिया और कड़वी सच्चाई छिपाने की बहुत अच्छी कोशिश की । प्रेजीडेंट एड्रेस किसी बैलेंस सीट की तरह होता है, इसमें एसेट्स जो सरकार की उपलब्धियां होती हैं और लाएबिलिटीज़ भी होती हैं, जहां कोई चूक हो गई या कुछ रह गया हो तो वहां से बहुत कुछ सीखने को मिलता है । यह अभिभाषण सरकार के लिए इलैक्शन का एक पार्टी मेनिफेस्टो है, दिल्ली और बिहार इलैक्शन एनाउंसमेंट का भाषण है । इन्होंने कुछ चुनिंदा उपलब्धियों के जश्न पर अभिभाषण में समय बिताया ।

लेकिन चुनौतियां हैं, उस पर पूरी तरह चुप्पी साधे रखी । ये आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं और उस पर बहुत लोग बोलें । अगर आधे से ज्यादा आबादी आत्मनिर्भर न होकर सरकार की जनकल्याण की स्कीमों जैसे अनाज के लिए उन्हें जाना पड़ता है तो क्या यह सही मायने में आत्मनिर्भरता है या यह आर्थिक विफलता का एक प्रमाण पत्र है?

सर, मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि ये गरीबी हटाना चाहती है या गरीबों को सरकार पर निर्भर रखना चाहती है? यह दुर्दशा ऐसी है, it is across. किसानों के बारे में भी मैं अकेला नहीं कहता, मेरी पार्टी या हमारे अलायंस के लोग नहीं कहते, बल्कि संविधान की जो सैकेंड पोस्ट है, उपराष्ट्रपति जी, उन्होंने कृषि मंत्री जी को कहा है कि कृषि मंत्री का हरेक पल भारी है और उन पर कालचक्र घूम रहा है । यह उपराष्ट्रपति जी ने कहा है । मैन्यूफैक्चरिंग में there is a drop. The job share has dropped to 11.4 per cent.

ईज ऑफ डूइंग बिजनैस इंडेक्स में ये वाहवाही करते रहे, लेकिन इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर सही होना बहुत जरूरी है । मैं अभिभाषण की प्रशंसा करूंगा कि कुम्भ मेले में जो जानें गईं, उनके बारे में उन्होंने वहां पर उल्लेख किया, लेकिन सरकार इसमें इफेक्टिव स्टेप्स लेने में क्या कहीं चूकी है? उनको यह भी कहना बहुत जरूरी था । महाराष्ट्र में हम साहू, फुले, अम्बेडकर, शिवाजी महाराज जी के आदर्शों पर चलते हैं । लेकिन हमारे

महाराष्ट्र में भी आज समाज में, जातियों में डिविजन पैदा करने की कोशिशें इस सरकार के द्वारा की गई हैं । मराठा आरक्षण के लिए लड़ते हैं, लेकिन इन्होंने मराठा आरक्षण की लड़ाई को मराठा विरुद्ध ओबीसी की लड़ाई बना दिया ।

सर, मैं धनगर आरक्षण के लिए बोलूंगा । धनगर चाहते हैं कि उनको एसटी में आरक्षण मिले, लेकिन एसटी विरुद्ध धनगर का झगड़ा लगाकर बीजेपी की सरकार झगड़ा बढ़ाती जा रही है । हमारे महाराष्ट्र में जैन समाज, जैन समाज में श्वेताम्बर और दिगम्बर आते हैं । हमारे वाशिम जिले में शिरपुर में एक मंदिर है ? पार्श्वनाथ मंदिर । मंदिर में पूजा के अधिकारों के लिए वहां पर मारा-पिटी होती है । जब दिगंबर समाज के लोग वहां पूजा करने जाते हैं, तो उन्हें मारा जाता है । ये एक ही धर्म के, एक ही समाज के लोग अगर झगड़ रहे हैं तो इनका झगड़ा खत्म करने, सॉल्यूशन निकालने का कोई भी प्रयास इस सरकार ने नहीं किया । क्या सरकार यह चाहती है कि लोग झगड़ते रहे और इसमें से हम जीतते रहे । अभी-अभी दुबे जी ने ओबीसी को धर्म से जोड़ लिया । ओबीसी का धर्म से क्या लेना-लेना? Caste is agnostic. It has nothing to do with religion. Every time, they want to convert this caste issue into a religious thing. सर, सरकार मिडिल क्लास को एक एटीएम की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश करती है । आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार नेट हाउसहोल्ड सेविंग 50 साल के सबसे नीचे स्तर पर पहुंच चुकी है ।

Sir, there is something called as the middle-income trap, and it is a real thing. Unfortunately, it looks like that this Government is leading all of us into that middle-income trap.

Anyway, Sir, in short, I could say that we have many opportunities. Thanks for allowing me to speak till now. यह सपनों का भारत नहीं, यह संघर्ष का भारत बनता जा रहा है । जनता महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी के बोझ तले दबी हुई है । सरकार सिर्फ जुमले और नारों की घुट्टी पिलाने में व्यस्त है । सरकार से मैं अनुरोध करता हूं कि विज्ञापन की सरकार न चलायें और काम करने वाली सरकार चलायें । मैं इतना बोलकर अपना भाषण खत्म करता हूं ।

जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम ।

श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी (बालासोर) : माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन पर बोलना चाहता हूं । आपने मुझे इसकी अनुमति दी, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं ।

राष्ट्रपति जी का अभिभाषण नाना दृष्टि से ऐतिहासिक है । यह भारत की उपलब्धि, आशा, आकांक्षा, स्वप्न और सम्भावना, सत्य और स्वाभिमान का प्रतीक है । सम्पन्न राष्ट्र चेतना का झंझकोर करने वाला यह भाषण ऐतिहासिक उपलब्धि से भरा है ।

मैं इसके समर्थन में बोलना चाहता हूँ । दुर्भाग्य है कि आज अपोजिशन पार्टी के लीडर ने इतना बचपना किया । प्रधानमंत्री जी उनका मुख-दर्शन नहीं करते हैं, उन्होंने ऐसा आरोप लगाया । यह क्या बकवास है? प्रधानमंत्री जी क्यों उनका मुख-दर्शन करेंगे? वे तो दर्शन करने लायक नहीं हैं । लोकतंत्र का ... @, जिन्होंने संविधान को लेकर, संविधान का अपमान करते आये हैं, मान्यवर प्रधानमंत्री जी उनका मुख-दर्शन क्यों करेंगे? देश के लिए समर्पित प्राण, मान्यवर प्रधानमंत्री जी ऐसे लोगों का मुख-दर्शन क्यों करेंगे?

वर्ष 1975 में, जो आज संविधान को पकड़कर चलते हैं, वे उस खानदान से बिलांग करते हैं, उस खानदान ने हमारे संविधान का अपमान किया था । माननीय सुप्रीम कोर्ट की राय का उल्लंघन करके निर्लज्जतापूर्वक संविधान में संशोधन किया और अपनी कुर्सी बचाने के लिए ही किया और बार-बार किया और उनके पिताजी ने भी कई बार किया । ऐसे खानदान से, ऐसे व्यक्ति का मुख-दर्शन करना जरूरी नहीं है । उन्होंने इमरजेंसी जारी करके गणतंत्र की आत्मा की हत्या की है । इसलिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी का अपमान करने वाले, हमारे संवैधानिक मूल्यों का अपमान करने वाले लोगों का मुख-दर्शन करना जरूरी नहीं है ।

भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सामने पेपर फाड़कर जिन्होंने बता दिया कि राजकुमार प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से और संविधान से ज्यादा महत्वपूर्ण है । वे उनका मुख-दर्शन क्यों करेंगे? मान्यवर प्रधानमंत्री जी लोकतंत्र के महानायक हैं ।

सर, ऐसा लगता है कि शैतान का वेद-पाठ है । Even devils can quote Scriptures for their own purpose. कोलकाता में एक व्यक्ति था, जो बोलता था कि:

> *I steal; I drink alcohol; I go to the brothel as well. But I have maintained the dignity of my character.*

उस संविधान को पकड़कर इतना बवंडर करने वाले ने संविधान की कितनी बार हत्या की, इसके बारे में सोचना चाहिए । उनके मुँह से संविधान और लोकतंत्र जैसे शब्द शोभा नहीं देते हैं । इसलिए इस प्रसंग में बिल्कुल विरोध करते हैं, क्योंकि वे संविधान का विरोध करते हैं । डॉ. अम्बेडकर का नाम लेकर, उनको प्रणाम करके और संविधान निर्माताओं को प्रणाम करके राष्ट्रपति जी ने अपना अभिभाषण शुरू किया । उनको यह सहन नहीं होता है । अम्बेडकर जी दलित वर्ग से आते हैं और दलितों का अपमान करने वाले ने अम्बेडकर का कितनी बार अपमान किया, उनको पराजित करने के लिए कितना दुष्चक्र किया, कितना दुष्कर्म किया, उस अम्बेडकर का सम्मान मान्यवर मोदी जी ने ही किया । चाहे पंच तीर्थ का निर्माण हो, अम्बेडकर जी की जन्म-जयंती का पालन हो, ये सारे काम मोदी जी ने किये । यह उनको सहन नहीं होता है ।

सर, महाकुम्भ के बारे में माननीय राष्ट्रपति जी ने उल्लेख किया । महाकुम्भ भारत की सनातन आत्मा का प्रतीक है । 144 साल के बाद यह दुर्लभ महाकुम्भ आया है । कुम्भ मेला एक मिनी भारत का प्रतीक है । सम्पूर्ण विश्व से लोग इसमें आते हैं । विश्व का सबसे

बड़ा मेला- महाकुम्भ है । यह न केवल एक मेला है, बल्कि यह त्रिवेणी संगम पर, गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर जो मेला होता है, यह संत गंगा, ज्ञान गंगा और अध्यात्म गंगा की त्रिवेणी है और सुख-समृद्धि के साथ यह होता है । लाखों साधु-संत, भिन्न-भिन्न वर्ग के लोग, हरेक सम्प्रदाय के लोग, शैव, शाक्त, गाणपत्य, पंचरात्र, वैखानस, वेदांती आदि सभी प्रकार के लोगों का यहाँ समागम होता है । यहाँ ज्ञान गंगा का निरंतर प्रवाह होता है ।

हमारा राष्ट्र एक सनातन राष्ट्र है । किसी सोशल कांट्रैक्ट थ्योरी के द्वारा इसका आविर्भाव नहीं हुआ है । पतित-पावनी गंगा जैसे हिमाचल की गिरी गुफाओं से निकल करके, कलकल, छल-छल, निनादिनी, भीमकांत गर्जन में, सारी धरती को प्रकम्पित करते हुए, वह समस्त भूमि को पवित्रता, स्निग्धता प्रदान करती हुई आती है और अंत में सागर में पतित होती है । ऐसा हमारा सनातन राष्ट्र चिन्तन है । हमारा वैदिक सनातन ऋषियों के ध्यान से निकलता है और यह राष्ट्र सनातन है ।

यह राष्ट्र कभी प्राचीन नहीं होता है । ब्रजेन्द्र नाथ सील महोदय ने लिखा है : ?India is ever aging but never old.? यह प्राचीन है, परन्तु आज भी हिमालय जैसा सनातन अनन्त तारम्य से अक्षय तेज में भारत माता विद्यमान है ।

सर, हमारा कुम्भ मेला भारत का प्रतीक है, भारत के अध्यात्म का प्रतीक है । अतीत के गौरव का प्रतीक है, भारत के भविष्य का महिमामयी चित्र इसमें समुद्भाषित होता है । यह वही भारत है, जो वैदिक ऋषियों से लेकर ऋषि दयानन्द तक, बुद्ध से लेकर नागसेन तक, चैतन्य से चन्द्रधर तक, महाराणा प्रताप से प्रताप आदित्य तक और समर्थ स्वामी रामदास से रामकृष्ण, विवेकानन्द तक, राजा अश्वपति और अश्वघोष से श्री अरविन्द तक, करोड़ों ऋषि, मुनि, साधु, संत, योद्धा, राष्ट्रनायकों का पवित्र पदरज में पवित्र कृत हुआ है । इस पावन भूमि को हम वंदन करते हैं । इसका बिन्दु-बिन्दु यज्ञ भूमि है । जिन्होंने इस भूमि को बेचा, जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए देश को तोड़ा, कोई राजनैतिक, भौगोलिक, अर्थनैतिक, सांस्कृतिक आधार पर नहीं है, साम्प्रदायिक आधार पर जिन्होंने इस देश को तोड़ा, देश के साथ गद्दारी की है, वे आज संविधान की बात करते हैं । इनका क्या अधिकार है?

सर, हिन्दुस्तान से पाकिस्तान का भाग नहीं हुआ है, बंटन हुआ, तीन बीघा, किसने किया, एक ही खानदान ने किया । आज ये संविधान, अखंडता की बात करते हैं । देश को तोड़ने वाले आज देश जोड़ने का नाटक करते हैं । यह नाटक जनता को भलीभाँति मालूम है । हमारा मार्ग भिन्न हो सकता है, परन्तु लक्ष्य एक है । साधन भिन्न हो सकता है, साध्य एक है । रचना भिन्न हो सकती है, साहित्य एक है । भाषा भिन्न हो सकती है, भाव एक है । रीति भिन्न हो सकती है, संस्कृति एक, यह भारतीय संस्कृति है ।

सर, जिस हिन्दुत्व के बारे में ये इतनी बकवास करते हैं, यह हिन्दुत्व ही भारतीय संस्कृति है । मनु महाराज ने बोला यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता:, जहाँ पर नारी का पूजन होता है, वहाँ देवता विहार करते हैं । माननीय राष्ट्रपति जी ने आज गरीब, महिला,

छात्र, शिक्षक, कृषक, श्रमिक सबके कल्याण के लिए मान्यवर प्रधानमंत्री जी के आवेगपूर्ण आवाह्न और प्रचेष्ठा के बारे में उल्लेख किया है । स्वामी विवेकानन्द जी कहते थे : ?Our great national sin is the neglect of women and tyranny over masses.? गरीबों के ऊपर, सामान्य जनता पर जो अत्याचार, जो अवहेलना और महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होता है, यह हमारे राष्ट्र का पाप है ।

आज मान्यवर मोदी जी की प्रचेष्ठा से भारत में महिलाओं का सम्मान बहुगुणित हो गया है । सुरक्षा बहुगुणित हो गई है । आज नाबालिग से बलात्कार पर मृत्युदंड की व्यवस्था है । ये सब लोग तो विरोध कर रहे थे । हजारों साल पहले हमारे देश में ऐसी व्यवस्था थी । कीचक ने देवी द्रौपदी का अपमान किया, उनको भीम ने मृत्युदंड दिया । द्रौपदी के अपमान के कारण कौरवों का समूल विनाश किया गया, उन्हें मृत्युदंड दिया गया । सीता माता के अपमान के प्रतिकार के लिए रावण का वध किया गया । इस तरह मृत्युदंड की व्यवस्था हजारों साल पहले थी ।

आज भी इसको मान्यवर मोदी जी ने पुन: प्रतिष्ठापित किया है । महिलाओं के सम्मान के लिए क्या कुछ नहीं किया गया है । कोई इक्का-दुक्का घटना हो जाती है, तो हम उसका विरोध करते हैं, प्रतिकार करते हैं और ये इसको लेकर उछाल करते हैं । महाकुम्भ में जो दुर्घटना हुई, उसने हमारी आत्मा को झकझोर दिया । सब लोग बहुत दुखी हैं, हम भी इसके लिए संवेदना ज्ञापित करते हैं । ऐसी घटना भविष्य में कभी न हो, यह प्रार्थना करते हैं, इसके लिए प्रयास भी करेंगे ।

सर, मान्यवर प्रधानमंत्री जी ने हमारे राष्ट्र का गौरव बढ़ाने के लिए क्या कुछ नहीं किया है । महामहिम राष्ट्रपति जी ने इस सबके बारे में उल्लेख किया है । हमारा देश अत्यंत प्राचीन देश है । महामहिम राष्ट्रपति जी ने लोगों के मेडिकल असिस्टेंस के लिए जिस व्यवस्था का उल्लेख किया है, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना से लेकर सारे विषयों की चर्चा की है । हाईस्ट रेलवे लाइन, हाईस्ट टनल हमारे देश के वर्चस्व, ताकत, शक्ति का प्रमाण करती है । आज भारत भीख मांगने नहीं जाता है ।

भारत ने 100 से ज्यादा देशों को कोविड की वैक्सीन दी है । हाइड्रोक्सीक्लोरीक्वीन अमेरिका को दी है । भारत का गौरव आकाश जैसा ऊँचा हो गया है । रूस-यूक्रेन के युद्ध के समय में, इतनी प्रतिकूल परिस्थिति में, कोविड के समय में, प्रधानमंत्री जी ने अपने पुरुषार्थ के द्वारा इस राष्ट्र चेतना को जाग्रत करके जनभागीदारी के द्वारा अद्‌भुत काम किया है ।

प्रधान मंत्री जी भारत की अर्थ नीति को 11वें नम्बर से 5वें नम्बर तक लाए हैं और वर्ष 2047 तक भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थ नीति बनेगी, यह संकल्प माननीय मोदी जी ने किया है । यह सेल्फ कांफिडेंस का भाव इस वक्तव्य से पूरे देश में झलक रहा है ।

माननीय सभापति : आप कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए ।

श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी : सभापति जी, भारत के इस बढ़ते कदम को जो सहन नहीं कर पा रहे हैं, उस देश के साथ इनका सम्पर्क बहुत मधुर है । मैं इस वक्तव्य का समर्थन करता हूं । यह भारत का विजन फार साइट और अत्यंत प्रभावी वैश्विक नेतृत्व को दर्शाता है । जी-20 में भारत ने एंटायर थीम को बदल दिया । सिर्फ आर्थिक विषय पर नहीं, वसुधैव कुटुम्बकम का महान भारतीय आदर्श का उद्बोधन करके सारे विश्व में भारत की चिंता, चेतना का प्रसारण किया । इससे सारे विश्व में भारत का संवर्धन हुआ । मैं इसका समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री मुरारी लाल मीना (दौसा) : महोदय, मैं सबसे पहले महाकुम्भ में हुए हादसे में मृतकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं ।

महोदय, सरकार रोजाना कुम्भ में स्नान करने वालों की संख्या बताती है । कभी एक करोड़ लोग, कभी दो करोड़ लोगों द्वारा स्नान करने की संख्या सरकार बताती है । मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जब करोड़ों की संख्या को गिना जा सकता है तो जो मृत श्रृद्धालु थे, उनकी संख्या क्या सरकार बता नहीं सकती है? मैं समझता हूं कि यह सनातन धर्म और हम सभी के लिए भी बहुत दुख की बात है कि आज तक मृतकों की संख्या बताई नहीं गई है । महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने भारत सरकार की विभिन्न उपलब्धियों को रेखांकित किया है । सरकार अपनी नीतियों की सराहना कर रही है जबकि निष्पक्ष मूल्यांकन किया जाए तो हकीकत कुछ और है । सरकार लगातार यह दावा कर रही है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक है लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि आर्थिक असमानता बढ़ती जा रही है । देश की दस प्रतिशत आबादी के पास 77 प्रतिशत सम्पत्ति है, जबकि आम आदमी महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहा है । सरकार की नीतियां पूंजीवाद को बढ़ावा दे रही हैं । वर्ष 2024 में भारत में अरबपतियों की संख्या 200 को क्रॉस कर गई है, जो वर्ष 2013 के मुकाबले 41 प्रतिशत अधिक है । वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार देश की 40 प्रतिशत सम्पत्ति केवल एक प्रतिशत लोगों के पास है । क्या सरकार पूंजीवाद के खिलाफ कोई कदम उठाने का विचार रखती है? यदि इस प्रकार असमानता बनी रही और बेरोजगारी बढ़ती गई, तो मान्यवर एक दिन ऐसा आएगा कि देश में जो बेरोजगार हैं, असहाय हैं वे इन पूंजीपतियों के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर देंगे जो हमारे प्रजातंत्र के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर सकता है ।

सभापति जी, मैं राजस्थान की दौसा लोक सभा सीट से आता हूं, जहां अधिकतर जनसंख्या एसटी, एससी,ओबीसी और किसान-मजदूरों की है लेकिन सरकार की प्राथमिकताओं में ये समाज कहीं नहीं दिखाई देते हैं । सरकार लगातार ?सबका साथ, सबका विकास? का नारा देती है लेकिन जब नीति निर्माण की बात आती है तो यह नारा मात्र एक जुमला बनकर रह जाता है । बेरोजगारी वर्तमान में चरम पर है लेकिन सरकार न तो नई नौकरियों का सृजन कर रही है और न पुरानी नौकरियों के रिक्त पदों को भर रही

है । 40 लाख पद देश के अंदर हैं, इनमें से 25 परसेंट सरकारी पद वर्तमान में खाली हैं । करीब 9 लाख पद के आस-पास वेकेंट पोस्ट्स देश में हैं । मनरेगा योजना, जो ग्रामीण भारत की रीढ़ थी, उसमें भी कटौती हो रही है । चार करोड़ से ज्यादा जॉब कार्ड्स पिछले सालों में रद्द हो गए हैं । मजदूरी महंगाई के अनुपात में बढ़ नहीं रही है । एक रिपोर्ट के अनुसार देश में 34 प्रतिशत लोग 100 रुपये प्रतिदिन में अपना घर चला रहे हैं और 80 प्रतिशत लोग 200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अपना घर चला रहे हैं । यह सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने की बात कह रही है और एक तरफ सरकार कह रही है कि 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से पार कर दिया है । इन दोनों बातों में भिन्नता है । सत्य क्या है, इसे सरकार को स्पष्ट करना चाहिए ।

मान्यवर, जहां तक किसानों का सवाल है, एमएसपी की मांग किसान लम्बे समय से करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक किसानों को, एमएसपी की गारंटी को कानून का दर्जा नहीं दिया ।

जो फसल बीमा योजना है, उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि प्राइवेट कंपनियां किसानों से करोड़ों रुपये वसूल कर रही हैं । मैं समझता हूं कि जितने पैसे बीमे के प्रीमियम के रूप में ले रहे हैं, उसका दस प्रतिशत भी वे किसानों को वापस नहीं कर रही हैं, क्योंकि किसान विधिवत रूप से समय पर उसके लिए आवेदन नहीं कर पाते हैं । उनकी पॉलिसी ऐसी है कि समय पर उसे एप्लाई नहीं करने की वजह से हजारों करोड़ रुपये कंपनियां कमा रही हैं । मैं समझता हूं कि इसमें सरकार को सुधार करना चाहिए ।

मान्यवर, वर्ष 2014 में आपने वायदा किया था कि हम हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे । मैं जानना चाहूंगा कि पिछले 11 सालों में सरकार ने कितनी नौकरियां दी हैं? मैं समझता हूं कि इसके उलट सरकार ने लाखों पदों को समाप्त कर दिया ।

आप एस.सी., एस.टी., ओबीसी की बात करते हैं । नौकरियों के कम होने से यदि सबसे ज्यादा किसी को नुकसान होता है तो वह एस.सी., एस.टी., ओबीसी को ही होता है । आप एक सोची समझी नीति के तहत काम कर रहे हैं । बीजेपी, आरएसएस की मूल भावना है कि आरक्षण खत्म होना चाहिए । आप सीधे तौर पर आरक्षण को खत्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष तरीके से पदों को समाप्त करके, निजीकरण करके आरक्षण को समाप्त कर रहे हैं । चाहे शिक्षा का निजीकरण हो, चाहे स्वास्थ्य का निजीकरण हो, चाहे रेलवे का निजीकरण हो, चाहे हमारे पब्लिक सेक्टर्स का निजीकरण हो, आपने सारे ऐसे काम किए हैं, जिससे लाखों नौकरियां खत्म हो गयीं और एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से हमारा आरक्षण समाप्त हो गया । यह इस बात को सिद्ध करता है कि आपकी हमारे प्रति क्या सोच है । यदि वास्तव में आप एस.सी., एस.टी., ओबीसी के पक्ष में हैं, तो बहुत से ऐसे विभाग हैं, जिनमें आपको आरक्षण की व्यवस्था को लागू करना चाहिए । मेरा आपसे निवेदन है । पिछली बार भी मैंने निवेदन किया था । एक तरफ तो मुझे खुशी है कि महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी ने भी एक रोज इसके बारे में कहा था । देश में सुप्रीम

कोर्ट और हाई कोर्ट्स में एस.सी., एस.टी., ओबीसी के ज़ीरो जजेज हैं । मेरा आपसे निवेदन है कि आप ऐसी कोई व्यवस्था करें कि देश में जिस तरह से भारतीय प्रशासनिक सेवा है, उसी तर्ज पर ज्युडिशियल सेवा भी लागू की जाए और उसमें आरक्षण को लागू किया जाए, ताकि न्यायिक सेवाओं में भी एस.सी., एस.टी. के लोगों की भर्ती हो सके । इसके अलावा, राज्य सभा और दूसरे संस्थान हैं, जिनमें आरक्षण को लागू किया जाए ।

महोदय, सबसे बड़ी बात यह है कि संविधान के अन्दर पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में आरक्षण की व्यवस्था है । देश में 10 प्रतिशत के आस-पास एस.टी. के लोग हैं, 16-17 प्रतिशत एस.सी. के लोग हैं । हर सर्वे में कई बार एस.सी., एस.टी. की संख्या भी बढ़ती जा रही है । इसलिए पॉपुलेशन के अनुपात में आरक्षण को भी बढ़ाया जाए । एस.टी. के आरक्षण को बढ़ा कर 10 प्रतिशत और एस.सी. के आरक्षण को बढ़ाकर 17 प्रतिशत किया जाए ।

महोदय, मेरा एक और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है । जो सांसद निधि है, इसके बारे में हमारे और साथियों ने भी कहा है । आप इस सांसद निधि को खत्म कर दीजिए या फिर विधायक के अनुपात में इसको बढ़ा दीजिए । हमारे राजस्थान में ही एक सांसद के क्षेत्र के अन्तर्गत आठ विधायक आते हैं । एक विधायक की विधायक निधि 5 करोड़ रुपये की होती है, 8 विधायकों की विधायक निधि कुल मिलाकर 40 करोड़ रुपये हो गयी और एक सांसद को मात्र 5 करोड़ रुपये मिलते हैं । स्थिति यह है कि एक सांसद एक ग्राम पंचायत में एक लाख रुपये भी नहीं दे सकता है, इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से, माननीय प्रधान मंत्री महोदय से, माननीय वित्त मंत्री महोदया से निवेदन है कि आप इस सांसद निधि को एम.एल.ए. निधि के पैरेलल 40 करोड़ रुपये कर दें या फिर इसे खत्म कर दें, ताकि सांसदों को बेइज्जती महसूस न हो ।

महोदय, राजस्थान के बारे में मेरा एक अंतिम निवेदन है । आपको पता है कि राजस्थान में पानी का बहुत अभाव रहता है । जब बीजेपी की सरकार थी, उस समय राजस्थान के 13 जिलों के लिए पीने के पानी के लिए ई.आर.सी.पी. के नाम से एक नहर परियोजना बनी थी । उसके लिए राजस्थान का मध्य प्रदेश के साथ समझौता हुआ था । वह समझौता 50 प्रतिशत निर्भरता पर हुआ था । उसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की फाईल बहुत लम्बे समय तक पड़ी रही, लेकिन उसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं किया गया । अभी जब राजस्थान में आपकी सरकार बनी है, तो अभी 75 प्रतिशत जल निर्भरता पर वह समझौता किया गया है । इससे राजस्थान को मिलने वाला पानी आधा ही रह गया है । राजस्थान को सिंचाई का पानी नहीं मिलेगा । इससे राजस्थान को बहुत घाटा हो गया है । इसलिए इसकी तरफ भी ध्यान दिया जाए ।

SHRI NILESH DNYANDEV LANKE (AHMEDNAGAR): Hon. Chairman Sir, thank you very much. Today, I rise to participate in the discussion on motion of thanks on the President?s Address. Sir, our life is very busy nowadays and that is

why our health is also very important. In this year?s budget, there are many announcements made by Central Government regarding health schemes, but still there are some shortcomings.

In this budget, Many major health related issues have been completely ignored. The total allocation for health has been increased but, it is still very less in comparison to the GDP. We have a population of 140 crore people and that is why it is a meager allocation. More primary health centers in rural areas and District Hospitals in urban areas are needed as the number of health centers is very less and not up to the mark.

In many hospitals and health centers, doctors and medical staff is not available. So, the recruitment of doctors and nursing staff in sufficient numbers is very necessary. All kind of medical infrastructure should also be developed at such centers.

This Government is implementing Ayushman Bharat Scheme, but it is beneficial only to the private hospitals and doctors. Public health service is deteriorating day by day and a common man is not benefitted out of it, but the private medical institutions are taking advantage of it.

Sir, we must focus on research in pharmaceutical sciences and new medical techniques and more fund should be allocated for this purpose. As you know, we had to face Corona Pandemic in the year 2019-20 and lakhs of people died during Covid. Keeping this in mind, the Government should allocate maximum fund for health sector. There is a medical emergency in our country because small children falling prey to the diseases like cancer. Neonatal and newborns are also facing the liver and kidney diseases. Considering this situation, we must allocate maximum fund for Health Ministry. In western countries, they prefer public health service and not the private one. These countries are providing all kinds of medical facilities to their citizens. But, in India, we are lacking behind and not providing sufficient and satisfactory health services to our citizens. Many schemes like Mahatma Jyotirao Phule Jan Arogya Yojana, Mukhyamantri Sahayata Nidhi, or Ayushman Bharat are being run by state and central Governments. But the financial assistance which is provided under these schemes is meagre and it cannot even match the hospital expenses. The

cancer like diseases require Rs. 30-40 lakh for treatment, and for kidney and liver transplant you need Rs. 20-25 lakh.

A common poor person cannot afford this huge medical expresses. Hence, it is need of the hour that we must allocate more funds commensurate with our GDP growth. I seriously feel that this government has completely ignored the interests of farmers. No concrete decisions have been taken for farmers? welfare in this year?s budget. There was no clear announcement regarding granting the legal sanctity to MSP.

There is a significant cut back in the subsidy for fertilizers, diesel and seeds and due to this, there is a higher possibility of increasing the production cost. But, the loan waiver and improved crop insurance still remains a distant dream for crores of farmers. Everybody was waiting for it, but it has been completely ignored while drafting the budget. This government is inviting big corporate players in agriculture business and that is why there is a potential threat to small and marginalized farmers. So, it is clear that, there was no focus on farmers in this budget.

The Union Government should start new schemes to increase milk rates. MSP should be given for the milk production and its procurement. It is at Rs. 35-40 per litre considering the production cost. But, the procurement rate should be based on the actual production cost of milk. Government should act strictly against the milk adulteration because the milk adulteration is causing cancer to small children. It is also very important to look into it seriously.

Please give me half a minute more.

श्री रोडमल नागर (राजगढ़) : सभापति महोदय, आपने महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के समर्थन में मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपके प्रति धन्यवाद प्रकट करता हूं । सरकार गरीब, युवा, किसान, महिला उत्थान के दृढ़ संकल्प एवं समावेशी संकल्प के साथ-साथ आगे बढ़ रही है । संरचनात्मक सुधार एवं पिछले दस सालों के दौरान किए गए परिवर्तनकारी कार्य सरकार के विकास के ट्रैक रिकॉर्ड की तरफ ध्यान आकर्षित कर रहे हैं ।

महोदय, सरकार ने देश में नागरिकों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए एक लाख पचहत्तर हजार आयुष्मान आरोग्य केंद्र बनाए हैं । यह समाज के लिए मंदिर ही है । देश में कैंसर मरीजों की बढ़ती संख्या और इलाज में होने वाले खर्च को देखते हुए अनेक कैंसर दवाओं को कस्टम ड्यूटी से मुक्त कर दिया है । प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र

पर अब आधी कीमत पर सस्ती दवाएं उपलब्ध हो रही हैं । सर्वाइकल कैंसर के लिए अब तक करीब नौ करोड़ महिलाओं की स्क्रीनिंग की जा चुकी है । भारत में आधुनिक आत्मनिर्भर कृषि व्यवस्था का लक्ष्य सरकार द्वारा तय किया गया है । सरकार किसानों को फसलों का उचित दाम दिलाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए समर्पित भाव से काम कर रही है । आज भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध, दाल और मसालों का उत्पादन कर रहा है । सरकार खरीब और रबी फसलों की एमएसपी निरंतर बढ़ा रही है और खरीदी भी कर रही है । पिछले एक दशक में धान, गेहूं, दलहन, तिलहन और मोटे अनाज की खरीदी पर तीन गुना ज्यादा राशि दी गई है । किसानों की आमदनी अधिक बढ़ाने के लिए सीमित जमीन में अधिक उत्पादन करने के लिए पिछले छह महीने में फसलों की जलवायु अनुकूल करके अच्छी उपज देने वाली 109 उन्नत प्रजातियों को विकसित किया गया है ।

महोदय, सहकारिता के माध्यम से अधिकतम लोगों को जोड़कर आठ लाख सहकारी संस्थाएं एवं उनके 29 करोड़ हितधारक सदस्य ग्रामीण भारत के करीब 90 प्रतिशत क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं । बीते वर्षों में शहरी क्षेत्रों में सरकारी संस्थाओं का विस्तार सरकार द्वारा किया गया है । सरकार के प्रयास से 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं । पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो सपना था, नदियों से नदियों को जोड़ना, उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सूखा ग्रस्त इलाकों में सिंचाई और पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए दो ऐतिहासिक नदी जोड़ो परियोजनाओं पर कार्य आगे बढ़ाया है । 40 हजार करोड़ रुपये की लागत से केन-बेतवा लिंक परियोजना से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लाखों ग्रामीण भाई-बहनों को लाभ मिलेगा । 72 हजार करोड़ रुपये की संशोधित पार्वती-काली सिंध-चम्बल लिंक परियोजना से राजस्थान और मध्य प्रदेश में सिंचाई और पीने के पानी की आवश्यकता की पूर्ति होगी । इस परियोजना से मेरे अपने लोक सभा क्षेत्र राजगढ़ में भी एक लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी । पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा करने के लिए 12 हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि भी सरकार ने स्वीकृत की है ।

महोदय, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी का कोई निजी मकान नहीं है । उनकी कृपा व आशीर्वाद से मेरे अपने लोक सभा क्षेत्र में दो लाख से अधिक मकान बने हैं । पूरे देश में चार करोड़ से अधिक मकान बने हैं, लेकिन उनका स्वयं का कोई मकान नहीं है । ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं । आजादी के दो दशकों के बाद भी हमारे आदिवासी समाज की उपेक्षा होती रही है । सरकार ने उनके कल्याण को पहली प्राथमिकता दी ।

महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में देश भर में 470 से अधिक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के माध्यम से लगभग सवा लाख आदिवासी बच्चों को शिक्षा दी जा रही है ।

23.00 hrs

माननीय सभापति : नागर जी, एक मिनट रुकिए । सभा का समय तीन मिनट और आगे बढ़ाया गया ।

अब आप बोलिए ।

श्री रोडमल नागर : जो लोग अंतिम पंक्ति में खड़े हैं, उनके चेहरे पर इस सरकार के कार्यक्रम से खुशहाली आ रही है । बड़ी खुशी की बात है कि मेरे स्वयं के जिले में, जो आकांक्षी जिला है, आदरणीय प्रधान मंत्री जी के सहयोग से वहां एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई है । पिछले दस वर्षों में आदिवासी बहुल इलाकों में तीस नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं । विशेष राष्ट्रीय मिशन चलाकर आदिवासी समुदाय की सिकल सेल से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं पर ध्यान दिया जा रहा है । इस मिशन के अंतर्गत लगभग पांच करोड़ व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है । जनजातीय विरासत को सहेजने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं । इस वर्ष भगवान बिरसा मुंडा का 150वां जयंती पर्व पूरे देश में जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है । चाहे धरोहर एवं सांस्कृतिक चेतना के पुनर्जागरण की बात हो, विश्व के सांस्कृतिक मंच पर भारत ने अपनी पहचान ग्लोबल लीडर के रूप में बनाई है । सरकार ने रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, ये तीन मजबूत स्तम्भ विकसित किए हैं, जो पूरी दुनिया में भारत के नए गवर्नेंस मॉडल का पर्याय बन गए हैं । वैश्विक अस्थिरता के वातावरण में भारत आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक स्थिरता का स्तम्भ बनकर विश्व के सामने आदर्श प्रस्तुत कर रहा है । चाहे जी-7 समिट हो, क्वाड, ब्रिक्स, एससीओ हो या जी-20, भारत के सामर्थ्य, नीति और नीयत पर पूरे विश्व ने भरोसा जताकर समृद्धि की दिशा में सरकार द्वारा किए गए सकारात्मक आमूलचूल परिवर्तनों को सार्थकता प्रदान की है ।

महोदय, मैं राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण का समर्थन करता हूं ।

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही कल मंगलवार, दिनांक 4 फरवरी, 2025 को प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

23.03 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, February 4, 2025/Magha 15, 1946 (Saka).

ANNEXURE-I

(i) Member-wise Index to Starred Questions

Sl No.	Member's Name	Question Number